Friday, April 07, 1978
Chaitra 17, 1900 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Sixth Series)

Vol. XIII

[April 5 to 19, 1978/Chaitra 15 to 29, 1900 (Saka)]

Fourth Session, 1978/1899—1900 (Saka)

(Vol. XIII contains Nos. 31—40)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

CONTENTS

No. 33, Friday, April 7, 1978/Chaitra 17, 1900 (Saka)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions:	
*Starred Questions Nos. 637, 638 and 640 to 644	1—35
Written Answers to Questions:	
Starred Questions Nos. 639, 645, 646 and 648 to 656	35—52
Unstarred Questions Nos. 5971 to 5983, 5985 to 5993, 5995 to 6043, 6045 to 6109, 6111 to 6114, 6116, 6117, 6119 to 6127 and 6129 to 6170	52—261
Papers laid on the Table	262, 266—72
Re. Question of Privilege	262—66
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—Reported indefinite tools down strike by workers paralysing work at the Vikram Sarabhai Space Centre at Thumba	272—80
Shri M. Ram Gopal Reddy	272, 275—78
Shri Morarji Desai	272—75, 278—80
Petition re. Enquiry into Affairs of Containers and Closures Limited and its Nationalisation	281
Statement re. Reopening of Railway Sponsored Students' Hostel at Patna Junction	281—82
Prof. Madhu Dandavate	281
Matters under Rule 377—	
(i) Reported Press Release by the Railways about holding up of railway wagons by Coal India Ltd.	
Shri Nirmal Chandra Jain	282—83
(ii) Reported agitation by Paddy producers for raising the price of paddy in Andhra Pradesh	
Shri P. Rajagopal Naidu	283—84
(iii) Constitution of a bench of High Court for Marathwada Region—	
Shri Keshavrao Dhondge	284—85
(iv) Reported purchase of shares of Birla Group of Industries	
Shri K. P. Unnikrishnan	285—86
Demands for Grants, 1978-79—	
Ministry of Health and Family Welfare	286—353
Shri Raj Narain	287—97
Shri V. Kishore Chandra S. Deo	297—306
Shri Keshavrao Dhondge	306—15
Shri Brij Bhushan Tiwari	315—23
Shrimati V. Jeyalakshmi	323—30
Shri Yuvraj	330—34
Shri Ajit Kumar Saha	334—39

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

COLUMNS

Dr. Bijoy Mondal . . . . . 339—43
Shri P. V. Periasamy . . . . . 343—48
Shri Saugata Roy . . . . . 348—53
Dr. Sushila Nayar 353

Bills Introduced—

(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 292 and 293) by Shri Om Prakash Tyagi 354
(2) Workmen's Compensation (Amendment) Bill (Amendment of section 2, 3, etc.) by Shri Prasannbhai Mehta . . . 354
(3) Payment of Wages (Amendment) Bill (Amendment of sections 1, 2, etc.) by Shri Prasannbhai Mehta . . . 354—55
(4) Payment of Gratuity (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 4, etc.) by Shri Prasannbhai Mehta . . . 355
(5) Employees' Provident Funds and Micellaneous Provisions (Amendment) Bill (Amendment, of sections 1,2, etc.) by Shri Prasannbhai Mehta . . . . . 355—56
(6) Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new article 16A) by Shri Roop Nath Singh Yadav 356
(7) Grains Board Bill by Shri Yadvendra Dutt . . . 413
(8) Backward Areas Development Board Bill by Shri Yadvendra Dutt 414
(9) Anti-Espionage Bill by Shri Yadvendra Dutt . . . 414

Mental Health Bill—*Withdrawn*—

Motion to consider—

Shri Purna Sinha . . . . . 356—361
Dr. Ramji Singh . . . . . 361—365
Shri Om Prakash Tyagi . . . . . 365—372
Shri Raj Narain . . . . . 372—385
Dr. Sushila Nayar . . . . . 385—392

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 51) . . 393—413

Motion to consider— . . . . . .

Shri Hari Vishnu Kamath . . . . . 393—408
Shri Kanwar Lal Gupta . . . . . 408—413

Motion re. Atrocities on Harijans— . . . . . 415—466
Shri Shiv Narain Sarsonia . . . . . 416—423
Shri Yeshwantrao Chavan . . . . . 423—429
Dr. Ramji Singh . . . . . 429—433
Shri C. M. Stephen . . . . . 433—438
Shri Yuvraj . . . . . 438—441
Shri Hukamdeo Narain Yadav . . . . . 441—444
Shri S. S. Lal . . . . . 444—447
Shri Morarji Desai . . . . . 447—459
Shri Ram Vilas Paswan . . . . . 459—466

LOK SABHA

Friday April 7, 1978/Chaitra 17, 1900 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य व्यापार निगम द्वारा बम्बई तथा कांडला में भण्डारण-टैंक किराये पर लिया जाना

*637. **श्री राम सेवक हजारी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने बम्बई तथा काडला मे कास्टेक्स (एक सरकारी उपक्रम) के भडारण-टैंक सीधे ही इस उपक्रम से न लेकर एक प्राइवेट पार्टी के माध्यम से किराये पर लिये है जिसके फलस्वरूप यह बिचौलिया पार्टी प्रतिवर्ष लाखो रुपये का मुनाफा कमा रही है जो कि राज्य व्यापार निगम के खाते से जाता है , और

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने दिल्ली में भी इसी प्राइवेट पार्टी को वित्तीय सहायता देकर बहुत अधिक रियायतो तथा विशिष्ट शर्तों पर इस पार्टी से भडारण-टैंक किराये पर लिये हैं जब कि अन्य मामलो में अन्य पार्टियो द्वारा विशेष अनुरोध किये जाने पर भी यह किसी को नही दी गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

(क) 31-3-78 को राज्य व्यापार निगम की बम्बई और काडला मे लगभग 1 10 लाख मे० टन की कुल भण्डारण क्षमता मे से बम्बई और काडला मे कालटेक्स की (जो उस समय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नही था) लगभग 11,200 मे० टन और 19,000 मे० टन की भण्डारण क्षमता राज्य व्यापार निगम द्वारा जुलाई, 1975 और अगस्त, 1976 मे डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (गैर सरकारी फर्म) से किराये पर ली गई थी और इस प्रकार उस की कुल टैंक-क्षमता 30,200 मे० टन हो गई थी । राज्य व्यापार निगम का इस प्रबन्ध मे डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा किये गये लाभ के बारे मे जानकारी नही है । ये टैंक सीमित टैंडर जारी करके किराये पर लिये गये थे ।

(ख) जनवरी, 1977 मे राज्य व्यापार निगम को लगभग 5 लाख मे० टन खाद्य तेल का व्यापक आयात कार्यक्रम आरम्भ करना था और निगम को खास तौर से उत्तरी भारत मे, जहा दिसम्बर 1976 के अन्त मे केवल 5,325 मे० टन भण्डारण क्षमता थी, बहुत ही अल्प सूचना पर भण्डारण क्षमता का प्रबन्ध करना पडा ।

डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन से एक प्रस्थापना प्राप्त हुई थी जिसमे उन्होने 3-4 महीनों के समय के भीतर दिल्ली मे 4,200 मे० टन क्षमता के टैंको का निर्माण करने की

पेशकश की थी। उनकी प्रस्थापना पर विचार किया गया और राज्य व्यापार निगम के निदेश मण्डल के अनुमोदन से प्रश्नाधीन टैंकों के निर्माण के लिये फरवरी, 1977 मे उनको आशय पत्र जारी किया गया। फर्म की प्रस्थापना थी कि टैंक के निर्माण के लिये राज्य व्यापार निगम पेशगी दे जिसका समायोजन हैंडलिंग प्रभारो आदि से कर लिया जाये लेकिन फर्म ने उस पेशगी का लाभ नही उठाया है। टैंको का निर्माण उन्होंने अपने पैसे से किया और ये टैंक राज्य व्यापार निगम को किराये पर दे दिये गये हैं। जिस समय अतिरिक्त टैंक बनाने के सम्बन्ध मे मै० डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन की प्रस्थापना पर राज्य व्यापार निगम द्वारा विचार किया गया, जो एकमात्र दूसरी प्रस्थापना प्राप्त हुई थी उसमे पेशगी दे कर या दीर्घावधि आधार पर किराये पर ले कर टैंको के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। बाद वाला विकल्प स्वीकार किया गया।

31 मार्च 1978 को उत्तरी भारत मे 53,000 मे० टन की कुल क्षमता मे से 4 200 मे० टन की क्षमता डिस्टिलर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन से ली गई है।

श्री राम सेवक हजारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है लेकिन जो सरकार की तरफ से जवाब आया है वह बहुत तोड मरोड कर दिया गया है। मै ने पूछा था कि—

क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने बम्बई तथा काडला मे काल्टेक्स (एक सरकारी उपक्रम) के भडारण-टैंक सीधे ही इस उपक्रम से न ले कर एक प्राइवेट पार्टी के माध्यम से किराये पर लिये है ....

इस का तोड-मरोड कर जवाब दिया गया है। मैं पूछना चाहता हू कि कालटेक्स को जब गवर्नमेंट ने ले लिया, 1975 मे यह प्राइवेट था, 1976 में सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो 1976 के बाद सरकार को सीधे ले लेना चाहिए था। फिर बीच मे बिचौलिये के साथ ऐग्रीमेट करने का क्या कारण था और यह ऐग्रीमेट किया गया तो 1976 से अभी तक कितने ऐग्रीमेट किए गए और कितने-कितने दिनों के लिए किए गए।

श्री आरिफ बेग : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्पष्ट किया है, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हू कि उस समय काल्टेक्स सरकारी कब्जे मे नही था और उस वक्त उसकी हैसियत सरकारी सस्था की नही थी जिस समय यह काट्रेक्ट किया गया। कालटेक्स का जितना भी स्टोरेज का टैंक था वह उस प्राइवेट फर्म के पास था लीज पर : और उस समय सरकार के आदेश के मुताबिक एस० टी० सी० को तत्काल यह व्यवस्था करनी थी, बडी मात्रा मे उन्हे टैंक स्टोरेज की व्यवस्था करनी थी इसलिए सीधे जिस फर्म के पास भी टैंक स्टोरेज थी उससे कांटेक्ट किया गया लेकिन जैसे-जैसे हमे सुविधा मिलती गई है हमने इस बात की कोशिश की है कि एस० टी० सी० स्वय अपनी स्टोरेज क्षमता बना ले। जैसे ही जनवरी, 1977 मे काल्टेक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ, हमने जितने भी सम्बन्ध किए है, सीधे काल्टेक्स से किए है। इसके बाद जितना भी हम काम कर रहे है उसमे इस बात की कोशिश की जा रही है कि अब किसी भी प्राइवेट फर्म से न ले बल्कि एस० टी० सी० स्वय की इतनी क्षमता बना ले कि हम अपनी जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

श्री राम सेवक हजारी : मै मत्री जी से जानना चाहता हू कि जब आपने सीधे काल्टेक्स से ले लिया तो फिर इसमे बिचौलियो को लेने का क्या कारण है? इसमे 77 लाख रुपए प्रति वर्ष का घोटाला होता है और करोडो रुपया गवर्नमेंट का जा रहा है तथा इसमे बडे बडे अधिकारियो का हाथ है। मैं माननीय मत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आपने काल्टेक्स के टैंकरो को ले लिया तो फिर अधिग्रहण के बाद इसको क्यो नही लिया, अगर नही लिया तो उसका क्या कारण है?

इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच में आप जो हैंडलिंग करने जा रहे हैं उसके लिए क्या आप टेंडर करेंगे ?

श्री आरिफ बेग : जैसा कि मैंने स्पष्ट आपके सामने निवेदन किया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह जो स्टोरेज टैंक्स हैं कास्टेक्स के कब्जे में उनको किसी इंडिवीजुअल से कांटैक्ट करने का सवाल नहीं है लेकिन जैसा आपने कहा इस सिलसिले में कुछ गलतियां हुई हैं, अगर आप स्पेसिफिक बतायेंगे तो उस पर हम ऐक्शन भी लेंगे ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रिगण हमेशा यह जवाब देते हैं कि सदस्य स्पेसिफिक बतायें, मैं पूछना चाहता हूं कि जो कुछ बताया गया है वह क्या आपके वास्ते काफी नहीं है ? क्या सदस्यगण सी आई डी का काम करें, जो हम आपको सूचना देते हैं उसके आधार पर उसकी तह में जाकर आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप सदस्य के ऊपर भार क्या डालना चाहते हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : यह जो सवाल आया है इस पर हमने विचार किया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि एस टी सी की तरफ से जिस वक्त हमने तेल लेने का इन्तजाम किया तो हमें जरूरत थी कि हमारे पास हमारे गोडाउन्स रहें । आज हाउस को खुशी होगी कि एस टी सी के पास लगभग 2 लाख 50 हजार टन तेल रखने का इन्तजाम हमने किया है । जो कालटेक्स कम्पनी थी उसने कुछ प्राइवेट लोगों के पास से लीज पर लिया था और जो प्राइवेट लोगों के हैं, जिनकी उनके पास लीज थी, जब तक वे लोग वहां हैं हम उनको हटा नहीं सकते हैं फिर भी हमारी कोशिश है कि हम डायरेक्ट लें । हमने एडवर्टीजमेन्ट किया था और हमने बराबर खयाल रखा है, हैंडलिंग चार्जेज मिलाकर 25 रुपए प्रति टन प्रति माह से ज्यादा कहीं भी किराया नहीं लिया जाता है । आप बम्बई के जायेंगे तो 40–50 रुपए से भी ज्यादा किराया गया है लेकिन हमने इसका खयाल रखा है । पोर्ट ट्रस्ट एथारिटी की तरफ से मद्रास, काण्डला और विशाखापत्तनम में हमें जगह मिली है 75 हजार टन तेल के स्टोरेज के लिए टैंक बनाने का काम एस० टी० सी करना चाहती हैं । हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते है, हम आत्मनिर्भर होने चाहते हैं, लेकिन इस बीच में तो तेल कहीं-न-कहीं स्टोर करना पड़ेगा, इस लिये ऐसी व्यवस्था की है, इस में कोई गडबड की बात नहीं है ।

Air Flight from Chandigarh to Bhuntu (Kulu)

*638 SHRI DURGA CHAND Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Air India flight was used to operate during the summer from Chandigarh to Bhuntu (Kulu),

(b) the year of starting and stopping this flight, and

(c) when this flight is likely to be resumed in view of the pressing demand of the people concerned?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 1976 के मानसून शुरू होने से पहले तक गर्मियों के दौरान चण्डीगढ से कुल्लू तक एयर इंडिया नहीं बल्कि इंडियन एयरलाइन्स अपनी उडान परिचालित करती रही ।

(ख) यह सेवा 1967 से 1976 में मानसून शुरू होने से पहले तक परिचालित की जाती रही ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की कुल्लू के लिये विमान सेवा फिर से शुरू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

SHRI DURGA CHAND: I was very shocked to hear the flat reply of the Minister. Indian Airlines had provided air service between Delhi and Kulu *via* Chandigarh since 1966-67. These flights were twice a week and undertaken from 10th May to 15th July and then from 15th September to 15th November This flights was suspended in 1976 after ten years operation Sir. everybody knows the importance of Kulu and Manali. So, Sir, I would like to know the reasons for suspending these flights and when they are going to be resumed again

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : यह सही है है कि 1967 से 1976 तक यह सेवा परिचालित की जाती रही है। इस सरकार के आने के पहले ही इस सेवा का परिचालन बन्द कर दिया गया था। जब यह सरकार यहां आई तो मैंने फिर से इस मामले की जांच कराई। मुझे बताया गया कि जो वर्तमान हवाई-पट्टी है, वह 3700 फिट लम्बी है, जिस में से केवल 2770 फिट को लम्बाई उपयोग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो वर्तमान जहाज है, उन का उस पर उतारा नहीं जा सकता है, इसलिए इस पर फिर से परिचालन करना सम्भव नहीं है।

SHRI DURGA CHAND: Sir, special repair of the aerodrome was done in August-September, 1976 and Rs 12.88 lakhs were spent on these repairs Recently, the Home Minister went to Kulu and the flight was operated and a big aeroplane was taken there. So, Sir, when the aerodrome is quite fit for the operation of the flight then I would like to know why Government is so negligent in not operating the flights.

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: जब पहले इस को परिचालित किया जाता था, उस समय इस की ट्रैफिक औसत 7 से 10 यात्री होती थी। आज भी जो पट्टी है.....

श्री दुर्गा चन्द: गृह मंत्री जी का प्लेन कैसे उतर गया .....(व्यवधान) .....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: इस में माननीय सदस्यों को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब तक उस में सुधार नहीं किया जायेगा, यह हो नहीं सकेगा। डी० जी० सी० ए० के अनुसार और इण्डिन एअर लाइन्ज के अनुसार उस में लोड-फैक्टर-पैनेल्टी अधिक है, हम 50 प्रतिशत से अधिक ट्रैफिक उस में नहीं ले जा सकते है। जो टब.-प्राप है, उस का ब्रेक ईवन भी 95 परसेन्ट होता है। इस लिये यदि हम 50 प्रतिशत सवारियां ले जायगे, तो निश्चित रूप से बहुत अधिक घाटा होगा। वर्तमान में जितनी लम्बी पट्टी है, यदि उसका उपयोग किया जायेगा, तो लोड-फैक्टर पैनेल्टी अधिक होगी। इस लिये जब तक उस का सुधार नहीं होगा तब तक यह सम्भव नहीं है।

दूसरी दिक्कत यह है कि माननीय सदस्य जानते है होंगे कि हवाई पट्टी के एक तरफ व्यास नदी है जिस का कटाव पट्टी के नजदीक तक आ गया है और दूसरी तरफ नदी का पुल भी है। इसलिए उस का विस्तार बहुत अधिक नहीं हो सकता है। टर्बो-प्रोप को अगर वह पर उतारना चाहते है तो उस के लिए कम से कम 5000 फीट से अधिक की लम्बाई की पट्टी चाहिए। जब तक छोटा जहाज न हो वह उतर नहीं सकता।

श्री दुर्गा चन्द : छोटा जहाज हो।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक: ऐसी स्थिति में लोड फैक्टर को देखते हुए और दूसरी चीजों को देखते हुए वहां पर जहाज मुनाफे पर चलाना सम्भव नहीं होगा। जैसा कि मैंने कई बार कहा

है कि सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम छोटे जहाज प्रचालित करें। जब यह योजना पूरी हो जाएगी, तब हम निश्चित रूप से इसे करेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो मुख्य बात बताई है। एक तो यह है कि हवाई पट्टी छोटी है और नदी के कटाव के कारण वह पट्टी बढ़ाई नहीं जा सकती। दूसरा यह कि घाटे में हम इसे चला नहीं सकते क्योंकि यात्री बहुत कम मिलते हैं। अभी हाल में आप ने काफी पैसा खर्च के कर हवाई पट्टी को बढ़ाया उस को ठीक किया है। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस में घाटा होगा इस लिए इस को आप नहीं चलाना चाहते है। दूसरी जगह पर भी घाटे में चल रही है और पोस्ट आफिसेज घाटे में चल रहे है। इस तरह से घाटे की बात देख कर आप चलने तो बड़ा मुश्किल होगा। यात्रियों को कितनी सहूलियतें आप दे सकते हैं यह देखना होगा। इसलिए माननीय सदस्य का उत्तेजित होना स्वाभाविक है जब 10 साल से यह सेवा चल रही थी और इमर्जेन्सी की ग्राउंड ले कर सर्विस को बन्द किया गया है, तो क्या मंत्री जी इस सर्विस के महत्व को देखते हुए, इस को शीघ्र चालू करेंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जिस तरह का टूरिस्ट ट्रैफिक वहां पर है और विदेशी पर्यटक वहां पर आते हैं और उन के लिए वह आकर्षण का केन्द्र है, उस को देखते हुए घाटे का सवाल नहीं है, लेकिन वहां पर जहाज की सुरक्षा का सवाल है। जब तक जहाजों को सुरक्षित रूप से उतारने की वहां पर व्यवस्था नहीं कर लेते, तब तक वहां इन जहाजों को उतारना सम्भव नहीं होगा। एट प्रेजेन्ट का मतलब 'फिलहाल' है। हमारा कहना यह है कि जितनी जल्दी हो सकेगा, निश्चित रूप से हम इस को करेंगे और माननीय सदस्य को हवाई सेवा हम प्रदान करेंगे।

SHRI K GOPAL The hon Minister in his reply made a very amusing revelation that because of the loss incurred, because he is not getting much passenger traffic he has discontinued

MR SPEAKER The landing ground and other things

SHRI K GOPAL That was one of the reasons given by him—not enough passengers I should like to ask him whether the break-even factor for Avro or Fokker Friendship, for Avro I am told is 120 per cent occupancy and for Fokker Friendship it was about 90 per cent (Interruptions) I am subject to correction When such is the case when he is supporting Avros and Fokker Friendships in other routes by subsidising them he is making profits only on jet flights, I hope he will agree with that will the hon Minister consider introducing the service even at the cost of subsidising it from other flights?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK I have already answered that, profitability is not the only consideration before the Government so far as operating the service to Kulu is concerned, it has got tourist attraction also But definitely from the air safety point of view and the minimum length of runway required for operating the service, it is not advisable

श्री गंगा सिंह : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह हवाई पट्टी 3700 फीट है और उस 3700 फीट में से 2700 फीट पट्टी बिल्कुल ठीक है, केवल 1000 फीट पट्टी ऐसी है जोकि आपरेट करने के काबिल नहीं

है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया हैं कि उन्होंने 12 लाख रुपया उस हवाई पट्टी के ऊपर खर्च किया है लेकिन वे वहां एअर सर्विस आपरेट नहीं करने जा रहे हैं, तब तो उस 12 लाख रुपए का उन्होंने दुरुपयोग किया है, यदि एयर सर्विस न चलायें। मैं यह जानना चाहूंगा कि 1000 फीट जो पट्टी है, उस को आपरेशन के काबिल बनाने के लिए कितना रुपया खर्च आएगा और उस रुपए को क्यों नही खर्च करते है।

श्री पुरुषोतम कोशिक : हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उस पर हवाई सेवा शुरु हो। जहां तक हवाई पट्टी बनाने का सवाल है, इसके लिए छठी पंच-वर्षीय योजना मे 11 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होगी कि हम इस काम को शरु करें।

'कोफपोसा' के अन्तर्गत जारी किये गये गिरफ्तारी वारन्ट

*640. **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक प्रत्येक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा 'कोफेपोसा' के अन्तर्गत कितने गिरफ्तारी वांरट जारी किए गए ;

(ख) उनमें से कितने पहली सरकार द्वारा जारी किए गए थे और कितने वर्तमान सरकार द्वारा जारी किए गए थे ;

(ग) इन वांरटो के आधार पर कितने लोग पकड़े गए है; और

(घ) शेष को पकडने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग). आपात स्थिति हटने से पहले (19-12-1974 से 20-3-1977 तक) विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1974 के उपबंधों के अधीन, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारो द्वारा, जारी किए गए नजरबंदी आदेशों की सख्या का और उनमे से 25 मार्च, 1978 तक नजरबद रखे गए व्यक्तियों का विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है। (विवरण-पत्र 'क') आपात-स्थिति हटने के बाद और 25 मार्च, 1978 तक (21-3-1977 से 25-3-1978 तक)' केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उक्त, अधिनियम के उपबंधो के अधीन, जारी किए नजरबंदी के आदेशो की संख्या का और उनमे से 25 मार्च, 1978 तक नजरबंद रखे गए व्यक्तियों का एक अन्य विरण-पत्र भी सदन पटल पर रखा गया है (विवरण-पत्र 'ख')।

(घ) 25-3-1978 की स्थिति के अनुसार उक्त अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को नजरबंद रखने के आदेश दिए गए थे उनमें से 189 व्यक्ति फरार थे अथवा नजरबंद नहीं किए जा सके थे। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सम्पत्तियो की कुर्की की कार्यवाही, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, की धारा 82 से 85 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत की गई है।

विवरण 'क'

आपात स्थिति हटने से पूर्व (अर्थात् 19-12-1974 से 20-3-77 के दौरान), विदेशी मुद्रा सरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए आदेशो की संख्या और उनमे से 25-3-1978 तक नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की सख्या

क्रम सख्या	नजरबन्द रखने वाला प्राधिकरण	आपात स्थिति हटने से पूर्व (अर्थात 19-12-1974 से 20-3-1977 के दौरान जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशो की सख्या	कालम (3) मे दिखाये गए नजरबन्दी के आदेशो मे से 25-3-1978 तक नजरबद रखे गए व्यक्तियो की संख्या
1	2	3	4
1	केन्द्रीय सरकार	322	278
2	आन्ध्र प्रदेश	48	42
3	असम	78	73
4	बिहार	280	116
5	चण्डीगढ	2	1
6	दादर और नगर हवेली	2	2
7	दिल्ली	58	53
8	गोआ, दमन और दिव	70	67
9	गुजरात	494	470
10	हरियाणा	5	5
11	जम्मू और कश्मीर	14	14
12	करनाटक	119	117
13	केरल	111	110
14	मध्य प्रदेश	26	26
15	महाराष्ट्र	726	648
16	मणिपुर	21	18
17	मेघालय	6	6
18	नागालैण्ड	1	1
19	उडीसा	3	3

1	2	3	4
20	पाण्डिचेरी	4	4
21	पंजाब	146	142
22	राजस्थान	14	14
23	तमिलनाडु	329	318
24	त्रिपुरा	54	46
25	उत्तर प्रदेश	180	153
26	पश्चिम बंगाल	235	191
	कुल :	3348	2918*

*इसमें से, 39 व्यक्ति आपात स्थिति हटने के बाद नजरबन्द रखे गए हैं।

विवरण 'ख'

आपात स्थिति हटने के बाद 25 मार्च, 1978 तक, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन जारी किए गए आदेशों की संख्या और उन में से 25 मार्च, 1978 तक नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की संख्या।

क्रम संख्या	नजरबन्द रखने वाला प्राधिकरण	आपात स्थिति हटने के बाद जारी किए गए नजरबन्दी के आदेशों की संख्या	कालम (3) में दिखाए गए नजरबन्दी के आदेशों में से 25-3-1978 तक नजरबन्द रखे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1	केन्द्रीय सरकार	7	6
2	दिल्ली	11	8
3	गोआ, दमन और दिव . . .	1	1
4	गुजरात	34	33
5	करनाटक	19	19
6	महाराष्ट्र	56	51

1	2	3	4
7	मणिपुर	3	1
8	पजाब . .	13	11
9	तमिलनाडु . .	13	11
10	उत्तर प्रदेश	11	10
11	पश्चिम बगाल	18	9
	जोड	186	160

श्री हुकम चन्द कछवाय · आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कोफेपोसा के अन्तर्गत काफी लोगो को बन्द किया गया और काफी लोग फरार रहे । क्या यह बात सही है कि फरार लोगो को अब तक गिरफ्तार नही किया जा सका है? क्या यह बात भी सही है कि जो लोग फरार हैं वे मीसा के कारण फरार रहे या बदले की भावना से भी फरार रहे ? क्या यह भी बात सही है कि इन से बदला लेने की भावना से इन पर आरोप लगाये गए थे ? क्या सरकार यह आश्वासन देगी जो लोग अभी तक पकडे नही गए है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ? क्या सरकार इस प्रकार का कोई विचार रखती है ?

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 19-12-74 से 20-3-77 तक जिन लोगों के खिलाफ डिटेंशन आर्डर्स जारी किए गए थे उनकी सख्या 3348 थी। उनमें से 2879 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया · वे एमर्जेंसी तक गिरफ्तार किए गए थे । बाकी व्यक्ति फरार रहे जो कि नही पकड़े जा सके । जो फरार व्यक्ति थे उनकी संख्या 469 थी । काफी व्यक्ति एमर्जेंसी रिवोक होने के बाद छोड़ दिए गए । एमर्जेंसी के रिवोक होने के बाद एब्सकाण्डर्स की सख्या 257 थी । उन 257 व्यक्तियो के केसिज रिव्यू किए गए और रिव्यू किए जाने के बाद 54 व्यक्तियो के खिलाफ आर्डर्स रिवोक किए गए और 39 व्यक्तियो को गिरफ्तार कर लिया गया । जिन व्यक्तियो के खिलाफ एमर्जेंसी के दौरान डिटेंशन आर्डर्स जारी किए गए थे उनमे से केवल 164 व्यक्ति ऐसे है जो अभी तक फरार हैं गिरफ्तार नही किए जा सके हैं । भारत सरकार ने फ्रेश गाइडलाइस 1 सितम्बर, 1977 को जारी कि हैं । उनके अनुसार इन सारे केसिज का समय समय पर रिव्यू किया जाता है । मेरिट के अनुसार जिनके डिटेंशन आर्डर रिवोक करना जरूरी समझा जाता है , उनके डिटेंशन आर्डर्स रिवोक कर दिए जाते हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने पूछा था कि जो लोग पकडे नही गए है, क्या उनके बारे मे सरकार न्यायालय मे जाने को तैयार है ?

MR SPEAKER He has said that they are being considered on merits

श्री हुकम चन्द कछवाय : मेरे प्रश्न का जवाब देंगे तभी मैं दूसरा पूरक प्रश्न करूंगा ।

पहले मंत्री जी इसका खुलासा कर दें कि क्या वे न्यायालय मे जाने की स्थिति मे है या नही ?

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो केसिज न्यायालय मे जा सकते है उनके बारे मे हम न्यायालय मे जा रहे है। साधारणत ता नीति यही है कि लागा को कोर्ट मे प्रासीक्यूट किया जाए। लेकिन माननीय सदस्य समझते है कि बहुत सारे फाइनेंशियल आरगेनाइजेशन्स हे जिनके खिलाफ सक्सेसफुल्ली प्रासीक्युशन नही हा सकता है वे इन एक्टीविटीज म दुबारा इन्वाल्व न हो उनके खिलाफ ये आर्डर्स हे और उनका रिवोक करने के बारे म मेरिट पर कार्यवाही की जाती है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार का ध्यान मद्रास हाई कार्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के उस निर्णय की ओर गया है जिस मे पिछली सरकार ने काफेपोसा जो लगाया था उसके खिलाफ इन न्यायालयो ने अपने निर्णय दिए हैं ? सरकार का उनके बारे मे क्या मत है।

श्री सतीश अग्रवाल . मद्रास हाई काट नें जो फैसला दिया है उसमे उन्होंने यह होल्ड किया है कि धारा 12ए के तहत एमरजेन्सी के दौरान जा डिक्लेरेशन दिए गए थे यानी ग्राउड्ज फर्निश नही किए जाए यह आवश्यक नहीं है उसके आधार पर मद्रास हाई कार्ट ने कहा है कि ऐसे डिटेशन आर्डर के आधार पर उस व्यक्ति को छाड दिया जाए उसके विरुद्ध भारत सरकार ने स्पैशल लीव पैटीशन सुप्रीम कार्ट मे की हुई है। गुजरात हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एमरजेंसी के दौरान धारा 12ए के डिक्लेरेशन थे उन आर्डर्ज का अपहोल्ड किया है हालांकि वह चीज वहा चैलेंज नही की गई है।

SHRI HITENDRA DESAI: Sir, with regard to the detentions under COFEPOSA, is the policy of the present Government the same as was adopted during the emergency, or is there any change due to the change of heart?

SHRI SATISH AGRAWAL The policy of the present Government is not the same as during the Emergency During the Emergency persons were indiscriminately and arbitrarily arrested while now people are being arrested on a selective basis on the evidence available before the Government

श्री ब्रज भूषण तिवारी ऐसे तस्करा का जिन का इटरपोल पुलिस ने भारत सरकार का हस्तान्तरित किया था उन मे से कितने जेल मे है और कितने इस समय बाहर है ?

श्री सतीश अग्रवाल मैंने निवेदन किया हैकि कुल डेटेन्यूज की संख्या 145 है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेन्यू 6 है और स्टेट गवनमेंटस डेटेन्यूज 139 है। इटरपाल द्वारा हैड ओवर किए गये लोगो की इन मे सख्या क्या है इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नही है और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे ता मैं दे दूगा।

मोती डूगरी महल की तलाशी में बरामद वस्तुएं

*641 **श्री रामनरेश कुशवाहा** : क्या वित्त मत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेगे कि

(क) मोती डूगरी महल की तलाशी मे बरामद वस्तुओ का ब्योरा क्या है और वे कितनी मात्रा मे बरामद हुई;

(ख) इन वस्तुओ को किसने जमा किया था तथा कहा पर, और

(ग) उनका कुल मूल्य कितना है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) (a) to (c) Income Tax authorities authorised under section 132 of the Income Tax Act, 1961 made seizures of the following articles from the Moti Doongri Palace, Jaipur

Date of Seizure	*Items of Seized*
5-6-1975	11 articles of jewellery valued at Rs 235·30 lakhs
10-6-1975	176 items of jewellery and other valuables valued at Rs 31 45 lakh.

The articles seized on 5-6-1975 were deposited in a bank locker in the State Bank of India and were later shifted to the Reserve Bank of India The articles seized on 10-6-1975 were deposited in the strong room of the Government of Rajasthan Treasury at Jaipur

Gold Control authorities made seizure of gold coins, sovereigns, primary gold articles and ornaments totally weighing 873 41 kgs and valued at Rs 460 28 lakhs from the Moti Doongri Palace Jaipur under the provisions of the Gold (Control) Act Besides silver coins (found along with gold coins) weighing 1988 Kg. valued at Rs 19,878/- were also seized from that palace

All the above seized gold and silver items were deposited for safe custody in the strong rooms of Bank of Baroda and United Commercial Bank both situated at Johari Bazar, Jaipur.

श्री राम नरेश कुशवाहा : प्रश्न संख्या 3292 जो कि 9 दिसम्बर, 1977 को मैंने पूछा था उस में मैंने यह पूछा था

"Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari etc. was not deposited or was deposited in short quantity,

(b) the places, where the remain- that today's answer is absolutely correct

(c) the person responsible therefor, and

(d) the action taken by Government in the matter"

इस का उत्तर मंत्री महोदय द्वारा यह दिया गया था कि मोती डूगरी में कुछ भी नहीं मिला। मैंने दोनों के बारे में मोती डूगरी और जयगढ़ के बारे में पूछा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा जवाब सही है ?

मैं आ रहा हूं उस पर।

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन का पहला जवाब सही है या आज का सही है ? अगर दोनों ही सही है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह खजाने में आज जमा हुआ है ? उस समय नहीं जमा हुआ था ? तो अब तक यह धन कहां था ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : मैंने जवाब में साफ कह दिया है कि किन किन तारीखों को यह तमाम चीजें जमा हुई है ? और 5 जून को और 10 जून को जमा हो चुकी हैं। कहां कहां जमा हुई है वह भी बता दिया है ? कुछ को इनकम टैक्स के आफिसर्स ने जमा किया है जो इनकम टैक्स के सिलसिले में पकड़ी गई थी, बाकी चीजों को गोल्ड कंट्रोल एक्ट में पकड़ा गया था और उन को गोल्ड कंट्रोल अथारिटीज ने जमा किया है। सब की सब उन तारीखों में जमा हो चुकी हैं।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दोनों सही हैं ? तो मैं वह जानना चाहता हूं कि पहला जवाब जो आया था वह कैसे सही है अगर उन्हीं तारीखों में जमा हुआ है ? या तो वह सही है या यह सही है। दोनों में से कौन सा सही है ? और अगर पहला सही है तो आज तक अपनी कस्टडी में रखने का जिम्मेदार कौन है ?

अभी हमारे पहले सवाल का जवाब ही नहीं साफ हुआ है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह गलत उत्तर दे रहे हैं। . . .

(व्यवधान)

श्री बुल्लिकार उल्लाह : इस सवाल में दूसरे पेलेसेज का जिक्र नही किया गया, कोई पूछा नही गया है । इस सवाल में मोती डूगरी पैलेस का ही पूछा गया है और उसी का जवाब दिया गया है । इसलिए यह जो अब माननीय सदस्य पूछ रहे हैं यह सही नहीं है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नही आया ।

MR. SPEAKER: He says there is a contradiction. He says that earlier, you have given a different answer.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): There is no contradiction. What he has said today is a correct answer. For the question that is put o-day, he answer is given. And he answer given o-day is correct, as of the date.

MR. SPEAKER: The Minister says that to-day's answer is absolutely correct.

श्री राम नरेश कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी सवाल रह गया है । आप हमारी बात तो सुन लीजिये । मेरा सवाल था :

"The reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari. . .

स्पष्ट था और उस समय जवाब दिया गया कि कुछ नहीं मिला । हमारा प्रश्न है कि आज का उत्तर अगर सही है तो वह खजाना आज तक कहां था । अभी तो हमारा पहला प्रश्न ही नहीं खत्म हुआ । हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिले फिर दूसरा सवाल करने का मौका दिया जाय ।

श्री बुल्लिकार उल्लाह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस का जवाब दूं । पहला सवाल सिर्फ जयगढ़ फोर्ट की खुदाई के मुताल्लिक था । . . . .

श्री हुकम चन्द कछवाय पहला उत्तर उन्होंने गलत दिया था और मंत्री जी ने माना.

(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Mr. Kachwai, he is competent enough to ask. Mr. Kushwaha, you can ask for a half-an-hour discussion, if necessary.

श्री हुकम चन्द कछवाय: वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास जमा था, इस को यह छिपाना चाहते हैं ।

MR. SPEAKER: If the answer is not satisfactory, you can ask for a half hour discussion. But you cannot insist on this.

You must know the rules. (*Interruptions*)***

MR. SPEAKER: Don't record Please, Mr. Kushwaha, I have allowed you 4 questions. If the answers are not satisfactory, you can ask for a half hour discussion. That will be considered.

(*Interruption*)***

MR. SPEAKER: Don't record.

(*Interruption*)***

MR. SPEAKER: Nothing is recorded.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Because he has referred to me, may say this? This is not the way of getting a reply from me, and it does not befit my hon. friend to talk in this manner. I must

***Not recorded.

tell him that. If he is going only to raise his voice like that and think he is right, it is very wrong That is not the way to deal with the question. I hope he will do better than that (*Interruptions*)

श्री भानु कुमार शास्त्री : इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी सदन में प्रश्न रखा था, जिसका उत्तर यह मिला कि वहां से कुछ प्राप्त नहीं हुआ । यह खेद का विषय है । मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो खजाना निकला, जो बैंकों में रखा गया है क्या यह नियम के विरुद्ध था, यदि नियम के विरुद्ध था, तो उन के खिलाफ बीच में कार्यवाही चली और फिर बन्द हो गई आज इतने महीने हो गए हैं वह केस किस स्टेज पर है । गोल्ड कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत या किसी अनियमितता के आधार पर जो केस चला था अब उस का क्या स्थिति है, वह किस स्टेज पर है ?

SHRI H M PATEL I would like to clarify First of all there is a lot of confusion What is referred to is the search for treasure which was said to have been hidden in Jaipur Fort That was one thing That search commenced in June 1976 and was abandoned in November 1976 The search was undertaken under an agreement entered into between the Government of India and Col Bhawani Singh of Jaipur Nothing was found Regarding the expenditure actually we spent quite a lot of money on these digging operations The question that was put today was very clear It says

"(a) the details and the quantity of articles seized during the search of Moti Doongari palace"

We have said what has been found in that Palace

"(b) who deposited these articles and where,"

There also the answer has been given where it is deposited So there is no question of keeping anything back from the House I do not know why the hon Member feels that it has not been answered Then he has asked a further question about the action taken for the enforcement of the Gold Control Act The position under the Gold Control Act is this Two show-cause notices covering the entire items excepting a gold parrot were issued to Shrimati Gayatri Devi Col Bhawani Singh and Shri Jai Singh on the 28th February 1975 and on the 3rd September 1975 A third show-cause notice was issued for the gold articles and parrot to Col Bhawani Singh In all three notices were issued The first two cases covering 895 107 kilo grams of gold has been adjudicated by the Collector of Central Excise Jaipur The seized items have been confiscated, but allowed to be redeemed on payment of a fine in lieu of confiscation of Rs 1 5 crores A personal penalty of Rs 5 lakh in addition has been imposed on Lt Col Bhawani Singh in his capacity as karta of the HUF No penal action has been taken against Shrimati Gayatri Devi as the case is jointly defended by the members of the erstwhile ruling family as HUF The party has paid the fine and the personal penalty on 6th February, 1978 and the goods have been redeemed An appeal filed by the party against the adjudication order has been received recently and is being processed

Tendency to purchase of Gold after Demonetisation

*642 SHRI DHIRENDRANATH BASU Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that after demonetisation of currency notes of Rupees one thousand and above, tendency to purchase of gold in Principal Bullion Markets of India and neighbouring countries like Nepal, Bangla-

desh and Pakistan etc. has considerably increased and some smugglers were also arrested at the borders;

(b) if so, what steps are being taken by Government to prevent them;

(c) whether it is a fact that the moneyed classes are prompt enough in evolving new strategies to dodge the Government by purchasing enough quantity of gold and converting them in making luxurious ornaments; and

(d) whether the Government are considering to allow a couple to retain not more than sixty tolas of gold?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). Under the Gold (Control) Act, 1968, there is a ban on possession/acquisition of primary gold by private individuals and hence the question of persons buying gold in the Bullion markets of India or converting it into ornaments does not arise and no marked increase in the purchase of bullion has been noticed. Reports received do not show that there had been any significant spurt in the smuggling of gold across the borders immediately after demonetisation. There have not been any major seizures of gold and no arrests were also made for smuggling of gold on the borders during the period Preventive vigil continues to check any inflow of gold into India through neighbouring countries. Government are not contemplating any proposal, at present, for a ceiling on private holding of ornaments.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: May I know from the hon. Minister how many persons have been arrested for smuggling of gold at the Nepal and Bangladesh borders.

MR. SPEAKER: He has answered it.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: I know that many thousand tolas of gold were seized and some smugglers were arrested. Subsequently two or three smugglers were released on bail. So, the answer given by the hon. Finance Minister is not correct.

May I know from the hon. Finance Minister whether it is a fact that after demonetisation the price of gold in the bullion market has been increasing and considerable purchases have been made by the rich people who are converting the gold into luxurious ornaments? This is evident from the bullion market reports and stock exchange reports. So, will the hon. Minister let us know how many persons were released after they were arrested for smuggling at the borders?

SHRI H. M. PATEL: The question began with reference to the demonetisation of notes, and I have clarified the position. The hon. Member chooses to say that the information that he has with him is correct and the information I have given is not correct. Let me assure him that the information that I have given is correct.

I will also point out to him that the report that we have received from the Collector, Central Excise, Shillong says that 213 gms. of gold valued at Rs. 13,560 was seized on the Indo-Bangladesh border during the period January-March, 1978. Two persons were arrested for their involvement in smuggling. No smugglers were arrested on the India-Burma border.

SHRI SAUGATA ROY: Indo-Nepal border.

SHRI H. M. PATEL: As far as I know no persons have been arrested.

SHRI SAUGATA ROY: He has not got the facts.

SHRI H. M. PATEL: My information is that during this period there was no seizure of gold on this border, but I will check if you like.

SHRI SAUGATA ROY: You please check it.

SHRI H. M. PATEL: Have you any definite information?

SHRI SAUGTA ROY He has already said that 21 persons have been arrested

SHRI H M PATEL I do not think that information is correct I began by saying that Therefore, it is up to him to tell me If he has more authentic information, I shall be very happy to investigate

SHRI DHIRENDRANATH BASU May I know whether smuggling activities are increasing day by day and huge quantities of gold have been seized by the guards on the borders? What steps the hon Minister proposes to take to prevent smuggling of gold?

SHRI H M PATEL Although this question relates to demonetisation, the hon Member is interested only in knowing whether smuggling activities have increased The question does not relate to that Demonetisation of these high dinomination notes has really got nothing to do with gold

So far as smuggling is concerned there has been no increase in smuggling during this period As far as our information goes the smuggling is on the decline even of gold He referred to the price in the stock exchange and bullion markets and so on The position really is that after the Budget announcement a certain amount of gold would be sold and that gold would be imported for purposes of jwellery which was to be exported it had certain effect on bringing the prices down Thereafter there has again been a slow rise in the price of gold The reason for that is that the market feels that there has not been any arrangement made for the sale of gold In regard to this some days ago I was asked a question by the press I clarified that it would take a little time for making arrangements for the sale of gold in such a manner that the gold is sold at the right price and it goes into the hands of the right people

मध्य प्रदेश के किसानों पर बैंकों के बकाया ऋण

*643 श्री राघव जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के उन किसानों पर बकाया पहले बैंक ऋण पर चालू दर का ब्याज माफ करने का है जिन की फसल इस वर्ष ओले गिरने से नष्ट हो गई है,

(ख) क्या ओले गिरने से प्रभावित किसानों को चालू वर्ष में उदारतापूर्वक बैंक ऋण देने के लिए अनुदेश देने का विचार है जिससे किसान उर्वरक, बीज, बैल आदि खरीद सकें और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) to (c) No Sir Under the guidelines issued by the Reserve Bank of India commercial banks have been advised to allow easy and appropriate rephasing of their recoveries in case of natural calamities or adverse seasonal factors If the damage to crops is more than 50 per cent due to natural calamities like flood drought etc banks generally extend to their borrowers the facility of converting the short term loans into medium term loans The concerned borrowers continue to be eligible for fresh finance for their agricultural operations.

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट रूप से ओला-वृष्टि से पीड़ित किसानों बारे में उल्लेख किया है जबकि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें बाढ़ सूखा आदि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का उल्लेख किया है तो मैं जानना चाहता हूं क्या इस में ओला-वृष्टि को भी प्राकृतिक विपदा माना गया है अथवा नहीं

और यदि माना गया है तो क्या रिजर्व बैंक स्पष्ट रूप से अपनी बैंकों को निर्देश देगी और ओला-वृष्टि का भी उस में समावेश किया जायेगा ? इस के अतिरिक्त जो गाईडलाइन्स रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी थी, वह किस सन् में जारी की गई थी ?

SHRI H. M. PATEL: The answer covers the point that he is concerned with. Whether it is hailstorm or whether it is anything else, if it damages the crops and the damage is of a certain magnitude, then the banks do give certain facilities. The facilities are in regard to re-scheduling the debts. They were required to pay the debts within a certain previously agreed period. Now, a longer period is allowed and certain other facilities are also given.

श्री राघव जी : अध्यक्ष महोदय, इस वक्त मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों में ओला-वृष्टि से भयानक नुकसान हुआ है, कहीं कहीं तो इतना नुकसान हुआ है कि किसानों के खेत में एक भी दाना पैदा नहीं हुआ है, । ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो कर्ज है उस के ऊपर अगर ब्याज भी लिया जाता रहा और विशेषकर पीनल इन्ट्रेस्ट तो बहुत ही अधिक होता है पीनल इन्ट्रेस्ट तो मूल रकम से भी अधिक हो जाता है । जिस का वह भगतान नहीं कर पायेगा, क्योंकि वे ऐसे इलाके हैं जहां बहुत अधिक ओला-वृष्टि हुई है तथा यहां दो फसलें पैदा नहीं होती है, केवल एक ही फसल पैदा होती है । इसलिये किसानों को मजबूर हो कर अपनी जमीनें बेचनी पड़ रही हैं । क्या भारत सरकार रिजर्व बैंक को कहेगी कि दण्ड-ब्याज और ब्याज माफ कर दिया जाय तथा ऐसे आदेश रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों तथा व्यापारी बैंकों को भेज दिये जायें । जिन जिला सहकारी बैंकों ने ऐसा निश्चय कर लिया कि वे ब्याज माफ कर देंगे—क्या उस को रिजर्व बैंक स्वीकार कर लेगा ?

SHRI H. M. PATEL: No, Sir. Such guidelines cannot be issued. But what will be done is that such matters are considered most sympathetically. First of all, there have not been received reports by us of the magnitude of disaster that the hon. Member says took place in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. If the damage is serious, the local bank manager will obtain the information from the collectors and give as much relief as they can. The waiving of penal interest can be considered. But the question of waiving the rest of the interest would be somewhat difficult to consider.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the hon. Minister consider whether it is not necessary to incorporate a rule so that interest is waived when the crops are destroyed by natural calamities?

SHRI H. M. PATEL: The hon. Member should realise that there is a difference between the Government taking certain action of waiving interest and, so far as the banks are concerned, they are commercial organisations and they cannot completely waive the recovery of interest What they can only do is that they can reschedule the debts, that is to say, instead of the farmer having to repay the loan within the period already fixed, he will be permitted to repay it later and a certain amount of concession would also be given in regard to interest.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: Sir, the answer given by the hon. Minister is an exercise in futility. The question is very specific but the answer is in general terms, that is, if we receive information like this, then we will issue instructions like this. You kindly see the question:

> "whether Government propose to waive the current year interest on the previous bank loans outstanding....."

MR. SPEAKER: He has answered it.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: What I want to ask is, whether any

instructions have been issued to the banks for showing laxity in the recovery of the current year's loans. That is a very specific question. I may also add that during my speech on the Budget, I had filed a paper showing how devastating the hailstorm was this year and how much damage has been caused to the crop. It is not, therefore, proper for the Finance Minister to say that he does not know it.

SHRI H. M. PATEL: My hon. friend may be correct in whatever he says about the extent of the damage caused. But the Government has to proceed on the basis of the reports they receive from the Government of the States concerned....

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN: It was a paper based on Government report.

SHRI H. M. PATEL: I must inform him that is the basis on which we would act. Nevertheless, I did answer the question. We cannot say precisely what would be done beyond this. I have said that in keeping with these guide-lines, where the damage to crop by natural calamities is more than 50 per cent of the crop, the banks have a provision of re-scheduling short-term loans into medium-term loans, that is to say, making it for three years. This allows some breathing time to the farmer whose repayment capacity has been impaired due to crop failure.

Blacklisting of firms for Infringement of Import/Export Regulations

*644. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to lay a statement showing:

(a) the number of firms blacklisted for infringement of import/export regulations in the current year and the broad nature of offences committed;

(b) whether any Government officials were found to have aided or abetted the offences; and

(c) if so, the number of such Officers and the action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) (i) Action has been taken against 1830 firms for infringement of Import Export Regulations during the year April, 77 to March, 78.

(ii) Broad nature of offences committed included misutilisation of imported goods, making false/misleading statements in the applications for licences, production of fabricated documents and violation of conditions of the connected licence.

(b) No official of the CCI&E Organisation has so far been found to have aided or abetted the offences in these cases.

(c) Does not arise.

SHRI S. R. DAMANI: May I know from the hon. Minister for how much period these firms had been blacklisted? I would also like to know whether their names had been published; and if so, when; if not, why? What is the value of the goods seized from these firms and the nature of goods?

श्री आरिफ़ बेग : अध्यक्ष महोदय, जिन फर्मों ने इस प्रकार से गलती की है उन के खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया है। उस में हम ने यह किया है कि इन फर्मों को आगे लाइसेंस देने से डिबार किया गया है। इस तरह की 1830 फर्में हैं और उन्होंने जैसा-जैसा गुनाह किया है, उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा।...(व्यवधान)...

मैं आप के माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि 1830 फर्मों के खिलाफ एक्शन लिया है और हर फर्म के खिलाफ जैसी उस ने गलती की है, उस के मुताबिक एक्शन लिया गया है। उस के लिए अलग-अलग से बताना इस वक्त हमारे लिए सम्भव नहीं है।

SHRI S. R. DAMANI: My question has not been answered. I want to know whether the names of these firms have been published and the value of the goods seized.

श्री आरिफ बेग : इस बारे में मालूमात कर के फिर बताऊंगा ।

SHRI S. R. DAMANI: My second question is in regard to (b) part of your answer—no official of the CCI&E Organisation has so far been found to have aided or abetted the offences in these cases. In this connection, may I know from the hon. Minister on what basis he has come to this conclusion that no official was involved in this case when such a magnitude of the offences had taken place and the experienced persons could not detect these mal-practices of frauds, as has been mentioned above?

श्री आरिफ बेग : मैंने स्पष्ट तौर पर यह बताया है कि

"No official of the CCI&F Organisation has so far been found to have aided or abetted the offences in these cases."

जैसा कि माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है हम मालूमात हासिल करेंगे और मैं आप के माध्यम से सदन को मैं यह आश्वासन दूंगा कि यदि कोई भी अधिकारी इस के अन्दर जिम्मेवार पाया जाएगा, तो उस के खिलाफ हम कदम उठायेंगे ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Air Accident Investigation Commission

*639 SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government has reversed its decision to set up 'Air Accident Investigation Commission'; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI FURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). The Civil Aviation Review Committee constituted by Government under the Chairmanship of Shri J.R.D. Tata, recommended in its interim Report submitted to Government in February, 1974, that the function of investigation of serious accidents should no longer be the responsibility of the Director General of Civil Aviation, but should be transferred to an Accident Investigation Commission, to be set up in the Ministry of Tourism & Civil Aviation. This recommendation was accepted by the then Government. The final Report of the Committee which included this recommendation also, was later remitted to an Empowered Committee. Considering that such a Commission when appointed may have very little work to do and also as in major fatal accidents to aircraft operating scheduled services, a Court of Inquiry, normally presided over by a High Court Judge is appointed, the Empowered Committee recommended to Government that setting up of a separate Accident Investigation Commission in the Ministry of Tourism & Civil Aviation as recommended may not be necessary. The recommendation is being processed for a final decision by Government.

Ban on Export of Skeletons

*645. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price of skeletons is rising around the world and India is the largest exporter;

(b) whether it is also a fact that India banned the sale of skeletons between 1976 and 1977 which led to a world-wide shortage and when the ban was lifted there was rush to buy skeletons; and

(c) whether it is also a fact that India's dominance of this lucrative market is well known but it is not known why most skeletons come from India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) to (c) Statistics in regard to world demand and international prices of Human Skeletons are not available It is, therefore, not possible to say whether India is the largest exporter of human skeletons Similarly it cannot also be said whether the price of skeletons is rising around the world

The ban on export of human skeletons was relaxed an 4th May, 1977, on the advice of Ministry of Health However, the export of the item was kept under Export Trade Control under Schedule B' Export is allowed on merits on production of certificate from the foreign buyers that human skeletons are required for biological and medical purposes only

Complaints about the quality of Indian goods

*646 SHRI G Y KRISHNAN Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether Government have received complaints from some foreign countries about the quality of goods imported by them from India;

(b) if so, the names of the countries which have complained and also the details of the goods and the names of the firms about which they have sent complaints,

(c) whether Government have ordered any enquiry into the authenticity of the complaints and whether the complaints have been found to be correct; and

(d) if so, what steps Government have taken against the offending firms?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (d) Some individual complaints regarding quality of goods exported from India have been received from time to time Some of these complaints have been from Ethiopia Kenya, Algeria, Afghanistan USA and USSR regarding chemicals and allied products, fruits and vegetables, marine products etc The complaints are examined as and when they come to the notice of Government in consultation with the Export Promotion Councils/Commodity Board etc., and necessary action taken in the light of the facts and circumstances of each case

Efforts are being made to strictly enforce prescribed standards of quality control and pre-shipment export inspection With a view to provide effective deterrents to export of sub-standard goods, it is also proposed to amend the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963

व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

*646. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अर्थात् 1975, 1976, और 1977 में सरकार ने भारतीय माल के निर्यात में वृद्धि के लिए विदेशों को कितने व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजे तथा ये प्रतिनिधिमंडल किन-किन देशों को भेजे गये थे

(ख) सरकार ने उन पर कितनी धनराशि खर्च की , और

(ख) इन प्रतिनिधि मंडलों के यात्राओं के फलस्वरूप निर्यात में कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख). 1975 में 14, 1976 में 14 तथा 1977 में 8 सरकारी प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न देशों की यात्रा की। उन देशों की सूची, जहां वे गए तथा उनके द्वारा किया गया व्यय विवरण में दिया गया है।

( ) निस्सन्देह विभिन्न देशों को सरकारी प्रतिनिधिमडल भेजने तथा वहा से आमंत्रित करने का इन देशो को हमारे निर्यात बढाने में उल्लेखनीय योगदान रहा है। सरकारी व्यापार प्रतिनिधिमडल भेजना तथा वहा से आमन्त्रित करना सरकार द्वारा व्यापार बढाने के लिये किए जा रहे विभिन्न पायो का एक अग मात्र है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं: मेलों प्रदर्शनियो में भाग लेना, अध्ययन-बहुबिक्री दलो का संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों को भेजना तथा बुलाना, अन्य देशों के बहुविभागीय भंडारोंमें भारत संवर्धन पखवाड़ो का आयोजन। अत: यह बताना कठिन है कि सीधे इन व्यापार प्रतिनिधि मडलो के दौरों के परिणामस्वरूप व्यापार के परिमाण में कितनी वृद्धि हुई है।

विवरण

क्रमांक	प्रतिनिधिमडल तथा देश, जहा का दौरा किया	किया गया व्यय
1	2	3
	1975	
1	ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा स्वीडन	29897.25
2	ब्रिटेन	77347.00
3.	पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन	55828.39
4.	ब्रिटेन	888.00
5.	ब्रिटेन	233.00
6.	(i) ट्यूनिशिया (ii) जोर्डन (4) (iii) सूडान प्रतिनिधिमंडल (iV) कुवेत सउदी अरबिया, आबू धाबा यमन तथा ओमान	85326.00
7.	अफगानिस्तान	7728.00
8.	पाकिस्तान	16493.25
9.	नेपाल	13830.55
10.	श्रीलंका	1685.82
11.	ईरान	10792.43
	1976	
12.	पुर्तगाल	28550.47
12	ब्रिटेन	49693.82
13	ब्रिटेन, इटली तथा पश्चिमी जर्मनी	71979.75
4	स्पेन	29806.50
5.	फ्रांस	66470.85
6.	इटली, यूगोस्लाविया तथा पश्चिम जर्मनी	22080.48
7.	इटली, स्विटजरलैंड पश्चिम जर्मनी तथा आस्ट्रेलिया	97529.30

1	2	3
8.	मिस्र का अरब गणराज्य	10503.00
9.	अफगानिस्तान	8547.00
10.	नेपाल	22642.46
11.	ब्राजील	97610.00
12.	(i) आस्ट्रेलिया (ii) हांग कांग (3 प्रति- (iii) सिंगापुर निधिमंडल)	75896.49

1977

1.	ब्रिटेन	63866.98
2.	ब्रिटेन, नीदरलैंड, बैल्जियम तथा फ्रांस	5522.00
3.	बैल्जियम	उपलब्ध नहीं
4.	बैल्जियम	37628.00
5.	सूडान	12033.00
6.	बंगलादेश	12295.70
7.	श्री लंका	4520.00
8.	अफगानिस्तान	4397.45

Trade between India and Arab States

*649. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to lay a a statement showing:

(a) whether the quantum of trade between India and the Arab States has been showing an upward or downward trend during the last five years;

(b) the details thereof, for each Arab State separately;

(c) whether there is any trade between India and Israel;

(d) if so, the details thereof;

(e) if not, the reasons therefor; and

(f) whether Israel has made any overtures to India for trade relations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) to (f). India's trade with Arab countries has been showing an upward trend during the past five years. A statement showing the country-wise trade figures from 1973-74 is given in the Statement.

2. India does not have any trade agreement with Israel. However, some private trade does take place. The value of trade with Israel since 1973-74 is indicated below:

(Rs. in crores)

	Exports to Israel	Imports from Israel
1973-74	3·85	0·83
1974-75	2·22	0·33
1975-76	3·37	1·22
1976-77	7·02	0·56
1977-78 (April 1977 to June 1977)	1·82	0·20

Statement

India's trade with Arab countries

(Value Rs. crores)

Name of country	1973-74		1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports (April Sep) 1977	Imports (April-June) 1977
Abu Dhabi	3·n	Neg.	4·7	Neg.	10·6	81·5	25·4	84·0	74·5	7·3
Duabi	22·4	0·1	40·2	0·04	55·8	0·1	135·2	0·6		
Bahrain	9·0	7·1	9·5	11·4	17·2	14·6	23·5	4·2	9·2	0·3
Kuwait	21·3	71·1	38·4	63·7	47·3	62·6	113·0	77·3	50·9	7·5*
Oman	6·2	0·3	16·7	0·1	19·5	4·9	30·0	0·4	13·9	0·1
Qatar	7·0	0·01	8·6	Neg.	10·6	3·7	19·3	13·7	9·1	1·5
Iraq	20·3	61·2	72·9	251·5	63·9	247·8	46·6	280·2	30·9	141·8*
Suadi Arabia	26·1	131·4	35·6	297·7	60·1	290·1	75·1	332·0	53·9	100·9*
Jordan	3·7	8·9	15·4	24·0	10·7	6·2	10·6	4·5	3·2	6·0*
Lebanon	3·0	0·5	4·1	1·4	2·4	0·2	0·6	0·1	0·2	0·03
Syria	2·6	Neg.	7·1	Neg.	2·0	Neg.	4·0	Neg.	3·7	..
People's Democratic Republic of Yemen	5·7	0·03	14·3	0·01	7·5	0·04	7·4	0·04	3·2	0·06
Yemen Arab Republic	2·7	Neg.	16·2	Neg.	16·2	Neg.	44·5	1·3	9·6	0·01
Arab Republic of Egypt	14·8	25·9	52·6	23·6	100·1	19·0	90·8	21·2	43·6	18·1*

Name of Country	1973-74		1974-75		1975-76		1976-77		1977-78	
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports (April-Sep) 1977	Imports (April-June) 1977
Sudan	18·6	21 9	66 5	5 0	36 5	3 6	51·2	19·0	16·9	11·8*
Algeria	0·2	Neg	0 2	Neg	1 5	Neg	2·4	0·1	0·3**	0·1
Libya	5·1	Neg.	8 6	Neg	4 3	Neg	13·1	Neg.	13·6	..
Morocco	0·9	8·6	12·6	19·0	0·8	6.8	0·6	7·8	0·8	7·4*
Tunisia	1·2	Neg	1 0	Neg	5 2	Neg	3·5	..	1·7	0·04
TOTAL	174·4	337·04	425·2	697 45	472 2	741·14	696·8	864·44	339·2	902·94

(*For the period April—September, 1977)

(** For the period April—June 1977)

हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम के जवाहिरात की बिक्री

*650. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के भूतपूर्व निजाम के विश्वविख्यात जवाहिरात बेचे जा रहे हैं। और यदि हां, तो उन का मूल्य क्या है ;

(ख) क्या इन जवाहिरातों को बहुराष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें विदेशों में बेचे जाने से रोकेगी;

(ग) यदि हां, तो यदि वे लोग, जिनके पास ये हैं; इन्हें बेचना चाहें तो क्या सरकार विश्व प्रसिद्ध इन जवाहिरात को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर स्वयं खरीद लेगी; और यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां निजाम के ज्वैलरी ट्रस्ट में रखे कुछ जवाहरात बेचे जा रहे हैं। सरकार यह नहीं जानती कि ट्रस्ट के सारे जवाहरात का मूल्य क्या है !

(ख) जी, नहीं। ट्रस्ट द्वारा जवाहिरात संबद्ध हिताधिकारियों (बेनिफिसरीज) के फायदे के लिए रखे गए हैं। सरकार का जवाहिरात की बिक्री को रोकने का कोई विचार नहीं है, जब तक कि किसी सुसंगत कानूनों के अंतर्गत की जाती हैं ।

(ग) सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और यह फैसला किया है कि लोक धन को बड़ी राशियों को जवाहिरात की खरीद में बांध कर न रखा जाए ।

Opening Bank branches in C. D. Blocks

*651. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to lay a statement showing:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India had issued instructions to all India natianalised banks to open 676 new branches in areas of community development blocks where no banking facilities are available;

(b) if so, which are the selected areas and the time limit upto which such banks can be opened; and

(c) how many such blocks have been selected in Madhya Pradesh and where would the branches of the Bank be opened there?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Banks have been asked to open at least one branch in each of the unbanked community development blocks by end-June 1978. There were over 700 unbanked community development blocks in the country at the end of December, 1976. By the end of December 1977, this number had been brought down to 318.

In Madhya Pradesh there were 134 unbanked community development blocks at the end of December 1976. At the end of December 1977, only 52 such blocks in the State were without a commercial bank branch.

The precise location of the proposed branches within the unbanked blocks allotted to individual banks cannot be indicated since it depends on the selection to be made by these banks themselves having regard to the availability of the requisite facilities, business potential etc.

उत्तर बिहार में हवाई अड्डा

*652. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डे का विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या इस में दरभंगा सिटी को भी सम्मिलित किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ). उत्तर बिहार में दरभंगा के विमान क्षेत्र सहित, जो कि रक्षा मंत्रालय नियंत्रण में हैं, मौजूदा किन्हीं भी हवाई अड्डों के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि न तो इंडियन एयरलाइन्स ने और न ही किन्हीं गैर-अनुसूचित प्राइवेट परिचालकों ने इन हवाई अड्डों के लिये विमान सेवाएं परिचालित करने में कोई रुचि दिखाई है ?

Exchange of soiled and mutilated notes by Commercial Banks

*653. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that commercial banks are persistently flouting the directive of Reserve Bank of India regarding exchange of soiled and mutilated currency notes; and

(b) if so, the remedial measures taken and total value of such notes exchanged during 1977?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Complaints are occasionally received regarding exchange of soiled and mutilated currency notes by the Public Sector Banks Branches at some places but it cannot be generalised that commercial banks are persistently flouting the directives of the Reserve Bank of India in this regard.

(b) Each such complaint is looked into and the concerned Bank advised suitably. It is not practicable to give the value of such notes exchanged during 1977 as collection of such information from a very large number of branches of public sector banks extending this facility will entail too much time and labour.

Subsidy to Exports

*654. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the total public expenditure incurred as subsidy to exports shot up from Rs. 85.35 crores in 1970-71 to Rs. 452 crores in 1976-77; and

(b) if so, the details of different forms in which subsidies are being provided for exports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). Perhaps the refrence is to the Cash Compensatory Support which is given under Marketing Development Assistance. The expenditure under this head has increased from Rs. 40.83 crores in 1970-71 to Rs. 239.64 crores in 1976-77.

Cash Comepnsatory Support under Marketing Development Assistance is being provided for Product Promotion Commodity Development, Export Credit Development, Export Development Organisations and for Market Development.

Manufacture of Mica Paper in India

*656. SHRI R. L .P. VERMA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Delegation of officials visited EEC countries in September-October last year to negotiate collaboration arrangements for the manufacture of mica paper in India;

(b) if so, what are the findings of the Delegation regarding possibilities of foreign collaboration;

(c) whether Government has decided to set up mica paper industry in the public sector; and

(d) if not, how it is proposed to implement the recommendations made by the Delegation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) A Delegation of technical officers, headed by the Chairman-cum-Managing Director, Mica Trading Corporation of India Limited (MITCO), visited selected EEC countries in September-October 1977. The Delegation was, *inter alia*, required to explore collaboration possibilities in the field of mica paper.

(b) The findings of the Delegation regarding foreign collaboration in the field of mica paper are at present being examined by MITCO.

(c) and (d). No dicision to set up or otherwise a mica paper plant in the public sector has been taken.

लघु उद्योग को शृंगार सामग्री पर उत्पाद शुल्क से छूट

*656. श्री रामदेनी राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या लघु उद्योग में बनी शृंगार सामग्री (कास्मेटिक्स) पर एक वर्ष में एक लाख रुपये तक के माल पर उत्पादन शुल्क की छूट न देने से बड़े उद्योगों के एकाधिकार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा;

(ख) क्या लघु उद्योगों में बनी शृंगार सामग्री पर उत्पादन शुल्क की छूट देने से इस उद्योग को और विकास एवं विस्तार होगा जिस से रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे, तथा सरकार को और राजस्व मिलेगा ।

(ग) यदि हां, तो लघु उद्योग को यह छूट न देने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का यह निर्णय उसकी नीति के विरुद्ध नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). सौंदर्य और स्वच्छता प्रसाधनों के जिन छोटे निर्माताओं की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उन के इस किस्म के उत्पादन की देश में ही उपयोग के लिए, कुल निकासियां 15 लाख रुपये (मार्च, 1968 को छोड़ कर, 1977-78 के सम्बन्ध में 13.75 लाख रुपए) से अधिक की नहीं थी, उन की एक वित्तीय वर्ष में उक्त माल की 5 लाख रुपये तक के मूल्य की प्रथम निकासियों पर सरकार ने राहत देने का उपाय के रूप में 1-4-1978 से उत्पादन शुल्क से पूरी छूट दी है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Employees in State Bank of India and its Branches in Jammu and Kashmir

5971. SHRI MOHD SHAFI QURESHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) total number of employees in the State Bank of India and its branches in the Jammu and Kashmir; and

(b) break up of these employees as follows:

1. State subjects;

2. Employees belonging to Scheduled Castes and Muslims amongst State subjects;

3. Non-State subjects and number of S. C. and minorities in non-State subjects?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The total number of employees in the State Bank of India and its branches in Jammu & Kashmir as on 31-12-1977, was 1122. Out of these, 1035 employees were the Residents of Jammu & Kashmir, including 16 Scheduled Castes and 37 Muslims.

The number of Non-Residents employees was 87, which included 8 Scheduled Castes and 7 from other minorities.

Increase in Services of I.A. to Calcutta-Agartala-Gauhati-Silchar Route.

5972 SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state·

(a) whether Government are aware that Indian Airlines has not only reduced its services on the Calcutta-Agartala route, services on the Calcutta-Agartala-Gauhati and Calcutta-Agartala-Silchar routes have also been drastically cut without giving any prior notice;

(b) whether Government are aware that there are now only twice a week services on each of the routes which causes great hardship to the passengers and mail services; and

(c) if so, what steps Government are going to take immediately to increase Indian Airlines services on the above mentioned routes?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Against two daily F-27 services between Calcutta and Agartala before 20-12-1977 Indian Airlines have introduced a daily Boeing 737 service on Calcutta-Agartala Route with effect from that date resulting in the increase of seat capacity from 68 to 126. There has been no change in the services on Calcutta-Agartala-Gauhati and Calcutta-Agartala-Silchar routes, which continue to be twice weekly

(b) and (c). In their Summer Schedule, Indian Airlines are taking steps to increase the frequencies on the above mentioned routes

Malpractices by Exporters of Mica·

5973. SHRI L. L. KAPOOR: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of malpractices continue by the exporters of Mica, if so, what are the effective steps that are proposed to remove such malpractices,

(b) whether Government have any scheme to encourage semi-processed Mica, if so, the details thereof; and

(c) whether it is a fact that a Mica Trading Corporation finds itself helpless against private exporters and therefore needs overhauling and reorganisation, if so, proposals in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) In the Third meeting of the Mica Advisory Committee held on the 27th January, 1978, certain allegations were made regarding non-payment of minimum wages, sale of scarce varieties of mica at prices lower than those which the market could bear, sale of "difficult-to-obtain" mica without cash memos and supply of mica to MITCO by the big exporters through the weaker section. The allegations, which were in general terms, are being looked into and, on receipt of specific complaints, suitable action in the matter would be taken.

(b) Semi-processed Mica generally refers to a stage in the course of processing crude Mica. As such, there cannot be any scheme to encourage the production of this item.

(c) No, Sir.

Need for Central Aid to States for Development Purposes

5974. SHRI C. N. VISVANATHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Prime Minister stated at the last Conference of Agriculture Ministers that States should increasingly depend on their own resources for developmental purposes;

(b) whether it is also a fact that many State Governments find it increasingly difficult to raise resources matching developmental needs and that a more massive aid from the Centre is inescapable since Central revenues are derived from only citizens of the States; and

(c) if so, the concrete steps proposed to ensure that the State Governments get equitable grants from the Centre for purposeful acceleration of developmental activity which concerns not only the State Government but also the whole of India?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The Prime Minister stated at the Chief Ministers' Conference on Agriculture and Rural Development held on 10th and 11th January 1978 that the Centre has to help the States but there are limits beyond which it cannot extend help and that, therefore, the real effort has to be made by the States in the matter of agricultural development.

(b) and (c). There is considerable scope for additional resources mobilisation by the States by tapping more intensively the sources in their fiscal jurisdiction and by securing adequate returns on investment in irrigation, power and other projects. The 7th Finance Commission was appointed in June 77 to recommend the States' share in Central taxes and grants-in-aid of revenues of States for the five year period from 1-4-1978. and is required to submit its report by 31st October 1978. A committee of the National Development Council will discuss, having regard to the Constitutional provisions, the fiscal arrangements, including the Gadgil Formula or allocation of Central assistance to States for State Plans, necessitated by the larger role assigned to the State Governments in development planning and execution.

खाद्य तेलों का आयात

5975. **श्री रामजीवन सिंह:** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार इस समय विदेशों से मुख्यत: किन-किन खाद्य-तेलों का आयात कर रही है; और

(ख) खाद्य तेलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सरकार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मुख्य रूप से रेपसीड तेल, सोयाबीन तेल तथा ताड़ के तेल का आयात कर रही है। उन्होंने मूंगफली के तेल तथा पामोलिन की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा आयात की है।

(ख) खाने योग्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों किस्म के उपाय तैयार किए गए हैं, जिन में, अन्य बातों के साथ साथ ये शामिल है :—

(i) सिंचित तथा असिंचित दोनों क्षेत्रों में सुधरी टैक्नालाजी का तेजी से विस्तार करके प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना ।

(ii) नयी सिंचाई परियोजनाओं के अंतगत पड़न वाले क्षेत्र में उपलब्ध संभाव्यता का उपयोग कर के सिंचित फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना ।

(iii) शुद्ध बीजों की आपूर्ति बढ़ाकर बीज उत्पादन कार्यक्रम को मजबूत करना ।

(iv) पौध संरक्षण उपायों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना । इस के लिए विशेष रूप से, जहां सम्भव हो, बहुत बड़े इलाके में हवाई छिड़काव करना ।

(v) समर्थन मूल्य निर्धारित करना तथा उन मूल्यों पर उपज खरीदने के लिए प्रबन्ध करना ।

(vi) कृषि विभाग के गहन तिलहन विकास कार्यक्रमों और अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणीकृत बीज फार्म तथा पौध संरक्षण के विभिन्न कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना ।

(vii) सूर्य मुखी तथा सोयाबीन जैसी गैर-परम्परागत तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना ।

Advance to Harihar Automobiles by UCO Bank, Lucknow

5976. SHRI BIJOY KUMAR MONDAL:

SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to part (c) of Unstarred Question No. 8308 on the 2nd May, 1975 regarding advance to small scale industry by United Commercial Bank, Lucknow and state:

(a) whether the Government are aware that an advance was sanctioned to Harihar Automobiles by Assistant General Managers Office, United Commercial Bank, Lucknow in 1973-74, by fraudulently classifying it as a small scale industry and that to reciprocate to this favour a partner of this firm had given a motor car No. DLJ 7989 to the Manager of the Bank;

(b) whether Government have made enquiries about the statement that the car was sold by partner of the firm and that the manager has resold it to the brother of partner of the firm after using it for eight months;

(c) if so, whether it is correct in view of the fact that there is no change of the name of the owner in the registration of this car; and

(d) if so, the action proposed to be taken thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). United Commercial Bank has reported that the credit facilities given by the bank to M/s. Harihar Automobiles Limited were sanctioned by the Assistant General Manager after he had carefully considered the same and after following the usual banking norms. United Commercial Bank has further reported that an officer of the bank in its Zonal Office, Lucknow, not connected with the sanctioning of limits to the party, had purchased a Car in December, 1973 from a partner of M/s. Harihar Automobiles. According to the bank as per the transfer register maintained by the Motor Vehicle Registration authorities, the transfer of the car in the name of the Officer has been made. The bank has further added that when this Officer was allotted a Fiat Car on priority basis, he had subsequently sold the Car in June 1974 to the brother of the partner from whom he had purchased. According to the bank, though the purchase of the Car by the Officer has not led to any favours being shown to the borrower, the Officer's action in buying a Car from a customer was considered to be not proper, and the bank has conveyed its displeasure to the Officer concerned.

कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

5977. **डा० रामजी सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि असमान और असंतुलित रूप से हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करना उचित नहीं मानती है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इस्पात और अन्य औद्योगिक उत्पादों के मूल्य सरकार के अनुमोदन से निर्धारित नहीं किए जाते हैं और यदि हां, तो इनमें सरकार की क्या भूमिका होगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). दोनों क्षेत्रों के व्यापारिक मूल्य में समय समय पर परिवर्त्तन होते रहते हैं जिनका मुख्य कारण यह है कि कृषि उत्पादन में घटबढ़ होती रहती है और उसी के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों के मूल्यों में कमी बेशी होती रहती है। थोक कीमतों के सूचक अंक (1970–71–100) के अनुसार, 1973–74 में करीब करीब समानता ही थी किन्तु उसके बाद 1974–75 में कृषि की ओर झुकाव रहा था। 1975–76 में कृषि के संबंध में व्यापारिक मूल्य स्थिति प्रतिकूल हो गई क्योंकि उस वर्ष फसल अच्छी हुई थी और अगले वर्ष के दौरान भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1977–78 में कृषि उत्पादों के मूल्यों में विनिर्मित्त वस्तुओं के मुकाबले अपेक्षाकृत काफी ज्यादा बृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप, व्यापारिक मूल्य स्थिति आधार वर्ष की स्थिति की तुलना में, कृषि के संबंध में कुछ कम अनुकूल रही। सरकार, बहुत सी कृषि वस्तुओं के समर्थन/खरीद मूल्य निर्धारित करके तथा संकट निरोधी भंडार बना कर, कृषि के हितों की रक्षा करती है। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों पर औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से नियंत्रण रखा जाता है। इन उपायों से, व्यापारिक मूल्य स्थिति के एक क्षेत्र अथवा दूसरे क्षेत्र की ओर बहुत ही ज्यादा झुक जाने की प्रवृत्ति की रोकथाम हो जाती है।

सोने के उपभोग की सीमा निर्धारित करने के बारे में सझाव

5978. श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुझाव दिये गये हैं कि वह व्यक्तिगत उपभोग के लिए सोने की प्रतिव्यक्ति सीमा निर्धारित करें ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत, शुद्ध सोने को निजी स्वामित्व/कब्जे में रखने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। यदि किसी परिवार के पास 4 किलोग्राम से अधिक तथा ऐसे किसी व्यक्ति के पास, जो किसी परिवार का सदस्य नहीं है, 2 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण/वस्तुएं हों तो स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत उनकी घोषणा करनी पड़ती है। वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति/परिवार द्वारा अर्जित किये जा सकने, अपने पास रखने अथवा अपने कब्जे में रखने योग्य आभूषणों की मात्रा अथवा शुद्धता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

तथापि सरकार को कुछ ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें, किसी व्यक्ति और परिवार द्वारा अपने पास अथवा कब्जे में रखे जा सकने योग्य स्वर्ण-आभूषणों की मात्रा के संबंध में उच्चत्तम सीमा निर्धारित करने के लिये कहा गया है। फिलहाल, ऐसे किसी उपाय पर विचार नहीं किया जा रहा है।

India's Position in the World regarding Tea Production

5979. SHRI DHARMA VIR VASISHT: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India stands first in the World today in tea production, productivity consumption and exports, if so, figures of the same;

(b) whether it is also a fact that the internal demand for tea is rising by seven per cent. per annum, the annual increase in the production is only three per cent, if so, steps taken to push up production; and

(c) whether this effort is reflected in the production during 1977-78, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) India stands first in the world as regards the quantity of tea produced, annually consumed and exported. Among black tea producing countries India has the highest yied per hectare. However, Japan, which produces green tea is having a higher yield rate than India for that type of tea. The production, export, consumption and yield for the year 1976-77 is as under:

Production	512 m. kgs.
Consumption	286 m. kgs.
Exports	242 m. kgs
Yield per hect.	1407 kg.

(b) and (c). The internal demand is estimated to have risen from 248 m. kgs. in 1973 to about 300 m. kgs. in 1977 i.e. by about 5 per cent per annum. During the same period production rose from 470 m. kgs. to 560 m. Kgs. i.e. by about the same 5 per cent per annum.

The production in 1977 was the highest recorded so far. In order to augment the production of tea, the Government is providing financial assistance through Tea Board to tea planters in the form of loans and subsidy. The tea development schemes include (i) Replantation Subsidy Scheme, (ii) Tea Plantation Finance Scheme under which subsidy and loans are given for planting and replanting of tea areas and (iii) Tea Machinery and Irrigation Equipment Hire Purchase Scheme under which machinery is provided on hire purchase basis.

Reservation for Tribals in Public and Private Sector

5980. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to make arrangement for the reservation of certain percentage of labour from among the tribals as it has been done in the ctses of S.C. and S.T. community in public and private sector; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). As regards Public Enterprises, instructions have been issued providing reservation of posts for the members of the S.C. and S.T. communities on the lines of reservations for these communities in respect of appointments in Government.

A proposal to reserve certain percentage of employment to the members of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities in the private sector undertakings was considered by Government and it was felt that statutory or other measures for ensuring such reservation would not be appropriate. It was considered that the trade organisations might continue to be persuaded to take steps to ensure that an adequate share of employment was given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In pursuance of

this decision an appeal was issued in 1975 to all industrial undertakings in the private sector through Directors of Industries, technical authorities and Chambers of Commerce and Industries urging them to impress on their constituents the desirability of providing a due share of employment in the private sector to the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities.

There is no proposal under Government's consideration to make arrangements for the reservation of posts in the public or private sector for the tribals other than those belonging to the Scheduled Tribes.

Multinational Corporations operating in India

5981 SHRI ROBIN SEN Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the number of multinational corporations and their names and assets, operating in India during 1965 to 1977, year-wise;

(b) the names of the Indian-collaborations of these multinational corporations, if any;

(c) the business they are carrying on;

(d) total outflow of profits during 1965 to 1977 year-wise; and

(e) total amount reinvested in India, if any, during the above period?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL). (a) The information is given in Annexure-I laid on the Table of the Sabha [Placed in Library See No. LT 2046/78].

(b) In the case of subsidiaries and branches of foreign companies, the question of Indian collaboration does not ordinarily arise.

(c) The industry-wise distribution of Indian subsidiaries and branches of foreign companies for the years 1972-73 onwards is given in Annexures III and IV laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT 2046/78].

(d) the remittances of profits and dividends by all foreign companies operating in India during the years 1965-66 to 1975-76 are given below:

(Rs. crores)

	Profits	Dividends
1965-66	13·50	19·40
1966-67	14·17	21·77
1967-68	15·95	33·70
1968-69	12·96	30·25
1969-70	12·72	31·41
1970-71	13·12	43·48
1971-72	9·94	38·87
1972-73	15·54	39·08
1973-74	21·91	37·51
1974-75	7·19	18·46
1975-76	20·36	24·84

(e) The earnings retained by foreign companies operating in India during the period 1965-66 to 1972-73 are given below:

(Rs. crores)

1965-66	18·8
1966-67	14·9
1967-68	18·8
1968-69	17·8
1969-70	29·0
1970-71	28·4
1971-72	33·9
1972-73	32·1

पश्चिम बंगाल के लघु उद्योगों को कम ब्याज की दरों पर ऋण दिया जाना

5982. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ लघु उद्योगों को इस वर्ष कम ब्याज की दर पर ऋण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किया जाएगा और कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी जायेगी और उस पर ब्याज की दर कितनी होगी ,

(ग) क्या ब्याज की वर्तमान दर में कमी करने का भी सरकार का विचार है , और

(घ) उन संस्थाओं के नाम क्या है जो इस प्रकार के ऋण देंगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) यद्यपि किसी विशेष राज्य केन्द्र शासित प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नही है, किन्तु औद्योगिक विकास मंत्रालय ने, हाल ही मे, राज्य सरकारो को वित्तीय सहायता देने की एक योजना बनायी है ताकि वे ऐसे छोटे एककों की कुल निवेश के 10 प्रतिशत तक की "मार्जिन" पूजी सुलभ करा सके जिनका सयंत्र और मशीनो में पूजी निवेश एक लाख रुपए से अधिक नही है ।

(ग) और (घ) छोटे पैमाने के उद्योगो के क्षेत्र मे पूजी विवेश को प्रोत्साहित करने के लिये, हाल ही मे, बैंको से कहा गया है कि वे ऋण गारटी योजना के अधीन व्याप्त छोटे पैमाने के उद्योगों और निर्धारित पिछड़े जिलो:/ इलाकों के छोटे एकको को, तीन वर्ष के अन्यून परिपक्वता की अवधि वाले सावधिक ऋणों पर 11 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज न वसूल करें ।

छोटे पैमाने के उद्योगो को सावधिक ऋणो के मामले मे बैंको को, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) से पुनर्वित्त प्राप्त की सुविधा सुलभ होता है, और जब इस पुनर्वित्त सुविधा का लाभ लिया जाता है तो बैंक, इस प्रकार के ऋणो पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल करते है और निर्धारित इलाको मे अवस्थित यूनिटों के मामले मे तो ब्याज की दरे 9 1/2 प्रतिशत ही होती है :

हाल ही मे भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंको के ऋणो पर ब्याज की दर मे सामान्य घटोतरी की घोषणा की है । घटी हुई ब्याज दरो का लाभ छोटे पैमाने के उद्योगो को सुलभ होगा ।

Help to Tribals by Panchayati Rural Bank, Jeypore, Koraput, Orissa

5983 SHRI GIRIDHAR GOMANGO Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether the Panchavati Rural Bank, Jeypore, Koraput Orissa has opened its branches so far;

(b) how far the branches played the role to help the tribals and weaker sections of the society so far; and

(c) proposals to open the branches in this district to cover the rest of the uncovered population by this bank?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M PATEL). (a) to (c). The Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jeypore (Orissa) which was set up on November 13, 1976 has already opened 31 branches as on January 1978 This bank, which is serving the predominantly tribal district of Koraput, has advanced an amount of Rs. 61.52 lakhs in 16187 Accounts to small/marginal

farmers and other weaker sections of the society by January 1978. The bank has a programme of opening another 18 branches in the near future.

Amount spent for Development of Tourism in Goa

5985. SHRI AMRUT KASAR: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what are the amounts spent from the Central Revenues on the development of tourism in the Union Territory of Goa for the financial years 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) on what projects these amounts have been spent; and

(c) what is the allocation for the Union Territory of Goa for the year 1978-79?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). The Central Government incurred the following expenditure on development of tourism in Goa:

Year	Scheme	Amount
		Rs
1975-76	(i) Construction of Youth hostel building at Panaji	5,07,970·00
	(ii) Hydrographic survey of selected beaches in Goa development of aquatic sports	624,000·00
1976-77	Hydrographic Survey	9,860·00
1977-78	Subsidy to State Government for management of the youth hostel at Panaji for the year 1976-77 and 1977-78 released in 1977-78	24,000·00

(c) (i) No provision exists in the Budget Estimates for 1978-79 for schemes in Goa. However, a subsidy of Rs. 12,000 will be released by the Department towards the management of the youth hostel at Panaji by the State Government.

(ii) The India Tourism Development Corporation also proposes to construct a hotel in Goa for which suitable provision will be made once the scheme is cleared by the Government.

Investment of Unit Trust of India

5986. SHRI VINODH BAI B. SHETH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

what is the bifurcation of investment of Unit Trust of India year-wise for the last five years-investment in companies and deposits?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT 2047/78].

Time limit for setting claims pertaining to Central Excise Matters

5987. SHRI MANOHAR LAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the time limit for settling claims of refunds of excess amounts charged and arising out from adjudication appeals, and revision applications, pertaining to Central Excise matters under the Central Excises and Salt Act, 1944, fixed or proposed to be fixed; and

(b) whether Government will lay a detailed statement on the subject?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) and (b). Where an order in adjudication, appeal

or revision directs the refund of duty or fine or penalty, the order is the basic authority for granting the refund and a formal claim is not necessary. The department will itself take necessary action to make the refund. However, in cases where the order is with reference to a principle and not a specific amount, the assessee is required to furnish necessary detail to enable the exact amount of refund to be worked out.

While there is no statutory time limit for making refunds in such cases, executive instructions have been issued to the Collectors of Central Excise, impressing upon them the importance of expeditious disposal of such claims. Collectors have been directed to make every effort to dispose of refund/rebate claims within a period of three months. It has been laid down that Collectors and Deputy Collectors, during their inspections of and/or visits to divisional offices, should make it a point to examine critically the progress made in the disposal of refund claims and in particular cases more than three months old. Collectors and other senior officers have also been directed to make it a point to inspect the work relating to refunds in their offices also more frequently to ensure that refund claims are not held up without valid reason.

अफीम के लागत और विक्रय मूल्य के बीच के अन्तर को कम से कम करने हेतु कार्यवाही

5988. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अफीम उत्पादकों से किस मूल्य पर अफीम खरीदती है और उसे ठेकेदारों द्वारा जो उसे अधिकृत बिक्री एजेंट हैं, किस मूल्य पर बेचा जाता है ; और

(ख) लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के अन्तर को कम से कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सती अग्रवाल) : (क) वर्ष 1977–78 के दौरान काश्तकारों से कच्ची अफीम जिस कीमत पर खरीदी गयी थी वह 70° गाढ़ता की अफीम के प्रति किलोग्राम के लिए 110 रुपए से 200 रुपए के बीच थी। वर्ष 1977–78 के दौरान अफीम के उपादन की औसत लागत 90° गाढ़ता की अफीम के प्रति किलोग्राम के लिए लगभग 228 रुपए थी और इसकी सप्लाई सीधे राज्य सरकारों को 230 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की गयी थी। सरकार ने किसी ठेकेदार को अफीम बेचने का अधिकार नहीं दिया है।

(ख) चूंकि लागत मूल्य और राज्य सरकारों को सप्लाई की जाने वाली अफीम से मिलने वाले मूल्य के बीच अन्तर बहुत थोड़ा है, इसलिए इसे और कम करने का प्रश्न नहीं उठता।

सरसों के तेल का आयात करने संबंधी नीति का पुनर्विलोकन

5989. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में दिल्ली अध्ययन द्वारा "मूल्य स्थिति" के बारे में आयोजित विचार गोष्ठी में भाग लेते हुए उन्होंने यह कहा था कि हाल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट ऐजेंसियों के माध्यम से सरसों के तेल का आयात करने संबंधी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Sale of Gold at International Prices to Goldsmiths

5990. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether the policy regarding sale of gold at international prices to goldsmiths as announced by him in his Budget speech, has since been formulated; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) and (b) In implementation of the policy announcement by Government, a scheme for the encouragement of the export of gold jewellery by supply of gold for this purpose at international price either from imports or Government gold stocks and a scheme for sale of gold from Government gold stock for internal consumption within the ambit of Gold Control Act are being finalised and will be announced soon.

Appointment of SC and ST as Probationary Officers in Nationalised Banks

5991. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any relaxation in minimum qualifications has been given by Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appearing in the examination for appointment as probationary officers in the nationalised banks; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b) Out of the 15 public sector banks which includes 14 nationalised banks and State Bank of India, direct recruitment at the level of officers is done by 12 banks In the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, these banks have prescribed a mere pass class in the Graduation examination as the minimum educational qualification as against first-class or high second class required from the general category of candidates

Loan advanced by Syndicate Bank to Premier Cooperative Transport Society Limited

5992 SHRI YASHWANT BOROLE Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Syndicate Bank has advanced loan(s) to the Premier Co-operative Transport Society Ltd., New Delhi,

(b) if so, the amount of each and date(s) thereof and the terms thereof, amount(s) towards interest and capital received from time to time and balance amounts of loans and interest to be recovered as on 31st March, 1978;

(c) has the said Society pledged its two buses to this bank and is the bank aware that the total amount of loan and interest due thereon far exceeds the market and depreciated prices of these buses; and

(d) if so, the steps taken todate to recover the same?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) The amount and dates of the two loans advanced are Rs. 60,000/- on 19th January, 1972 and Rs. 72,000/- on 14th April, 1973. The Society was to repay the loan in monthly instalments of Rs. 2,200/- and Rs. 2,000/-. In accordance with the practices and

usages customary amongst the bankers and also in conformity with the provisions in the statute governing the public sector banks the rest of the information cannot be divulged

(c) The Society has hypothecated the buses to the bank and the bank is fully aware of the position of the accounts

(d) The bank proposes to take legal action to recover the outstanding balance and has issued a legal notice to the Society

Dilution of Share by Sterling Tea Companies

5993 SHRI SHARAD YADAV Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether a large number of Sterling Tea Companies having foreign bases have not yet undergone processes of share dilution in accordance with the provisions of Foreign Exchange Regulation Act

(b) whether these Sterling Companies have agreed to transfer their interest control and management to newly formed Indian Companies having their registered offices in the States of West Bengal and Assam to avoid share dilution to the extent of 60 per cent of their holdings

(c) if so the facts thereof and

(d) the action being proposed to be taken against all foreign and Sterling Tea Companies having their Tea Estates in India to enforce reduction of their shareholding to 40 per cent of their respective paid up capital?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI M PATEL) (a) Almost all the Sterling Tea Companies have submitted their proposals for Indianisation in accordance with the directives given to them under the Foreign Exchange Regulation Act These Indianisation proposals are engaging the consideration of the Government/ Reserve Bank of India

(b) According to FERA directives, the Sterling Tea Companies have to convert themselves into Indian companies in which the non-resident interest shall not exceed 74 per cent The Indianisation proposal of most of the Sterling Tea Companies consist of a group of Sterling Tea Companies merging into Indian companies formed for the purpose of taking over the Indian business These Indian companies are mostly incorporated in West Bengal and Assam

(c) Does not arise

(d) The FERA directives are statutory in nature and the companies concerned have either to comply with them or wind up their business in India

Export of Coir and Coir Products

5995 SHRI VAYALAR RAVI Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) the total quantity of coir and coir products exported and value earned for last three years and

(b) its product wise break up during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) and (b) A statement is attached

Statement

Exports of Coir and Coir Products

Qty. in tonnes
Value in Rs. lakhs

	1975-76		1976-77		1977-78 (April '77 to Jan. '78)	
	Qnty.	Value	Qnty	Value	Qnty.	Valu (provisio nal)
Coir Fibre . . .	266	6·94	134	2·88	36	1·02
Coir Yarn	22970	1002·19	26567	1052·32	20063	810·48
Coir Mats . . .	7488	562·48	9582	735·18	9408	723·95
Coir Mattings, Rugs, Carpets etc.	5276	337·11	7020	462·00	6758	527·78
Coir Rope. . . .	269	6·70	185	5·42	117	3·52
Curled Coir . . .	1024	19·52	868	19·48	486	10·38
Rubberised Coir Goods .	1	0·26	1	0·27	3	0·45
Total	37294	1935·20	44357	2277·55	36871	2077·58

(Source Coir Board, Cochin)

Loan Sanctioned by S.B.I. Bombay to M/s. Vivek Textile Mills Vikuroli, Bombay

5996. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether M/s. Vivek Textile Mills, Vikuroli, Bombay was sanctioned limits to the extent of Rs. 46.25 lakhs by State Bank of India head office Bombay directly and the accounts were transferred to Ghotkopur (East) branch from Vikuroli branch;

(b) reasons for the same;

(c) whether adverse remarks regarding this transaction have been passed by Bank's officer-in-charge inspection and auditor; and

(d) whether firms outstanding have received to 40 lakhs from June, 1975 to March, 1977 progressively diminishing security to 2 lakhs approximately?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). The Hon'ble Member has sought information relating to the details of the account of a constituent of State Bank of India. In accordance with the practice and usage customary among bankers and also in coformity with the provisions of section 44(1) of the State Bank of India Act, 1955, information relating to or to the affairs of the constituents of the State Bank of India cannot be divulged.

वनस्पति घी का उत्पादन करने वाले कारखाने

5997. **श्री राम किशन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में वनस्पति घी के कितने कारखाने हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) गत चार वर्षों मे उनके उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) वनस्पति घी की प्रति किलो उत्पादन लागत क्या है तथा उपभोक्ता को इसका प्रति किलो क्या मूल्य देना पड रहा है और उत्पादन शुल्क, बिक्रीकर, चुगी, भाडा, कमीशन आदि के अलग-अलग ब्यौरे सहित इसकी उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य मे कितना अन्तर है ?

वाणिज्य तथा नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) :(क) वनस्पति उत्पादन यूनिटें 85 है, जिनकी वार्षिक संस्थापित क्षमता 12 91 लाख मीटरी टन है।

(ख) पिछले चार वर्षो मे वनस्पति के उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है —

वर्ष	वनस्पति का उत्पादन लाख मीटरी टनो मे
1974 .	3 54
1975 .	4 58
1976 .	5 45
1977	5 80

(ग) वनस्पति की प्रति किला उत्पादन लागत उत्पादन शुल्क का छोडकर 8 06 रुपए हान का अनुमान है। उपभोक्ता द्वारा उत्पादन शुल्क बिक्रीकर चुगी, भाडा आदि मिलाकर दिया जाने वाला मूल्य 9 03 से 9 65 रुपए प्रति किला के बीच है। ब्यौरा सलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

केन्द्र	16 5 कि०ग्रा० के टीन की फैक्टरी मे चलते समय की कीमत (उत्पादन शुल्क सहित)	बिक्री कर और बिक्री कर पर अधिप्रभार	चुंगी और अन्य	थोक विक्रेताओं का लाभ	फुटकर विक्रेताओं का लाभ	16 5 कि० ग्रा० टीन के फुटकर मूल्य	प्रति कि० ग्रा० का लगभग फुटकर मूल्य (स्तम्भ 7 के आधार पर निकाला गया)
1	2	3	4	5	6	7	8
अहमदाबाद . .	136.00	11.53 @ 8 48%	0 62क	2.00	2.00	156.15	9.46
बम्बई . .	140 00	9 80 @ 7%	—	2.00	2 00 ख	153.80	9.32
कलकत्ता . . .	140 00	12 48 @ 8 913%	—	1.65	2 48	156.61	9.49
दिल्ली	140 00	7 00 @ 5%	—	1.00	1 00	149 00	9.03
हैदराबाद . . .	140.00	9.31	—	2 00	2.00	153.31	9.2

1	2	3	4	5	6	7	8
जयपुर . .	140 00	14 00 @10%	—	0 50	0 50	155 00	9 39
मद्रास .	140 00	11 76 @8 40%	—	2 00	2 00	155 76	9 44
नागपुर	140 00	9 95 @7%	[illegible] 2[illegible]ख	3 00	1 00	159 20	9 65

क इसमें प्रति टीन 0 47 रु० चुंगी और 0 15 रु० माल उतारने का खर्च भी शामिल है।

ख इसमें प्रति टीन 3 05 रु० चुंगी और 2 20 रु० माल सुपुर्दगी खर्च भी शामिल है।

स्रोत वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय (निरीक्षण रिपोर्ट)

Prize Deposit Schemes of Bank of Madura

5998. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bank of Madura had started two Prize Deposit Schemes of Rs. 50/- and Rs 500 - a few years back and if so the facts thereof,

(b) whether Government's approval was taken to start these draws;

(c) whether Government have received complaints of irregularities and malpractices in the draws conducted by the Madura Bank for distribution of prizes,

(d) if so, details thereof and action taken against the bank; and

(e) whether there is any Government check on conducting prize draws by that bank and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) In December, 1974 the Bank of Madura Ltd. had introduced two fixed deposit schemes of ten years duration referred to by the Hon'ble Member. The schemes provide for payment of double the amount of deposit on maturity and entitle the depositors to participate in monthly draws of prizes during the currency of deposits

(b) and (c). The permission of the Central Government/Reserve Bank was neither taken by the bank nor was it required for the conduct of the above schemes. However, banks have to comply with the laws of State Governments governing lotteries etc., in the States where draws are held.

(c) Reserve Bank of India have reported that although some complaints had been received in regard to the procedural/operational aspects of the bank's schemes, no specific malpractice has come to their notice.

(d) Does not arise.

Advance Central Assistance to West Bengal

5999. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Finance Minister of West Bengal requested the Government of India to give them an advance Central assistance of Rs. 49 crores, for meeting the budgetary gap in the current year; and

(b) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) In accordance with the general policy adopted for covering gaps in resources of the State Governments in 1977-78, Government of West Bengal was given advance Plan assistance of Rs. 17.50 crores. The State Government was expected to meet the remaining gap through its own efforts at economy in non-Plan expenditure, improvement in revenues, better collection of Government dues and similar measures

Development of Air Strip of Lohagaon (Pune)

6000. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration for the development of air strip of Lohagaon (Pune) in Maharashtra;

(b) if so, since when, and the details thereof;

(c) what is the total cost involved; and

(d) when the said development of Lohagaon and air strip shall be completed?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) to (d). The aerodrome at Lohagaon (Pune) belongs to the Indian Air

Force and is suitable for operations with Boeing 737 aircraft The Civil Aviation Department have constructed a new civil enclave at a cost of about Rs 24 lakhs which was commissioned in August, 1977 There is no proposal at present for further development of this aerodrome

Offer from Government of Assam for providing Man Power for Central Projects Undertakings

6001 SHRI AHMED HUSSAIN Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether Government of Assam have offered to provide man-power and technical people for various Central Projects Undertakings and have requested the Centre to issue suitable instructions to various Central Projects Undertaking in Assam to furnish their man power requirement to the State Government of Assam to facilitate the development of technical skills and employment of trained personnel and

(b) the action taken/proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) and (b) The information is not readily available and will be obtained and placed on the table of the House

Evasion of Central Excise Duty by Bengal Lamp of Calcutta

6002 SHRI T K CHANDRAPPAN Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether the Bengal Lamp of Calcutta has tried to evade Central excise duty for some time, and

(b) if so, whether Government have taken action against Bengal Lamp and if so the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) and (b) M/s Bengal Electric Lamp Works Ltd., Calcutta are alleged to have tried to evade Central Excise duty amounting to about Rs 35 lakhs during the period between 1974 and early 1977 A show-cause notice has been issued to them by the Central Excise authorities and the case is under departmental adjudication

Complaints against working of Customs Warehouse, Calcutta

6003 SHRI S S GUPTA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether Government have received complaints against the working of Custom Ware House, Calcutta and if so the nature of complaints received,

(b) whether it is also a fact that some persons while removing confiscated goods in league with high officers of Calcutta Custom Ware House from the Custom House Calcutta were caught red handed outside the Custom House during the year of 1977,

(c) whether such persons who were caught red handed are never to be found and

(d) whether Government have taken any legal action against the officers responsible for their commission and omission and if not the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) No, Sir Government have not received any such complaints recently

(b) and (c) No, Sir Reports received by Government do not show that any such incidents occurred However, on 19th August 1977, a labourer working with M/s MEK Engineering Works (P) Ltd, and engaged in fixing steel racks in the seizure shed of the Custom House was apprehended with one 3-Band National Transistor Radio while coming out of the seizure shed gate after his day's work While arrangements were being made to hand over the accused

with the stolen article to the Police, he managed to escape. Officers were deputed to keep surveillance on the house of the accused in his native village for detaining him, but he could not be apprehended.

(d) The persons who were in charge of the accused at the time of his escape have been cautioned.

Arrears of Income Tax in Dhanbad, Giridih, Hazaribagh and Jamshedpur Industrial Complex

6004. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of car, truck, dumper and other power driven vehicle owners in Dhanbad, Giridih, Hazaribagh and Jamshedpur industrial complex of Chhotanagpur in Bihar; and

(b) what percentage of them pay income tax and the arrear pending with them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) and (b). The information is being collected and will be furnished as soon as it is available.

Ministers, M.Ps. and Journalists sent abroad during Emergency

6005. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many Ministers and Members of Parliament were sent to foreign countries during the period of Emergency by the Government;

(b) the total number of journalists and others who were sent to other countries during that period by the Government;

(c) how much money was spent by the Government on all of them;

(d) the names of the countries visited by them;

(e) the names of the Ministers and Members of Parliament who were sent to foreign countries after March, 1977; and

(f) the total amount spent on them by the Government?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). Similar information was asked for the periods 1974-75, 1975-76 and 1976-77, in Unstarred Question No. 3615 in the Lok Sabha on the 15th July, 1977. The said information is being collected separately and will be laid on the Table of the House as soon as possible. The information for the period of Emergency will thus be available in the information to be furnished in reply to Unstarred Question No. 3615.

(e) and (f). In Unstarred Question No. 5148 answered in the Lok Sabha on the 31st March, 1978, similar information was, *inter alia*, called for, the period from 1st April, 1977 to 31st March, 1978. This information is being collected separately and will be laid on the Table of the House as soon as possible. The information called for in the present Question regarding tours of Ministers and Members of Parliament will thus be available in the information to be furnished in reply to Unstarred Question No. 5148.

Evasion of Income Tax and Excise Duty by Jaypore Sugar Company

6006. SHRI M R. LAKSHMINARAYANAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether due to the sale of 14,000 bags of levy sugar in black-market by the Jaypore Sugar Company, the Central Board of Excise has imposed a penalty of Rs. 6 lakhs on the company;

(b) whether C.B.I. had source information to the effect that the Management and three high Income Tax Officials of Andhra Pradesh colluded with

the company by reason of which there was evasion of income tax and excise duty of Rs. 25 lakhs or above; and

(c) if so, what action his Ministry proposes to take against the company to collect the income tax?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) During the period from January to June 1972, M/s. Jaypore Sugar Company Limited, Chagallu, had cleared a number of consignments of sugar manufactured by the company on payment of duty at a concessional rate applicable to levy sugar under the Central Excise Tariff. It was later on found out that those consignments cleared by the Company were diverted by them for sale in open market and hence they were not entitled to the concessional rate of assessment on the sugar cleared by them. A case was registered under the Central Excise and Salt Act, 1944 and in the departmental adjudication proceedings the party was left off, as the Adjudicating Authority held that the charges levelled against the Company were not established. When this case came to the notice of Central Board of Excise and Customs, the original adjudication order was reviewed after issue of due notice to the party and the Board held the Company guilty of deliberate evasion of Central Excise Duty to the tune of Rs. 2.68 lakhs, and set aside the original adjudication order and a penalty of Rs. 6 lakhs was imposed on the Company.

(b) The C.B.I. had received an information against three Senior Officers of the Income-tax Department posted in Andhra Pradesh alleging showing of undue favours to M/s. Jaypore Sugar Company in the matter of evasion of taxes. This information was passed on to the Director of Inspection (Investigation), attached to the Central Board of Direct Taxes for examination and thereafter to refer the matter to C.B.I. if a C.B.I. investigation was called for.

(c) The Income-tax Department has been conducting investigations regarding allegation of sale of levy sugar in blackmarket by M/s. Jaypore Sugar Company Limited on the basis of complaints received and in close liaison with the Central Excise authorities. The assessment of the Company for the assessment year 1973-74 was completed relying on the original adjudication order passed by the Central Excise Authorities in October, 1974. After the issue of Board's review order in January, 1978, on the basis of enquiries conducted and material now collected, steps have been taken by the Income-tax Department to rope in the income that may have escaped assessment.

The case referred by the C.B.I. to Directorate of Inspection has been examined by the Director of Inspection (Vigilance) whose report is under consideration.

Joining of Department of Revenue to Minstry of Home Affairs for the Posts Created for Hindi Work

6007. SHRI MOHAN LAL PIPIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Department of Revenue has not agreed to join the proposed common cadre being constituted by the Ministry of Home Affairs for the various posts created for Hindi work in different Ministries and Departments in the Government of India;

(b) whether the above decision has been taken at the instance of the senior Hindi Officer of that Department in utter disregard to the representations made by the staff of that Department;

(c) whether it is also a fact that conduct of the senior Hindi Officer has been under investigation for various irregularities and malpractices committed by him in the perfor-

mance of his official duties, if so, the nature of action already taken against him on that account; and

(d) whether it is proposed to restrain this officer from acting in a manner prejudicial to the interests of the staff working under him?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) The matter is still under consideration.

(b) Does not arise.

(c) During 1976-77 on one occasion, the displeasure of the Government was conveyed to the Senior Hindi Officer when it came to the notice of the Government that the Officer was carrying on without previous sanction, a fairly regular side business as an astrologer or a priest. He has represented against the displeasure communicated to him and the same is under consideration.

(d) Since our inability to join the proposed common cadre for Hindi posts so far has been due to public interest and not at the instance of the Senior Hindi Officer, the question of restraining him does not arise.

Chairman and General Manager of Federal Bank Limited, Trivandrum

6008. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the persons holding post of Chairman and General Manager of Federal Bank Limited, Trivandrum are real brothers,

(b) if so, is it not against the Banking Rules; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) There is no provision in the Banking Regulation Act, 1949 prohibiting the appointment of persons related to each other in the same Bank.

(c) Does not arise.

Export of Gur, Shakkar and Khandsari

6009 DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI DURGA CHAND:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have taken step to export gur, shakkar and Khandsari in view of the steep fall in prices of these products in the Mandis of U.P., Bihar and Maharashtra, and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). Yes, Sir. Export of gur is now freely allowed without any quota restriction. Even the condition of 100 per cent L.C. or advance payment for permitting exports has been removed for export of gur. Government have also released a quota of 5,000 tonnes of Khandsari sugar for export during the year 1978-79.

पेंशन नियमों का सरलीकरण

6010. श्री लालजी भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेंशन संबंधी नियमों को और अधिक सरल बनाने तथा स्पष्ट करने का है जिससे सेवा निवृत्त होने वाले सैकड़ों व्यक्तियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) और (ख) पेन्शन के मामलों को निपटाने के सबंध में विलम्ब को समाप्त करने के लिए नियम तथा कार्यविधिया समय-समय पर सशोधित की जाती है। 1-3-76 से प्रभावी एक सरलीकृत कार्यविधि को लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को पेंशन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले अनिवार्यत प्राधिकृत की जाएगी। इस कार्यविधि की मुख्य-मुख्य बातो का विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अधिवर्षिता और मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान की अदायगी मे विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से फरवरी 1976 म एक सशोधित कार्यविधि निर्धारित की गई थी। सशोधित कार्यविधि की मुख्य मुख्य बाते निम्नलिखित है --

(1) पेशन की सगणना 36 महीने की बजाए 10 पूर्ण महीनो की औसत परिलब्धियो के आधार पर की जाएगी।

(2) सभी मामलो म अधिवर्षिता पेंशनो की अदायगी देय महीने की पहली तारीख से शुरु होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय अध्यक्षो और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियो के लिए विभिन्न अवस्थाओ पर कार्य के लिए एक निश्चित समय सारणी निर्धारित कर दी गई है और प्रत्येक अवस्था के लिए निश्चित विभाजन तारीखें निर्धारित की गई है।

(3) विपरीत विशिष्ट सकेत न होने की स्थिति मे, केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा की दो अवधियो के बीच सेवा मे आए व्यवधान को माफ किया समझा जाएगा और व्यवधान पूर्व सेवा को पेशन के लिए हिसाब मे लिया जाएगा। इसी प्रकार असाधारण छुट्टी की ऐसी अवधियो को भी जिनको गैर-अर्हतादायी बनाने के लिए विशिष्ट प्रविष्टिया न हो उनको पेंशन के लिए हिसाब मे लिया जाएगा।

(4) पेंशन के सबंध म प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(5) यदि किन्ही कारणो से सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख के एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी करना सभव न हो तो कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अनन्तिम पेंशन और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान की स्वीकृति तथा भुगतान किया जाएगा। अनन्तिम पेंशन छ महीने की अवधि के पश्चात अन्तिम हो जाएगी।

(6) सरकारी कर्मचारी से बकाया देय रकमो (सरकारी आवास से भिन्न) का निर्धारण करने के मामले म पेंशन सबधी कागजो को तैयार करने की अवस्था म पिछले रिकार्ड की जाच सेवा-निवृत्ति से पूर्व दो वर्ष की अवधि तक ही सीमित रखा।

जहा तक सरकारी आवास के उपयोग से सबधित देय रकमो का सबध है सपदा निदेशालय को किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करना होता है। अगले आठ महीनो के लिए इसम वह स्वीकार्य अवधि भी शामिल है जिसमे सेवा-निवृत्ति के बाद आवास को रखा जा सकता है। लाइसेंस फीस कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वसूल की जाएगी। स्वीकार्य अवधि से ऊपर सरकारी आवास को रखने के सबध म लाइसेंस फीस सपदा निदेशालय द्वारा सीधे ही अलाटी से वसूल की जाएगी और इस कारण से उपदान की अदायगी को रोका नहीं जाएगा।

सूचना मिली है कि फरवरी 1976 मे निर्धारित सशोधित कार्यविधि सतोषजनक कार्य कर रही है।

Setting up of Industries in Public Sector in Kerala

6011. SHRI GEORGE MATHEW: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the industries that are going to be set up under the public sector in Kerala in 1978;

(b) the industries in the public sector under construction in Kerala; and

(c) the total amount that is going to be invested in the public sector in India during 1978 and 1979?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). As far as the Central Government Industrial Projects are concerned the following are under construction in Kerala and the amount of investment estimated to be incurred during 1978-79 is indicated against them:—

(Rs. in crores)

Name of Undertaking	Proposed investment in 1978-79
1. Cochin Shipyard Ltd. . .	13·57
2. Hindustan Paper Corporation Ltd. (Velloor Plant) . .	40·00
3. Fertilizer & Chemicals Travancore Limited (Cochin Division Phase II) . . .	15·61
Expanded Plant Operations Improvement Programme—Cochin Phase I	
4. Hindustan Insecticides Ltd. (Endosulfan Technical Project, BHC, BHH, Granulation Project, DDT Formulation)	9·80

(c) Total investment in Central Government and Commercial Undertakings during 1978-79 is proposed to be Rs. 2281.74 crores.

Report of Bhoothalingam Panel

6012. SHRI JYOTIRMOY BOSU: SHRI D. B. CHANDRAE GOWDA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) when the Bhoothalingam panel is expected to submit its report;

(b) whether the Central Trade Union organisations have boycotted the panel; and

(c) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H .M. PATEL): (a) By the end of April, 1978.

(b) and (c). The Study Group addressed a communication towards the end of November/early December, 1977 to a large number of organisations e.g., employees' organisations and Trade Unions in different industries, Chamber of Commerce etc., inviting their views on the terms of reference of the Study Group by 15th January 1978. Till 16th February 1978 views had been received from one employees' organisation. Two employees' organisations have formally intimated that they are boycotting the Study Group. It is the intention of the Government to have a dialogue with Trade Unions before formulating its policy on Wages, Incomes and Prices.

Indo-Dutch Co-operation

6013. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Ministerial level trade delegation from Holland had recently visited India and discussed measures for widening Indo-Dutch co-operation in trade and economic fields; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) No Sir

(b) Does not arise

Schemes for Tourism sanctioned for Andhra Pradesh during 1977-78

6014 SHRI P RAJAGOPAL NAIDU Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) the number of schemes sanctioned for Andhra Pradesh during 1977 78 to develop tourism and

(b) the allotment made for them?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) and (b) During the financial year 1977-78 only one scheme was taken up in Andhra Pradesh relating to the purchase of two motor launches for operation at Nagarjunasagar The total cost of the Scheme was Rs 27 75 lakhs The final amount of Rs 13 13 lakhs for this scheme was released in 1977-78

Expansion of Banking Facilities in Backward and Adivasi Areas in Gujarat

6015 SHRI AMARSINH V RATHAWA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether there is proposal for the expansion of banking facilities in backward and Adivasi areas in Gujarat,

(b) if so the details thereof, and

(c) the names and number of banks to be opened in such parts of Gujarat upto March, 1979 and 1980?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) to (c) For the Formulation of their branch expansion programmes for the year 1978 the Reserve Bank of India have advised the commercial banks to select unbanked rural centres in such districts as have per bank office population in excess of the all-India average It is expected that this approach will secure larger branch expansion in tribal and backward areas which are also comparatively underbanked

In the State of Gujarat the Reserve Bank of India have classified six districts viz Amreli Banaskantha, Dangs Panchmahals Sabarkantha and Surendranagar as deficit or under banked districts for the purpose of branch expansion

The branch expansion plans for the year 1978 have not yet been received by the Reserve Bank of India from all the banks They have however, reported that as at the end of December 1977 the banks had on hand eleven licences comprising 6 for rural centres and 5 for semi-urban centres in four of the underbanked districts in Gujarat

Assistance for development of Tourism in Maharashtra

6016 SHRI VASANT SATHE Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether the Government of Maharashtra have submitted some proposals for development of tourism in the State for approval of the Central Government seeking financial assistances,

(b) if so furnish details of each of such proposals with financial indications and the decision taken thereon, and

(c) details of provision of funds made and schemes finalised/approved for development of tourism in Maharashtra and allocations made for 1978-79?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) and (b) A 'perspective plan' for development of tourism has been received from the Government of Maharashtra A total

of 112 places have been proposed for provision of infrastructural facilities. The estimated expenditure on the provision of these schemes/facilities has not been indicated. These proposals will be discussed with the State Government at the time of finalising the next Five Year Plan (1978-83) in the Planning Commission to determine which schemes would be taken up in the Central and State sectors depending upon the availability of resources.

(c) The Central Department of Tourism has made a provision of Rs. 6,00,000 for the construction of a Yatri Niwas at Sewagram in the budget estimates for 1978-79.

Amount sanctioned to Big and Small Scale Industries through IDBI

6017. SHRI GANANATH PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of money, State-wise, sanctioned by the Government for big and small scale industries through the Industrial Development Bank from 1st April, 1977 to 1st January, 1978;

(b) the number of State-wise figures of applications received by Industrial Development Bank and total number of cases disposed of and the pending cases for the last six months; and

(c) the amount of loan sanctioned so far to the State of Orissa?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL): (a) to (c). The information in being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available.

वर्ष 1977 के दौरान भारत में तस्करी से लाया गया सोना और गिरफ्तार किए गए तस्कर

6018. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 के दौरान भारत में 225 करोड़ रुपये का 40 टन सोना तस्करी करके लाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये और सोने की तस्करी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख). देश में चोरी छिपे लाये गये सोने की मात्रा और मूल्य का अनुमान लगाना संभव नही है। लेकिन, 1978 के दौरान, सीमाशुल्क अधिकारियों ने 1.6 करोड़ रुपये मल्य का 264 कि०ग्रा० निषिद्ध सोना पकड़ा और सोने की तस्करी में लगे होने के कारण 153 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तस्करी के खतरे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किये गये है। इसके अलावा, सोने की तस्करी की बुराई को रोकने के लिए सरकार ने अपने स्टाक में से सोना बेचने का निर्णय किया है। सरकार ने निर्यात के लिए जेवरात बनाने के लिए सोने के आयात की मजूरी देने का भी फैसला किया है।

Direct trading role for S.T.C.

6019. SHRI MANORANJAN BHAKTA:
SHRI G. S. REDDY:
SHRI PARMANAND GOVINDJIWALA:

Will the Minister of COMMERCE, AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether the Government have a proposal to assign direct trading role to the State Trading Corporation in order to enable it to secure overseas orders direct and make its own manufacturing and procurement of goods arrangements etc.;

(b) if so, full details of the proposal; and

(c) what will be its impact on the private export and other trade activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). The Government is considering a suggestion that the State Trading Organisations should undertake a substantial amount of actual trading on their own account including buying, selling, stocking, etc., *vis-a-vis* the conventional back-to-back contracts entered into by State Trading Organisations at present.

(c) The Corporation's proposed activity will be supplementing the efforts of the private export trade. It will assist particularly the small scale stocking, etc., *vis-a-vis* the convenbase and upgrading the quality and the packaging in order to meet the international standards

राजस्थान में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें

6020. श्री चतुर्भुज : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में चल रही उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित की गई है और उनमें से प्रत्येक योजना के लिये राजस्थान सरकार को कितना सहायता अनुदान दिया जा रहा है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : यह मंत्रालय राजस्थान सरकार को दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात् (1) उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की योजना और (2) राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में उपान्त धन (मार्जिन मनी) सहायता प्रदान करने की योजना के अंतर्गत सहायता दे रहा है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1977–78 के दौरान राजस्थान सरकार को लगभग 12.87 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी गई है। यह वित्तीय सहायता 2 बहु-विभागी भंडार एक भरतपुर में और एक अलवर में, दो छोटे (मीनी) बहु-विभागी भंडार जयपुर में और 50 छोटी छोटी शाखायें उन स्थानों में जहां अधिकतर कमजोर/असंगठित क्षेत्रों के लोग रहते हैं, खोलने के लिए दी गई है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	लाख रु०
(i) अंशपूंजी अंशदान	9.20
(ii) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स के लिए ऋण	1.58
(iii) आर्थिक सहायता जिसमे प्रबंधकीय आर्थिक सहायता भी शामिल है	2.09
योग	12.87

2. अब तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा था, जिसके अंतर्गत वह राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण के रूप में उपान्त धन (मार्जिन मनी) सहायता दे रहा था। राज्य सरकारों द्वारा यह सहायता आगे थोक विक्रेता के रूप में कार्य कर रही सहकारी विपणन समितियो को केवल इस रूप में दी जा रही थी—(क) निर्बन्ध (क्लीन) अंशपूंजी अथवा (ख) न्यूनतम ब्याज अथवा लाभ संबंधी किसी शर्त रहित प्रतिदाय

अंशपूंजी अथवा (ग) ब्याज की उस रियायती दर पर अर्द्ध-इक्विटी जो संघ द्वारा अंशपूंजी पर आम तौर पर दिये जाने वाले लाभांश से अधिक नहीं होगी, ताकि वे उर्वरकों और अन्य कृषि निवेशों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए बैंक वित्त ले सकें। यह स्कीम चौथी योजना में शुरू की गई थी और 31 अगस्त, 1977 तक चालू रही। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने राजस्थान सरकार को कुल 78.775 लाख रुपये की सहायता दी है, जिसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

	लाख रुपये में
1973–74 . .	3.00
1974–75 . .	32.50
1975–76 . .	23.275
1976–77 . .	शून्य
1977–78 तक .	20.00
	78.775

इस सहायता के फलस्वरूप, राजस्थान में सहकारी समितियों, उर्वरकों और अन्य कृषि निवेशों का वितरण कार्य 1973–74 के 1230 लाख रुपये से बढ़ाकर 1975–76 में 2904 लाख रुपये कर सकीं।

अब यह योजना समाप्त कर दी गई है। इसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर उपान्त धन के लिए आग्रह किये बिना बैंकों द्वारा उर्वरकों के लिए धन दिया जा रहा है।

पर्यटन केन्द्रों के लिए जनता होटल

6021. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे पर्यटक केन्द्रों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में जनता होटल स्थापित करने का है तथा इसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे पर्यटक केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में जनता होटल स्थापित करने का निर्णय किया है और क्या सरकार ने खजुराहो और ओरछा पर्यटक केन्द्रों में भी जनता होटल स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या पर्यटक केन्द्रों में जनता होटलों के अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी उपलब्ध कराई जायेंगी जैसा कि स्विमिंग पूल और हैली काप्टर सेवा; और

(घ) क्या खजुराहो में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य इस बीच आरम्भ हो गया है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). 1978–83 की अवधि वाली पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के चार महा नगरों में जनता होटलों का निर्माण करने पर बल दिया गया है। 1978–79 के दौरान नई दिल्ली में जनता होटल परियोजना के लिए 50 लाख रुपए के व्यय का अनुमोदन किया गया है। मध्य प्रदेश के केन्द्रों तथा अन्य उन केन्द्रों का निर्धारण, जहां केन्द्रीय क्षेत्र में जनता होटल स्थापित किए जाएंगे, एक सर्वेक्षण करने के बाद किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(ग) पर्यटन केन्द्रों पर हैलीकोप्टर सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, पर्यटन केन्द्रों पर सभी चार तथा पांच स्टार होटल और कुछ मामलों में तीन स्टार होटल भी स्विमिंग पूल की सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम अपने खजुराहो स्थित होटल में एक स्विमिंग पूल का निर्माण करने पर विचार कर रहा है। परन्तु, यह साधनों की उपलब्धता तथा पानी की नियमित और पर्याप्त सप्लाई पर निर्भर करता है।

हिन्दी में नोट और मसौदे लिखने वाले अनुभाग

6022. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय/विभाग में कुल कितने अनुभाग हैं और उन में से ऐसे कितने अनुभाग हैं जिन में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी 80 प्रतिशत से अधिक हैं ;

(ख) इस समय कुल कितने विभागों में नोट और मसौदे हिन्दी के लिखे जाते हैं और शेष अनुभागों में ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सभी अनुभागों को हिन्दी में नोट और मसौदे लिखने के स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) मंत्रालय में 81 अनुभाग हैं जिन में से अब 64 अनुभागों में 80 प्रतिशत से अधिक हिन्दी जानने वाले कर्मचारी हैं।

(ख) और (ग). 48 अनुभागों में नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग में हिन्दी का आंशिक प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है परन्तु सरकारी कार्य में हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिये कर्मचारियों पर कोई बाध्यता नहीं है।

IAC's Tight Scheduling of Available Aircrafts for Civilian Traffic

6023. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian Airlines Corporation is at present making maximum possible use of all available aircrafts for civilian traffic;

(b) if so, whether such a tight scheduling results into several charges and cancellations of routine daily flights causing inconvenience to passengers and loss of revenue to Indian Airlines Corporation;

(c) whether Government propose to buy more aircrafts to relieve the said pressure on daily traffic; and

(d) if so, when and how and at what estimated cost?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir.

(b) It does sometimes create problems which affect regularity of services. However, it does not result in any loss to the Indian Airlines.

(c) Yes, Sir.

(d) Two more Airbus A300B2 aircraft are to be inducted into Indian Airlines fleet in May/June, 1978, at an estimated cost of Rs. 48 crores.

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातित अरण्डी के तेल, चीनी, सीमेंट, चावल तथा काफी का मूल्य

6024. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तथा 1976-77 के दौरान राज्य व्यापार नगम के माध्यम से निर्यातित अरण्डी के तेल, सीमेंट, चीनी, चावल, काफी अर्ध परिष्कृत चमड़े (सैमी प्रासैस्ड लैदर) तथा चान्दी का मूल्य कितना है, और

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वर्ष 1977-78 में कितने मूल्य की उक्त प्रत्येक मद का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग):

(क) और (ख) .

(मूल्य करोड़ रु० में)

	मद	1973-74	1976-77	1977-78 (अनन्तिम)
1.	अरण्डी तेल	2.2	31	25
2.	सीमेंट	2	33	16
3.	चीनी	—	152	16
4.	चावल	2	5	3
5.	काफी	3	56	115
6.	अर्ध-साधित चमड़ा . . .	148	156	117
7.	चादी	—	94	82
	योग	157·2	526	374

Export of Jewellery

6025. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the extent of jewellery export he expects to allow as per the scheme he announced in the budget for 1978-79; and

(b) what will be the *modus operandi* of this jewellery export and gold import for that purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) and (b). The simplified scheme for encouragement of export of gold jewellery by allowing either import of gold or by sale of gold from Government stocks at International price is being finalised and will be announced soon. The export of jewellery is expected to increase considerably as a result of this scheme at least to about Rs. 50 crores initially from the present level of about Rs. 3 crores.

आपात काल के दौरान पता लगाया गया काला धन

6026. श्री ईश्वर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात काल के दौरान मारे गये छापो के परिणाम स्वरूप राज्यवार, कितने कालेधन का पता चला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जुलफिकार उल्लाह): तलाशिया के बारे मे आकडे आयकर आयुक्तो के अधिकार क्षेत्र वार रखे जाते है। एक विवरण-पत्र सलग्न है जिसमें जुलाई, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में आयकर प्राधिकारियो द्वारा ली गई तलाशिया के परिणामस्वरूप पकडी गई परिसम्पत्तियो का मूल्य बताया गया है।

विवरण

जुलाई 1975 से मार्च 1977 तक पकडी गई परिसम्पत्तियो का मूल्य

क्रम सं०	आयकर आयुक्त का अधिकार क्षेत्र	पकडी गई परिसम्पत्तियो का मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3
1	आगरा	3 38
2	इलाहाबाद	17 29
3	अमृतसर	4 78
4	आन्ध्र प्रदेश	116 35
5.	असन सोल	0 85
6	असम नागालैण्ड मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा	14 37
7	बिहार	3 12
8	बम्बई [जिसमें बम्बई (सेन्ट्रल) शामिल है]	1084 82
9	दिल्ली [जिसमे दिल्ली (सेण्ट्रल) शामिल है]	142 55
10.	गुजरात	211 84
11	जयपुर और जोधपुर	90 09
12	जालन्धर	1 48
13	कानपुर	93 73
14	कर्नाटक	137 57
15	केरल	98 54
16	लखनऊ	143 11

1	2	3
17.	मध्य प्रदेश	62 80
18.	मेरठ	33 97
19	उड़ीसा	28 09
20	पटियाला	26 65
21.	पूना	88 63
22.	रोहतक	0 74
23	तामिलनाडु [जिसमें मद्रास (सेण्ट्रल) और कोयम्बतूर शामिल है]	192 89
24	विदर्भ और मराठवाड़ा	83 51
25	पश्चिम बंगाल [जिसमें कलकत्ता (सेण्ट्रल) शामिल है]	822 98
	जोड़	3504 13

Sale of Cement on production of Ration Cards in Delhi

6027 SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO OPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cement is allowed to be sold on production of ration cards in Delhi;

(b) if so, the particular reasons for which the cement is asked to be sold on ration cards;

(c) whether Government have received reports that most of the people who purchase cement on ration cards sell that in black market and they do not need cement for their own use;

(d) whether it has also come to his notice that the sale of cement on ration cards encourages unauthorised construction;

(e) whether in view of above Government contemplates to order for stopping sale of cement on ration cards and allow sale of cement only on sanctioned building plans and house tax receipts; and

(f) if so, when; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) to (d). For ensuring availability of cement to consumers at controlled prices, sale of cement has recently been regulated by the Delhi Administration in such a way that 17 per cent of the total quantity of cement is sold against the sanctioned building plans and permits and rest for repairs. 10 bags of cement can be sold against ration cards only for repairs. An amendment to the Delhi Cement (Licensing and Control) Order March, 1972, has been promulgated on 10th March, 1978, stipulating that no permit holder or any person who has purchased cement either on ration card or against sanctioned building plans can transfer his permit for ceemnt to other person, a contravention of which is punishable under the Essential Commodities Act, 1955. There is no definite information that sale of cement on ration cards for repairs encourages unauthorised constructions.

(e) and (f) No change in the existing policy is at present contemplated Stopping of sale of cement for repairs on ration cards will cause a great hardship to the consumers

Setting up Tobacco Auction Centres

6028. SHRI PRASANNBHAI MEHTA Will the Minister of COMMERCE, AND CIVIL SUPPLIES AND CO OPERATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that Union Government are considering to set up tabacco auction centres to protect the interest of growers,

(b) if so when the same is likely to be set up,

(c) what are the places where these centres will be set up,

(d) whether it is also a fact that the State Trading Corporation had decided to enter the tobacco market and

(e) what are the other facilities being considered for the tobacco growers during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) Yes Sir A Bill to amend the Tobacco Board Act 1975 for empowering the Tobacco Board to establish auction platforms for virgina tobacco is proposed to be introduced during this session

(b) and (c) Intention is to set up the auction platforms as early as possible after legislative amendments are made but it is not possible at this stage to indicate a definte date or the location of the centres

(d) The State Trading Corporation is buying 5,000 metric tonnes of tobacco of 1978 crop on its own account and risk as its normal commercial activity

(e) The measures taken this year include fixation of minimum export prices, indicative prices, evolution of standard farm grades, introduction of tobacco leaf purchase voucher system, disbursement or financial asistance to tobacco growers in Andhra Pradesh whose crop and curing barns were affected by cyclone etc

Jaigarh Fort Treasure

6029 SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) was any treasure found in Jaigarh Fort or anywhere in Rajasthan during the excavations searches etc, made within three years time; if so, how much worth

(b) how much money was spent in the exploration, search, etc, and

(c) who had actually ordered these excavations, explorations and searches etc?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) (a) to (c) Information available shows that a search for the treasure believed to have been hidden in Jaigarh Fort was commenced in June, 1976 and was abandoned in November, 1976 No treasure was found The search was undertaken under an agreement dated 22nd May 1976 entered into in this behalf by the Government of India (in the Department of Culture) and Colonel Bhawam Singhji of Jaipur The expenditure booked for the digging operations comes to Rs 2,40,989 as intimated so far by the various agencies invloved in the operations

Reservation of SC/ST for promotion in S.T.C.

6030 SHRI SHIV SAMPATI RAM Will the Minister of COMMERCE, AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state

(a) whether reservation orders in promotion for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes are implemented in STC, if so, from which date,

(b) how many employees have been promoted in each cadre includ-

ing Office Manager (General) and Assistant cadres since the inception of STC;

(c) what is the proportionate representation of SC/ST in Office Manager (General) and other cadres;

(d) whether there is any backlog/shortfall for SC/ST in Office Manager (General) and other cadres against promotion quota; and

(e) if so, how the backlog/shortfall in Office Manager (General) and other cadres would be filled in?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir. Rosters are being maintained for promotion by Selection from January 1970 and for promotion by Seniority-*cum*-fitness from 27-11-1972.

(b) and (c). The number of employees promoted and the proportionate representation of SC/ST in each category since inception of STC is not available. However, the required information since the implementation of the Government directives by STC is given as per enclosed statement.

(d) Yes, Sir.

(e) The reserved quota for promotion has to be filled from within and all eligible SC/ST employees have been promoted as per the directives As and when more SC/ST employees become eligible they will be considered against reserved quota for promotion.

Statement

Statement showing the total number of employees promoted in each cadre indicating separately number of SC/ST employees promoted.

Sl. No.	Cadre	Total number of persons promoted	No. of SC/ST promoted out of Col. 2
	1	2	3
1.	Dy. Marketing Manager Gr. I	2	..
2.	Dy. Marketing Manager Gr. II	94	1
3.	Office Manager (General)	214	7
4.	Dy. Finance Manager Gr. I	13	..
5.	Dy. Finance Manager Gr. II	24	2
6.	Office Manager (Accounts)	15	1
7.	Dy. Marketing Manager—I (Tech)	2	1
8.	Dy. Marketing Manager—II (Tech.)	9	1
9.	Office Manager (Technical)	19	1
10.	Inspector (Tech.)	2	2
11.	Assistant	221	10

NOTE : In case of Sl. Nos. 1, 2, 4, 5, 7 & 8, the reservation orders applicable from 1-7-78 as result of reclassification of posts by the Government.

Installation of a Plant of Currency Paper in Security Paper Mill, Hoshangabad

6031. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a plant required for the manufacture of currency paper, has been installed in the Security Paper Mill at Hoshangabad;

(b) whether the Plant has been commissioned;

(c) if so, the quantity of currency paper so far manufactured at the plant; and

(d) what is the amount of foreign exchange saved as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) and (b). The main plant for manufacture of currency paper was commissioned as early as 1967-68. It is presumed that the Question refers to a mould cover making plant installed recently in the Security Paper Mill at Hoshangabad to help in the manufacture of currency paper. This mould cover making plant was commissioned in March, 1977.

(c) About 8500 reams of bank note paper and 4700 reams of plain paper have been produced so far from the mould covers made in India.

(d) Rs. 4.00 lakhs.

बेरोजगार व्यक्तियों और लघु उद्योगों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाना

6032. श्री रामजी लाल सुमन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान जिन व्यक्तियों को बेरोजगार कर दिया गया और जिन व्यक्तियों के लघु उद्योगों को बन्द कर दिया गया था, उन्हें कम ब्याज पर ऋण देने का सरकार का विचार है जिस से वे व्यक्ति अपने उद्योगों को पुनः चालू कर सकें; और

(ख) क्या मीसा और डी० आई० आर० के अधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). आंतरिक सुरक्षा अधिनियम अथवा डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत आपात काल के दौरान नजरबन्द अथवा कैद रहने वालों को नियोजन प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत नये स्वयं नियोजन उद्यम शुरू करने के लिये अथवा अपने वर्तमान कारोबार की स्थिति सुधारने के लिए सक्षम बनाने के लिये बैंकों को सलाह दी गई है कि उन्हें उपेक्षित क्षेत्रों की अपनी वर्तमान किसी योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर ऋण सहायता दें ।

आपात काल के दौरान, अपने राजनैतिक सम्बन्धों अथवा भूतपूर्व प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता के कारण जो व्यक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए नजरबन्द अथवा कैद रहे थे, वे सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार की सहायता पाने के पात्र हैं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

6033. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को छोटे उद्योगों की स्थापना करने के लिए

राष्ट्रीयकृत बैंकों से 40 करोड़ रुपये की धनराशि ऋण के रूप में दिये जाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में वर्ष 1977-78 के दौरान (जनवरी, 1978 तक) इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि के ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) और (ख). यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये 40 करोड़ रुपये के ऋण देने की कोई विशिष्ट योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है, फिर भी, सरकार ने विभेदी ब्याज दर योजना आरम्भ की है, जिस का विशिष्ट उद्देश्य यह है कि हरिजनों सहित सब से कमजोर वर्गों के पात्र ऋण कर्ताओं को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से, उत्पादक कार्य शुरू करने के लिये, 4 प्रतिशत रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाये। हाल ही में सरकार ने इस योजना का कार्य क्षेत्र और व्याप्ति पूरे देश तक विस्तृत कर दिया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के सुरक्षण के उद्देश्य से, इस संशोधित योजना के अधीन बैंकों से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन दिये गये उन के ऋणों का कम से कम एक तिहाई भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिले।

राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, दिये गये ऋणों की बकाया राशि सितम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार क्रमशः 33082 और 76765 ऋण खातों में 203 लाख और 367 लाख रुपए थी।

Janata Hotel in Calcutta and Bombay

6034. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether there are plans to set up Janata Hotels in Calcutta and Bombay; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). Yes, Sir. The Five Year Plan 1978—83 envisages the construction of a Janata hotel in Calcutta and Bombay.

Realisation of Taxes from M/s. Kores India

6035. SHRI RAMESHWAR PATIDAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount paid as taxes during the last three years by M/s. Kores India;

(b) the total amount of business they have done during the period; and

(c) whether taxes have been realised in full; if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) Income-tax and Surtax paid by M/s Kores India Limited for the last three assessment years is as under:

Assessment year	
1975-76	Rs. 56.76 lakhs
1976-77	Rs. 48.89 lakhs
1977-78	Rs. 65.17 lakhs

(b) The total sales of the company during the accounting periods relevant to the aforesaid assessment years was Rs. 9.53 crores, Rs. 10.47 crores and Rs. 13.33 crores, respectively.

(c) Gross income-tax demands aggregating to Rs 90,827 are outstanding against the company as on 31-3-78 These demands are disputed in appeals and have been stayed till their disposal

आयात एवं निर्यात विभाग में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारी

6036 श्री राम विलास पासवान क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आयात एवं निर्यात विभाग में कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और

(ख) उक्त विभाग के अधीन अनुसंधान तथा सांख्यिकी निदेशालय में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2048/79]

Opposition by Planning Commission in respect of Reduction in Interest Rates

6037 SHRI G S REDDI Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether the recent reduction in interest rates has been opposed by the Planning Commission or any member of it,

(b) if so, what is his reaction to this opposition and

(c) whether the cut in interest rates has helped banks to dispose of their idle savings?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) At a symposium organised by the National Institute of Public Finance and Policy, Prof Raj Krishna Member, Planning Commission had expressed the view that the recent lowering of the interest rates announced by the Reserve Bank of India was not justified

(b) The decision to lower interest rates was arrived at after taking all the relevant factors into account

(c) Banks do not keep investible resources idle If the reference is to credit expansion, it is too early to assess the impact if any, of the reduction in interest rates on the volume of credit

Request to review the uprooting and replanting subsidies from tea Board for hill tea gardens

6038 SHRI K B CHETTRI Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether Government have received any request to review the uprooting and replanting subsidies from Tea Board specially for the hill tea gardens, and

(b) if so the reactions of Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) and (b) The Tea Board's proposals for the revision of the rates of subsidy for uprooting and replanting of tea areas for the gardens in the plains as also in the hill areas are under examination

New Flight Routes Started by Janata Government

6039 SHRI BALDEV SINGH JASROTIA Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) what are the new flight routes started by the Janata Government

and since when to cope with increasing demand of air service;

(b) if not, why not, if so, with what yard stick;

(c) is it a fact that all the flights on all the routes are totally successful from all points;

(d) Jammu and Kashmir being natural gifted whether there is any proposal with the Government to develop Udhampur and Poonch, Baderwah and Nuri Chamb Sarthal and Sanasr for tourist attraction to provide flights; and

(e) if so, when and if not, reasons for the same?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Besides augmenting capacity on some routes, the following new services have been started by Indian Airlines:—

(i) Effective 5-5-77 Jabalpur and Raipur were included as halts on the route Delhi/Gwalior/Bhopal/Indore/Bombay on two days in a week The route structure of his service has since been realigned to provide a daily link to Gwalior and thrice a week frequency to Jabalpur and Raipur.

(ii) A thrice weekly F-27 service on the Calcutta/Patna route with effect from 15th November, 1977.

(iii) A daily Boeing-737 service on the Delhi/Nagpur/Hyderabad route with effect from 20th December, 1977.

(iv) A thrice weekly Boeing-737 service on the Calcutta/Jorhat/Dibrugarh route with effect from 20th December, 1977.

(b) and (c). New services are introduced by Indian Airlines not only on the basis of economic viability but also for meeting the requirements of remote areas for an air link Operations on such routes may not be totally successful from all points.

(d) and (e) There is no proposal at present to develop udhampur and Poonch, Baderwah and Nuri Chamb Sarthal and Sanasr for tourist attraction. The Indian Airlines aircraft resources do not permit any new airlinks at present.

पर्यटन तथा होटल प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय संस्थान

6040. **श्री नाथू सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन तथा होटल प्रबन्ध के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का है,

(ख) ऐसा संस्थान स्थापित करने के लिए मूल आवश्यकतायें क्या है;

(ग) क्या इन आवश्यकताओं के अनुसार इसके लिये जयपुर उपयुक्त स्थान है ;

(घ) क्या उक्त संस्थान जयपुर में स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). पर्यटन उद्योग मे पहल से ही नियुक्त कर्मचारियों के लिये "एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम" (ई डी पीज) शुरू में देश के विभिन्न केन्द्रों पर प्रस्तुत किए जाएंगे। संस्थान को किसी विशेष स्थान पर स्थापित करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब पर्यटन के सम्बन्ध मे एक नियमित दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अत संस्थान स्थापित करने के लिये मूल अपेक्षाएं तथा संस्थान स्थापित करने के लिए स्थान का चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तुत किया जाने वाला स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार का है तथा उस कार्यक्रम के विकास के लिए किस प्रकार की सुविधाएं अपेक्षित हैं।

Contributions to various schemes of Small Savings

6041. SHRI HITENDRA DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the contributions to the various schemes of Small Savings in each of the States and Union Territories of India; and

(b) do Government consider any other scheme for more incentives to the small saver?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) (a) The net collections (i e. gross collections minus withdrawals) through the various small savings securities amounted to Rs 416 46 crores during 1976-77 and Rs. 259.85 crores during April to December 1977 (Information for later months is awaited) State wise details of these net collections are given in the statement annexed.

(b) The small savings scheme, are constantly kept under review and suitable modifications/additions to the extent found necessary, are made from time to time.

Statement

State-wise details of net small Savings collections

(In Rs crores)

S No	State	1976-77	April—December, 1977
1	2	3	4
			(Provisional)
1.	Andhra Pradesh	11·39	7·39
2	Assam	9 08	13·66
3.	Bihar	48 69	22 64
4.	Delhi	19·78	16·51
5	Goa	1·81	2·80
6.	Gujarat	28·16	30·41
7.	Haryana	9·75	3·37
8	Himachal Pradesh	6·49	2·18
9.	Jammu & Kashmir	1·83	2·57
10.	Karnataka	24·79	4·80
11	Kerala	2·91	4·76
12.	Madhya Pradesh	15·57	7·65
13.	Maharashtra	62·27	31·87
14.	Manipur	0·30	0·05
15.	Meghalaya	(—)0·24	0·38

1	2	3	4
16.	Nagaland	0·09	0·07
17.	Orissa	110·11	8·61
18.	Punjab	0·18	1·17
19.	Rajasthan	17·03	(—)0·66
20.	Sikkim	0·04	0·01
21.	Tamil Nadu	33·22	22·68
22.	Tripura	0·39	0·63
23.	Uttar Pradesh	54·59	32·18
24.	West Bengal	56·73	43·63
25.	Chandigarh	0·51	0·50
26.	Lakshadweep	0·01	0·01
27.	Mizoram	0·22	0·16
28.	Pondicherry	0·11	0·13
29.	Andaman & Nicobar Islands	(-)0·35	(-)0·31
	Total	416·46	259·85

Expenditure on Political Donations out of Shri Aga Khan's Income

6042. DR. SUBRAMANIAM SWAMY. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether he is aware of an article in October, 1977 issue of "Volunteer" a Gujarati journal from Bombay, which indicates that part of the Aga Khan's income in India has been spent on political donations, at the time of the recent elections;

(b) the truth of this article,

(c) what is the Aga Khan's income
(i) from various properties in India;
(ii) from other sources in India;

(d) whether this is treated as his personal income, or as the income of the community headed by him; and

(e) how much of it has been permitted to be remitted abroad in the last ten years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH). (a) and (b). There is no truth in the article published in October, 1977 issue of "Volunteer" that H. H. Aga Khan has made donations to political parties at the time of recent elections.

(c) As per the latest completed assessment for the assessment year 1975-76, the income of H H. Aga Khan is as under:—

(i) Income from vocation
Rs. 3,00,000

(ii) Income from property.
Rs. 88,135

TOTAL: Rs. 3,88,135

The properties are situated in various parts of India, such as Maha-

rashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Union Territory of Goa, Daman and Diu, etc

(d) The income from the properties and vocation is treated as personal income of H H Aga Khan and not as the income of the community headed by him. He is assessed as a non-resident individual in respect of the above income

(e) No amount out of the income of H H Aga Khan has been remitted abroad for the last ten years

Steps to augment accommodation for Tourists in Ladakh

6043 SHRIMATI PARVATI DEVI Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the steps Government propose to take to augment the accommodation facilities for tourists in Ladakh?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) The Central Department of Tourism has no schemes at present for augmenting tourist accommodation in Ladakh It is however understood that besides the existing accommodation in Leh about 3 new hotels/paying guest accommodation have come up in the private sector and the State Government has also plans to provide tented accommodation at Kargil and Leh to meet the requirements of tourists for accommodation in Ladakh.

Companies Issuing Shares to Public

6045 SHRI NATWARLAL B PARMAR Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that the companies issuing shares to the public do not generally allot shares to the small investors and the Bombay Stock Exchange also neglect them,

(b) whether it is a fact that the present method and scheme of allotment of shares is detrimental to small investors,

(c) what steps Government propose to see that rich persons do not corner stock exchanges and instead small investors be afforded opportunities to apply for new issues, and

(d) whether Government propose to issue instructions or guidelines for the good of small investors, and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHR H M PATEL) (a) No, Sir

(b) No Sir

(c) and (d) Government has already issued instructions in January, 1961 and again in July 1972 to all the Stock Exchanges stating that applicants in lower category particularly those who apply for 5 or 10 shares if the shares are of Rs 100 each or for 50 shares or 100 shares if the shares are of Rs 10 each are to be given due weightage by reducing the number of shares to be allotted to applicants in higher categories In this connection it may also be added that the minimum trading lots at the Stock Exchanges at present are 5 shares of Rs 100 each or 50 shares of Rs 10 each The Stock Exchanges have also been directed to make allotment of shares in lots of 25 of Rs 10 each in cases where there is substantial over-subscription

पूंजी लागत अनुदान योजना

6046. श्री भजन सिंह ठाकुर : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूंजी लागत अनुदान योजना (कैपिटल कास्ट ग्रान्ट स्कीम) के अन्तर्गत पिछड़े जिले का समस्त क्षेत्र आ सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कुछ जिलों/क्षेत्रों को निवेश सबंधी सहायता की केन्द्रीय योजना के प्रयोजन के लिये योग्य होने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। ऐसे जिलों/क्षेत्रों की एक सूची 16-11-1977 को पूछे गए अतारांकित

प्रश्न संख्या 845 के उत्तर में प्रधान मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखी गई थी । जहां किसी पूरे जिले को विशेष सहायता योजना के लिए योग्य चुन लिया गया है वहां यह योजना जिले के समस्त क्षेत्र पर लागू होती है । लेकिन जहां किसी राज्य में किसी "क्षेत्र" को इस प्रयोजन के लिये चुन लिया गया हो वहां पर यह योजना केवल ऐसे विशिष्ट क्षेत्र पर ही लागू होती है ।

Absorption of employees of Erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity in Trade Fair Authority of India

6047 SHRI SHIV NARAIN SARSONIA Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 1491 dated 3rd March 1978 regarding absorption of employees of Exhibitions and Commercial Publicity Directorate in Trade Fair Authority of India and State

(a) whether the employees of erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity will get interest on their G P F upto the date on which the final payment thereof is made to them

(b) if so when will the final payment of G P F along with interest upto date be paid to them

(c) if the interest is not to be paid up to-date what is the reason thereof

(d) when will they get the benefits accruing to them in lieu of their past Government Service and whether a specific time limit has been fixed for the finalization of their cases if not why and

(e) whether a special cell is proposed to be created for expediting the final settlement of their long standing cases without any further loss of time?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) to (e) The benefits relating to pension gratuity G P F etc accruing to the officials of the erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity, on the basis of their past Government service had to be finalised in consultation with the Ministry of Finance (Department of Expenditure) Ministry of Home Affairs (Department of Personnel) Bureau of Public Enterprises etc This time-consuming process has already been completed Necessary orders are expected to be issued shortly Under the G P Fund (C S) Rules 1960 these officials will be entitled to interest on their G P F up to the date of issue of orders It is however expected that necessary bills in respect of the claim of each official will be presented to the Accounts authorities for payment soon after the issue of orders

Since the policy issues relating to payment of G P F etc to the employees of the erstwhile Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity have since been finalised it may not be necessary to create a special cell for this purpose

छोटी आटोमैटिक बोर्ड मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट

6048 श्री आर० एन० राकेश क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या छोटे उद्योगों का बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने कम क्षमता के उत्पादन वाले उद्योगों का बढ़ावा देने का फैसला किया है किन्तु बड़ी मिलों के अनुपात में छोटी आटोमैटिक बोर्ड मिलों को कोई छूट नहीं दी गई है

(ख) यदि हां तो 10,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली बड़ी आटोमैटिक बोर्ड मिलों पर केवल 17 प्रतिशत उत्पादन शुल्क बढ़ाने और केवल 2,000 टन उत्पादन क्षमता वाली छोटी मिलों के लिए उत्पाद शुल्क में 32 प्रतिशत वृद्धि करने के क्या कारण है और

(ग) छोटी कागज मिलों अर्थात् 2000 टन क्षमता के लिए 75 प्रतिशत, 2000 से 5000 टन क्षमता के लिए 60 प्रतिशत और 5000 से 10000 टन क्षमता के लिए 50 प्रतिशत की तरह की 3,000 टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली छोटी ऑटोमैटिक बोर्ड मिलों के लिए शुल्क में 75 प्रतिशत छूट न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जिन छोटे निर्माताओं की पिछले वर्ष में निकासियां, 5 लाख रुपये की प्रथम निकासियों पर देय शुल्क से 15 लाख रुपये से अधिक नहीं थी, उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने 1978 के बजट प्रस्तावों के अनुसरण में 69 निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माणकर्ता छोटे एककों को छूट दी है। परन्तु आटोमैटिक मिल बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड मिलों के मामले में भारत सरकार राजस्व विभाग की 16 मार्च, 1976 की अधिसूचना संख्या 70/76 के० उ० शु० द्वारा उत्पादन शुल्क से छूट की एक अलग योजना प्रदान की गयी है।

(ख) प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है। वर्तमान बजट में विशेष उत्पादन शुल्क लगाने के परिणामत, लगने योग्य मूल शुल्क के 1/20 भाग को छोड़ कर कागज और गत्ते पर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है, यह शुल्क बड़ी और छोटी दोनों बोर्ड मिलों पर लागू होता है।

(ग) छोटी कागज मिलों को जिन कारणों से शुल्क में यह रियायत दी गयी है वे अन्य बातों के साथ-साथ लागत संबंधी घाटे हैं जो छोटी कागज मिलें अपेक्षाकृत बड़ी कागज मिलों के मुकाबले उठाती है। छोटी आटोमैटिक बोर्ड मिलों के मामले में, इस प्रकार के घाटे बड़ी बोर्ड मिलों के मुकाबले प्रभावी रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं।

टाटा कम्पनी जमशेदपुर (बिहार) पर करों की बकाया राशि

6049. श्री आर० पी० दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा कम्पनी जमशेदपुर, बिहार पर 1 मार्च, 1978 को करों की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): इस प्रश्न का सम्बन्ध संभवत टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से है, जिस का मुख्यालय जमशेदपुर में है। 1-3-1978 की स्थिति के अनुसार, इस कम्पनी पर 17.91 लाख रुपये की सकल मांग बकाया थी। यह मांग विवाद ग्रस्त है और अपील का निपटान होने तक इसे रोक दिया गया है।

ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत

6050. श्री राम कंवार बेरवा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दांतवाला समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार करते हुए ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से श्रमिक समस्याओं पर बातचीत की थी तथा इस बारे में क्या प्रगति हुई है और यह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : चूंकि कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ नहीं है, इसलिए दांतवाला समिति ने ऐसे किसी संघ से बातचीत नहीं की। 23-2-1978 को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई दांतवाला समिति की रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक की टिप्पणी के शीघ्र सरकार को प्राप्त उपलब्ध होने की संभावना है।

आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिए कुर्की आदेश

6051. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 और 1977-78 में आयकर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये कितने मामलो मे कुर्की आदेश जारी किये गये तथा कितने मामलो मे जारी नही किये गये ;

(ख) क्या कुछ मामले है जिनमे आयकर निर्धारित किये बिना कुर्की आदेश जारी किये गये और यदि हा, तो इसका क्या औचित्य है , और

(ग) क्या बहुत से ऐसे मामलो मे भी कुर्की आदेश जारी नही किये गये जिनमे कर निर्धारण कर लिया गया था तथा वसूली आदेश जारी कर दिये गये थे और यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुलकिकार उल्लाह) :(क) से (ग) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर की बकाया की वसूली के लिए कर-वसूली अधिकारियो ने वर्ष 1976-77 मे 31,040 मामलों मे और वर्ष 1977-78 मे 28 फरवरी, 1978 तक 42,602 मामलो मे चल तथा अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण की कार्यवाही की थी : प्रश्न मे पूछी गई अन्य सूचना तत्काल उपलब्ध नही है और इसे एकत्र करने मे काफी समय और श्रम लगेगा। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले अथवा मामलो के बारे मे ऐसी सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

Complaints against Director of Export Inspection Agency

6052. SHRI V. M. SUDHEERAN: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to refer to

(a) whether many complaints against the Director of Export Inspection Agency were received from the Shah Commission; and

(b) if so, what action has been taken on these complaints?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Three complaints in regard to working of the Export Inspection Council/ Agencies have been received by Government from the Shah Commission for such action as may be deemed fit Some references m these complaints have been made against the Director of Inspection and Quatlity Control, Export Inspection Council

(b) These are under examination.

Change in the functioning of Urban Cooperative Banking System

6053. SHRI MOHINDER SINGH SAYIANWALA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is proposed to bring about a change in the functioning of urban cooperative banking system;

(b) the new frame-work in which these banks are supposed to tone up their working; and

(c) whether some steps are being taken to see that the service of these banks reach almost every corner of the country especially the backward regions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA

KUMAR GOYAL): (a) and (b). The Reserve Bank of India has set up a Committee on Urban Cooperative Banks to go into the working of the Urban Cooperative Banks and suggest, among others, measures for improving the functioning of the system. The terms of reference of this Committee are:

(1) To evaluate the role of Primary (Urban) Cooperative Banks in the banking system.

(2) In the light of the above, to indicate their future role and, in particular, to assess whether any additional facilities or assistance are needed.

(3) To examine aspects such as viability, lending procedures and policies particularly from the point of serving the small borrowers.

(4) To assess the extent of professional management and adequacy of training facilities.

(5) To consider any other problem relevant to the above terms of reference and make recommendations.

(c) Urban cooperative banks are organised mainly to extend banking services to the people in and around urban areas. As such their objective is not to reach their services to the people living in every corner of the country namely, rural areas. However, to promote organisation and development or urban banks in towns in backward areas/regions where there are no urban banking facilities, the Reserve Bank of India has granted special relaxations in matters relating to collection of share capitals and membership for licensing of new urban cooperative banks.

Recovery of Excise Arrears from Textile Mills

6054. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the recovery of excise arrears amounting to about Rs. 2 crore from textile mills has been stayed;

(b) whether it is a fact that the textile mills have demanded to waive this amount; and

(c) what are the details and Government's decision on their demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) Yes, Sir. Recovery of excise duty on account of duty paid on yarn on compounded basis, amounting to about Rs. 3.46 crores has been stayed.

(b) Yes, Sir. The textile mills have requested for the waiver of the amount of differential duty demanded for the period prior to 31-5-1977.

(c) The representations of the textile mills for the waiver of the duty are under consideration of the Government and a decision is likely to be taken soon.

Harassment of Passengers by Customs Officers at Delhi and Bombay Airports

6055. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether reports of ugly and indecent harassment of passenger, particularly lady passengers, by Delhi and Bombay Airports Customs Officers have come to the knowledge of the Government; and

(b) if so, steps taken or proposed by the Government for removing such harassment of passengers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) and (b). The reference probably appears to be to an incident which occurred at Palam airport on 2-6-1977. An out-going lady passenger had complained that

she had been assaulted by a Customs Officer at the time of her departure The concerned customs officer was immediately transferred from the airport. The complaint was later enquired into in detail. No definite evidence, however, came forth in the investigation in regard to the alleged incident, beyond a strong suspicion against the officer. He has been administrered a warning.

Leasing out of Corridors of Common Passage in Jeevan Deep Building

6056. SHRI SURENDRA BIKRAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the corridors meant for common passage in the first floor of Jeevan Deep Building in Parliament Street, New Delhi has been leased out to a private commercial firm;

(b) if so, the considerations on which the step has been taken;

(c) whether it is not a violation of the terms of lease with the other tenants; and

(d) whether Government propose to consider putting the place back to its genuine use?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M PATEL): (a) and (b). A passage on the first floor the LIC's "Jeevan Deep" Building on Parliament Street, New Delhi, other than the common corridor which had been made available to the existing tenants in terms of leases executed in their favour, was rented out by the LIC to a firm in July, 1977. The purpose was to prevent misuse of the passage and to increase rental income from the building.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

विदेशी कम्पनियों के माध्यम से चीनी का निर्यात

6057. श्री भारत सिंह चौहान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी का विदेशी कम्पनियों के माध्यम से निर्यात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस लेन-देन पर होने वाले लाभ में कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस नये प्रबन्ध की पृष्ठभूमि क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शारिक बेग): (क) जी नहीं। जब से चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत हुआ है, तब से विदेशी फर्मों के माध्यम से चीनी का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) 1974 से चीनी के निर्यातों से अर्जित लाभ-हानियां निम्नोक्त प्रकार रही हैं :—

वर्ष	मात्रा (लाख मे० टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)	लाभ हानि (करोड़ रुपये)
1974—75 .	6.24	314.34	+ 155.90
1975—76 .	11.88	468.48	+ 150.56
1976—77 .	5.80	152.01	—27.30
1977—78* .	0.69	16.33	—2.00

*अनन्तिम

(ग) प्रश्न नहीं उठता

Delinking of General Managers and Managing Director General Insurance Companies

6058. SHRI KISHORE LAL Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that it was decided that the General Managers and the Managing Directors of the now merged General Insurance Companies be delinked from their original companies and

(b) if so how many have been transferred and what are the reasons for not transferring the other General Managers and the Chairman cum-Managing Directors?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) No Sir

(b) Does not arise

Production based Control of Central Excise

6059 SHRI PIUS TIRKEY Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether Production Based Control of Central Excise in the self removal procedure units has proved a failure because big units having three shift production, Central Excise Staff have no check on production but to ditto the figures given by the factories,

(b) whether there is no proper distribution of work as in so many cases one officer has to control 10 to 30 units at a time,

(c) whether after a start from 1st February, 1978 any improvement has come to notice in revenue by the Government and if not, the criteria of this type of expensive system, and

(d) what action Government propose to take in the matter and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) The production based pattern of control, which does not deviate from the essentials of the Self Removal Procedure having been introduced with effect from 1-2-1978, it is too early to make an assessment about its working It is, however not correct that the figures of production given by bigger units are accepted by Central Excise Officers without proper verification and checks

(b) Deployment of Central Excise staff is based on various considerations like the revenue yield from the units the number of shifts worked, the concentration or dispersal of the units the man-power available and other relevant factors In the case of smaller units a number of these would necessarily have to be grouped together and placed under the charge of a single officer According to the information available it is the exception rather than the rule for an Inspector to have charge of more than 10 units and in such cases all or most of the units would be ones yielding low revenue Further Government are in the process of recruiting additional staff to implement the revised pattern of control, and this will progressively provide for more concentrated control

(c) Complete figures of revenue realisation during the month of February, 1978 have not yet become available In any case, the revenue figures for a single month can hardly form the basis for a judgement

(d) The working of the Scheme is being kept under review with a view to making whatever modifications might be found necessary in the light of experience

Appointment of Air Hostesses against Reserved Vacancies during last year

6060 SHRI R. L. KUREEL Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that some vacancies of Air Hostesses were reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes last year,

(b) if so, how many applications were received from Scheduled Castes/ Scheduled Tribe candidates and how many of them were found having minimum qualifications required by the Department; and

(c) how many of them were appointed against reserved vacancies?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) Yes, Sir.

	Indian Airlines	Air-India
S/C	18	55
S/T	8	29

(b)

	Indian Airlines		Air-India	
	S C	S T	S C	S T
Number of applications received	630	168	1034	247
Number of eligible candidates	338	87	767	178

(c)

	Indian Airlines	Air-India
S/C	18	43
S/T	8	17

मूल्यों में अन्तर के कारण स्वर्ण की तस्करी

6061. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारत में विद्यमान मूल्य के प्रति 10 ग्राम 135 रुपये कम है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अन्तर के कारण स्वर्ण विदेशों से तस्करी करके यहां लाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :(क) 21 मार्च, 1978 को लागू मूल्यों के संदर्भ में, 10 ग्राम सोने का लंदन में बताये भाव के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य, भारत में प्रचलित मूल्य के मुकाबले लगभग 184 रुपये कम था।

(ख) जी, हां।

(ग) तस्करी की बुराई दूर करने के लिए सरकार ने अपने पास रखे स्टाक से, सोने की बिक्री शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने, स्वर्ण जवाहरातों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, सोने के आयात की मंजूरी देकर अथवा सरकारी स्टाक से, सोने की बिक्री करके एक सरलीकृत योजना शुरू करने का फैसला भी किया है।

गणेश फ्लोर मिल लिमिटेड, कानपुर का कार्यकरण

6062. श्री राम लाल राही : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें गणेश फ्लोर मिल लिमिटेड, कानपुर की वर्तमान स्थिति के बारे में पता है, जो नवम्बर, 1972 में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गणेश फ्लोर मिल की बकाया राशि का

भुगतान करने का निर्णय कर लिया था परन्तु प्रशासनिक स्तर ने उसके भुगतान मे अब तक विलम्ब किया है और इसके परिणाम-स्वरूप वहां असन्तोष व्याप्त है

(ग) यदि हां, तो भुगतान कब तक और किस प्रकार किया जायेगा ; और

(घ) क्या इस मामले मे ससद् सदस्यो ने भी कोई पत्र लिखा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क)जी हा। कम्पनी की मानी स्थिति, जो उसे अधिकार मे लेने के समय ऋणात्मक (नेगेटिव) अर्थात् 45 16 लाख रु० (माइनस) थी, अब धनात्मक अर्थात् लगभग 218 लाख रु० है। कम्पनी ने लाभ कमाना भी आरम्भ कर दिया है।

(ख) से (घ). ससद सदस्यो सहित कई लोगो से देय राशियो का शीघ्र भुगतान करने के लिए अभ्यावेदन मिले है। नवम्बर, 1977 मे, देय राशियो के भुगतान के लिए दी गई मोहलत की समाप्ति के बाद, कम्पनी को अधिकार मे लेने से पूर्व की देयता का क्रमबद्ध भुगतान करने के लिए एक योजना बनाई गई है, जो निम्न प्रकार है .—

(i) समस्त सांविधिक देय राशियो और रक्षित लेनदारो की देय राशियो, केवल उन्हें छोडकर जिनके बारे मे मुकदमे चल रहे है , का भुगतान, वचन के अनुसार, योजना के चालू होने की तारीख से पाच वर्षों की अवधि मे क्रमबद्ध रूप मे किया जाना चाहिये।

(ii) समस्त रक्षित लेनदारो, जिनके दावो के बारे से मुकदमे चल रहे हैं, को जब कभी न्यायालयों का निर्णय उपलब्ध हो उसके अनुसार भुगतान किया जाए।

(iii) कम्पनी की ऐसी सांविधिक जमा-राशियो, जो देय हो चुकी हैं, के जमाकर्त्ताओ मे से प्रत्येक को इस योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष 10,000 रुपयो (दस हजार रुपये केवल) का भुगतान किया जाना चाहिए और सांविधिक जमा की शेष राशि, यदि देय हो, का भुगतान योजना के कार्यान्वयन के दूसरे वर्ष किया जाना चाहिए।

(iv) सब विविध लेनदारो मे से प्रत्येक को योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष 10,000 रुपये (दस हजार रुपये केवल) का भुगतान किया जाना चाहिए तथा दूसरे वर्ष 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये केवल) तक का भुगतान किया जाना चाहिए।

(v) सब विविध लेनदारो, जिनके 25,000 रुपये से अधिक के दावे हैं, मे से प्रत्येक को योजना के कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष से तीन बराबर वार्षिक किस्तो मे भुगतान किया जाना चाहिये।

कम्पनी इस बात का सुनिश्चय करेगी कि उपर्युक्त धनराशियो की अदायगी इसे नियंत्रण मे लेने के बाद हुए लाभ मे से की जाये तथा इस योजना को कार्यान्वित करने से कम्पनी के नकदी के प्रवाह (कैश फ्लो) की स्थिति तथा उसके अपने लिए अपेक्षित कार्यचालन पूजी पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। यह योजना इसी समय से लागू होगी।

Reserved Quota for SC/ST in Income Tax, Central Excise, Customs and Nationalised Banks

6063 SHRI SOMJIBHAI DAMOR Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the extent to which the reservation quota laid down for SC/ST

separately in Income Tax, Central Excise, Customs and Nationalised Banks is filled up and what is the shortfall against its existing strength for each class of service;

(b) if there is heavy shortfall, what action Government contemplates to take and by what dates this shortfall is likely to be completed; and

(c) whether he is considering about the crash programme for filling up these vacancies similar to that adopted by Minister of Railways?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2049/78].

Operational Efficiency of Nationalised Banks

6064. SHRI G. M. BANATWALLA:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI SUKHENDRA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the operational efficiency of the nationalised banks has been constantly deteriorating; and

(b) if so, what action Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Although the nationalised banks have undertaken rapid branch expansion and faced the problem of rising costs over the past few years, there is no reason to believe that their operational efficiency has been constantly deteriorating. The functioning of the public sector banks is kept under continual review by the Government, the Reserve Bank of India through its various departments and the Boards of Directors of these Banks.

Excise yield from Aerated Waters

6065. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the sale of aerated water during the year 1971, 1972 and 1973 and the excise yield from the sale;

(b) whether it is a fact that the sale of aerated water has steeply fallen because of heavy dose of excise, and

(c) if so, what Government propose to do in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) Information regarding sale of aerated water for the period mentioned in the question is given below:

Year	Sale in thousands of (bottles)	Excise yield Rs in thousands
1971 . . .	945854	30730
1972 . .	1157956	61025
1973 .	1124027	54590

(b) and (c) No Sir, the year-wise figure of clearances given against part (a) of the question does not indicate any steep fall in sale of aerated water

इण्डियन एयर लाइन्स वर्कमैन एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन

6066. श्री हर गोविन्द वर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को इंडियन एयरलाइंस वर्कमैन एसोसिएशन से एक ज्ञापन मिला है जिसका शीर्षक है "ओपन लैटर एड्रैस्ड टू द चेयरमैन, इंडियन

एयरलाइन्स" (इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन का सम्बोधित खुला पत्र),

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) यदि कोई जांच की जा रही है तो क्या सम्बन्धित अधिकारियो को स्थानान्तरित नही किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिकायत की जांच-पड़ताल की जा रही है।

Gold Bonds

6067 SHRI R VENKATARAMAN Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the amount of Gold subscribed for the Gold Bonds issued by the Government of India,

(b) whether the amount subscribed is retained by the Government of India in specie, and

(c) the earliest and last date of repayment of the Gold Bonds

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) Subscriptions to Gold Bonds which were issued thrice by Government (viz 6½ per cent Gold Bonds, 1977 in November, 1962, 7 per cent Gold Bonds, 1980 in March, 1965, and National Defence Gold Bonds, 1980 in October, 1965) amounted to 35162 kgs approximately

(b) The subscriptions received were refined into gold of 995 fineness which forms part of Government's stock.

(c) The bulk of the 6½ per cent Gold Bonds, 1977, which matured on 12th November, 1977, stands repaid while the National Defence Gold Bonds 1980, the last in the series, will mature on the 27th October, 1980

Civil Aircraft Services from Dum Dum to Cooch Behar

6068 SHRI AMAR ROYPRADHAN Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether Government have any intention to operate civil aircraft services from Dum Dum to Cooch Behar,

(b) whether it is also a fact that citizens of Cooch Behar and nearby areas and foreign tourists have constantly been demanding for a civil airport at Cooch Behar, and

(c) if so, what are the details in this regard and the action taken so far by the Government?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) (a) No Sir, not at present

(b) and (c) A representation was received in July, 1977 demanding re opening of the aerodrome at Cooch Behar to enable Indian and foreign tourists to visit North Bengal, specially Jaldapara protected forest area A reply was sent stating that neither Indian Airlines nor any non-scheduled operator have evinced any interest in operating to Cooch Behar, and it is, therefore not possible at present to reopen this aerodrome

विदेशी मुद्रा

6069. श्री गंगाभक्त सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक अर्जित विदेशी मुद्रा कहा और किस रूप मे रखी गई है और 1977-78 मे सरकार ने उस से कितना राजस्व कमाया और 1978-79 मे कितना राजस्व कमाये जाने का अनुमान है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : रिजर्व बैंक के पास जो विदेशी मुद्रा होती है, वह विभिन्न प्रमुख करेंसियो मे नकद, सरकारी

राजकोषीय हुंडियों, सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों/शेयरों और प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों में जमा के रूप में रखी जाती है। 30 जून, 1977 को समाप्त रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार से 190.94 करोड़ रुपए की और 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त छमाही में 141.04 करोड़ रुपए की आय हुई थी। यह बताना संभव नहीं है कि वर्ष 1978-79 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार से कितनी आमदनी होगी क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार की राशि और विदेशी में ब्याज की दरों में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है जिनके संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

Nationalisation of Export Trade of Coir and Coir Products

6070. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the Kerala Assembly has adopted a resolution unanimously urging the Centre to nationalise immediately the export trade of coir and coir products; and

(b) if so, the details and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir. The Government of Kerala has informed this Ministry on 23-3-78 that a resolution to this effect has been adopted.

(b) The Kerala Legislative Assembly has resolved that "the Government of India nationalise immediately the export trade in coir and coir products". In view of the resolution, the matter will be considered by the Government.

बढ़े हुये करों से मूल्य में हुई वृद्धि के कारण तैयार माल में मूल्यों में वृद्धि

6071. श्री रामानन्द तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क में हुई 2 से 5 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़े हुए करों से मूल्य में जो वृद्धि होगी, उससे तैयार माल के मूल्यों में भी वृद्धि होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या 5-6 प्रतिशत मूल्य वृद्धि की आशंका है जबकि कर प्रस्तावों में 0.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) क्या उनका मंत्रालय इस बात के लिए सजग है कि मूल्यों में इस अनुमान से अधिक वृद्धि न हो जिससे उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार पड़े ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1978-79 के बजट में कोयले पर और बिजली-निर्माण पर नये उत्पादन शुल्क लगाए गए हैं। जिन वस्तुओं पर पहले से ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ लागू है उनके मामले में विद्यमान शुल्कों में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है अर्थात् वृद्धि विद्यमान शुल्क के बीसवें हिस्से के बराबर है। "जो वस्तुएं अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं" और जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944, की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आती हैं, उन पर 1975-76 के बजट में पहली बार, एक प्रतिशत का शुल्क लगाया गया था। 1977-78 में इसे बढ़ा कर 2 प्रतिशत कर दिया गया था और अब इसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है। इन वस्तुओं (मद संख्या 68) से उत्पादन शुल्क की बहुत ही कम प्राप्तियां होती हैं और शुल्क वृद्धि का प्रभाव भी बहुत ही कम रहेगा।

(ख) मूल्य स्तर में, बजट प्रस्तावों के कारण, 0.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि

का अनुमान थोक कीमतों के सूचक अंक में सम्मिलित वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव का स्थूल अनुमान है।

इस अनुमान से, उस अप्रत्यक्ष प्रभाव को हिसाब में शामिल नहीं किया गया है, जो कि उपयोगी वस्तुओं के विद्यमान शुल्कों, जिनमें कोयले और बिजली पर लगने वाले नए शुल्क भी शामिल हैं, में हुई वृद्धि के कारण पड़ेगा। इस के कुल मिलाकर प्रभाव का ठीक ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि बाजार की प्रतिक्रिया बहुत सी बातों पर निर्भर करती है। बजट के बाद पहले सप्ताह में थोक कीमतों के सूचक अंक में 0 6 प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसका एक कारण यह था कि चीनी के मूल्यों में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि ऐसे कारणों से हुई जिनका बजट से प्रत्यक्ष रूप में कोई भी संबंध नहीं है। बजट के बाद, तीसरे सप्ताह तक कुल मिलाकर जो वृद्धि हुई वह 1 2 प्रतिशत है।

(ग) सरकार मूल्य स्थिति पर बराबर नजर रखती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है, मूल्यों में होने वाली अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

Improvement of Haldi Ghati for Tourist Facilities

6072 SHRI S S SOMANI Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether any plan has been sent by the State Government of Rajasthan to the Central Government for the improvement of Haldi Ghati for the tourist facilities, and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Central Government thereon?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURSHOTTAM KAUSHIK) (a) No, Sir, However, the Central Department of Tourism released an amount of Rs 1 lakh in 1976-77 to the State Government for effecting environmental improvement at Haldighati

(b) Does not arise

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने वाली विदेशी कम्पनियां

6073. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) ऐसी विदेशी कम्पनियों एवं उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और भारत में अपने व्यापार का समापन करने का निर्णय किया है,

(ख) उनके द्वारा अपने व्यापार का समापन कब तक किये जाने की संभावना है, और

(ग) भारत सरकार के इस बात का सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि इन कम्पनियों का यदि राष्ट्रीय बैंकों को कोई राशि देनी हो तो वे चुपचाप अपनी परिसम्पत्तियों का निपटान न कर दें?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अब तक तेरह कंपनियों ने देश में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 27 के अनुपालन के लिए निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार अनुमित साध्य पूंजी स्तर के अन्तर्गत कार्य करने में अक्षमता प्रकट की है। इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इनमें से कुछ एक कम्पनियों ने तो अपने व्यापारिक/वाणिज्यिक/औद्योगिक क्रियाकलाप बंद कर दिए हैं और दूसरी कम्पनियां 1978 के दौरान ऐसा करेंगी। तथापि उनके व्यापार के वास्तविक समापन, जैसे कि परिसंपत्तियों आदि के निपटारे में, कुछ समय लगेगा।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों अनुसार, कोई भी विदेशी कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी परिसंपत्तियों का निपटारा नहीं कर सकती। इसके अलावा मूल्याकन और बिक्री की प्राप्तियों को अपने देश को वापस भेजने के आवेदनों का विपदाते समय, सभी बकाया देनदारियां जैसे कि बैंकों आदि का देय रकमों का समायोजन किया जाता है।

विवरण

1 ए० जौलसन एण्ड कंपनी (इंडिया) ए० वि० कलकत्ता (शाखा)

2 बैंकर पार्किसन्स इंटरनेशनल लि० बम्बई (शाखा)

3 बुगे एण्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता (शाखा)

4 कोका कोला निर्यात निगम नई दिल्ली (शाखा)

5 कोलंबिया ग्रामाफान कंपनी आफ इंडिया (प्राइवेट) लि० कलकत्ता (रुपया कंपनी)

6 कंसोलिडेटेड न्यूमेटिक टूल कंपनी लि०, बम्बई (शाखा)

7 इली लिली एण्ड कम्पनी आफ इंडिया इनकारोपरेटिड बम्बई (शाखा)

8 ईग्रा, नई दिल्ली (शाखा)

9 आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन नई दिल्ली (शाखा)

10 केंडाल फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता (रुपया कंपनी)

11 दोराब एण्ड सन्स लि०, मद्रास (शाखा)

12 बान राम इंडिया वी०वी० कलकत्ता (शाखा)

13. बैंडेक्स (इंडिया) लि०, कलकत्ता (रुपया कंपनी)

Amount Shown under the Heading "Entertainment" by Kores India

6074 SHRI RAMESHWAR PATIDAR Will the Minister of FINANCE be pleased to state·

(a) whether it is a fact that M/s Kores India are showing a large amount on "entertainment"

(b) the total amount shown under this head during the last three years, year-wise

(c) the percentage ratio of expenditure on 'entertainment' to the net income and

(d) whether they are resorting to this tactics to save taxes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) (a) to (d) The information is being collected and will be furnished as soon as it is available

Expenditure on Guest Houses by Kores India

6075 SHRI RAMESHWAR PATIDAR Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the number of guest houses being maintained by M/s Kores India,

(b) the amount being spent on rent furnishing, maintenance and other things on these guest houses

(c) whether the expenditure of residences of executives are also included as expenditure on guest houses and

(d) whether rebate is granted while reckoning the taxable amount of company?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) (a) to (d) The information is being collected and will be furnished as soon as it is available

आम टैक्सटाइल मिल, बम्बई के मालिकों द्वारा आयकर की अदायगी

6076. श्री हुकम चन्द कछवाय क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आम टैक्सटाइल मिल, बम्बई के मालिको ने गत तीन वर्षों मे कितना आय-कर अदा किया और वर्तमान मालिको तथा साझीदारो के नाम क्या हैं, और

(ख) क्या इन प्रत्येक साझीदारों की किसी अन्य उद्योग व्यापार मे भी साझीदारी है और यदि हा, तो उक्त प्रतिष्ठानो के नाम क्या हैं तथा इस मिल से सम्बन्धित साझीदारो की अन्य प्रतिष्ठानों के साथ साझीदारी का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): (क) और (ख). आम टैक्सटाइल मिल की मालिक मेसर्स आम मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, बम्बई है। उस हैसियत मे, इसमे कोई भागीदार नही है। उक्त कम्पनी द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, अदा किए गए आयकर के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है —

	रुपये
1974—75	2 704
1975—76	23,125
1976—77 .	2,903

Investment made by L.I.C in Private Sector

6077. SHRI JYOTIRMOY BOSU: will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Starred Question No 264 dated 10th March, 1978 regarding "Investment policy of Life Insurance Corporation of India" and state:

(a) total investment made by L.I.C. in the Private sector to-date;

(b) share of each 20 largest industrial Houses in this total;

(c) total L.I.C. investment in the public sector undertakings and cottage and small scale industries to date, separately;

(d) whether the Government is considering to change the pattern of L.I.C Investment; and

(e) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL): (a) As on 31st March, 1977, the total book values of LIC's investments in all the Public Limited Companies comprising the 'Private Corporate Sector' was Rs 324 49 crores

(b) Total investments made by LIC as on 31st March, 1977 in 'Large Groups' amounted to Rs. 184 95 crores. Break-up of this figure in different 'Large Groups' is given in Annexure 'A' [*Placed in Library See* No. LT-2050/78)

(c) As on 31st March, 1977 the total book value of LIC's investments in all Public Limited Companies in the Public Sector (Viz, Government Companies) was Rs 37.14 crores.

The LIC does not normally give direct assistance to cottage and small scale industries for the reasons that these industries are mostly run as proprietary concerns or partnership or as private limited companies and LIC is not permitted by law to make investments in such concerns. However, assistance is provided by the LIC to these sectors by subscribing to the Bonds and shares of the State Financial Corporations which in turn give loans to cottage and small scale industries and by grant of loans to industrial estates. As on 31st March, 1977, LIC's investments in Bonds and shares of State Financial Corporations and also in the outstanding loans to Industrial Estates was Rs. 62.53 crores.

(d) and (e). The matter is under consideration.

Opening of Branches of Bank of America in India

6078. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) when the Bank of America opened its first branch in India;

(b) how many branches have been allowed to be opened by this multinational bank to-date;

(c) total profits earned and total amount remitted (including remittances on accounts of head office expenses) by the bank to-date, yearwise, since inception; and

(d) salary, emoluments and perks per year allowed to the 10 top managerial staff of the bank?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The Bank of America opened its first branch in India, in Bombay on 20th May 1964.

(b) As on date, the Bank has been allowed to open four branches in India.

(c) Information to the extent available in the Reserve Bank is given in the enclosed statement.

(d) The form of Profit and Loss Account prescribed in the III Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 requires the banks to indicate by way of a note to the Profit and Loss Account the particulars of remuneration relating to the Chief Executive Officer only. The bank is not required to disclose such particulars in respect of its other officers. Reserve Bank have reported that particulars of remuneration paid to the Chief Executive Officer of Bank of America as indicated in its Profit and Loss Account for the year 1976 are as under:

	Rupees
Salary	2,05,805·00
Allowances	42,024·00
Monetary value of other benefits or perquisites (calculated according to the income tax Rules)	37,918·00
Total	2,85,747·00

Statement

Year	Amount of actual net profit as per balance sheet and profit and loss account.	Total amount remitted (including head office expenses)
	Rs.	Rs.
1964	(Loss 7,91,903)	55,189
1965	12,11,246	5,04,015
1966	9,08,346	14,44,756
1967	12,81,069	17,97,154
1968	12,59,590	22,61,646
1969	38,01,937	51,32,955
1970	32,71,066	45,86,984
1971	39,08,081	58,28,609
1972	37,02,295	58,46,701
1973	35,24,697	41,26,259
1974	55,33,958	65,19,920
1975	59,12,828	70,20,913
1976	83,53,327	Nil so far

Loans given by Nationalised Banks for Fisheries and Piggeries in Mawana Tehsil of Meerut District

6079 SHRI DAYARAM SHAKYA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the name of the nationalised bank which gave a loan of rupees 7 lakhs for fisheries and piggeries in Mawana Tehsil of Meerut district in U P in 1974-75 and whether the same has been paid back to Government,

(b) whether the bank officials advanced the loan without adhering to the banking norms and whether the persons who were given loan have been declared insolvent and

(c) if so the action taken by Government to realise the same?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) to (c) The Reserve Bank of India have informed that they are not aware of any case of a nationalised bank advancing a loan of such a nature in Mawana Tehsil of Meerut

In the absence of the name of the bank no further information could be gathered

Loss as a result of Strike by Development Officers of L I C

6080 SHRI PRASANNBHAI MEHTA Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that due to the month long strike launched by development officers the Life Insurance Corporation has resulted in a loss of 300 crores, and

(b) if so how far this is true?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) and (b) The information is being collected It will be laid on the Table of the House as soon as it is received

Export of Iron and Manganese Ore

6081 SHRI AMRUT KASAR Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether Government are aware of the recession in the export of iron and manganese ore from Goa to Japan and as a consequence fall in the foreign exchange earnings of the country,

(b) whether Government have taken steps to find out new avenues for export of iron and manganese ore from Goa (India), and

(c) if not, do Government have any plan to utilise the indigenous iron and manganese ore in India so that the mines are not closed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) to (c) Exports of iron ore and manganese ore of Goan origin to Japan have been adversely affected due to severe recession in the steel industry India, as a matter of policy, is making continuous efforts towards diversifying its iron ore and manganese ore markets As regards manganese ore, in view of inadequate reserves and the growing demand for indigenous consumption, exports have been restricted by the Government.

Offices of A.H Wheeler and Company

6082 SHRI R L KUREEL Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether M/s A. H Wheeler are deceiving railways and income-tax department, by showing expenditure under heads 'maintenance' and 'entertainment',

(b) the justification for having offices in Delhi, Calcutta, Bombay and London by the above firm and

(c) whether the proprietors of the said firm appoint in the firms their relations and members of their families to high positions on very fat salaries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) and (b). Railways get royalty from A. H. Wheeler and Company Private Limited on its total sales turnover of books, magazines, etc. at station premises and are not concerned with the company's expenditure.

The income-tax assessments of the company are made after due scrutiny, disallowing claims of expenses to the extent require under the Income-tax Act. The assessments for the assessment years 1973-74 to 1975-76, have been completed after making disallowances out of claims for 'entertainment' and 'establishment' expenses, etc.

(c) Requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House

Loan cases pending with State Finance Corporation under Scheme for providing employment

6083 SHRI CHHABIRAM ARGAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of loan cases pending with State Finance Corporations (State-wise) under the scheme for providing employment to educated unemployed persons indicating the date since when pending; and

(b) whether Government would make arrangements for the immediate disposal of the loan cases of educated unemployed persons within the prescribed period by giving them all kinds of facilities under the scheme of the present Government to remove unemployment within 10 years?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The State Financial Corporations functions under the administrative control of the concerned State Governments. Central Government is not, therefore, primarily concerned with these corporations.

Bonn Profits at India's Cost

6084. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a report published in the Economic Times; New Delhi in its issue, February, 1978 under the caption "Bonn Profits at India's cost"; and

(b) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.

(b) Gujarat Steel Tubes, Ahmedabad had received an offer from M/s. Fried Krupp of West Germany for the supply of 21,000 tonnes of various sizes of steel tubes to China The price settled during the negotiations between the two firms was approximately Rs 5 crores, f.o.b.

No Indian firm had earlier sold steel tubes to China and the Steel Tubes Panel of the Engineering Export Promotion Council had not listed China as one of the destinations for which floor prices had been stipulated by them There was, however, a general entry, for unspecified destinations, after listing various destinations giving a floor price for each destination or group of destinations. The floor prices fixed by the Panel were on C&F basis.

Gujarat Steel Tubes had approached the Government in November 1977, before signing the contract for relaxing the floor price stipulation made for unspecified destinations. The argument advanced was that there

was no specific floor price for China and that, after taking into account the freight rate, the price being quoted to the West German firm was quite fair if the floor prices for certain neighbouring destinations like Hong Kong were taken into account.

Since this was a large value contract, and for the first time, a breakthrough was being made into the Chinese market, the Engineering Export Promotion Council was advised to accept the price being offered by the Gujarat Steel Tubes. The matter was placed before the Steel Tubes Panel of EEPC and the Panel also allowed the firm to conclude the contract at the prices negotiated taking into account the views that had been expressed by Government

Since the goods are being shipped direct to Chinese ports from Bombay, although payment is being effected by the West German firm, the transaction is not a re-export. The price being offered by the Chinese buyer to the West German firm is not known to the Government. There has not been any loss to the country on account of the contract, as reasonably fair prices have been secured

International Fund for Agricultural Development

6085. DR VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the United Nations has sponsored a new Agency *viz.*, International Fund for Agricultural Development (IFAD) which is to provide aid for agricultural development in underdeveloped countries;

(b) if so, has any proposal been presented to the IFAD of agriculturally backward areas of India; and

(c) what efforts are being made to tap this new source for agricultural development in the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The idea of establishing a separate international fund to finance agricultural projects primarily for expansion of food production in developing countries was first mooted by the World Food Conference and this recommendation was endorsed by the U.N. General Assembly. The Agreement establishing IFAD entered into force on November 30, 1977.

(b) and (c). Various proposals are being processed and will be presented to the Fund in due course.

Delegations sent abroad

6086. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many delegations have been sent abroad since the formation of Janata Government indicating the dates and the names of the countries to which they were sent;

(b) the criteria adopted in selection of each member of the delegations; and

(c) the total expenditure incurred on them?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (c). Similar information relating to the periods indicated below was called for in Unstarred Questions Nos. 3615, 661 and 5038 answered in the Lok Sabha on 15th July, 1977, 24th February, 1978 and 31st March, 1978 respectively:—

Unstarred Question No.	Period for which information called for
3615	1974-75, 1975-76 and 1976-77.
661	For three years ending on 31st December, 1977.
5038	1975-76, 1976-and from 1-4-77 to 31-3-78.

The above information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible. Accordingly, information called for in the present Question for the period from 25th March, 1977 to 31st March, 1978 will be available in the information to be furnished in reply to Unstarred Questions Nos. 3615, 661 and 5038 mentioned above.

(b) A rigorous procedure has been laid down for clearance of proposal received from different Ministries. These proposals are scrutinised by a Committee of senior Secretaries in the case of Government officials and non-officials, and at the level of Finance Minister/Prime Minister i nthe case of Ministers. Strictest norms are applied in deciding the necessity of inclusion of each person in the deputations|delegations abroad.

Loan from Financing Agencies by .. Sugar Mills

6087. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) how many Sugar Mills have taken loans from Financing Agencies such as IFC and Insurance Companies etc., and what is the mill-wise amount involved; and

(b) whether the mills are in a position to repay the amounts involved, specially in consideration of the alleged losses being incurred by them, if not, how would Government assist the mills to ensure repayment of loans?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The amount of loans given by the all-India long term public sector financial institutions, namely, the Industrial Finance Corporation of India (IFC), the Industrial Development Bank of India, the Life Insurance Corporation of India, the General Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India to sugar mills (mill-wise) is given in the attached Statements I, II, III, IV and V respectively. [*Placed in Library. See* No. LT-2051/78].

(b) The IFC, which is the lead institution for assistance to sugar industry, has reported that the credit record of the sugar industry has been by and large satisfactory. Government has also not received any report from any institution of widespread default by this industry in repayment of dues.

Employees in L.I.C. in Jammu and Kashmir State

6088. SHRI MOHD. SHAFI QURESHRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) total number of employees in L.I.C. in Jammu and Kashmir State;

(b) number of employees belonging to minority (Muslim) Community and their official status in the State, and

(c) break-up of employees in Gazetted and non-gazetted category in the State?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) 146.

(b) and (c). There are 8 Muslim employees. Out of 8, 6 are Class II Officers (Development Officers), 1 is (Class III Clerical and 1 Class IV (Subordinate Staff) employee.

There are no appointments such as gazetted and non-gazetted in the Life Insurance Corporation of India. The Class-wise break up of the employees is as under:—

Class I	Class II	Class III	Class IV	Total
12	46	76	12	146

Forged Withdrawal of Cheque from S. B. Account No. 2497 of S. B. I. Chandni Chowk, Delhi

6089. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the reasons for not reporting the case of payment made by the State Bank of India, Chandni Chowk, Delhi on the basis of a cheque from SB account No. 2497 in 1974, bearing forged signatures to the Delhi Police when it was made clear by the constituent that the signatures on the cheque were not his signatures;

(b) whether the Delhi Police on a report (FIR) lodged by the constituent declared that the signatures on the impugned cheque were forged and the Bank did not take appropriate action after it;

(c) whether the Chairman of the State Bank received a letter dated 28th June, 1976 from the constituent containing the financial irregularities, misdeeds of the officers but did not initiate any action in the matter, if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that the Director, Central Forensic Science Laboratory, R. K. Puram, New Delhi has also declared that the signatures on the cheque do not tally with the signatures of the constituent; and

(e) in view of the reports of Delhi Police and the Director of Central Forensic Laboratory, New Delhi, whether Government propose to hand over the whole case to Delhi Police and the CBI for further investigations as the Bank Officers have been trying to hush up the matter and shield the culprits?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) State Bank of India has reported that as the signatures appearing on the cheque for Rs. 622/- paid by the Bank were considered to be genuine by the Bank's handwriting expert, the matter was not reported by the Bank to the Police.

(b) On receipt of the report from the police that the signatures appearing on the cheque were not that of the constituent, the Bank considered it necessary to have a third expert opinion and had therefore referred the matter to the Central Forensic Science Laboratory, New Delhi. On receipt of the report of the Central Forensic Science Laboratory that the signatures appearing on the cheque were not similar to the standard signature of the constituent, the Bank immediately refunded the principal along with uptodate interest to the constituent.

(c) The Chairman, State Bank of India had received a letter dated the 28th June, 1976 and necessary action was initiated by the Bank with a view to establishing whether the drawing was genuine or not.

(d) Yes, Sir.

(e) State Bank of India has reported that the Bank is not trying to hush-up the matter and shield the culprits. The Bank is already looking into the accountability of the staff involved and will take appropriate action against the officials concerned.

Confirmation of Balance in Saving's Bank Account in S.B.I.

6090. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the State Bank of India Savings Bank Rule number under which the balance in Savings Bank account is got confirmed from the constituent;

(b) whether a constituent of Savings Bank Account No. 2497 of Chandni Chowk (Delhi) Branch was asked to confirm the balance in Savings Bank account *vide* letter No. PBD/1894 dated 8th October, 1975 after a case of fraud, cheating and criminal breach of trust as reported in case FIR No 725 dated the 25th June, 1975—PS Kotwali, Delhi—was lodged by him with the Delhi Police;

(c) whether this action of the Manager, Personnel Division State Bank of India, Delhi was to justify and regularize the fraudulent withdrawal allowed by the Bank through an instrument never issued by the Bank as per the entry made and certified by the Officer in the Savings Bank Pass Book; and

(d) whether Bank Officers being in the know of the conspiracy took up the above steps to cover up the lapses and did not report the matter to the Delhi Police and the CBI in 1974 or 1975 for investigations and now what action is proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) State Bank of India Savings Bank Rules do not contain any provision for the issue of letters to the constituents asking them to confirm the balances The bank has also reported that the balance confirmations in respect of Savings Bank Account are not generally obtained from the constituents The constituents are themselves required to have their respective Pass Books regularly completed and bring to the notice of the bank any discrepancy they notice.

(b) In its letter No. PBD/1894 dated the 8th October, 1975, the Chandni Chowk branch of the State Bank of India had merely indicated the balances in the account.

(c) and (d). State Bank of India has reported that there has been no conspiracy on the part of the bank's staff. The bank has stated that on receipt of the report of the Central Forensic Science Laboratory, New Delhi stating that the signatures appearing on the cheque were not similar to the standard signatures of the constituent the bank had immediately refunded the pricipal along with the up-to-date interest to the constituent. The bank has further reported that it is already looking into the accountability of the staff involved and will take appropriate action against the officials concerned.

Financial Irregularity in Delhi Branch of United Commercial Bank

6091. SHRI BIJOY KUMAR MONDAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government is aware that in Delhi premises for one branch of United Commercial Bank have been taken on rent of Rs. 5000/- per month, that the owner of this premises was granted an advance of Rs. 2 lakh without security to build the premises;

(b) if so, has any enquiry been made on the irregularity;

(c) is it also a fact that the United Commercial Bank is paying rent of Rs. 10,000 per month and 6 thousand per month for the premises of two United Commercial Bank branches at Delhi for the last two years without even obtaining licences from the Reserve Bank to open the branch; and

(d) if so, do Government propose to institute an enquiry in this case?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL): (a) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the hiring of the premises for the bank's branch at Mayapuri in New Delhi. This is a three-storeyed building and the bank had taken a total area of 2088 square feet at a rent of Rs. 4700/- per month. The Landlord was sanctioned a loan of Rs 2 lakhs on interest of 13½ per cent per annum and is also reported to have put in considerable funds of his own for its construction in addition to incurring expenditure on purchase of the plot. The advance is secured by equitable mortgage of the land and building. The rent payable by the bank of Rs. 2.25 per square feet is reported to be in accordance with the prevailing rents in the area.

(c) The two premises referred to by the Hon'ble Member were obtained by the Bank on long lease as alter-

native sites for its branches at Pusa Road and Patel Nagar in the wake of the prosecutions launched by the D.D.A against the managers of the above branches for functioning in non-conforming areas Reserve Bank have already issued licence to the bank for its site at South Patel Nagar and its request for a licence at the second site is being processed

(b) and (d) Reserve Bank have reported that there is no contravention of any of its regulations by the Bank in regard to hiring of the aforesaid premises As such the question of instituting any enquiry in this regard does not arise

Financial Irregularities by United Commercial Bank for last two years

6092 SHRI BIJOY KUMAR MONDAL
SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI

Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) what are the amounts expended by the United Commercial Bank during the last two years for which balance sheets have been published on furniture, stationery and public relations;

(b) is it a fact that expenditure on the said items is abnormally high, and

(c) if so, do Government propose to make investigations whether the amounts were spent judiciously and that there are no irregularities?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) As per the balance sheets of the United Commercial Bank the amount spent by it on furniture and fixtures, stationery, printing and advertisement and public relations and publicity during the years 1975-76 is as follows

(Rs in lakhs)

		1975	1976
1	Furniture & Fixtures	108 35	146·12
2	Stationery, Printing and advertisement etc	99 92	106 74
3	Of (2) above Public Relations and Publicity	19 09	27·68

(b) Reserve Bank of India have reported that the expenditure incurred by the Bank compares favourably with the expenditure incurred on these items by other banks of comparable size

(c) Does not arise

Role of Banks and Cooperative Societies to Check Private Money Lending in Tribal Areas of Orissa

6093 SHRI GIRIDHAR GOMANGO Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the role played by the banks, Cooperative societies and the financial institutions to check the private money lending in tribal areas of Orissa,

(b) whether this system is still operating in those areas and

(c) the steps taken by the Government of Orissa to check this economic exploitation of tribals so far?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c) The State Government of Orissa like other States, has passed legislation for liquidation of rural indebtedness with a view to provide relief from debt to small and marginal

farmers, landless agricultural labourers, rural artisans and share croppers. This legislation is in itself helpful in curbing private money lending. In addition to this, the State Government of Orissa has organised 220 large sized agricultural multi-purpose cooperative societies (LAMPS) in the tribal areas of Balasore, Boudh, Berhampore, Bhawanipatna, Keonjhar Koraput, Mayurbhanj, Sambalpur and Sundargarh districts to provide all types of credit to the tribals in addition to other services. The Reserve Bank of India and the commercial banks are also extending financial assistance to them by providing finance to the LAMPS.

Additional Increment to Officials in Public Undertakings in Delhi

6094. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in a number of public undertakings in Delhi, the officials are given an additional increment after every five/ten years or after fixed interval of service;

(b) if so, the names of such undertakings and the details of the schemes in each of them; and

(c) whether Government propose to extend this incentive to other Government departments also and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). From the information available 23 Central Government enterprises in Delhi have reported that they have not given any additional increment after every five/ten years or after fixed intervals of service. Six enterprises have reported schemes of giving additional increments as follows—

(i) *National Seeds Corporation Ltd*:

Two advance increments are granted to the Class IV employees after completion of five years service in the grade having clean record. Similarly, one advance increment to Class III employees whose maximum of scale does not exceed Rs. 900 is granted on completion of five years service in the grade having clean record. The above premature increments are granted only once in the entire service. This incentive is not being granted to Class II officers and above.

(ii) *State Trading Corporation*:

(iii) *Projects and Equipment Corporation of India*:

(iv) *Handicrafts and Handloms Export Corporation of India*:

(v) *Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd*:

In the case of public sector undertakings at serial numbers (ii) to (v), employees in unionised cadres are allowed one additional increment if they remain in a grade without promotion for eight years and another increment if they complete 15 years in that grade without promotion.

(vi) *Bongaigaon Refinery and Petro Chemicals Ltd*:

Although no additional increments are granted on a time-bound basis to officers and staff additional increments varying between one and two have been granted only to 10 employees in the staff category on merit basis during the year 1977 in recognition of their services.

(c) There is no such proposal under consideration since the position obtaining in respect of Government employees in regard to the terms and conditions of service, as a whole, differs from those applicable to the employees of public enterprises.

Payment of Compensatory Allowance at Goa

6095 SHRI AMRUT KASAR Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Third Pay Commission has recommended payment of compensatory allowance to places of pilgrimage etc,

(b) whether this recommendation has been accepted by the Government, and

(c) If so, whether the case of Goa is proposed to be considered for the payment of compensatory allowances as Goa is always flooded with the tourists and as a consequence the prices are high and the cost of living has gone extremely high?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) to (c) In para 14 Chapter 56 Volume IV of their Report, the Third Pay Commission had recommended as follows —

"There would be certain towns which for reasons of comparative isolation or by virtue of being places of pilgrimage with a large floating population or State capitals etc may in fact be abnormally expensive while they may not qualify for th egrant of a CCA according to the population criterion Such cases should obviously call for special treatment in relaxation of the norms and the Government should consider each such case on merits for the grant of CCA'

The Government accepted this recommendation in principle and steps are being taken to implement it as early as possible Goa is one of the places whose case is being considered on this basis.

Proposal to give Smuggled Goods as Incentive

6096 SHRI DURGA CHAND Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Government are having a proposal to give smuggled goods as incentives for the implementation of various Government schemes, and

(b) if so, the details thereof,

(c) what is the criteria to be followed for giving these goods as incentives, and

(d) what is the value of smuggled goods at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) No such proposal is under the consideration of the Government

(b) and (c) Do not arise

(d) In December, 1977, the total value of smuggled goods seized and confiscated by the Customs authorities was about Rs 46 crores

रक्षा प्रतिष्ठानों को अंग्रेजी शराब की सप्लाई करने वाले उत्तर प्रदेश के शराब निर्माताओं द्वारा आयकर का भुगतान

6097 श्री दयाराम शाक्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रक्षा प्रतिष्ठानों को अंग्रेजी शराब की सप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के किन शराब निर्माताओं को लाइसेंस दिए गए हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान, वर्षवार, उन्होंने कितना आयकर अदा किया है, और

(ख) किन शराब निर्माताओं पर आयकर की राशि बकाया है तथा वह राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुलफिकारउल्लाह) : (क) और (ख). रक्षा प्रतिष्ठानों को भारत में बनी विदेशी शराब की सप्लाई करने वाले शराब निर्माताओं के संबंध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

Development of Tourism in Gwalior and Gwalior Region

6098. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) the progress in implementation of long pending proposals, under consideration of the Government for development of tourism in Gwalior and Gwalior Region;

(b) whether the Government will also consider the demand of halting Boeing flight Delhi-Agra Khajuraho-Varanasi-Delhi, at Gwalior, under the new plans for tourism development;

(c) if so, the details of the plan; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) As the proposals received from various parties relating to the introduction of conducted coach tours from Gwalior to Khajuraho via Shivpuri and Jhansi and the renovation of the Gwalior Fort do not come under the purview of the Central Department of Tourism, they have been forwarded to the State Directorate of Tourism and the Archaeological Survey of India respectively for necessary action.

(b) Due to the tight flight schedule of available aircraft, Indian Airlines do not find it possible to route Delhi-Khajuraho flight via Gwalior.

(c) and (d). Do not arise.

Forged Receipts pledged by M/s. Navneet Trading Company with the Bank of Maharashtra

6099. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bank of Maharashtra (Connaught Place Branch) had given a loan of Rs. 5,00,000/- to M|s. Navneet Trading Company;

(b) whether the company had pledged forged receipts with the Bank;

(c) whether a case has been lodged with the Delhi Police, by the Bank; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (d). In accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and in accordance with the usages and practices customary among bankers, details of individual clients is not to be divulged. Bank of Maharashtra has, however, reported that as there were some irregularities in the conduct of the account relating to M/s. Navneet Trading Company, it has already recalled the advances and has recovered a major portion of the amount due to the bank. While the Bank of Maharashtra, itself, has not filed any criminal complaint against the Company according to information available with it, a police complaint has been lodged against the company by a Transport Company alleging that the Motor Transport receipts relating to certain Bills purchased by the bank were from books stolen by the representatives of M|s. Navneet Trading Company.

Grant of Loans by Chairman, United Commercial Bank

6100. SHRI BIJOY KUMAR MONDAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) is the Minister aware that Chairman of United Commercial Bank has allowed some loans to be granted on political consideration without adhering to Banking norms;

(b) has any loan been sanctioned to finance the film 'Chorus' and some other films;

(c) if so, the name of such films to whom the loan was sanctioned by the Bank; and

(d) the details thereof and the amount of loan recovered by the bank from the film producer of the film "Chorus"?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). It is presumed that the reference is to financing of film production/distribution by the United Commercial Bank According to the United Commercial Bank, it has granted credit facilities to certain parties in the normal course for production and distribution of feature films in Bengali as also for production of documentary films, including the film "Chorus".

(c) and (d). In accordance with the practices and usages customary among bankers and also in conformity with the provisions of the statutes governing the public sector banks, information relating to individual constituents of the bank cannot be divulged.

छापों के दौरान जब्त किया गया माल

6101. श्री राघव जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1978 को सरकार द्वारा मारे गये छापों के दौरान कितनी कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का स्वर्ण, आभूषण करेंसी नोट, हीरे और अन्य वस्तुएं जब्त की गई ;

(ख) उन वस्तुओं का मूल्य क्या है जिनके लिये विभिन्न न्यायालयों में विवाद चल रहे है तथा कितने मूल्य की वस्तुओं के बारे में अब कोई विवाद नहीं है ;

(ग) पहली अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक कुल कितने मूल्य का माल जब्त किया गया ; और

(घ) विवाद रहित माल के बारे मे सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सेतु.राम अग्रवाल) : (क) और (ख). 28 फरवरी, 1978 को ली गई तलाशियों के दौरान आयकर प्राधिकारियो द्वारा कोई अभिग्रहण नही किया गया ।

प्रवर्तन निदेशालय, बम्बई ने कोलाबा बम्बई स्थित एक परिसर से 28 फरवरी, 1978 को 250 अमरीकी डालर तथा कनाडियन डालर पकड़ा। इस मामले में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 8(1) के उपबन्धो का उल्लंघन किये जाने के कारण, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले से संबंधित कोई भी विवाद किसी न्यायालय मे विचाराधीन नही है।

प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि 28 फरवरी, 1978 को सीमा शुल्क प्राधिकारियो द्वारा 54,591 रु० मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया। 28 फरवरी, 1978 को पकड़े गये माल के संबंध मे किसी भी विवाद के न्यायालयो मे विचाराधीन होने की रिपोर्ट नही मिली है। यदि 28 फरवरी, 1978 को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कोई माल पकड़ा गया हो तो उसका ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) और (घ) : आयकर प्राधिकारियों ने 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान 275 लाख रु० से अधिक के अनुमानित मूल्य की परिसम्पत्तियां पकडी। जब कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियां पकड़ी जाती है तो सबसे पहले, माल पकडे जाने के 90 दिनों के भीतर, धारा 132(5) के अन्तर्गत, पकड़ी गई ऐसी परिसम्पत्तियो को रोक रखने के लिए आदेश जारी किया जाता है जो प्रकट नही की गई आय पर सरसरी तौर पर आकी गई कर की देनदारी (जिसमे ब्याज तथा दण्ड शामिल है) तथा विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत वर्तमान देनदारियो को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हों। उसके बाद नियमित कर निर्धारण कार्यवाही तथा जहां कहीं आवश्यक हो, दंड सबधी कार्यवाही आरम्भ की जाती है। धारा 132(5) के अन्तगत रोक रखी गई परिसम्पत्तियों के बारे मे अधिनियम की धारा 132ख में निर्धारित तरीके से कार्यवाही की जाती है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियो द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी 1978, तक पकड़े गये माल का कुल मूल्य 29 96 करोड़ रु० है : पकड़े गये जिस माल के बारे में कोई विवाद नही उठाया जाता है उसे जब्त कर लिया जाता है और जहां कही आवश्यक होता है तस्करी मे अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियो के विरुद्ध दण्डात्मक की कार्यवाही भी चालू की जाती है।

स्वर्ण नियंत्रण प्राधिकारियो द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान पकड़े गये माल का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

Irregularities in United Commercial Bank

6102. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:
SHRI MADHAV PRASAD TRIPATHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is the Government aware that some appointments have recently been made to allure certain Government officials on the Board of the United Commercial Bank on deputation in the Bank;

(b) if so, is it a fact that a niece of one Government director of the Bank has been appointed apprentice by creating a special post;

(c) is it also a fact that Reserve Bank officer on deputation in the United Commercial Bank has been appointed Chief Vigilance Officer and Chief Inspector in continuation of the deputation on his retirement from the Reserve Bank on a much higher salary and perks, and

(d) if so, the action proposed to be taken by the Government thereon?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL): (a) and (b) It is presumed that the reference is to the appointment of certain apprentices in the United Commercial Bank. According to the bank one Kum Anjana Guha was appointed as an apprentice on 2nd January, 1976 for a period of two years on a monthly stipend of Rs 250 without any obligation on the bank to absorb her in its service. The appointment was made on the recommendation of Clarion Advertising Services Ltd, the bank's publicity agents. She left the bank on 31st December, 1977 on completion of the apprenticeship. It is reported that Kum. Anjana Guha is a distant relation (daughter of sister-in-law) of Shri D. N. Ghosh who was once a Government Director on the Bank's Board. Shri Ghosh ceas-

ed to be a Director of the bank even prior to Kum Guha's appointment as an apprentice in the bank on 2nd January, 1976

The bank similarly appointed two more apprentices during the period

(c) The Reserve Bank has reported that none of the officers of Reserve Bank of India (Department of Banking Operations and Development) either in service or retired, is at present on deputation with the United Commercial Bank Shri D P Galwankar and Shri A K Basu, two senior officers of the Department of Banking Operations and Development were placed on deputation with the bank effective from 18th July 1970 and 22nd May 1972 respectively and were permitted by the Reserve Bank to continue in that bank on a contract basis for a period of two years after their retirement in July 1973 and October 1972 respectively While Shri Galwankar was designated by the bank as Officer on Special Duty Shri Basu was designated as Chief Inspector Neither of these two officers is at present, in the service of that bank

(d) In view of the foregoing no action in the matter is called for

बचत तथा उपहार योजनाओं का बन्द किया जाना

6103 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बचत तथा उपहार योजनायें बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप इन योजनाओं में काम कर रहे लाखो लोग बेरोजगार हो जायेंगे तथा क्या समाज के कमजोर वर्गों को राष्ट्रीयकृत बैंको की तुलना मे कम ब्याज की आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त करने मे बहुत कठिनाइयो का सामना करना पडेगा ,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन योजनाओ के अधीन उनकी पूजी राष्ट्रीयकृत बैंको मे ही जमा होती है जिससे सरकार को लाभ होता है , और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन योजनाओ को बन्द करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री जेम्स एस० राज की अध्यक्षता मे गठित गैर-बैंकिंग कम्पनियो विधेयक अध्ययन दल ने, औरोके साथ साथ बचत और इनामी योजनाओ का भी अध्ययन किया था। इस दल का मत था कि इन योजनाओ से कोई सामाजिक प्रयोजन पूरा नही होता, ये सार्वजनिक हित के लिए घातक है और ये सरकार की मौद्रिक और वित्तीय नीति के कुशल सचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अत: इस दल ने सिफारिश की कि इस प्रकार की योजनाओ पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। सरकार को इस प्रकार की योजनाओ के संचालको के भ्रष्ट तरीकों के बारे मे अनेक शिकायतें भी मिली हैं।

सरकार माननीय सदस्य की इस आशका से सहमत नही है कि इन योजनाओ पर प्रतिबंध लगाने से रोजगार की स्थिति, बैंको मे

जमाओं और समाज के कमजोर वर्गों को प्राप्त ऋण-सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबन्ध के बाद, आशा है, इन योजनाओं के संचालक उत्पादक कार्यों में लगेंगे।

West Bengal Government Concern on Export of Sugar

6104. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether West Bengal Government have shown their concern at the Centre's decision to allow the export of 650,000 tonnes of sugar; and

(b) if so, what are their main objections?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). Yes, Sir. The concern expressed by the Government of West Bengal regarding allowing export of 6 5 lakh tonnes of sugar is a part of the general concern expressed by them on the sugar policy as a whole viz. raising the retail price of levy sugar from Rs. 2.15 to Rs 2 30 per kg. and allowing further rebate on Excise Duty on sugar.

As far as the decision to export 6.5 lakh tonnes of sugar is concerned, West Bengal Government have not indicated their precise objections.

Sugar Exported during 1977 and Foreign Exchange Earned

6105. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to export sugar during the current year; and.

(b) if so, the quantity of sugar exported during 1977 and foreign exchange earned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir. Government have decided to export 6.5 lakh tonnes of sugar during the calendar year 1978.

(b) During the calendar year 1977 2.55 lakh metric tonnes of sugar was exported, which resulted in a fore'gn exchange earnings of Rs 57 54 crores.

Export of Wagons and Coaches

6106. SHRI M. RAM GOPAL REDDY:

DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA:

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state the number of wagons and rail coaches exported during the last five years and the names of the countries to which exported and foreign exchange earned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): A statement is placed on the Table of the House.

Statement

Year	No exported		Countries to which exported	Approximate foreign exchange earnings
	Wagons	Coaches		
				(Rs. in lakhs)
1973-74 . .	664	6	Poland, Iran and Zambias . .	462
1974-75	344	50	Yugoslavia, East Africa, Bangladesh .	904
1975-76 .	898	90	East Africa, Yugoslavia, Malaysia, Bangladesh, Philippines	1371
1976-77 .	791	17	Yugoslavia, Malaysia, Bangladesh, Iran, Tanzania	1176
1977-78	101	Nil	Iran, Tanzania	159

Steps to increase Production in Public Sector

6107 SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) how many plants are not working in full capacity in the public sector,

(b) its reasons and the action taken by the Government to see that all the plants work with full capacity, and

(c) what specific steps Government propose to take to increase the production in the public sector?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL): (a) According to information available, it is estimated that out of 118 manufacturing units, 54 were operating below attainable capacity (which is estimated as 75 per cent of the installed capacity on an average) during the period April—December, 1977

(b) and (c) The main reasons for under utilisation were:

(i) Power shortages, fluctuations and failures.

(ii) Inadequacy of demand.

(iii) Equipment break down.

(iv) Labour unrest.

(v) Short-comings in managerial structure

(vi) Old age of plants

(vii) Lack of balancing equipment

(viii) Inadequacy or poor quality of raw materials.

With the objective of increasing production in public undertakings, the following major steps have been taken:

(i) Provision of captive power plants

(ii) Diversification of product-mix

(iii) Provision of balancing equipment, modernisation and rehabilitation of plants

(iv) Research and development

(v) Development of ancillary units

(vi) Streamlining procedures for import of raw materials/components and capital goods

(vii) Better maintenance of equipment

(viii) Improvements in managerial and operational efficiency.

(ix) Improving labour productivity by providing incentives and adoption of participative style of management.

(x) Development of operating skills by training.

(xi) Conducting special studies of problem areas for finding solution etc.

The performance of these undertakings are constantly reviewed so as to be able to take timely remedial action for effecting improvements

Smuggling out of Indian Films

6108 DR VASANT KUMAR PANDIT Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the custom authorities have unearthed large scale clandestine export of Hindi films to foreign countries, and

(b) if so, how many such cases have been detected and what action has the Government taken to stop smuggling in Indian films out of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) and (b) Reports received by Government do not indicate any large scale smuggling of Hindi films. During the period from January 1977 to February, 1978, three cases involving attempts to smuggle four Hindi films out of India were detected The films were seized and nine persons arrested who were later released on bail. Appropriate action against the persons concerned with the offence has also been initiated under the law. To curb smuggling of films more effectively, preventive and intelligence machinery have been kept on the alert and suitable checks are carried out on baggage of outgoing passengers.

जाम टैक्सटाइल मिल, बम्बई पर करों की बकाया राशि

6109. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जाम टैक्सटाइल मिल, बम्बई पर विभिन्न करों की कितनी धनराशि बकाया है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कर की बकाया राशि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : जाम टैक्सटाइल मिल्स बम्बई के मालिक मेसर्स जाम मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड है । कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 के लिए 8 जनवरी, 1977 को जारी की गयी आयकर की 60,763 रुपए की माग ही, दिसम्बर 1977 मे, उक्त कम्पनी की ओर बकाया थी।

Agents Registered with Custom Authorities

6111, SHRI NATHU SINGH Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 2385 on the 10th March, 1978 regarding registration of clearing and forwarding agents/companies with custom authorities and state.

(a) the number of custom house agents registered with custom authorities at the end of the First Plan, at the end of the Third Plan and as on 1st January, 1978 at Ports of (1) Bombay, (2) Calcutta, (3) Madras, (4) Visakhapatnam, (5) Cochin, and Airports of (1) Delhi, (2) Bombay, (3) Calcutta, (4) Madras and (5) Amritsar;

(b) the functions, complete address and number of members of Custom House Agents Association and whether this body is represented on any official Committees; and

(c) whether an agent licensed at one port can do business at another port under the same licence and the number of personnel one agent is allowed to engage for work at custom station premises at ports/airports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) A statement giving the number of the Custom House Agents registered with the Customs Authorities at the end of First Plan at the end of Third Plan and as on 1-1-1978 is laid on the table of the House

(b) There is a Federation of the Custom House Agents Associations and tthis has various Associations of the Clearing Agents at different ports or places as its federating units The Federation's Office is at Kalikushroo Building 237 P D' Mello Road Bombay Government does not have information about the functions, number of members of addresses of the various Associations The Federation is represented at the Customs and Central Excise Advisory Council which has been constituted by the Government of India Some of the local Associations of the Custom House Agents have their representatives on the Advisory Committees appointed for the respective ports/airports

(c) Custom House Clearing Agents licensed at one port cannot transact any business at another port under the same licence Having regard to the volume of work handled by the Clearing Agent he may engage any number of persons

Statement

Port/Airport	As at the end of the first Five year Plan	As at the end of the third Five year Plan	As on 1-1-1978
BOMBAY (including airport)	164	397	455
CALCUTTA (including airport)	131	123	117
MADRAS (including airport)	89	107	92
COCHIN	32	48	48
VISAKHAPATNAM	18	18	16
DELHI	10	20	66
AMRITSAR	7	13	9
	451	728	803

Growth of Public Sector

6112 SHRI C K CHANDRAPPAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether Government are curbing the growth of public sector and if so, the details thereof,

(b) how far it is true that Government's direction is not development oriented for the basic industries, and

(c) if so the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) No Sir On the contrary, the new Industrial Policy envisages an expanding role for the public sector in several fields

(b) and (c) While the new Industrial Policy has as its main thrust the effective promotion of cottage and small industries it also recognises

that basic industries, such as steel non-ferrous metals, cement, oil refineries, etc. are essential for providing infra-structure as well as for fostering the development of small and village industries.

Resumption of Trade Between India and China

6113. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that trade between India and China has been resumed or is likely to be resumed;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) in what commodities trade between the two countries has been resumed and with what results?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir, the trade has been resumed.

(b) and (c). Trade with China is permitted to be transacted in the same manner as in the case of any other country with whom India has trade in convertible currency. It is not restricted to specific commodities only. Deals concluded between commercial organisations of the two countries after resumption of trade so far include exports of 600 M/T of shellac, 20000 M/T of pig iron and steel tubes to China and imports of 315 M/T of antimony, 1200 M/T of zinc and 3500 flasks of mercury from China.

Enquiry against Kapadia's

6114. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have since completed the enquiry into the Rs. 86 crore fraud committedd by Kapadia's as reported in the Current dated 10th December, 1977;

(b) if so, the details of the enquiry so conducted; and

(c) action taken by the Government in regard thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). A One-man Committee consisting of Shri D. N. Ghosh, Director in the Office of the Comptroller and Auditor General, New Delhi was appointed by Government to enquire into the credit facilities given by Central Bank of India to M/s. Kohinoor Mills Co., Ltd. The One-man Committee has since submitted its report on 1st December, 1977.

Government's consideration of the report is expected to be completed shortly and the House will soon be informed about the action proposed to be taken on the report.

Bungling in Bharat Tubes Company

6116. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) is Government aware of the fact that there is a great bungling in the case of Bharat Tubes Company and its Directors;

(b) is Government also aware of the fact that there was a connivance between the owners of the company and some of the Officers of the Income Tax Department;

(c) is it a fact that the Income Tax Officer, who was the assessment officer was employed by this firm on a salary of about Rs. 6,000/- per month; and

(d) what action has been taken against the concerned Officers and against the firm by the department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) There is no

company by the name of Bharat Tubes Company. The reference presumably is to Bharat Steel Tubes Limited, a company belonging to Raunaq Singh Group.

The cases of Bharat Steel Tubes Limited and its Directors have been centralised under the jurisdiction of the Commissioner of Income-tax Delhi (Central), for necessary investigations.

(b) to (d). The Income-tax Officer who was dealing with the case of the company from December, 1975, resigned from Government service with effect from the 30th April, 1977. According to information available, he took employment with Bharat Steel Tubes Limited as General Manager (Taxation), soon after his resignation from Government service, on the following terms—

A basic salary of Rs. 3,000/- (Rupees three thousand only) per month.

Unfurnished residential accommodation subject to rent ceiling of 30 per cent of basic salary.

Reimbursement of car expenses up to a limit of Rs. 5,400 (Rupees five thousand and four hundred only) per annum for using his car in connection with the business of the company

Leave Travel Assistance of Rs. 1,800 (Rupees one thousand and eight hundred only) per annum for each completed year of service.

Benefits of Provident Fund Superannuation Scheme, Gratuity and Medical Benefits as per rules of the Company.

There is no need or scope for any action against any officer of the Income-tax Department on the basis of the information presently available. Appropriate action will be taken taken against the company and also others, if required, on completion of the investigation being made in the company's case.

Appointment to the various Posts of Federal Bank

6117. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact only Malayalis are considered for appointment to the various posts in the Federal Bank, Trivandrum;

(b) what is the present strength of Malayalis and other than Malayalis in all Branches of Federal Bank; and

(c) the action proposed to be taken by Government for this discrimination in making appointments of Malayalis only?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). Till the end of 1972 Federal Bank Ltd., had confined its activities only to the Kerala State. Since 1973, the Bank is reported to be advertising posts of officers on an All India basis and for this purpose conducting examinations in Bombay, Calcutta, Delhi and Madras in addition to those in Kerala State. It is also reported to be conducting examinations at regional centres for clerical staff.

As banks are not required to maintain statistical data about their employees according to the States to which they belong, Reserve Bank have no state-wise break-up of the employees of this bank. A quick review of the staff position of the bank's branches in Bombay area has indicated that 30 per cent of its staff in these branches comprised of non-malayalis.

Export of Traditional and Non-Traditional Items

6119 SHRI S R DAMANI Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) the targets set for export in 1977-78 in respect of all traditional and non traditional items and the actual achievement as per latest available figures indicating the percentage of variation over the previous year;

(b) the items in which a shortfall is expected and the reasons thereof; and

(c) the steps taken to strengthen the export prospects of those items in the coming year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) to (c) The overall export target for 1977-78 was earlier set at around Rs 5750 crores Based on the provisional figures India's overall exports during the first ten months of 1977-78 (April—January) at Rs 4374 36 crores registered an increase of 6 2 per cent over the level of exports in the corresponding period of the previous year Item-wise export targets are set only by some export organisations like Engineering Export Promotion Council which has been announcing the target for engineering goods exports Within the Department of Commerce exercises about export outlook are carried on all the time in the light of performance and expected supply/demand position with a view to take suitable steps to regulate/promote exports The performance of exports of principal items during the first half of 1977-78 (latest available) as compared to the corresponding period of the previous year with per cent variations in exports is indicated in the Statement enclosed

Export were lower particularly in the case of items like sugar, vegetable oils cotton ready made garments, leather and leather manufactures iron and steel Exports of sugar, vegetable oils and cotton were reduced in order to meet essential requirements within the country In the case of steel also there was lesser availability of the exportable surplus due to increased domestic demand The exports of readymade garments have been largely affected due to protectionist tendencies where in the case of leather and leather manufactures substantial inventories with the European tanners and recessionary situation were responsible

With the prospects of larger sugar production in the country and a quota of 6 5 lacs tonnes allotted to India under International Sugar Agreement, exports of this item are expected to be larger during 1978 79 In order to fully exploit the export potential for the garment a separate Export Promotion Council in the name of Apparels Export Promotion Council has been set up A number of export production projects have been sanctioned by the Government under the Handloom Development Programme to further improve the production base of export of handloom So far as iron and steel is concerned the policy for exports is yet to be finalised The new impor-export policy recently announced by the Government would also significantly contribute towards strengthening the base of export production and then help in increasing the exports from India.

Statement

India's Exports of principal traditional and non-traditional items

(Value in Rs Crores)

Sl No	Item	April—September 1976	April—September 1977 (Prov)	% variation in Apr - Sept 1977 over 1976
1	2	3	4	5
1	Tea . .	113 02	267 58	+136·3
2	Coffee .	59 21	122 84	+107·

1	2	3	4	5
3	Tobacco unmanufactured	73·98	86·44	+ 16·9
4	Sugar	89 61	10 53	—88·3
5	Feeding stuff for animals	93·55	106·90	+14·3
6	Fixed vegetable oils and fats	33·69	10·51	—68·8
7	Spices	20·84	45·30	+ 117·4
8	Cashew kernels	68·95	106·26	+54·1
9	Raw Cotton	26·56	0·10	—99·6
10	Fish	87·85	88·06	—0·2
11	Iron ore	93·85	102·54	+ 9·3
12	Leather & leather manufactures	135·12	121 34	—10·2
13	Cotton fabrics	3·16	4·86	+53·8
14	Ready-made garments	161 47	145·33	+10·0
15	Coir manufactures	11·23	11·42	+1·7
16	Jute manufactures	84·99	111·54	+31·2
17	Chemicals & allied products	48·19	62·45	+29 6
18	Machinery & transport equipment	141 23	150 62	+6 7
19	Iron and Steel	108·44	137 55	—27·0
20	Handicrafts	161 13	290·71	+79·3
	(i) Pearls precious semi-precious stones	91 41	203·63	+ 122·8
	(ii) Other handicrafts	69 72	87·08	+24·9
	Grand Total incl re-exports	2330·03	2584·66	+10·9

Raids conducted on Coal and Cement Dealers

6120 SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that in recent raids carried out by the Delhi Administration, malpractices adopted by coal and cement dealers were detected;

(b) if so, the full details thereof; and

(c) the action taken against the dealers apart from suspension or cancellation of licences?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a to (c) On receipt of information about malpractices by coal and cement dealers, the Delhi Administration conducted raids resulting in detection of 24 cement dealers and 56 coal dealers indulging in fictitious sales, maintenance of incomplete addresses of consumers and non-maintenance of proper accounts. 9 cases were detected where persons were found selling cement without a licence. Eight quintals of coal were seized while it was being taken out of

Delhi in an unauthorised manner. Apart from departmental action and suspension of licences, FIRs have been lodged with the Police. The Delhi Administration have set up a special Intelligence Cell to keep a watch on such malpractices.

Equity Debt Norms

6121. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at the instance of the Union Finance Ministry the Management Development Institute prepared a study on equity-debt norms, which was submitted to Government; and

(b) if so, the details regarding its recommendations?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M PATEL): (a) yes, Sir.

(b) the Report on a Study of the Debt Equity Ratio Norms has been published by the Management Development Institute, New Delhi in January this year and a summary of main conclusions and recommendations has been given in Chapter 6 of the Report

Import of D. D. T. From Poland

6122 SHRI PARMANAND GOVINJIWALA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the STC had placed an order to import 1500 M. Tonnes of D.D.T. Technical with Poland;

(b) if so, whether it is not also a fact that Poland did not supply the goods according to import schedule; and

(c) if so, whether the S.T.C. has incurred any losses; if so, the amount of losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. However, supply of 1,000 MT has been completed. Shipment of balance 500 MTs is expected to be made by end of April, 1978.

(c) No, Sir.

Direct flights from Bombay, Madras, Bangalore, Nagpur to Varanasi

6123. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government has given any quota of seats in Boeing as Parliamentary Quota to Varanasi; and

(b) is the Government going to connect Varanasi by direct flights to Bombay, Madras, Bangalore, Nagpur and other important centres, as Varanasi is one of the most important tourist and religious centre of the country?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) No, Sir

(b) No, Sir.

Seizure of ornaments from President and Chairman of J. K. Synthetics Ltd.

6124. SHRI YADVENDRA DUTT: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Half-an-Hour Discussion on the 20th December, 1977 regarding seizure of ornaments from President and Chairman of J. K. Synthetics. Ltd. and state:

(a) whether the enquiry has been completed and if so, what is the report; and

(b) when it will be laid on the Table of the House?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) and (b). Investigations in this case have been carried out and not tangible and incriminating evidence has yet been available. Since these are secret investigations, the question of laying the Report on the Table of the House does not arise

Loss in Foreign Exchange due to fall in Dollar and Pound Price

6125 SHRI YADVENDRA DUTT Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 2375 on the 10th March 1978 regarding loss to India's accumulated foreign exchange due to depreciation in value of Dollars and Pounds and state the amount of loss suffered by India in its accumulated Foreign Exchange with the continuous fall in Dollars and Pound price in the international monetary market?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) In accordance with the practices and usages customary among Central Banks the details of investments of the foreign exchange reserves or the gain or loss on such disposition are not divulged as such disclosure would not be in the public interest The rupee value of India's foreign exchange reserves did not show any decrease in 1977 78 on account of exchange rate variations

Japanese and American Woollen clothing smuggled into Agartala

6126 SHRI YADVENDRA DUTT Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether his attention has been drawn to the statement of the Chief Minister of Tripura alleging that vast quantities of Japanese and American woollen clothing and other articles at throw-away prices are being smuggled into Agartala, and

(b) if so, what action the Government are taking to prevent this vast smuggling?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) No Sir. Reports received by the Government do not indicate any large scale smuggling of these goods into Agartala. This is borne out by the fact that during the period from 1-1-1977 to 31-3-1978 total seizures of contraband were only of a value of Rs 35,760/- comprising of old and used woollen and synthetic garments of a value of Rs 7,274/-, textiles of a value of Rs 22,986/- and six pieces of tape recorders of a value of Rs 5,500/-.

(b) Although smuggling across Tripura Sector of the Indo-Bangladesh border is well contained, the preventive and intelligence efforts in this sector have been intensified and the concerned staff of the Border Security Force and the Customs Department are kept on alert to thwart any attempt at smuggling from across this border

Pricing Policy of Tea

6127 SHRI M RAM GOPAL REDDY Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that inconsistency in export and pricing policy of Government has harmed Indian Tea in the International Market,

(b) if so whether Government is considering the pricing policy and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) No Sir

(b) Does not arise

(c) It is the endeavour of Government to ensure that adequate quantity of tea is available for domestic consumption at reasonable prices at all

times. The quantity for export has been decided only after taking into account internal demand. With this in view the export figure for the 1977-78 was fixed at 225 m.kgs. even though the production for the year 1977 was higher than the production for 1976 by about 48 m. kgs. As a consequence of this policy and other measures taken by Government internal prices of tea, which had shot up early last year, settled down to reasonable levels We also secured good prices for our export of tea as a consequence of which tea export earnings in 1977-78 are likely to be well in excess of Rs. 500 crores as against Rs. 295 crores in the last year.

Recommendations of Central Excise (Self Removal Procedure) Review Committee

6129. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the salient recommendations made by the Central Excise (Self Removal Procedure) Review Committee of 1971;

(b) the new procedures for levy and collection of Central Excise introduced from 1st February, 1978;

(c) the details of the compounded levy scheme that has been formulated; and

(d) the names of commodities that have been brought under this new system?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) A copy of the Report of the Central Excise (Self Removal Procedure) Review Committee was laid on the Table of the Sabha on the 9th September, 1974. A statement showing the recommendations of the Committee and the decisions of the Government thereon was laid on the Table of the Sabha on the 1st September, 1976. Reference is invited to the above-mentioned documents.

(b) The reference apparently is to the Records Based and Production Based patterns of Control which were introduced with effect from the 1st February, 1978. A short note bringing out the broad features of these procedures is at Appendix 1. [*Placed in Library. See* No. LT—2052/78].

(c) Assuming that the reference is to the Clearance Based Control-*cum*-Simplified Procedure for payment of duty by small manufacturers of specified excisable goods which was introduced with effect from the 1st March, 1976, a short note bringing out the main features of the Scheme is at Appendix 2. [*Placed in Library See* No LT—2052/78].

(d) A statement showing the commodities under Records Based Control is at Appendix 3. [*Placed in Library. See* No. LT—2052/78] The bulk of the remaining excisable commodities (namely, other than those covered by physical type of control, Clearance Based-*cum*-Simplified Procedure, special procedures commonly known as Compounded Levy Scheme or Item No. 68 of the Central Excise Tariff) are covered by the system of production Based Control.

Value of Licences granted under Liberalised Import Policy

6130. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) what is the value of licences granted under the liberalised import policy in the current year;

(b) what impact had this policy in the current year on the market prices of cloves; and

(c) whether it is proposed to continue the same policy next year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-

OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) The value of licences granted from April 1977 to January 1978 for import of cloves under the liberalised policy was of the order of Rs. 17.31 crores.

(b) A statement showing the month-end Index Numbers of whole sale price of cloves is attached.

(c) Yes, Sir.

Statement

Month-end Index Nos. of Wholesale Prices for Cloves

Month-end	1976	1977	1978
January	186 8	140 2	80 5
February	188 0	140 2	70·3
March	192 9	140 2	
April	192 9	135·3	
May	177 8	107 7	
June	174 8	99·6	
July	135 5	89 8	
August	142 0	84 8	
September	135 5	84·8	
October	135 5	72·6	
November	135 5	72·6	
December	135 5	80·5	

S T.C 's ability to export Canalised Items

6131. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether STC has been able to export canalised items themselves or they are all exported through their business associates;

(b) what was the value of exports made by STC directly in the last three years; and

(c) what are the reasons for decrease in the value of exports of canalised items handled by the STC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Export of major canalised items like Rice, Sugar, Castor Oil, Footwear, Silver and Cement is generally undertaken by the Corporation on its own.

However, in a few cases like Salt, Semi-processed leather and to some extent footwear, shellac, etc. established trade channels, have been allowed to continue.

(b) and (c). A statement is attached.

Statement

Statement showing export of canalised items made by STC directly during last 3 years

(Value in Rs. Crores)

Item	1975 76	1976-77	1977-78 (Prov.)	Reasons for shortfall
1 Basmati Rice	11 51	6.29	3 20	(i) Restrictions on the export of mass consumption goods with a view to increasing the domestic availability.
2. Sugar	408 49	152 01	16 33	(ii) Downward trend in international prices. (iii) Fall in the value of dollar.
3 Silver	5 33	93 60	82 00	Exports undertaken on the basis of quota allocations, which were same for both the years. Fall in realisation is due to fall in the value of dollar.
4. Footwear	3 97	6 70	5 00	STC's direct exports of footwear have steadily increased during the last few years. There is, however, a fall in exports during the current year mainly because of fall in shipment of leather footwear to USSR. Infrastructural adjustments are now being made in the local units which will be reflected in future contracts when increased export prices commensurate with change in quality standards/demand of buyers shall be possible. Possibilities of developing export market for high value shoes to other countries are being explored with a view to achieve a break through.
5. Castor Oil	16 25	30 81	25 00	Exports of Castor Oil were banned during February to May, 1977. There was a consequential fall in the export activity during the year.
6 Shellac/Seedlac	4 68	1 96	1 31	Export of Shellac/Seedlac has almost been stagnant because of : —Competition from synthetic substitutes, —availability of seedlac from Thailand at much lower prices. —uncertainty among foreign buyers about regular availability of Indian Shellac at suitable prices.
7 Cement	15·22	32 60	16 31	Exportable surpluses are released by the Government from time to time. In view of restrictions on export of Cement, there has been a corresponding fall in the value of the exports.

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा विकलांगों को ऋण सुविधाएं

6132 **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि बैंक आफ इंडिया ने विकलांगो को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ की है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत इस समय किस प्रकार की सम्थाएं सम्मिलित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक ने विकलांग के वित्त पोषण का कोई पृथक योजना नहीं बनाई है फिर भी बैंक द्वारा अपनी सामान्य योजनाओं के अधीन उनकी तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। 10 000 रुपए से अधिक के ऋणों पर उनसे 8 प्रतिशत रियायती दर से ब्याज लिया जाता है और इस सीमा से अधिक के ऋणों पर सामान्य दर से ब्याज लिया जाता है। रियायती ब्याज दर योजना के अधीन पात्रता को पूरा करने वाले व्यक्तिगत विकलांग व्यक्तियों और विकलांगों की संस्थाओं को भी ब्याज की 4 प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाता है।

हवाई अड्डों के लिये "कंट्रोल टॉवर"

6133 **श्री सुखेन्द्र सिंह** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या निर्धारित उड़ानों वाले कुछ हवाई अड्डों पर कोई कंट्रोल टावर नहीं है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे हवाई अड्डों के क्या नाम हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) ऐसे सभी सिविल विमान क्षेत्रों पर नियंत्रण टावर उपलब्ध है जिनसे होकर इंडियन एयरलाइंस अनुसूचित विमान सेवाओं का परिचालन करती है। तथापि पंचवर्षीय योजना (1978-83) में निम्नलिखित सिविल विमान क्षेत्रों पर आधुनिक प्रकार के नियंत्रण टावरों/तकनीकी ब्लाकों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है।

1 गोहाटी (तकनीकी ब्लाक तथा टावर)
2 त्रिवेन्द्रम (तकनीकी ब्लाक तथा टावर)
3 इम्फाल (तकनीकी ब्लाक)
4 विशाखापत्तनम (तकनीकी ब्लाक)
5 अहमदाबाद (नियंत्रण टावर)
6 रायपुर (नियंत्रण टावर)
7 लखनऊ (नियंत्रण टावर)
8 रांची (तकनीकी ब्लाक तथा टावर)
9 जबलपुर (तकनीकी ब्लाक)
10 पोर्ट ब्लेयर (नियंत्रण टावर)
11 बेलगांव (तकनीकी ब्लाक)
13 बंगलौर (तकनीकी ब्लाक)
13. औरंगाबाद (नियंत्रण टावर)
14 बैंहाला (नियंत्रण टावर)
15 राजकोट (नियंत्रण टावर)
16 मद्रास (नियंत्रण टावर)

विशाखापत्तनम में एक नये नियंत्रण टावर के निर्माण की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। योजनाएं तथा डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं और निर्माण कार्यों के 1978-79 में आरम्भ हो जाने की आशा है।

वनस्पति तेलों के लिये राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता

6134. **श्री चतुर्भुज :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा वनस्पति तेलों के लिये (एक) राज्य सरकारों, (दो) अन्य एजेंसियों को दिये गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री कृष्ण कुमार गोयल) : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों अथवा अन्य अभिकरणों को वनस्पति तेलों के लिए कोई अनुदान नहीं देती है। तथापि साफ करने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले रेपसीड तेल निर्गम मूल्य के लिए 25-8-77 से 1000/- रु० प्रति मीटरी टन की आर्थिक सहायता दी गई है, ताकि राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को यह तेल अधिक से अधिक 7.50 रु० प्रति कि० ग्रा० के अन्तिम उपभोक्ता मूल्य पर दे सकें। आर्थिक सहायता के लिये अब तक नीचे दिये दावे मिले है —

अभिकरण	राशि रुपयों में
(i) दिल्ली प्रशासन	2,01,074.00
(ii) राजस्थान सरकार	3,41,926 00
(iii) पश्चिम बंगाल सरकार	9,51,749 75
(iv) तमिलनाडु सरकार	2,03 878 75
(v) नागालैंड सरकार	98,570 00
(vi) गणेश फ्लोर मिल्स	6,36,786 00
(vii) महाराष्ट्र सरकार	54,52,800 00
योग	78,86,784.50

अन्य राज्य सरकारों से अभी दावे प्राप्त नहीं हुए हैं।

पिल्लई समिति और गट्ठा समिति की सिफारिशें

6135. **श्री चतुर्भुज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार ने पिल्लई समिति और गट्ठा समिति बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उन समितियों के प्रतिवेदन मिल गये है ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उन प्रतिवेदनों में निहित सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ). सरकार में बैंकरो के एक दल से पिल्लै समिति की सिफारिशो के कार्यान्वियन के तरीके के बारे मे सुझाव देने के लिय कहा था, श्री पी०एफ० गटठा इस दल के 1 सदस्य थे। सरकार ने इस दल द्वारा सुझाये गये कुछ सशोधनो के साथ, राष्ट्रीयकृत बैंको के अफसरो के वेतनमानो भत्तो और अनुलाभो के मानकन के बारे मे पिल्लै समिति की सिफारिशे स्वीकार कर ली है।

पिल्लै समिति ने राष्ट्रीयकृत बैंको क अफसरा के वेतनमाना के ढाचे को शासित करने वाले सिद्धान्ता की समीक्षा करने के बाद एक मानकित वेतन-मान-ढाच की सिफारिश की है जिसमे सात वेतनमान है। ये वेतनमान अफसरो के सदर्भ मे उत्तर-दायित्व के स्पष्ट स्तरा पर आधारित है। इसने दायित्वो और कार्यो के प्रकार के आधार पर बैंक में अफसरा के विभिन्न पदो के मूल्याकन के कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त भी सुझाये थे जिनक आधार पर उन पक्षो का समिति द्वारा सुझाये गय वेतनमानो मे से एक में वर्गीकरण किया जा सकता है। इस समिति ने अफसरो को दिये जाने वाले महगाई भत्ते तथा सभी अन्य भत्तो और अनुमानो व लाभो के भी मानकन की सिफारिश की है। समिति ने उच्चतम स्तर पर एक बैंक से दूसरे मे तबादलो की सभावना के बारे मैं भी सिफारिश की है।

बैंकरो के दल ने सामान्यत. पिल्लै समिति की सिफारिशो से सहमति व्यक्त करते हुए कुछ सिफारिशें का उद्धार बनान के लिये कुछ साधारण से सशोधनो के सुझाव दिये हैं।

2. राष्ट्रीकृत बैंको से कहा गया है कि वे सरकार द्वारा यथास्वीकृत इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दें।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में हिन्दी में नोट तथा मसौदे लिखने वाले कर्मचारी

6136. **श्री नवाब सिंह चौहान**: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उनके मत्रालय मे श्रेणीवार कर्मचारियो की वर्तमान सख्या कितनी है और उनमे से कितने कर्मचारी काम चलाऊ हिन्दी जानते है अथवा हिन्दी मैं प्रवीणता प्राप्त कर चुके है,

(ख) काम चलाऊ हिन्दी जानने वाले अथवा हिन्दी मे प्रवीणता प्राप्त ऐसे कर्मचारियो की सख्या कितनी है जो इस समय हिन्दी मे नोट तथा मसौदे लिख रहे है,

(ग) उनमै से कुछ कर्मचारियो द्वारा हिन्दी में नोट तथा मसौदे न लिख जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों को हिन्दी मैं नोट तथा मसौदे लिखने के आदेश दिये गये है, और यदि नही तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निम्नोक्त प्रकार है —

श्रेणी	कर्मचारियों की सख्या	हिन्दी मे कार्य साधन ज्ञान अथवा प्रवीणता रखने वाले	हिन्दी मे नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग करने वालों की सख्या
ग्रेड—क . .	117	92	19
ग्रेड—ख . .	158	130	46
ग्रेड—ग . .	569	489	102

(ग) और (घ) हिन्दी जानने व कर्मचारियों का हिन्दी में अपना कार्य करने के लिय प्रात्साहित किया जाता है लेकिन सरकारी काम मे हिन्दी इस्तेमाल करने के लिए उन पर कोई बाध्यता नहीं है।

Visit of British Team to India

6137 PROF P G MAVALANKAR
SHRI PRASANNBHAI MEHTA

Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether a high level British team visited India recently for talks with him and the Government of India,

(b) if so, broad details thereof,

(c) whether any new trade agreements were signed as a result of the said talks and if so, facts thereof, and

(d) the broad pattern of Indo-British trade during the year 1975, 1976 and 1977?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) Yes, Sir A British delegation led by the Rt Hon Edmund Dell M P, Secretary of State for Trade visited India recently for the meeting of the Indo-British Economic Committee held in New Delhi on 13th and 14th March 1978

(b) Discussions were held on various aspects of bilateral economic relations including commercial and industrial co-operation There was also exchange of views/discussions on other issues concerning Indo-EEC relationship Common Fund and Multilateral Trade Negotiations

(c) No, Sir

(d) The figures of India's trade with U K during the last three years, as available, are indicated below

(Rs in crores)

Year	Imports	Exports	Total	Balance
1975-76 . .	284 0	419 78	703 78	+135 78
1976-77	329·50	520 69	850 19	+191 19
1977-78 (April-Sept)	222 50	240 36	462 86	+17 86
1976-77 ((April-Sept.)	179·00	235·48	414 48	+56·48

(d) The figures of India's trade with U K during the last three years, as available, are indicated below

(Rs in crores)

Year	Imports	Exports	Total	Balance
1975 76	2d4 o	419 78	703 78	+135 78
1976 77	32) 50	520 69	850 19	+191 19
1977-78 (April-Sept)	222 50	240 36	462 86	+ 17 86
1976 77 (April Sept)	179 co	235 48	414 48	+ 56 48

Coordination between the Tourism Departments of Union and State Governments

6138 PROF P G MAVALANKAR Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether Government are aware that several State Governments in the Union have Departments of Tourism and/or special Boards for promotion of Tourism in their respective regions,

(b) if so whether there is any co-ordination and cooperation between the Union and State agencies in this regard so as to avoid duplication and enhance tourist traffic all over the country

(c) if so broad details thereto, and

(d) if not why not?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) Yes Sir

(b) and (c) The broad division of responsibility in the tourism sector between the Central and the State sectors has been that the Centre invests in the projects and programmes intended predominantly to stimulate international tourism the State Governments concentrate on development of facilities meant primarily for domestic tourists A close link of coordination and cooperation between the Centre and the States is provided at the time of Annual Plan/Five Year Plan discussion with the Planning Commission Coordination in the Central and State tourism programmes is also effected through the Tourist Development Council and the 4 Regional Tourist Advisory Committees, and the State Tourist Advisory Committees

(d) Does not arise

Staff Training Colleges of Nationalised Banks

6139 PROF P G MAVALANKAR Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether one or more of the nationalised banks in the country have got their own Staff Training Colleges

(b) if so full facts thereof

(c) the broad outline of the courses-structure and syllabus wise-offered at the said colleges,

(d) the number of trainees at such colleges in the year 1977 78, who teaches at the said colleges and

(e) whether knowledgeable and expert outsiders are also invited to give lectures at the said places?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) and (b) Yes Sir A statement-I of Staff Training Colleges of the Public Sector Banks is attached

(c) A Statement-II is enclosed

(d) According to the latest available information, 26023 officers and 32556 other categories of staff had been trained by banks during the period January, 1977 to 30th September, 1977

Each training college has its own nucleus faculty mainly drawn from its operational staff

(e) Banks do invite outside experts for lectures according to the needs and requirements of training

Statement-I

Staff Training Colleges of Public Sector Banks

Bank	Name of the College (mainly for training officers)	*No. of Centres mainly for training other categories of staff (As on 31-12-76)
1. State Bank of India Group.	State Bank Staff College, Hyderabad . . .	41
2. Central Bank of India .	Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers, Training College, Bombay. (Jointly with Dena Bank). . . .	11
3. Bank of India .	(i) Staff Training College, Andheri, Bombay .	9
	(ii) Bank of India and Bank of Baroda Staff Training College, Bombay. . . .	
4. Punjab National Bank .	Staff Training College, Delhi	5
5. Bank of Baroda .	(i) Staff Training College, Ahmedabad . . .	8
	(ii) Bank of India and Bank of Baroda Staff Training College, Bombay. . .	..
6. United Commercial Bank.	Staff Training College, Calcutta	3
7. Canara Bank .	Staff Training College, Bangalore . . .	3
8. United Bank of India .	Staff Training College, Calcutta	..
9. Dena Bank . . .	Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers Training College, Bombay (Jointly with Central Bank of India) . . .	9
10. Syndicate Bank .	(i) Staff Training College, Manipal . . .	4
	(ii) Staff Training College, New Delhi . . .	..
11. Union Bank of India .	Staff Training College, Bombay . . .	2
12. Allahabad Bank .	Staff Training College, Calcutta . . .	2
13. Indian Bank . .	Staff Training College, Madras . . .	6
14. Bank of Maharashtra .	Staff Training College, Poona . . .	2
15. Indian Overseas Bank .	Staff Training College, Madras . . .	4

*The Staff Training Centres of the banks cater to the training needs mainly of the category of staff other than officers.

Statement-II

Broad course structure and syallabus offered at the staff colleges of the banks

Sl. No.	Name of the Course	Syllabus
1.	Promotee Officers' Course . . .	Banking Operation, customer service, new trends in banking and human relation etc.
2.	Course for Direct Recruits . . .	Basic banking operation, Management of cash, subsidiary banking services, principles of advances, inter personal relations etc.
	(a) Orientation	
	(b) Induction	
	(c) Intermediate	
3.	Course for officers above first line supervisors :	
	(a) Accountant and other officers above the first line supervisors.	Collection and payment of cheques, principles of advances including priority sector advances, management functions, performance budgeting.
	(b) Rural Branch Managers .	Socio-economic environment of a rural branch, promotional activities and schemes of assistance to priority sectors, credit guarantee scheme, performance budgeting, inspection and audit, etc;
	(c) Managers of Small branches .	Performance budgeting, RBI credit control credit appraisal, priority sector advances refinance facilities, management functions, industrial relations, customer service, inspection and audit, etc
4.	Middle Management level :	
	(a) Branch Managers of Medium sized branches.	Business planning and development, branch administration, personal management and human relations etc.
	(b) Credit management for branch Managers and other officers likely to handle advance proposals relating to medium and large industrial borrowers.	Techniques of financial analysis, Cash/funds flow, credit appraisal including working capital and term finance and a broad view of refinance facilities available, export and import finance etc
5.	Course for Senior Management .	Development of high managerial skills to help solving specific organisational problems, to bring awareness in them about the corporate objectives and goals also to develop an appreciation of the changing environment.
6.	Courses for Specialisation :	
	(a) Agricultural Finance/SSI Course .	Basic operations and the accounting procedure of the bank, the mechanism, system and procedure of farm finance and other priority sector advances and credit appraisal relating to agricultural and other priority sector advance and in the formulation of projects.
	(b) Export Finance . . .	Functions of the Foreign Exchange Dealers Association, statutory provisions relating to bills, shipping documents, letters of credit, functions of ECGC.
	(c) Personnel and Industrial Relations .	Manpower planning, motivation and inter personnel relations, industrial relations, etc.

1976 and 1977

6140. PROF. F. G. MAVALANKAR Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether any tourist literature—pamphlets, picture postcards, publications, maps, etc. was printed and published during the years 1976 and 1977,

(b) if so, full details thereof including cost in each case, where was the material printed, number of copies etc;

(c) whether any of the said material is for sale, or is it all gratis and meant for gift; and

(d) how and where does the said tourist literature get distributed and used?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK). (a) Yes, Sir.

(b) A statement listing publicity literature produced by the Central Department of Tourism through the India Tourism Development Corporation during 1975-76 and 1976-77 is laid on the Table of the Sabha [*Placed in Library. See* No. LT-2053/78]. This literature was printed in India. Occasionally overseas Tourist Offices print publicity material to meet local exigencies.

(c) and (d). The tourist publicity literature produced by the Department of Tourism is distributed free through Government of India Tourist Offices in India and abroad. Token quantities of this literature are also made available to Indian Missions abroad.

निर्यात किये गये तम्बाकू का मूल्य

6141 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान किन-किन देशों को तम्बाकू का निर्यात किया गया,

(ख) भारतीय तम्बाकू के मुख्य आयातकर्त्ताओं के क्या नाम है,

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन देशों को कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया गया, और

(घ) वर्ष 1977-78 के दौरान कितने मूल्य का तम्बाकू निर्यात किया गया और वर्ष 1978-79 के दौरान कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान अनिर्मित तम्बाकू का देशवार निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया** / देखिये संख्या एल टी 2051/78]

(ख) ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा जापान।

(ग) देश का नाम	निर्यातों के मूल्य (करोड़ रु० में)		
	1974-75	1975-76	1976-77
ब्रिटेन	38 96	30.31	42 34
सोवियत संघ	17.23	28.91	23.99
जापान	6.48	9.52	8.76

(घ) वर्ष 1977-78 के लिए 110 करोड रु० का लक्ष्य रखा गया था तथा यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रैल 1977 से फरवरी 1978 के दौरान 105 37 करोड रु० के निर्यात हुए। 1978-79 के लिए 115 करोड रु० का अनन्तिम निर्यात लक्ष्य रखा गया है।

चाय का उत्पादन, खपत और निर्यात

6142 **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 से 1977-78 तक के दौरान चाय का किलोग्राम में वर्षवार अन्य शेष माल, उत्पादन, देश में खपत, निर्यात और इतिशेष माल कितना था?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : 1973-74 से 1977-78 तक के दौरान चाय के प्रारंभिक स्टाक उत्पादन, घरेलू खपत, निर्यात तथा इतिशेष माल के किलोग्राम में वर्षवार आकडे निम्नवत प्रकार है —

(आकडे मि० कि० ग्रा० में)

वर्ष	प्रारंभिक स्टाक	उत्पादन	घरेलू खपत	निर्यात	इतिशेष माल
1973–74	135	470	248	190	167
1974–75	167	494	260	225	176
1975–76	176	483	272	211	176
1976–77	176	512	286	242	160
1977–78 (प्राक्कलित)	160	560	300	225	195

पोरबन्दर-अहमदाबाद-पोरबन्दर विमान सेवा

6143. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पोरबन्दर वाणिज्य तथा उद्योगमण्डल, गुजरात ने 3 नवम्बर 1977 को पोरबन्दर–अहमदाबाद–पोरबन्दर विमान सेवा आरम्भ करने की मांग की थी

(ख) यदि हां तो उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में क्या कारण बताये है,

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पोरबन्दर सौराष्ट्र का बडा औद्योगिक शहर है और जूनागढ जिले का सबसे बडा शहर है उपर्युक्त विमान सेवा कब आरम्भ की जायेगी, और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) (क) जी हां।

(ख) मांग के समर्थन में दिये गये कारण ये थे कि,

(1) पोरबंदर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है जिसमे बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, तथा

(2) पोरबदर और अहमदाबाद के बीच सडक/रेल यातायात अत्यधिक है तथा इसकी यात्रा मे लगभग 18 घटे का समय लगता है।

(ग) और (घ) कारपोरेशन के विमान-साधन फिलहाल इतने नही है कि नये स्थानों को विमान सेवाओ से जोड़ा जा सके।

Submission of National Resolution on Cooperative Policy to Planning Commission

6144. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Government propose tl submit a national resolution on Co-operative Policy to the Planning Commission; and

(b) if so, the salient features and objectives thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) (a) The National Cooperative Policy Resolution, which was adopted in the last All India Conference of State Ministers of Cooperation, held at New Delhi, on 17th December, 1977 has been circulated among all the Ministries of the Government of India. including the Planning Commission, all the State Governments (in Cooperation Departments), National Cooperative Federations, State Cooperative Unions etc. for implementing the various policies enunciated in the Resolution.

(b)The objective of the National Cooperative Policy Resolution is to promote the development of the co-operative movement on sound lines, so that it can serve as an effective instrument of socio-economic transformation. The text of the Resolution is reproduced in the annexure. [*Placed in Library. See* No. LT-2055/78].

Functioning of Call Money Market

6145. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has introduced recently any changes in the functioning of call money market, and

(b) if so, whether this has led to reduction of call money rates?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M. PATEL): (a) No. Sir It may be stated, however, that the Reserve Bank has recently made it clear to all scheduled commercial banks that the prohibition on payment of brokerage contained in its directive of 22nd July 1974 on rates of interest on deposits also applied to operations in the inter-bank call money market.

(b) The rates of interest of inter-bank borrowings are regulated by the Indian Banks' Association. The Association is reported to have reduced the ceiling on the rate of interest on inter-bank call money transactions from 10 per cent to 8.5 per cent in the context of the revision in the rates of interest on deposits and advances made by the Reserve Bank with effect from 1st March 1978.

Withdrawal of Cash Subsidies for Exports

6146. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether he expects any impact on our exports as a result of the withdrawal of cash subsidies for exports; and

(b) if so, what he proposes to do tu help our exports to compete in the exceedingly competitive markets abroad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) Cash compensatory support has been withdrawn only in a few cases Decisions in these cases were taken after taking into account all relevant factors Withdrawal of this support is not expected to adversely affect exports

Refixation of the Price of Natural Rubber

6147 SHRI GEORGE MATHEW Will the Minister of COMMERCE CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) when do Government propose to refix the price of natural rubber which was previously fixed till 31st March, 1978,

(b) whether Government propose to do justice to the small growers of natural rubber in India by fixing a price at Rs 9/- per kilo and

(c) what are the guidelines, Government are going to follow, when refixing the price of natural rubber?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) to (c) Government had raised the minimum price of RMA—I Grade of natural rubber from Rs 520 per quintal with differentials for other grades with effect from 6th August 1977 and for a period upto the 31st March 1978 Government have since extended the period of vallidity of these prices till 31st May 1978 In the mean time the position is being reviewed

Government while considering the question of refixing the prices will give due regard both for the need to give a fair return specially to the small grower, and maintaining prices of essential commodities at reasonable levels

Export of Natural Rubber

6148 SHRI GEORGE MATHEW Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) what is the total quantity of natural rubber exported from India till 31st March, 1978,

(b) what is the total quantity that was sanctioned to be exported till 31st March 1978

(c) what is the balance quantity that still remains to be exported, and

(d) which are the agencies that are supposed to export this balance quantity and when do they propose to do it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO OPERATION (SHRI ARIF BEG) (a) As per provisional figures a total quantity of 11,080 tonnes of natural rubber has been exported during the financial year ended 31st March 1978 This quantity includes the quantity allowed for export during 1977 78 and the carry over from the quantity sanctioned for export during 1976 77

(b) Government had authorised the STC to export 10 000 tonnes of natural rubber during the year ended 31st March 1978

(c) and (d) Out of the total quantity of 21 000 tonnes of natural rubber authorised for export during 1976 (including 4 000 tonnes to be exported by growers or a consortium of growers through STC) and 10,000 tonnes of natural rubber allowed for export through STC during 1977, a total quantity of 7,624 tonnes remains to be exported at the end of 31st March 1978, This quantity includes 3,949 tonnes to be exported by STC and 3,675 tonnes to be exported by the growers of rubber through STC This

balance quantity is likely to be exported by STC/growers during the current financial year.

Surplus Natural Rubber

6149. SHRI GEORGE MATHEW: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) what is the total quantity of natural rubber that will be surplus in India by the end of 31st March, 1978;

(b) how do Government propose to deal with this surplus stock of rubber so that the prices do not slump below the cost of production for the small growers; and

(c) what is the estimated need for natural rubber for the next ten years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) The surplus stock of rubber is estimated to be of the order of 12,000 tonnes.

(b) The surplus rubber is already being allowed to be exported by STC so that prices of rubber do not slump to uneconomic levels

(c) As per Rubber Board's estimates, the consumption of natural rubber in the country is likely to increase from 1,53,000 tonnes in 1978 79 to 2,60,000 tonnes in 1987-88.

Abolition of Sales Tax on some Exportable Goods

6150. SHRI GEORGE MATHEW Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) has the Central Government got a time table for the abolition of the sales tax;

(b) what are the Government's plans far compensating the state of Kerala for the loss of sales tax by the State, due to the abolition of the sales tax by the centre on some of the exportable goods; and

(c) whether Central Government propose to give those taxation powers to the States or reduce the State's powers?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) The question of abolition of sales tax and its replacement by excise duty has been discussed with the Chief Ministers/Finance Ministers of States. The Chief Mimsters|Finance Ministers have generally shown lack of enthusiasm for this proposal. This is a matter which cannot be settled within a specified time table and calls for continuing efforts in this direction

(b) The special problems with regard to the sales tax revenue of Kerala are considered as a part of the larger problem of gap in resources for financing the approved Plan and as such the question of giving any compensation does not arise

(c) By amendment of the Central Sales Tax Act, 1956 w.e.f 1st April, 1976, the last sale or purchase of any goods preceding the sale or purchase occasioning the export of those goods out of the territory of India was also deemed to be in the course of such export if such last sale or purchase took place after, and was for the purpose of complying with the agreement or order for or in relation to such export. This amendment was carried out in the interest of promoting the export trade of the country and in the overall national interest. There is no proposal to make any change in this position.

Restrictions imposed in Budget in respect of advertising Publicity and Sales

6151. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that President of Indian and Eastern Newspapers Society has appealed to the Finance Minister to reconsider the restriction proposed in the Union Bud-

get for 1978-79 in respect of advertising, publicity and sales promotion, which will have an adverse impact on the national economy and severally hit the newspaper industry; and

(b) if so, the reaction of the Union Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) Yes, Sir.

(b) The representations received by the Government in this regard, including the representation made by the President of the Indian and Eastern Newspaper Society, are under consideration. The Government will take a decision in the matter before the Finance Bill, 1978 is taken up for consideration by the Lok Sabha.

Withdrawal of Benefits under Export Development Expenses

6152. SHRI R. V. SWAMINATHAN Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that representation has been made to the Ministers of Finance and Commerce by the Calcutta Jute Febrics Shippers Association regarding withdrawal of benefits under export market development expenses envisaged in the 1978-79 Union Budget;

(b) if so, whether the Finance Minister has examined their request;

(c) if so, the reaction of the Union Government; and

(d) whether this decision of the Government will hit hard jute goods export?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). The representations received by the Government in this regard, including the representation made by the Calcutta Jute Fabrics Shippers Association, are under consideration. The Government will take a decision in the matter before the Finance Bill, 1978 is taken up for consideration in the Lok Sabha.

Report of the Committee regarding expansion of branches of Nationalised Banks

6153. SHRI R. V. SWAMINATHAN:
SHRI PRASANNABHAI MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Government have received the report of the Committee which was appointed by the Reserve Bank of India for expansion of branches of nationalised banks;

(b) if so, the details of the same;

(c) whether Government have examined the report;

(d) if not, when the same is likely to be received;

(e) whether for the time being Government have decided not to expand the branches of the banks; and

(f) how many branches were opened during 1977?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL). (a) to (d). The Committee set up by the Reserve Bank of India under the Chairmanship of Shri James S Raj to Study the different aspects of the functioning of the public sector banks, including their branch expansion, has submitted an interim report to the Reserve Bank in January 1978. The recommendations contained in the interim report are under examination in the Reserve Bank. The final report of the Committee is awaited.

(e) No, Sir.

(f) The Commercial banks opened 3348 branches during 1977.

पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग

6154. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का अधिकाधिक योगदान तथा सहयोग प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). पर्यटन विभाग होटल मालिकों तथा यात्रा अभिकरणों का विदेश में प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए विदेशी मुद्रा का विमोचन करके विदेशी पर्यटकों के स्रोत स्वरूप देशों में भारत के लिए पर्यटन की अभिवृद्धि करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करता है। पर्यटक कारों के रूप में परिचालन के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से बड़ी कारों का आवटन, पर्यटक टैक्सियों के रूप में परिचालन करने के लिए कारों की खरीद के लिए परिवहन परिचालकों को ऋण देना आदि पर्यटन विभाग द्वारा किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय है।

इसी प्रकार पर्यटन विभाग वित्तीय सहायता के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन सम्भागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में होटलों के निर्माण के लिए 15% का सीधा उपदान तथा अनिवार्य वस्तुओं के आयात के लिए प्राथमिकता में विचार एवं प्रोत्साहन कोटा आदि प्रदान करके निजी क्षेत्र को और अधिक होटल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

Annual Session of U.N. Economic Commission for Asia and Pacific at Bangkok

6155. SHRI PRASANNABHAI MEHTA: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state

(a) whether it is a fact that India also attended the Thirtyforth Annual Session of the U.N. Economic and Social Commission for Asia and Pacific at Bangkok on 8th March, 1978;

(b) if so, whether Indian delegation put forward a proposal for self-reliance;

(c) if so, how far this proposal was accepted in the Conference;

(d) what were the subjects and decisions arrived at; and

(e) to what extent they will be beneficial to India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) Yes, Sir. The Session was held from 7th to 17th March 1978

(b) In his policy statement at the Session, the Minister of Commerce Civil Supplies and Cooperation who led the Indian delegation had *inter-alia* stressed that achievement of collective self-reliance by developing countries was an integral element of the New International Economic Order and that only a greater and confident spirit of self-reliance on the part of the developing countries would guarantee the restructuring implied in the New Order

(c) The concept of collective self-reliance was fully endorsed by the Commission

(d) A statement is laid on the Table of the House

(e) The decisions adopted at the Session will be collectively beneficial to all developing countries, including India

Statement

The 34th Session of ESCAP was held at Bangkok from 7th to 17th

March 1978 The Agenda of the Session *inter alia* included review of progress and consideration of issues in various fields of activities of ESCAP regional inputs for the International Development Strategy for the 1980s raising of extra budgetary resources the ESCAP work programmes and progress reports on major regional projects and regional training and research institutions

2 The main theme of the 34th Session of ESCAP was the evolution of regional inputs for the International Development Strategy for the 1980s The main conclusions of the discussion were as follows

(1) In order to make a positive contribution to the early establishment of a New International Economic Order a new development strategy should embody the spirit of the Resolutions of the 6th and 7th Sessions of the General Assembly specifying effective measures to remove the main obstacles to the independent development of developing countries so as to enhance their individual or collective self-reliance It should aim at accelerated economic growth with social justice with a view to alleviating poverty This calls for the fulfilment of the basic needs of the people, more equitable distribution of income and wealth greater and more active participation by all sections of society particularly the poorer in the development process, and effective integrated rural development programmes

(2) In the formulation of new Development Strategy for 1980s the shortcomings evident in the strategy for 1970s should be avoided

(3) Any new strategy should take into account the differences among countries, including levels of development, the potentials for and the constraints to development and the characteristics of social systems and objectives

(4) The objective of the strategy should include improvements in the standard of living of all people in the region It should include provision for greately enhanced employment opportunities, better mobilization of financial resources expanded and more widely acceptable social service and improvement in human settlements and environmental standards

(5) Co-operation would also constitute an essential element of the strategy

The Commission also adopted a resolution on the subject

The Commission endorsed the recommendation of the ESCAP Committee on Trade for convening in New Delhi in the middle of August 1978 a meeting of the Ministers of Trade of ESCAP member countries to take stock of developments in the field of trade since the Kabul declaration of 1970 and to give new directions for expansion of intraregional trade containing a package of concrete measures for the purpose

4 India along with 8 other countries, was elected to the membership of the First Government Council of the Regional Mineral Resources Development Centre to be located in Indonesia

5 The Commission also adopted Resolutions on the following subjects

(a) Role of Human Settlements in improving conditions of the people

(b) Greater emphasis on solution of population problems

(c) Support of Lumbini Development Project Nepal

(d) Strengthening and supporting activties of International Year of the Child

(e) Mobilisation of resources for the implementation of Work Programme of ESCAP and the Regional Training and Research Institutions

(f) Strengthening of the Regional Training and Research Institutes under the aegis of ESCAP.

(g) Development of Water resources in the Lower Makong Basin.

(h) Role of Public Sector in Promoting Economic Development of Developing Countries

(i) Relationship between the ESCAP Committee on Population and Committee on Social Development.

(j) Development of Pacific Island Countries.

Refund of Foreign Travel Tax collected by Airlines

6156. SHRI VINODBHAI B. SETH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether foreign travel tax collected by Airlines is not duly refunded to travellers who have not undertaken the journey;

(b) how much is the total collection of foreign travel tax lying with Government;

(c) has Government received any representation from Travel Agents and travellers for refund;

(d) is it true that non-refund of such tax has tarnished our image amongst tourists who prefer to purchase tickets from abroad, and

(e) what steps Government propose to take for immediate refund of foreign travel tax?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) to (e) Under the Law, the Government does not collect the tax from the passengers but collects it from the carriers It is also the carriers who are liable to pay to the Government any tax not paid or under paid or erroneously refunded. Extract of the relevant rule viz. Rule 9 of Foreign Travel Tax Rules, 1971, is at Annexure A [*Placed in Library. See* No. LT-2056/78]. Conversely, any refund of tax due from the Government is given to the carriers. Extract of relevant rules *viz.* Rule 6 and Rule 7 of the Foreign Travel Tax Rules, 1971 are at Annexure B hereto. Total amount of the refund claims made by the carriers in respect of the foreign travel tax and pending with the Customs Houses as on 28-2-1978 is Rs. 50 lakhs (approx.). Bulk of the amount is outstanding on account of non submission of the requisite supporting documents by the applicant carriers. On the other hand, the amount of foreign travel tax arrears due from the carriers to the Government on the same date is Rs. 1.14 crores (approx,). If tickets are purchased abroad or in India against foreign exchange, the travel tax is not leviable at all Representations about the refunds have been received from time to time from the travel agents, passengers etc. and they have been advised to approach the carriers.

Unit Trust of India

6157. SHRI VINODBHAI B. SHETH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether investment of Unit Trust of India is on sound basis;

(b) whether main income of Unit Trust of India is from Deposits and not from Dividends; and

(c) whether it is unproductive investment and needs change in the policy of investment?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M PATEL): (a) Yes, Sir. The unit Trust of India was established in February 1964. The primary objective of the Trust is to encourage and mobilise savings of the community and channelise them into productive corporate investments so as to promote the growth and diversification of the country's economy. The Trust makes investments which are sound, provide good return and have growth prospects. The Trust has been regularly paying dividends under its various schemes

(b) No, Sir The main income of the Trust is derived from investments in equity and preferences shares, debentures and advance deposits The income from fixed deposits for the year ending June 1977 accounts for only about 1 per cent of the total income of the Trust

(c) No Sir

Tourist Potential of Hill Districts of Uttar Pradesh

6158 DR MURLI MANOHAR JOSHI Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state

(a) whether any effort has been made to assess the tourist potential of the hill districts of Uttar Pradesh, and

(b) if so, the details thereof and the steps taken or proposed to be taken to exploit this potential with a view to develop these areas and to attract more tourists there?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) and (b) The Department of Tourism was associated with the Working Group set up by the Planning Commission in 1972 to report on the development of tourism in the U P Hill areas The Working Group report has recommended the development of tourism in six areas of U P hills namely, Nainital, Kausani Mussoorie, Pauri Garhwal, Badrinath-Kedarnath and Gangotri-Yamnotri. Basic to the development of tourism in the U P hill areas however, will be the availability of basic infrastructural facilities such as transportation and comunications adequate and regular water and electricity supply etc

At the suggestion of the Department of Tourism, the State Government has prepared a master plan (land-use plan) of Kausani for ensuring the preservation of the natural beauty of the place through regulated growth

Further, at the instance of the Department of Tourism, the Government of U.P has prepared a perspective plan of tourism development in the State They have proposed accommodation facilities at Badrinath-Kedarnath, Gangotri-Yamnotri, Hemkund, Hardwar, Rishikesh, Kausani, Almora, Nainital and Mussoorie The proposals will be discussed with the State Government at the time of the finalisation of the next Five Year Plan (1978 83) in the Planning Commission when it will be determined which schemes would be taken up in the Central and State Sectors depending upon the availability of resources

जूता उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापार वार्ता

6159. **श्री रामजीलाल सुमन** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार जूता उद्योग को प्रोत्साहन देने के और उसके निर्यात सम्वर्धन के लिये कोई व्यापार वार्ता आयोजित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख) सरकार विदेशों से आने वाले प्रतिनिधि मंडलों के साथ तथा विभिन्न मंचों पर अन्य चीजों के साथ साथ जूता के निर्यात के लिए समय समय पर नीति स्तर की व्यापार वार्ताएं करती रही है। व्यापार योजना देशों के लिए जूतों आदि के निर्यात के लिए विशिष्ट सौदों के संबंध में विस्तृत वार्ताएं राज्य व्यापार निगम की मार्फत की गई हैं। गैर-व्यापार योजना देशों के संबंध में वार्ताएं किसी भी बड़ी निजी पार्टियों द्वारा स्वयं क्रेता विक्रेता आधार पर की जाती है। आयातक

देश की नीतियों के संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए निजी पार्टियां जिन कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाती हैं। उनके संबंध में संबंधित सरकारों के साथ उपर्युक्त रूप में बातचीत करने के प्रयास किये जाते हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पोलिस्टर धागे का मूल्य बढ़ाया जाना

6160. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा पोलिस्टर धागे की कीमत 500 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाई जा रही है,

(ख) क्या पालिस्टर धागे की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप कपड़े के मूल्य में, जो पहले ही बहुत अधिक है, 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहती है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। पिछले बजट में सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क की दरों में संशोधन करने के कारण 75 तथा 150 डेनीयर के पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की कीमतों में केवल 5 रु० प्रति कि०ग्रा० की वृद्धि हुई है तथा 40 और 50 डेनीयर की कीमतों में 20 रु० प्रति कि० ग्रा० की वृद्धि हुई है।

(ख) इस संबंध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई तम्बाकू की मात्रा

6161 **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय।** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में तम्बाकू (विर्जिनिया) उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए तम्बाकू खरीदना आरम्भ कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां तो राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना तम्बाकू खरीदा जायेगा और उत्पादकों को क्या वसूली मूल्य दिया जायगा?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग). (क) और (ख). विर्जिनिया तम्बाकू के प्रमुख उत्पादक राज्य आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक हैं। जो फसल इस समय बाजार में आ रही है वह आन्ध्र प्रदेश में उगाई जाती है। इस फसल में से सरकार के खाते में कोई वसूली नहीं की गई है। तथापि राज्य व्यापार निगम अपने सामान्य वाणिज्यिक कार्यकलाप के रूप में सहकारी क्षेत्र और लघु तथा मध्यम पूर्तिकर्ताओं से अपने खाते में और अपनी जोखिम पर 5,000 मे०टन ग्रेडिड और एगमार्क तम्बाकू खरीद रहा है। राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने पूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्यात कीमतों पर आधारित हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरों के साथ धोखाधड़ी

6162. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 13 मार्च, 1978 के "नव भारत टाइम्स" के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित

उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है, जिसमे जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी होल्डरो का धोखा देने की बात कही गई है।

(ख) क्या यह सच है कि उक्त समाचार मे दी गई जानकारी के अनुसार जीवन बीमा निगम ने व्यपगत पालिसियो के बारे मे शर्तों का तीन वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष करने के बारे म काई प्रचार नही किया गया था, और

(ग) यदि हा तो वर्ष 1976-77 और 1977-78 म दस हजार रुपय से अधिक मूल्य की कितना पालिसिया दिल्ली मे व्यपगत हो गई थी?

वित्त मत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) जी हा।

(ख) जी नही। वह समाचार उस परिवर्तन के बारे म है जो जीवन बीमा निगम ने 1-1-76 अथवा उसके बाद जारी की गई पालिसियो के सबध म चुकता पालिसियो के भुगतान की शर्तों म किया था। पहले यह शर्त थी कि चुकता पालिसी तभी देय होगी यदि पालिसी का प्रीमियम 3 वर्ष तक दे दिया गया हो, 1-1-76 **को अथवा उसके बाद जारी की गई पालिसियों** के बारे मे यह शर्त है कि चुकता पालिसी तभी देय होगी यदि पालिसी का प्रीमियम 5 वर्ष अथवा पालिसी के प्रीमियम अदायगी की मूल अवधि के एक चौथाई वर्षों तक (कम से कम 3 वर्ष तक) जो भी कम हो दिया गया हो।

निगम ने यथा समय इस परिवर्तन की सूचना कार्यालय परिपत्रो, गृह पत्रिकाओ और समाचार बुलेटिना द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियो (विकास अधिकारी और एजेंट) को दे दी थी।

(ग) 1976-77 के दौरान दिल्ली मे 22,142 पालिसियां व्यपगत हुई लेकिन इसका कारण पालिसी की शर्तों मे परिवर्तन नही था। 1-1-76 को अथवा उसके बाद जारी की गई पालिसियो पर इस परिवर्तन का प्रभाव पालिसियो के चालू रहने के चौथे और पाचवे वर्ष मे देखा जा सकेगा और इसलिए इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन पालिसिया मे से काई पालिसी 1976-77 अथवा 1977-78 के दौरान व्यपगत नही हो सकती।

पश्चिमी एशिया के देशो को वस्तुओं का निर्यात

6163. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पश्चिम एशिया के देशो को किन-किन वस्तुओ का निर्यात किया जा रहा है,

(ख) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान कुल कितने मूल्य के सामान का निर्यात किया गया; और

(ग) गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वित्तीय वर्ष मे इस व्यापार मे कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) पश्चिम एशिया के देशो को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओ की एक विवरण सलग्न है

(ख) 1976-77 542 करोड रु०

1977-78 264 करोड रु०

(अप्रैल-सितम्बर 1977)

सितम्बर 1977 के बाद की अवधि के निर्यात आकडे अभी उपलब्ध नही है।

(ग) 1977-78 के पहले छ महीना मे पश्चिम एशिया के देशो के निर्यात मे,

1976-77 की उसी अवधि की तुलना म 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विवरण

पश्चिम एशिया के देशो को निर्यात की जा रही प्रमुख वस्तुओं की सूची

मास तथा मास उत्पाद

मछली तथा मछली उत्पाद

अनाज और उससे तैयार की गई वस्तुए

फल

सब्जी उत्पाद

इमली सूखी

चाय

काफी

मसाले

तम्बाकू

चीनी

बैराइटीन बेटानाइट

रासायनिक तत्व तथा यौगिक

विस्फोटक पदार्थ

रग रोगन तथा वार्निश

रगने तथा कमाने की सामग्री

औषधीय तथा भेषजीय उत्पाद

सुगन्धित पदार्थ तथा प्रसाधन सामग्री

साबुन

प्लास्टिक का माल

रबड का माल

काष्ठ तथा कार्क का माल

कागज तथा कागज उत्पाद

सूती माल हथकरघा तथा मिलनिर्मित दाना

कपडा

तिरपाल

कपडे के थान

पटसन उत्पाद

फर्श बिछावन

एसबेसटास उत्पाद

काच का सामान

बहुमूल्य रत्न

लोह अयस्क तथा इसके सान्द्रण

लोहा तथा इस्पात

इस्पाती ट्यूब तथा पाइप

धातुओ से बनी वस्तुए

मशीनरी विद्युत तथा गैर-विद्युत दाना

वैज्ञानिक यत्र

सडक मोटर गाडिया

परिवहन उपस्कर

सैनिटरी फिटिंग्ज

सिरामिक टाइले

बिजली लगान के फिक्शचर तथा फिटिंग्ज

फर्नीचर

हस्तशिल्प की वस्तुए

आभूषणो की मदे

खेलकूद का सामान तथा खिलौने

मुर्गी पालन उत्पाद

पशुओ के लिए पोषक उत्पाद

रूपक चित्र

चमडे का माल

जूते

रेयन के गैस मटल

कुटीर उद्योगों के लिए हरिजनों को ऋण

6164 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों को कुटीर उद्योगों के ऋण देने हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई परियोजना आरम्भ की जायगी और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) बैंक कमजोर वर्गों को उत्पादक कार्य जिनमें कुटीर उद्योग भी शामिल है शुरू करने के लिए अधिकाधिक ऋण सहायता दे रहे हैं। हाल ही में उद्योग मंत्रालय ने एक नयी योजना आरम्भ की है जिसका उद्देश्य 'मार्जिन" तथा सीड पूंजी के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वह छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने की अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सकें। इस योजना में ऐसे एककों को मार्जिन धन देने की व्यवस्था है जिनमें मशीनरी और मशीनों के लिये किये गये निवेश 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उद्यमियों के मामले में सीड पूंजी सहायता कुल स्थिर पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अथवा 20 हजार रुपये (इनमें जो भी कम हो) तक होती है जबकि दूसरे मामलों में यह सीमा कुल निवेश का 10 प्रतिशत होती है। आशा है कि राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली इस योजना के कार्यान्वयन के साथ, समाज के कमजोर वर्गों को विशेषतः हरिजनों को मिलने वाले ऋण में वृद्धि होगी।

श्रीलंका के साथ आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए नया समझौता

6165 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में श्रीलंका का एक प्रतिनिधिमण्डल भारत में दौरे पर आया था,

(ख) क्या भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कोई नया समझौता किया गया है, और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) श्रीलंका सरकार के वित्त और योजना मंत्री श्री रानी डी मेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल 11 जनवरी 1978 से 14 जनवरी 1978 तक भारत के दौरे पर आया था।

(ख) और (ग) श्रीलंका द्वारा भारत से खरीदी जाने वाली भारी मशीनरी और अनुवर्ती वस्तुओं की वित्त व्यवस्था के लिए श्रीलंका की सरकार के साथ 24 जनवरी, 1978 को 10 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत सरकार ने श्रीलंका को 50,000 मेट्रिक टन गेहूं का ब्याजमुक्त वस्तु ऋण देना भी स्वीकार कर लिया है जिसकी वापसी अदायगी वस्तुरूप मे की जाएगी। इस बारे मे करार पर अभी हस्ताक्षर नही किए गए है।

Janta Hotel at New Delhi

6166 SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA·

SHRI SAUGATA ROY.

Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) if there is any proposal to instal a Janata Hotel in New Delhi;

(b) if so, the expenditure involved and accommodation therein; and

(c) when the above mentioned hotel will be ready?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) (a) Yes, Sir

(b) and (c). The 250-bed Janata Hotel at New Delhi will be constructed at a cost of Rs 300 lakhs Work on this project will commence shortly, and is likely to be completed in two phases, within a period of to two to three years

Foreign Fellowships/Scholarships for Non-Technical Government Servants

6167. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state·

(a) whether it is a fact that most of the foreign fellowships/scholarships (for one academic year) which are meant for non-technical Government servants belonging to the IAS, Central Services, IES/ISS etc. and which are finally decided by the Department of Economic Affairs are given to the IAS Officers;

(b) what was the number of officers sent abroad on such fellowships during 1976-77 and 1977-78 (till February, 1978); and

(c) what was the number of IAS Officers in each year i.e. 1976-77 and 1977-78 (till February, 1978)?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) to (c). During 1976-77 and 1977-78 (upto February 1978) 31 and 38 non-technical officers respectively were awarded foreign fellowships for one academic year Of these the number of IAS officers was 15 and 24 respectively in the two years

Deposits of Governmental Institutions in various Banks in Karnataka

6168. SHRI K LAKKAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the number of deposits of Governmental institutions in various banks in the State of Karnataka during the last one year; and

(b) the names of such depositors and the amounts of deposits?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b) The Reserve Bank of India have reported that under the existing arrangements for collection of statistical data from banks information in the required manner is not collected

Warrant of arrest against an Industrialist belonging to Singhania House

6169. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2316 on the 10th March, 1978 regarding "arrest warrant against an industrialist belonging to Singhania House" and state:

(a) what were the specific charges against Shri Bharat Hari Singhania for which arrest warrant was issued against him by the Commissioner of

Police, Calcutta under Internal Security Amendment Ordinance, 1974; and

(b) the reasons why a fresh arrest warrant was not issued against him after enactment of COFEPOSA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL) (a) Shri Bharat Hari Singhania was ordered to be detained by the Commissioner of Police Calcutta under Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance 1974 with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the conservation of foreign exchange Since the detention order was issued by an empowered officer of the Government of West Bengal, the grounds on which the order was issued by the Commissioner of Police, Calcutta are available with the State Government of West Bengal

(b) No order of detention was issued under the provisions of Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act 1974 in respect of Shri Bharat Hari Singhania as this was not found to be a fit case for detention

डी० सी० एम० तथा इसकी सहायक मिलों द्वारा आय कर का भुगतान

6170 **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान दिल्ली क्लाथ मिल तथा इसकी सहायक मिलों तथा फैक्टरियों द्वारा कितने आयकर का भुगतान किया गया और उनके द्वारा कितना आयकर अभी दिया जाना है और

(ख) क्या उनके द्वारा कर अपवचन की कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कम्पनी लि०, दिल्ली द्वारा (जो बहुत सी मिलों और कारखानों की मालिक है) वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान अदा की गई आयकर की कुल रकम, 4 करोड 42 लाख रुपये थी। 31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार, उक्त कम्पनी की तरफ कोई कर बकाया नहीं थे।

(ख) जी, हां। इस मामले की जांच की जा रही है।

12.00 hrs

SHRI KRISHAN KANT (Chandigarh) I did not want to raise any point of order during the Question Hour So, I did not ask at that time And you went on to the next Question The question here is this You are here to give protection to Members and also protection to the Government if something goes wrong

The point raised by Mr Kushwaha, I think was very valid Here is the question dated the 9th December The question was

> "The reasons why the treasure recovered in Jaipur from Jaigarh and Moti Doongari, etc, was not deposited "

Both those things were mentioned in the question dated the 9th December Now, see the reply given by the Government

> "Excavations for locating hidden treasure were undertaken only at Jaigarh Fort"

Today's question was about Moti Doongari And the Minister, Shri Zulfiquarullah, is giving us this sort of reply Here you should protect us The Ministry was completely wrong in saying that earlier nothing was available in Moti Doongari and today they say that from Moti Doongari not available in 1977—on 5-6-1975 and 10-6-1975

MR. SPEAKER: I am on my legs...

SHRI KRISHAN KANT: Let me complete it, Sir.

MR. SPEAKER: I am on my legs. You are a senior Member of the House, Direction 115 clearly says:

> "A ember wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a Minister or any other member shall, before referring to the matter in the House, write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek his permission to raise the matter in the House".

Please write to me first.

SHRI KRISHAN KANT: This is not something said during a statement—when a statement is made by him. This was during the Question Hour. If every time a Minister gives a wrong answer and I write to you, the Members will have no right to ask supplementaries....

MR. SPEAKER: Then you can raise it in the House. That is what is provided for.

SHRI KRISHAN KANT: I will meet you in the Chamber. The rule which you have read out is not relevant for the Question Hour.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): On a similar question, I seek your protection, Sir. I have given notice of a call-attention motion also. This is about the kidnapping of a girl from Nadia district, who is now in Bangladesh. I was not allowed to raise it...

MR. SPEAKER: I think, the Professor should confine himself to relevancy. If there is anything he wants to raise, he should give notice to me.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I have given notices. This has appeared in a daily. A girl, aged about 13 years, was kidnapped and tortured in Bangladesh, in an adjacent district, Kushtia. I have given notice of questions, I have given notice of call-attention motion; I have not been permitted. I have given notice to raise it under rule 377; I have not been permitted. What should I do?

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): I have given notice of an Adjournment Motion on firing of workers in Baladilla project of National Mineral Development Corporation in the tribal-infested district of Kirundel A large number of our friends have also given notice of call-attention motions on this. I rise to point out to you the attitude of the Ministry of Steel and Mines towards its workers. First, there had been firing on the workers in Baladialla. Yesterday there was lathi-charge on workers. *(Interruptions)* After we asked a question in Parliament, yesterday there was a lathi-charge on workers in Khettri, Hindustan Copper Mines, on which we debated in this House. If this is the attitude of the Ministry of Steel and Mines, I think, there will be no peace anywhere

MR. SPEAKER: I have allowed a call-attention motion on this This has already been listed. And I have also informed you about it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): With your permission, Sir, I would like to make a submission. You just quoted a rule when the question was raised by Mr. Krishan Kant. I agree with you that, normally, this is the procedure: if there is an inaccurate answer given by the Minister, the Member should write to you. Suppose I do something wrong while questioning the Minister, you can stop me. It is your right and we cannot question you. But at the same time, if the Minister is not giving the proper reply, do you expect the Members every time to write to you?

MR. SPEAKER: Mr. Gupta, if a proper reply is not given...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Please give me a minute and I will finish: and your verdict will be final.

In this case it is not an inaccurate answer: it is completely wrong answer. Two days back I asked a question about tribal areas but the figures were given for 1972-73...

MR. SPEAKER: We are on one thing and you are now raising a point on some other question.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: This has been the practice . (*Interruption*)

MR. SPEAKER: You are merely rising to raise some objection. Why don't you follow the rules?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: It is the practice of the Ministers that they don't do their homework and reply accurately. So, you have to safeguard the right of the Members: that is my contention.

MR. SPEAKER: All right. (*Interruptions*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You should direct the Ministers to give proper replies to questions. Kindly do this. Unless you protect us we cannot...

MR. SPEAKER: I have to protect myself against some of you. Every time, you raise a point of order or a point of submission or some other point. Please follow the rules.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Sir, just one submission.

MR. SPEAKER: You have made one submission already. Now, Papers to be laid.

12.10 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS OF MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION FOR 1978-79

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of Ministry of Agriculture and Irrigation for 1978-79. [*Placed in Library. See* No. LT-2029/78]

12·10½ hrs

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, what about the question of privilege.

MR. SPEAKER: That comes after Papers Laid.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: No sir, it comes before Papers Laid. Please consult the Directions.

MR. SPEAKER: I have called for a report from the Editor, and that is the standing practice. If you want I have got all the records and . .

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: But the question has to be raised in the House. The House has to know the nature of the offence: and then, of course, you can say that you have called for an explanation from the person concerned. First the House has to know at the earliest what kind of offence has been committed. It is the practice in the House of Commons and also here that at the earliest opportunity, the House has to know the nature of the offence that has been committed. So, my submission is that you may kindly allow me to place before the House what kind of offence has been committed and what kind of injury has been done, and then you can of course say that you have called for an explanation from the person concerned.

MR. SPEAKER: The practice here is...(*Interruptions*). Please! I am referring to the Directions and Rules.

The practice here is—I don't know what the practice in England is—and it is a well-established practice, that if a newspaper reports inaccurately the proceedings of the House or makes comments casting a reflection on the House or a Member, the Speaker may, in the first instance, give an opportunity to the Editor of the Newspaper to present his case before giving his consent to raising the question of privilege in the House. The Speaker normally withholds his consent to the raising of the question of privilege after the Editor or Press Correspondent of the Newspaper concerned has expressed his regret for publishing it. That is up to me, later; but the earlier procedure, which is a well-established practice, is that we should call for such comments because we should know the other side of the picture. *Prima facie*, whatever you have said may be correct, but I must give the other side also an opportunity.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: That can be only in extenuation of the offence. But here the offence is so clearly established that there is no need for calling for an explanation from the person concerned. Can there be another version of this? I have the document...

MR. SPEAKER: Quite right, but in our country we do not act arbitrarily. Either the Parliament or the Speaker should not act arbitrarily.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Would it be your pleasure to ask me to give you instances where the question had been allowed to be raised and then the Chair had said that he has called for an explanation? I can quote a number of instances.

MR. SPEAKER: Let us see later. I have called for a report and probably in a day or two we will get the report.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: But let it be quite clear that whatever explanation is offered by the other side, it cannot be in extenuation of the offence. I am not going to allow the matter to rest there because injury has been done and an offence has been committed, and it is so deliberate and patent that I will have to make this clear. No amount of explanation from the other side can be entertained by the Chair so far as the offence is concerned. That is my contention.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Sir I am referring to proviso to Rule 225 and I hope that you will make a liberal interpretation of this particular proviso—not a narrow interpretation but a liberal interpretation. My Hon. friend Shri Mishra is quite right when he raised this point There are two provisos to Rule 225 and the first proviso says that if the Speaker does not give his consent, he may, if he thinks it necessary—I hope he thinks it necessary in this case (that is why I said 'liberal interpretation')—he may read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order.

MR. SPEAKER: Quite right: before refusing it, that procedure will be followed. If I am refusing it, I will certainly follow that. At this stage, I have merely called for an explanation.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Your ruling, I submit in all humility, is incomprehensible.

MR. SPEAKER: How? The proviso says that before I refuse I may read out to the House. It is 'before I *refuse*': I have not refused it at all. You have not followed Mr. Kamath. I have not refused permission. I have called for an explanation from the Editor and I will thereafter consider it. That is what I have said—and that is a well-established practice in this House.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Is the position now that you have neither withheld your consent nor given your consent? Is it hanging fire?

MR. SPEAKER: I have not refused: it is under consideration.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): About the submission I made before you, when do I get your permission to raise the issue?

MR. SPEAKER: I don't know why everybody wants to make himself felt in the House'

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I tried to contact you yesterday and day before you can ask your bearer

---

श्री सुरेन्द्र विक्रम : (शाहजहापुर)। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नो के सम्बन्ध मे मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले मे जगलो मे कुछ विदेशी राजनयिकों द्वारा शिकार किए जाने के सम्बन्ध मे दिया था। वहा पर राजनयिको द्वारा बिना परमिशन लिए क्लोज्ड सीजन मे चीतल का शिकार किया गया जिस की शिकायत वहा की सरकार के अधिकारियो ने केन्द्रीय सरकार से की है। इसके बारे में मैंने प्रश्न दिया तो आपके सचिवालय के प्रश्न विभाग के अधिकारी मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि विदेशी राजनयिकों के बारे में इस तरह से प्रश्न पूछने की परम्परा नही रही है, इस वास्ते मेरा प्रश्न स्वीकार नही हो सकता है। वे लोग हमारे यहां के नियम तोड़ें और हम उसके बारे में प्रश्न पूछ कर जानकारी भी न ले सकें तो हम से बड़ा नालायक कौन होगा? अत: प्रश्न स्वीकृत हो।

MR. SPEAKER: Everybody who gives a question has a right to raise it in the House, is it? Every question is being considered in accordance with the rules. If you have any doubt about it, you can come and discuss. After putting a question you cannot again raise the matter here. I don't know whether you are a new Member or an old one, but if your question has not been selected, it may be that the ballot has not favoured you. Or if it has not been admitted, you will be informed. We can discuss this, but it should not be raised in the House.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Sir, I would like to know whether you have given any time to the Editor within which he should submit his explanation.

MR SPEAKER: I have said 'Immediately'.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: That is, by Monday...

MR. SPEAKER: If we don't get it by Monday, we will see. But I am sure we will be getting it before Monday

---

12.14 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

SHRI K P UNNIKRISHNAN (Badagara): Sir, regarding Item No 3(2)(i) and (ii), this should have come before Parliament, as was the normal practice, in the last July session itself because these accounts relate to the year 1975-76. Now, here he comes before the House even without a statement of reasons for the delay. This has become the normal practice in this House and I am sorry you are permitting it instead of asking him to produce the reasons for the delay. This House cannot be taken for granted like this. This has become the normal feature here: they bring forward any account relating to any period and without even a statement explaining the reasons

[Shri K. P. Unnikrishnan]

for the delay. And you are permitting it to be laid on the Table of the House. I want a ruling on this.

MR. SPEAKER: Why have you not given the reasons?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : पहले भी मैंने निवेदन किया था कि इन रिपोर्टस को प्रस्तुत करने में सिर्फ हिन्दी वर्जन लेट आने के कारण ही दिक्कत होती है : अध्यक्ष जी, मैंने आपको पहले भी कहा था। इसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हू कि मैं मालूम कर लूगा कि इसके अलावा भी कोई और डिले का कारण है।

MR. SPEAKER: Even if that is so.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह जो बारबार हिन्दी वर्जन की बात की जाती है तो इसका इंतजाम क्यो नही करते हैं।

MR. SPEAKER: Why don't you wait till I finish? I was putting a question to the Minister. Would you not allow me to do that? Should your question have a priority over mine?

Mr. Minister, even if that is so, under the rules you must give an explanation. I do not know whether your reason is good or bad; even if you have good reason, you must give an explanation.

श्री आरिफ बेग : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, और ऐहतियात रखूंगा कि इस प्रकार में ऐक्सप्लेनेशन आपके सामने आते रहें।

MR. SPEAKER: Mr. Unnikrishnan, whenever you want to raise any such objection, you must send me notice earlier.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: But please do direct the Minister...
(*Interruptions*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): My friend, Shri Unnikrishnan, raised this question and you made an observation on that. You have made this observation many times on this issue. The rule for this is and we have made recommendations many times that along with the audit report, the review should come and the reasons for delay, if any, should come. We have given this recommendation not once, but at least ten times, to every department of the Government, but in spite of this, neither the review comes nor the reasons for delay come and the delay sometimes is for five-six years. My submission is that you may kindly direct the Government, not only this Ministry. This happens with every Ministry. We have lot of files on this matter and our difficulty is how to dispose them of.

MR. SPEAKER: A number of times, I have directed them in the House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: They even do not read the recommendations of the Committee.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा यह कहा जाता है कि हिन्दी वर्जन नही आया। तो हिन्दी का स्टाफ क्यो नही रखा जाता है ताकि हिन्दी वर्जन साथ ही आ जाये। हिन्दी का स्टाफ यहां नहीं है इसलिये साल, 6 महीने की देरी हो जाती है। तो आप हिन्दी स्टाफ का ज्यादा प्रबन्ध करें ताकि दोनो वर्जन साथ ही आ जाया करें।

श्री राम अवधेश सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर हाउस में बहस होनी चाहिये। क्योंकि जनता पार्टी ने कहा है कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट लागू की जायेगी। लेकिन हाउस के बहुत से सदस्यों को अभी तक मालूम नहीं

है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट पर बहस करायी जाये और मैं कम से कम चार दिन की बहस की मांग करता हूं मैंने नियम 184 के अन्दर नोटिस भी दिया।

MR. SPEAKER: Mr. Singh, you seem not to know the rules. You can give a motion under Rule 184, you can give a motion under Rule 193; You cannot jump up and speak.

श्री राम अवधेशसिंह : नियम 184 मे मैंने नोटिस दिया है और मेरी मांग है कि उस पर बहस हाउस मे करायी जाये क्योंकि बहुत से मदस्यों को भी मालूम नहीं है कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट क्या है।

MR. SPEAKER: Do not record.
*(Interruptions)***

ACCOUNTS AND AUDIT REPORT OF TEXTILES COMMITTEE, BOMBAY FOR 1976-77, REVIEW ON THE WORKING AND ANNUAL REPORT OF HANDICRAFTS AND HANDLOOMS EXPORTS CORPORATION FOR 1975-76 ETC.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Certified Accounts (Hindi and English versions) of the Textiles Committee, Bombay, for the year 1976-77 and the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 13 of the Textiles Committee Act, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-2030/78].

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619 A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1975-76.

(ii) Annual Report of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 1975-76 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-2031/78].

(3) A 'Corrigendum' to the Certified Accounts* of the Textiles Committee, Bombay, for the year 1975-76. [*Placed in Library. See* No. LT-2032/78].

(4) A statement (1) correcting the reply given on the 16th December, 1977 to supplementary questions by Dr. Vasant Kumar Pandit and Shri Shiv Sampati Ram on Starred Question No. 453 regarding closure of Bone Mills and (ii) given reasons for delay in correcting the reply. [*Placed in Library See* No. LT-2033/78].

SOLVENT EXTRACTED OIL DE-OILED MEAL AND EDIBLE FLOUR (CONTROL) AMENDMENT ORDER, 1978

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत विलायक निस्सारित तेल, तेलरहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 18 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 177(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[*Placed in Library. See* No. LT-2034/78].

**Not recorded.

*The Accounts were laid on the Table on the 15th July, 1977.

NOTIFICATIONS UNDER CENTRAL EXCISE RULES, 1944 CENTRAL EXCISE (6TH AMDT) RULES, 1978, NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT 1962 AND DELHI SALES TAX (1ST AMDT) RULES, 1978 ALONG WITH A STATEMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) I beg to lay on the Table

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Central Excise Rules, 1944 —

(i) G S R 204 (E) and 205 (E) published in Gazette of India dated the 30th March, 1978, together with an explanatory memorandum

(ii) G.S R 206 (E) published in Gazette of India dated the 31st March 1978

(iii) G S R 208 (E) published in Gazette of India dated the 31st March 1978 [*Placed in Library See* No LT 2035/78]

(2) A copy of the Central Excise (Sixth Amendment) Rules 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No G S R 207 (E) in Gazette of India dated the 31st March, 1978 under section 88 of the Central Excises and Salt Act, 1944 [*Placed in Library See* No LT-2036/78]

(3) A copy of Notification No G S R 220 (E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 1st April, 1978 under section 159 of the Customs Act 1962 together with an explanatory memorandum [*Placed in Library See* No LT-2037/78]

(4) (i) A copy of the Delhi Sales Tax (First Amendment) Rules, 1978 (Hindi and English versions) published in Notification No F 4(2)/78-Fin (Genl) in Delhi Gazette dated the 16th February, 1978, under section 72 of the Delhi Sales Tax Act, 1975

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification [*Placed in Library See* No LT-2038/78]

12.20 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED INDEFINITE TOOLS DOWN STRIKE BY WORKERS PARALYSING WORK AT THE VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE AT THUMBA

SHRI M RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon

The reported indefinite tools down strike by workers paralysing work at the Vikram Sarabhi Space Centre at Thumba

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) Mr Speaker, Sir, I am obliged to the Hon Member for having raised the question before the House which enables me to put the whole matter in its proper perspective and show how oblivious of the country's interests in keeping such an undertaking ontinously in operation a section of the employees on a question of minor importance is prepared to hold the Space Centre, and through them the Government to ransom

The whole trouble arose as a result of the implementation of the decision of the Space Commission to rationalise transport charges and prescribe uniform rate of subsidy for plate meals in all Indian Space Research Organisation canteens The House will be interested to know that in other ISRO Centres at Sriharikota, Bangalore and Ahmedabad this

scheme has been implemented without any agitation on the part of the employees At the Vikram Sarabhai Space Centre, Thumba, however, an agitation was mounted by the employees on Saturday the 1st April and on the morning of Monday the 3rd April there was violent agitation, stone throwing and assault and intimidation of engineers outside the Rocket Fabrication Facility The workers attacked the factory and caused extensive damage to plant equipment, machinery and other Government property A detailed assessment of the quantum of damage is being made

Faced with this situation and in fulfilment of their duty to maintain law and order the State Government police and the local Additional District Magistrate intervened but the position was not brought under control until as a result of stone throwing the magistrate of the State Government was injured and hospitalised

SHRI K P UNNIKRISHNAN (Badagara) Why magistrate of the State Government?

SHRI MORARJI DESAI Arising out of this some employees have been arrested in connection with the violent incidents and three cases for investigation in connection with the assault on the Additional District Magistrate and damage to Government property have been registered Shri Oomen Chandy, Minister for Labour, Government of Kerala interceded and held separate discussions with the Controller, VSSC, and the representatives of the workers Among the points raised by the employees were

1 Shifting the location of X-Ray and Radiographic units at the Rocket Fabrication Facility in view of alleged violation of safety and health standards I may state that the whole question has been examined in great detail by an expert of the Bhabha Atomic Research Centre who went into the question for three days and reviewed all the safety precautions and was satisfied that there was no radiation hazard whatsoever which would constitute a health risk

2 Reduction in the cost of plate meals from Re 1/- per plate meal to the earlier price of sixty five paise This is the second point It was explained that a uniform subsidy not exceeding thirty five paise per plate meal had been fixed whereas previously the quantum was larger and there was no limit on the amount of food served on a plate meal. Nevertheless the Centre authorities expressed readiness to make necessary adjustments and lower the price of the plate meal subject to a corresponding reduction in the quantum of the food elements that constituted the plate meal

3 Restoration of salary cuts effected on account of unauthorised absenteeism in earlier agitations Since the principle of No work no pay has been well established the position was explained to them and since they have absented themselves deliberately the same principle would have to be applied

The House will notice that notwithstanding the resort by a section of the employees to violence the Centre authorities adopted a conciliatory attitude but the only response has been for the employees to go on strike and see that no activity worth the name takes place in the Centre The employees however are not only continuing their strike but the employees who want to work are being prevented from functioning and are being forced out of their offices It is understood that two cars belonging to the Centre have already been destroyed by the agitators

I have stressed more than once the obligation on the part of both employers and employees to settle points of dispute by resort to negotiations It is quite clear that in this case the employees have chosen the path of violence and indulgence in damage to public property They have failed to recognise that by causing damage they were not caus-

(Shri Morarji Desai)

ing injury only to the individuals, officers or otherwise, but to the country itself, because the factory is undoubtedly of vital importance and is an asset to the institution It is reprehensible that in order to force the authorities into conceding their demand the employees have lost sight of their obligations to the very properties of the Centre on which and in respect of which their work depends I cannot but strongly condemn this attitude of the employees and I should like to make it clear to the House that there can be no submission to such tactics of violence and wanton injury to public property I understand that an Hon Member of the House is in Trivandrum and that three meetings were held outside the premises of the Centre yesterday after the permission for holding meetings within the premises had been refused This was followed by a meeting in the city at which the employees were asked to continue their illegal strike I am also informed that some employees are dragging staff out and indulging in coercion and intimidatory action to the point of even cutting of water and elecriticity Obviously we have to deal with these activities with firmness If per chance violence is again repeated, there would be no alternative but to take measures to protect Government property and to deal with the situation with such force that may be required and may be at our disposal

SHRI M RAM GOPAL REDDY: I am grateful to the Prime Minister for having made a detailed statement But I want to say that our Prime Minister is the greatest Gandhian living in this country Sometimes the sanest persons and the credulous persona are also made to utter, if not lies, at least untruths, half truths In Mahabharat Yoddha, Dharmaputra's chariot used to move in the battle field about one foot above the ground level Here our Prime Minister is made to uttar at least some half truths and now he has come down to the level of all other Members of this House

Now, here the main point is the workers wanted only food subsidy as was existing for the last six years.

SEVERAL HON MEMBERS Transport.

SHRI M RAM GOPAL REDDY Both

Transport was given to the persons working there The Vikram Sarabhai Station is situated about twenty miles away from the main city There is nothing available in that area and in such places the people working there should be given full meals The Prime Minister says that you pay for the half But they cannot work on empty stomach

He is very much interested in the factory We are also interested in the factory But I want to know from the Prime Minister, is he not interested in the workers who are working there? Those workers are working in the factory for the last six years There was not a single strike

Why, all of a sudden, has this erupted? I request the Prime Minister to go into details and find out why it has happened and, the Prime Minister also referred to an hon Member of this House, that is, Mr Vayalar Ravi He is an experienced trade union leader, he is also very much interested in this country and in the plant and unnecessarily he will never ask the workers to go on strike As a matter of fact, the strike was forced by the inefficient officers and engineers who are not working upto efficiency required These officers and engineers have prompted the administration to stop the transport and also the subsidy for food Is it right on the part of the Government to stop these two things which are very vital for the maintenance of good health? Moreover the X-ray plant established near the workshop can be shifted to some other place But, the Prime Minister says that it was examined by the experts of the Bhabha Atomic Research

Station for three days. Is it enough? Many of the workers are not having children due to radioactivity and their health is also affected. I want to know from the Prime Minister whether he wants to reduce the population by this method. I request him to reconsider the whole issue and not to paralyse the work there and he may immediately start negotiations with the workers. The State Government was ready to mediate in this. Mr. Chandy was doing his best but the management and the Central Government are very adamant They are not at all listening to reason That is why the trouble has arisen. I want to know whether the Prime Minister will leave the entire case to the State Government officials who are responsible persons?

MR SPEAKER I think it is enough.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Please allow him He is suggesting some solutions

SHRI M RAM GOPAL REDDY The State Government is in a position to control the situation. There is a feeling that the Central Government is trying to discredit the State Government and they are not allowing them to do their job There is absolutely no necessity to send the military there That is the provocation to the people After all they are numbering 1 000 or 1,200 workers or so. When the State Government is controlling it, why has the Centre chosen to send the military there You know, Sir, the military people may not be able to understand the local conditions. That was the reason why all these things had happened. That is why I request the Prime Minister to reconsider the whole issue and let him send the Labour Minister to the spot and see that he settles this dispute.

SHRI KRISHAN KANT (Chandigarh): Sir, I rise on a point of order for your consideration. The statement which he has made—he talked of truths and half truths and then he said that the Prime Minister has come down to the level of a Member—can be a matter of privilege. Are we, Members, speaking half truths? He is degrading himself by that. I would request you to go through it so that such a statement which can be a matter of privilege—he does not mean it because he does not know what he speaks—does not find a place in the proceedings. (*Interruptions*).

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): There must be some doubt because the Prime Minister was reading the statement. So, he only said the Prime Minister has come down to the level of a Member. (*Interruptions*).

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: He said that it contained half-truths and untruths This is what he was saying.

MR. SPEAKER: The point raised by Shri Krishan Kant is not about the half-truth or untruth. Shri Reddy might have said it in a jocular mood He said that he was at a very high level at one time and he has now gone down to the lower level. This is what he said. I think he said it in a jocular mood. Let us not take it seriously. We are not small men to take it like that.

SHRI C. N. VISVANATHAN (Tiruppattur). Members are not at lower levels.

MR. SPEAKER: He said that in his jocular mood.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I never wanted to drag our Prime Minister to the level of an ordinary person. I did not mean any offence.

SHRI MORARJI DESAI: I am very grateful to my hon. friend for giving me a compliment at his own cost. But may I say I do not consider myself above the Members of this House? I cannot I am as good or as bad as

(Shri Morarji Desai.)

any other member in the House. But after having given me the compliments about my faith in Gandhian philosophy he charges me with having believed half-truths but adds that I am made to utter them. It is good of him to say that I was made to do it. But that means I am very credulous; that I believe readily in what they say and that I make statements which are half-truths. Can he say that whatever he has said is true? But he has already accepted that what Members are doing is very wrong. I can not support him because nobody does that knowingly. It is possible that I may have been wrongly informed. If the hon'ble Member gives me details, I will make enquiries and punish the officer who gave me wrong information. But will the hon'ble Member apologise if he is wrong? I would expect that. But even if he does not do that, I will do my part. Let me say that. Because my doing my part does not depend upon whether another man does his. But in this case does he not see that the Labour Minister of Kerala Government was there, their Additional Magistrate was there and they are aware of the situation. They tried to negotiate with them But he was injured. Why does he not see that? Whatever may be the rights or wrongs of the employees, they have no right to resort to violence under any circumstances whatsoever. That cannot be condoned. I will have to ask for damages from them for all the loss to the property because they have caused it. What would he have to say then? Therefore, why does he encourage such things by this method of supporting them. This is not right. This is not at all a correct thing to do. And, therefore, there is no question of not going into that. Already they want to consider and talk to them but until they go back to work and give up these methods, I am going to instruct them not to have any talks with them.

SHRI SAUGATA ROY: Is it a fact that the Prime Minister has written to the State Chief Minister asking him to withdraw the recognition or de-recognise the union led by Mr. Vayalar Ravi? If so, does it behave the Prime Minister? (*Interruptions*)

SHRI MORARJI DESAI: There are no union activities in this Centre. These are scientific installations. There cannot be any union activities.

SHRI SAUGATA ROY: Sir, is it a fact that the Prime Minister has written to the State Chief Minister to de-recognise the union led by Mr. Vayalar Ravi?

MR. SPEAKER: This is a separate matter. The Labour Minister will deal with this matter and not the Prime Minister. This is Call Attention motion

(*Interruptions*)

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Will you unilaterally withdraw the recognition given to a union?

SHRI MORARJI DESAI: I have written to the Chief Minister that these scientific installations do not fall under industrial relations.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Mr. Speaker, Sir, may I request him to withdraw the troops· he has not said anything about it, I request him to tell us whether he is going to withdraw the troops and also start negotiations with the workers.

MR. SPEAKER: He has already said it.

SHRI MORARJI DESAI: No military has been called; it is a lie. Until this morning there was none. If it was called in afterwards I do not know.. (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I have to accept what the hon Ministers say.

SHRI SAUGATA ROY: I repeat my statement about the military... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Let us go to the next business. Shri Saugata Roy.

12.41 hrs.

PETITION RE ENQUIRY INTO AFFAIRS OF CONTAINERS AND CLOSURES LIMITED AND ITS NATIONALISATION

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) I beg to present a petition signed by Shri Raghunath Ghosh, General Secretary Containers and Closures Staff and Shramik Union Gorifa 24—Parganas regarding enquiry into affairs of the Containers and Closures Limited and its nationalisation

---

12.41½ hrs

STATEMENT RE REOPENING OF RAILWAY SPONSORED STUDENTS' HOSTEL AT PATNA JUNCTION

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दण्डवते) : अध्यक्ष महोदय, कल श्री राम विलास पासवान ने मई 1974 मे पटना मे रेलवे सहायता प्राप्त छात्रावास के बन्द किये जाने तथा इसे पुन न खोलने के सम्बन्ध मे किये गये हाल के निर्णय का उल्लेख किया । मैंने कल सदन को आश्वासन दिया था कि एक दिन के अन्दर इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय कर लिया जायेगा । मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि पटना मे सहायता प्राप्त छात्रावास जो बन्द होने के 15 वर्ष पूर्व से चल रहा था को पुन खोलने का आज निर्णय कर लिया गया है । छात्रावास के सुचारूरूप से सचालन की व्यवस्था करने के लिये पूर्व रेलवे के महाप्रबधक को आवश्यक अनुदेश जारी किये जा रहे है । यह भी निश्चय किया गया है कि आवेदन-पत्रो की समुचित छानबीन की जायेगी ताकि केवल पात्र छात्रो को ही छात्रावास मे भर्ती किया जाये ।

SHRI N SREEKANTAN NAIR (Quilon) On a point of order Generally Ministers make statements in English because in this House we do not understand Hindi If he wants, he can lay the Hindi version on the Table, that was the practice all along May I request him to speak in English?

MR SPEAKER The Member had raised it in Hindi, you were not present when the Member spoke in Hindi that is why he is making a statement in Hindi There is no point of order in this

---

12 43 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(1) REPORTED PRESS RELEASE BY THE RAILWAYS ABOUT HOLDING UP OF RAILWAY WAGONS BY COAL INDIA LTD ETC

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : 27 मार्च का रेलवे ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जो 28 मार्च का हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स आफ इन्डिया मे छपी है । उसमे इन शब्दो का प्रयोग किया गया है ।

'The blame must surely rest on Coal India Ltd, the collieries, the steel plants and some other thermal power plants who receive coal on priority but hold up the wagons"

रेलवे का यह कहना है इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा कि 10 हजार वैगन प्रति दिन इन को देते है, जिन मे से कोल इन्डिया लि० के खदानो से 900 वैगन प्रति दिन नही भर पाते है और इस तरह से 9 प्रतिशत शक्ति का नुकसान होता है और कोयला खदानो के मुह पर पडा रहता है । इस्पात के कारखानो मे स्टील प्लान्टस मे 2300 बोक्स वैगन्स प्रति दिन नही भरे जाते हैं और वे यहा पर पडे रहते हैं और थर्मल पावर प्लान्ट 300 वैगन्स प्रति दिन भरने मे असमर्थ रहते है । इस के कारण

[श्री निर्मल चन्द जैन]

वैगन्स वही पर रुक जाते हैं और दूसरी जगह जहां उन की आवश्यकता होती है, वहा पर नही भेजे जा सकते हैं। कल इन्डिया ने यह कहा है और ऊर्जा मत्री जी का भी एक वक्तव्य है कि अप्रैल 1977 से फरवरी 1978 तक 90 7 मिलियन टन कोल निकाला गया और रेलवे मत्रालय की प्रैस विज्ञप्ति के द्वारा उन का यह कहना है कि 87 मिलियन टन कोयले के लिए 1978-79 मे वे वैगन देने मे समर्थ हैं यानी जितना कोयला निकाला गया उस से कम कोयले के वेगन्स दिये जाते हैं लेकिन फिर भी वे उस का लदान करने मे असमर्थ हैं और कोयला वही पडा रहता है और वैगन्स भी वही पडे रहते है। यह सब को ज्ञात है कि देश मे कोयले की बहुत कमी है। इस तरह से इन दोनो विभागो से जो विसगति पैदा हुई है, उस को दूर करना चाहिए। यदि रेलवे मत्रालय का कहना सही है, तो ऊर्जा मत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिस से कोयला वहा न पडा रहे और कोयले का वहा से लदान हो सके और देश के अन्य भागो मे वह जा सके। उन्हे रेलवे मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहिए कि आप हमे इतने वैगन दीजिए जिन को भरने मे हम समर्थ हैं। क्योकि दोनो विभाग सरकार के पास हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हू कि सरकार के ये दोनो विभाग मत्रणा कर के किसी प्रकार के नतीजे पर पहुचे जिससे कि सभी को कोयला मिल सके।

(11) REPORTED AGITATION BY PADDY PRODUCERS FOR RAISING THE PRICE OF PADDY IN ANDHRA PRADESH

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) Sir, the Minister of Agriculture is not here If I make the statement

MR SPEAKER If you want you can make the statement

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU Will it be conveyed to him?

MR. SPEAKER It has already been conveyed to him

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU: In Andhra Pradesh, the paddy producers are agitating for raising the price of paddy

MR SPEAKER You know the rules Whatever you have given that should be read out Under rule 377, you cannot make a speech You must have seen the bulletin

SHRI P RAJAGOPAL NAIDU. Yes, I have seen the bulletin Sir, that demand has not been accepted till now At the same time the paddy is not purchased The paddy is of two kinds— one is cyclone affected and the other is good paddy The cyclone affected paddy can be boiled and can be sent to Kerala and other places where they are taking it The other paddy can be purchased but the FCI is not purchasing Now the price is Rs 45 per 75 kg whereas the price fixed is Rs 75 In Circars district a large quantity is available and therefore it must be purchased Therefore, I request the hon Minister to see that all the paddy is purchased at the fixed price

(111) CONSTITUTIONS OF A BENCH OF HIGH COURT FOR MARATHWADA

श्री केशव राव धोंडगे (नान्देड) अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 377 के द्वारा विधि और न्याय मत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हू कि महाराष्ट्र मे मराठवाडा क्षेत्र के पाच जिलो के लिए अभी तक औरगाबाद मे हाई कोर्ट की बेंच का इन्तजाम नही किया गया है। वहा के लोग महाराष्ट्र सरकार से वहा पर हाई कोर्ट की बेंच कायम करने की माग करते रहे हैं। वहां की बार एसोसियेशन ने भी वहा हाई कोर्ट की बेंच कायम करने की मांग की है। मैं बीस साल असेम्बली मे भी इस बारे मे सवाल करता रहा हू। प्रशासकीय प्रस्ताव लाया गया। मुझे आश्वासन मिला।

पिछली 22 मार्च को महाराष्ट्र विधान सभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें यह विनती की गयी है कि केन्द्रीय सरकार औरंगाबाद में हाई कोर्ट की बेंच तुरन्त कायम करे। राष्ट्रपति जी से भी विनती की गयी है कि वे इस मामले में कार्यवाही करें। महाराष्ट्र राज्य कायम होते वक्त नागपुर करार के अन्दर भी इस बात का आश्वासन मराठवाड़ा की जनता को दिया गया था लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मराठवाड़ा के लोगों को इससे बहुत तकलीफ है। इसलिये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह जनता की मांग को देखते हुए औरंगाबाद में हाई कोर्ट की बेंच कायम करे। इससे मराठवाड़ा के पांच जिलों के लोगों को सहूलियत होगी।

(iv) REPORTED PURCHASE OF SHARES OF BIRLA GROUP OF INDUSTRIES

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Sir, I wish to bring to the notice of the House a matter of great public importance. The Life Insurance Corporation of India, the General Insurance Corporation of India and the Unit Trust of India have recently bought shares worth crores of rupees in some firms belonging to a particular industrial house after the recent budget. These shares of Gwalior Rayons, Keshoram, Hindustan Aluminium and Orient Papers, all belonging to Birla group are reported to have been bought at exorbitantly high prices in the Stock Exchanges of Bombay and Calcutta. The news was deliberately leaked out and the prices of the shares went up. Even though these companies are well known and the shares are known as leaders of the market, this huge purchase of shares took place at a time when the yields of these shares are at a very low level and the prices high and it has not helped the public financial institutions or public exchequer, but only the business house in question. The prices of these shares have subsequently shot up also even after the purchase took place. Obviously, speculation and gambling cannot be the guideline of a public financial institution. It can only be a well laid down policy of sound investment. The Finance Minister should come forward with a statement in the House and inquire into the scandal. After I wrote to you, a Calcutta financial daily *Business Standard*, has also come out with a story which is entitled "Another Mundhra Scandal". This is a very important thing talked about in financial circles in Bombay, Delhi and Calcutta and I request you to direct the Finace Minister to come forward with a statement.

12.15 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS*, 1978-79—*Contd.*

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 44 to 48 relating to the Ministry of Health and Family Welfare for which 5 hours have been allotted.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amount on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1979, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 44 to 46 relating to the Ministry of Health and Family Welfare."

---

*Moved with the recommendation of the President.

[Mr Speaker]

12 15 hrs.

Demands for Grants, 1978-79 in respect of the Ministry of Health and Family Welfare submitted to the vote of Lok Sabha

No of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16-3-1978		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
		Rs	Rs	Rs	Rs
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
44	Ministry of Health and Family Welfare	14 77,000		73 83,000	
45	Medical and Public Health	30 80 53 000	19,53,71,000	151 99,97,000	67,68 58,000
46	Family Welfare	20 34 60,000	17,000	101,73 01 000	83,000

MR SPEAKER Sarvashri Shibban Lal Saksena and Keshavrao Dhondge have tabled cut motions to the Demands for Grants relating to the Ministry of Health and Family Welfare I would like to know if they are present in the House and desire to move their cut motions

Shri Saksena is not present Shri Keshavrao Dhondge is also not present So both the cut motions are not moved

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) श्रीमन्—

MR SPEAKER I am not calling you The practice here is we don't call you now But if you on your own want to make a statement, it is another matter I personally request you not to because it will become a bad precedent later

श्री राज नारायण हमने जो कुछ नई नई स्कीमें चला रखी है उनके बारे में पहले मैं थोडा सा दस पन्द्रह मिनट आपकी आज्ञा हो तो कह दूं ताकि अच्छा डिसकशन हो।

MR SPEAKER You will get an opportunity to say in the end

श्री राज नारायण लास्ट में फिर वे बेचारे क्या कहेंगे ?

SHRI A C GEORGE (Mukandapuram) Sir in this particular case you may have to take precaution The time allotted must not be impinged upon It will become a dangerous precedent

MR SPEAKER The time allotted will be consumed Anyhow let us stick to some practice In the case of other Ministries we have not allowed

श्री राज नारायण अगर आपको इस में कोई असुविधा हो तो ठीक है मैं बाद में बोल लूंगा। मैंने हमेशा देखा है और पार्लिमैंटरी स्वस्थ पद्धति भी यही है कि विभाग का मंत्री थोडी अपनी बात कह दे और बाद में डिसकशन हो और वह जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप नहीं चाहते है तो मैं नहीं बोलूंगा।

SHRI A C GEORGE The time taken by the Minister should be deducted from the time allotted to the

ruling Party Then we have no objection

MR. SPEAKER The Demands for Grants are not generally moved in the House by the Minister concerned That is the practice Once in a way exceptions have taken place Last year also I understand exceptions have taken place At the end you can make a longer speech In the middle also you can

SHRI A C GEORGE My submission is whatever the time is taken by the hon Minister may be reduced from the time allotted to the ruling Party

MR SPEAKER That is true That has got to be done

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar) I suggest another alternative because while I see substance in what you are saying that we should not normally depart from the practice I must say also that I see something in what the Minister is saying If the Minister has got some important decisions to announce to the House as a kind of initiation or introduction for the debate, certainly it is within his right to tell us because then the discussion will be on the basis of the introductory remarks that he may just now be making which will be more effective and meaningful But he can do so only on one condition At the end when he is going to reply supposing he has got a set number of minutes, say, half an-hour or 45 minutes, then whatever time he takes now shall be deducted from the time that is given to him at the end We can agree if he divides his time between now and at the end, together the total time taken should be the same, not more

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) Sir, there is a provision in the rules for a statement by a Minister If the Minister wants to make a statement on anything with previous notice to you, he can make a statement. But it is not necessary for him to make the statement at the time of the budget debate Let him make the statement any time on Monday, or when he wants, but the scope and the right of initiation of the debate should be left to the Opposition

MR SPEAKER Surely.

SHRI SAUGATA ROY. We expect you, as Speaker, to be more partial towards the Opposition

MR SPEAKER I am expected not to be partial to anybody

SHRI SAUGATA ROY We expect you to protect the rights of the Opposition

MR SPEAKER Rights of all the parties

SHRI SAUGATA ROY We don't want to give up the right of initiating the debate

MR SPEAKER Initiating the debate is the right of the Opposition But if the Minister wants to make a statement he can always make it He has given notice I am only requesting him But if he wants, I have to allow him because the earlier rulings also say that if the Minister wants to do it, he has the right But normally it is not done If he wants to I will have to allow him, but I will deduct the time at a later stage, from his party

SHRI A C GEORGE. This preamble of the *modus operandi* of discussions need not go on. You and I understand the spirit of what is going on I think the Minister will understand why this procedural wrangle has occurred, and he may think of restricting his speech

MR. SPEAKER It is upto him, not for me . .If he wants to make a statement, I have to allow him

श्री राज नारायण : दस मिनट का समय तो इसी में चला गया है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि मुझे मालूम नहीं कि यह प्रथा कैसे क्यों चली। मैंने राज्य सभा में भी देखा है और ब्रिटिश पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस भी है और मेज पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस को भी आप देख लें कि माननीय सदस्य बराबर आप आप कहते है। आप शब्द केवल स्पीकर के लिए इस्तेमाल होना है मेम्बरों के लिए नहीं होता है।

श्री सौगत राय : पढ़ते हैं।

श्री राज नारायण : मेज पार्लिमेंटरी प्रेक्टिस में क्या है क्या नहीं हम भी जानते हैं। हमने भी इसमें अपने पच्चीस साल का जीवन खपाया है। इसलिए उस मे बहस न करें। मंत्री अगर अपने विभाग के बारे में या अपनी स्कीमों के बारे में या अपनी योजना के बारे में पहले कुछ नहीं बताएगा तो बहस अच्छी नहीं होगी। इसलिए बराबर हमने असैम्बली में भी देखा है कि जिस मंत्री का जो विषय रहता है पहले वह खड़ा हो कर बोलता है। अगर आप नहीं चाहते है तो ठीक है। मैं नहीं बोलता हूं।

MR. SPEAKER: Mr. Minister, you can make the statement, if you want to.

श्री राज नारायण : मैं आपकी आज्ञा से बहुत जल्दी में कुछ खास-खास बातें कह देना चाहता हूं। इस साल का हमारा बजट कुल 387.03 करोड़ का है। यह तीन भागों में बंटा है :

(1) सचिवालय के प्रावधान से सम्बन्धित

(2) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित

(3) परिवार कल्याण से सम्बन्धित।

जो व्यवस्थायें पहली सरकार की थीं उसके ऊपर हमने क्या नई इम्प्रूवमेंट की हैं उसी के बारे में मैं बता देना चाहता हूं।

83.28 करोड़ स्वास्थ्य पर 1977-78 में था और इस साल हमने 146.48 करोड़ रखा है यानि 1978-79 के लिए रखा है। जन स्वास्थ्य रक्षक, मलेरिया और भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अलग-अलग है। परिवार कल्याण पर गत वर्ष 98.18 करोड़ था इस साल हमने 111 करोड किया है। केवल कल्याणकारी कार्यों पर अगली पंचवर्षीय योजना में 1978-83 तक स्वास्थ्य पर 1330 करोड़ और परिवार कल्याण पर 665 करोड़ खर्च होगा। ग्रामीण स्वास्थ्य में हम ने 70 प्रतिशत की वृद्धि की है और परिवार कल्याण में 73 प्रतिशत की वृद्धि की है। सम्पूर्ण पंचवर्षीय योजना जो चलेगी उस में हमारे विभाग में 70 प्रतिशत स्वास्थ्य और 75 प्रतिशत जन कल्याण के लिए है। आपको जानकार खुशी होगी कि जो जन स्वास्थ्य रक्षा की हमने योजना चलाई है एक हजार पर एक जो नई स्कीम है यह पहले कहीं नहीं थी। तो 30,000 जन स्वास्थ्य रक्षक इस समय फील्ड में चले गये हैं और वहां काम कर रहे हैं। वहां इनका ज्यादातर काम प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है। यहां पर बहुत सी उनकी आलोचना हुई है। कि क्वैक पैदा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह डाक्टर्स नहीं हैं। कम्युनिटी का इन्वोल्वमैंट, हमारे मंत्रालय ने पहली बार ज्यादा जोर दिया है कि कम्युनिटी का इन्वोल्वमैंट हो। इसलिये हमने एक हजार की आबादी पर कम्युनिटी से एक जन स्वास्थ्य रक्षक चुनने की बात की है। तीन महीने की इनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें इनको 200 रु० दिये जाते हैं और उसके बाद 50 रु० प्रति माह और दवाओं से भरा किट देते हैं।

12.00 hrs.

एक योजना और चलाई है प्रशिक्षित दाई की हर गांव में। यह योजना पहले नही थी । इस योजना में 50,000 प्रशिक्षित दाइयां अब तक हो गई है और 1976 में केवल 3 हजार थी । अगले साल एक लाख तक करने की हमारी स्कीम है । तो हमारे माननीय सदस्य जब इस पर बोले तो जन स्वास्थ्य रक्षक का जो एक महत्वपूर्ण विषय हमने चलाया है उसके बारे में भी देखेंगे ।

इसके अलावा हमने एक मैनुअल भी बनायी है जो सभी भाषाओं में है, केवल दो को छोड़कर—एक तमिलनाडु और दूसरे कर्नाटक को छोड़ कर--बाकी जितनी राष्ट्र की भाषायें है सभी में यह मैनुअल है और वह हर जन स्वास्थ्य रक्षक के हाथ में है । जहा पढाई होती है उनकी वही उनको दे दी जाती है । तमिलनाडु और कर्नाटक में बोली जाने वाली भाषा में उसका अनुवाद नही हुआ क्योंकि वहा की सरकारे इस योजना से डिफरेंट योजना सेन्टर की इजाजत से चला रही है और उनकी भी योजना अच्छी है, हमने उनकी मान्यता द दी है कि उस अपनी योजना को चलाये क्योंकि वहा वह योजना चल रही थी, उनका डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नही होगा ।

बर्ल्ड बैंक की एक टीम आयी उसने यू०पी० और कर्नाटक का दौरा किया और उन लोगो ने आकर के इस योजना की बहुत प्रशसा की है और कहा है कि भारत ने जो योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी की है उसकी नकल पश्चिम के देश भी करेंगे । वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि पजाब के खरड ब्लाक में गये थे और उन्होने भी इसी भाव को व्यक्त किया कि हमने आपके ट्रेन्ड जन स्वास्थ्य रक्षक जो हैं उनसे बातें की और हम बहुत प्रभावित हुए हैं किन्यू काइन्ड आफ रिवौल्यूशन स्वास्थ्य विभाग इस देश में कर रहा है ।

अभी तीन दिन हुए जापान, कनाडा, वेस्ट जर्मनी और यू०के० के पार्लियामेंटरी डेलीगेशन हमारे यहा आये थे और परसो मेरठ में खानपुर ब्लाक में गये और वहां जा कर उन्होने कहा कि हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं । ऐसी योजना सारी दुनिया में हो और भारत लीड दे रहा है इस मामले में विश्व के अन्य विकसित देशो को ।

कुछ अखबारो मे चर्चा होती है कि परिवार नियोजन हमने ठप्प कर दिया है । ऐसा नही है । वह कार्यक्रम चालू है । ठप्प हमने किया है कम्पल्शन और कोअर्शन । इससे माननीय सदस्य जान जायेंगे कि 8 लाख से ऊपर, जब से यह सरकार आयी है, स्टेरेलाइजेशन्स हो गये है । ज्यादातर इसमें आन्ध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में हुए हैं । अपने उत्तरी प्रदेशो में नही हुए । उसका कारण है । क्योंकि यहा पर जबरदस्ती ढग से स्टेरेलाइजेशन स्कीम चली उसने जनता के मन में यह सदेह पैदा कर दिया और इसलिये स्वेच्छा से लोग नही आये । लेकिन धीरे धीरे लोग अब सेन्टर्स पर आने लगे है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यह काम बढ़ाना चाहिए ।

श्री राज नारायण : हा, बढाना चाहिए ।

गर्भ-निरोध की हमारी योजना मे केवल स्टेलाईजेशन ही नही है, बल्कि हम ने अनेक योजनायें बनाई हैं, जो मे बाद मे बताऊगा ।

हम ने माता और शिशु कल्याण की प्रगति के लिए अगले पाच वर्षों में 38,000 केन्द्र बनाने की योजना बनाई है । इस के अतिरिक्त हम ने शिक्षा सस्थाओ मे भी माता और शिशु कल्याण के सम्बन्ध में शिक्षा देने की स्कीम बनाई है । पैसा हमारा हैल्थ

[श्री राज नारायण]

विभाग देगा, लेकिन एजूकेशन विभाग से हमारा सम्बन्ध हो गया है। उन्हें कोर्स दे दिया जायेगा और वे अपनी शिक्षा संस्थाओं में उसे लागू करेंगे। दवा की एक पेटिका भी हम उन को दे देते है।

इस वक्त जन्म दर 1000 के पीछे 33 है जिसको 1000 के पीछे 30 तक करने की योजना है। लेकिन यह लक्ष्य 1978-79 मे नही पूरा हो सकता है। हम ने सब बातो को सोच-समझ कर इसे 1982-83 तक बढ़ाया है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि यदि यह उससे पहले ही जाये, तो ज्यादा अच्छा है।

जहा तक मलेरिया का सम्बन्ध है, हम ने डी०डी०टी०, बी०एस०सी० और मैलाथियन आदि दवाओं के छिडकाव का व्यापक प्रबन्ध किया है। दवाओं की जो कमी पहले थी, वह अब नही रह गई है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में भी हम ने बहुत प्रगति की है। हम ने आयुर्वेद यूनानी, नेचरोपैथी और योग पर ज्यादा बल दिया है। जहा पंच-वर्षीय योजना में इस के लिए पहले 25 करोड रुपया रखा गया था, वहा हम ने इस रकम को बढा कर 60 करोड रुपय कर दिया है। हम अपने मंत्रालय मे इन्डिजिनस सिस्टम के लिए एक नया डायरेक्टोरेट भी खोल रहे हैं। पहले ऐसी कोई योजना नही थी। पहले इन्डिजिनस सिस्टम की एक राष्ट्रीय परिषद् थी। दस दिन पहले हम न उस को चार विभागो में बांटा है। उस की चार कौंसिल्ज होगी। अगर आगे चल कर कही योग और नैचुरोपैथी की आपस में कोई दिक्कत पडी, तो हम उन के लिए अलग अलग कौंसिल बना देंगे।

रानीखेत मे एक केन्द्रीय फार्मेसी बनाई जा रही है। राज्य फोर्मेसियो को भी अनुदान दिया जा रहा है। दिल्ली में विलिंग्डन हास्पिटल में 300 बैड्ज का एक नया हास्पिटल बनाया है।

पहले प्राइमरी हैल्थ सैंटर्ज में दो दो डाक्टर रहते थे। अब हम ने राज्यो को सुझाव दिया है कि हर प्राईमरी हैल्थ सैंटर में एक डाक्टर और बढ़ा दिया जाये। वह डाक्टर किसी भारतीय चिकित्सा पद्धति का होगा—चाहे वह आयुर्वेद का हो यूनानी का हो होमियोपैथी का हो योग का हो या सिद्ध का हो।

माननीय सदस्य इनटर्नशिप और हाउस जाब्ज के बारे में बहुत से प्रश्न पूछते रहे है। इस के लिए हम ने अपने डायरक्टर की अध्यक्षता मे प्रमुख लोगो की एक अच्छी कमेटी बना दी है, ताकि वह सोच-समझ कर अपने सुझाव सरकार को दे कि इस विषय मे क्या किया जा सकता है। बहुत से माननीय सदस्यो ने कहा था कि हाउस जाब्ज सब को मिलनी चाहिए। हमारे यहा 12 000 से ले कर 14 000 तक डाक्टर पैदा होते है। उन सब को हाउस जाब्ज देना नामुमकिन और असंभव है—हम नही दे सकते है। लेकिन इनटर्नशिप के बारे मे पैसे की बात है। पंजाब और बिहार ने उन के लिए 400 450 और 500 रुपये तक कर दिया है। हमारे यहा 350 रुपये दिये जाते हैं। हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन्टर्नशिप के लिए पैसा बढ़ा दिया जाये। अगर हमारे पास फंड्ज हो, तो हम बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे।

हम लोग कुष्ठ रोग की काफ़ी रोकथाम करने जा रहे है। अल्पेपन को दूर करने के लिए 2 37 करोड रुपये की रकम रखी गई है, जबकि पहले वह 1 करोड़ थी। कुष्ट रोग पर भी पहले 32 लाख था, उस मे 4 3 लाख किया है। पिछले साल से इस साल 7 करोड कर दिया है। अस्पतालो में सुधार की व्यवस्था के लिए हम ने डा० सिद्धू

जो राज्य सभा के सम्मानित सदस्य हैं, की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। दिल्ली में जितने अस्पताल हैं, उन में सुधार कैसे किया जा सकता है, क्या और व्यवस्था हो सकती है, इस के बारे में वे अपना सुझाव देंगे। उस सुझाव के आने के बाद आगे हम अपने कार्य को बढ़ायेंगे। सम्मानित सदस्यों ने बार बार इस का जिक्र किया है कि यहां का अस्पताल गन्दा है तो उस के लिए यह हम ने कर दिया है।

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ मेडिकल साइंसेज के लिए भी एक रिव्यू कमेटी बना दी है। शाहदरा में एक नया मेडिकल कालेज और अस्पताल पांच सौ बैड का बनेगा। मेडिकल कालेज जो अभी सफदरजंग से नत्थी है वह अलग हो कर शाहदरा चला जायगा। हम ने सभी स्वयंसेवी संगठनों से अपील की है और उन की एक कान्फरेंस हम अगले महीने की पहली दूसरी तारीख को बुलायी है कि वे हमारी इन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सहायता दें।

हम सम्मानित सदस्यों से कहेंगे क्योंकि सभी आदरणीय सदस्य कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है तो राष्ट्रीय प्रश्न को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाना चाहिए, उस के ऊपर पार्टिजन दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए। यह हमारी विनम्र अपील है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी सम्मानित सदस्य अपना पूरा पूरा सहयोग दें। हम इन के सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

13 12 hrs

[MR DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SHRI V KISHORE CHANDRA S. DEO (Parvathipuram) Mr Deputy-Speaker, Sir, with great pleasure I rise to initiate the debate on the Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare. I just heard the lengthy introductory remarks of the hon Minister

MR DEPUTY SPEAKER It was very short

SHRI V KISHORE CHANDRA S DEO I have also gone through the report of this year which is quite a voluminous one incidentally, it has more pages than last year's report I feel this report reflects the Health Ministry which is suffering from two serious diseases, constipation of ideas and diarrhoea of words

Incidently, as far as the Health and Family Welfare is concerned, one of the main dangers that faces the country is explosion of population and poverty I have inter-connected these From statistics, we can see that the poverty level which was 35 per cent has increased to 67 per cent along with the subsequent increase in population

There has been a lot of controversy about sterilisations and family planning programmes that had been undertaken especially during recent times I would like to stress that it was neither the policy of the Government nor that of my party to have forced sterlisations in the country Such things did happen during the Emergency and even a couple of years before that But I would like to state that the people who did this were neither the members of the Government nor that of the Congress Party So just because this was done by force by some people at a particular time I do not think it is necessary that we should completely give up this policy of sterilisations and family planning which is so essential and necessary to our country

Poverty has been increasing steadily and slowly The pang of poverty has been spreading its clutches over a larger area of society in our country.

[Shri V. Kishore Chandru S. Deo].

The sterilisation rate, if you go through the statistics, will show that in the year 1977-78, it was only 8 lakhs, as the hon. Minister himself said as against a rate of 70 lakhs in 1976-77. Then, the hon. Minister has himself said that not only sterilisations will eventually succeed in containing the population. I entirely agree with him. But in the National Population policy of 1976 which was expounded by Dr. Karan Singh, to contain the problem of increase in poulation, he had approached the problem with a multi-faced angle. Women literacy has to be increased; there has to be freezing of representation to the Lok Sabha and the State Assemblies on the basis of 1971 Census and the aid given by the Central Government to the States should also be on the basis of 1971 Census. There are several other suggestions in regard to this.

The fact remains that the present Government has overlooked many of the suggestions which were made in the Report of 1976-77. The Janata Government since last year has been capitalising on this problem for their political purposes and elections which is not a healthy thing for a developing country where this sort of population explosion is only a phase of transition. The hon. Minister knows that in a primitive economy, both the death-rate and the birth-rate are always high When a country reaches the stage of affluence, both the death rate and the birth-rate become low, thus maintaining the population growth whereas in a developing economy, during the demographic transition, it is obvious that due to advance in medical sciences, the death-rate will come down and the birth-rate will go up Therefore, it is necessary to educate the people and to spread the programme to rural areas and see that these programmes are taken up by the Government on a war-footing rather than capitalising on these issues for political gains.

With respect to this, I would like to know from the hon. Minister what happened to the anti-pregnancy vaccine which was being developed by Dr. G. P. Talwar of the All India Institute of Medical Sciences. Unfortunately, nothing has been known after that. I want to know what happened to that. This would have a major break-through in the field of population control and family planning also. Only a vaccine could have done the trick. But so far nothing has been known about that.

In short, I would like to tell the hon. Minister that his Government should revert back to the policy of 1976 which was evolved by our Government minus the coercion part of it. Two years back, there were extra-Constitutional forces, the people not belonging to the Government, not belonging to the Congress party, who were engaged in an operation of sterilising the people by force. Now, we have the Janata Government which is seized of implementing the programme of prohibition and the programme of aute-urine therapy. Do you want to have a country of celibates and ascetics? This is not what we would expect from the Janata Government I would like the hon. Minister to give a serious thought to this and that he goes back to the earlier policy of 1976 which was a unique document in itself.

Coming to the health services, I regret to tell the hon. Minister that services in Delhi hospitals specially have been deteriorating very badly. I know of an incident of a senior journalist who died in the Willingdon Hospital due to lack of proper medical services. I have got a petition which will go to the hon. Minister. One journalist, Shri S. K. Das, who was admitted in the Willingdon Hospital was not cared for by either the senior or junior doctors and due to lack of proper care, he expired in the hospital This is a petition which his son has sent to the hon. Health Minister. And this is, I think enough proof to show how the services have been deteriorating in

these hospitals. The situation in the All India Institute of Medical Sciences is also in a very deplorable state I hope the hon Minister will stop political interference into these autonomous bodies like the All India Institute of Medical Sciences and the post-Graduate Institute at Chandigarh We have some of the top doctors of Asia working in these institutes They should be left alone and the autonomy of these bodies should not be disturbed because alienating these top doctors will only result in spelling disaster and nothing more There have been several instances where there had been a lot of political interference I think it also happens in the case of appointment of the Director-General of the Health Services I hope the Government will take note of this serious situation and refrain themselves from interfering into the exclusive preserve of the doctors and medical servicemen

Then coming to rural health service, just now the Minister gave a lot of statistics and also sugessted several means by which he was going to spread this machinery to the rural areas Well, I appreciate a lot of things that he has said and it has been mentioned in the Report also The ideas of the hon Minister are good He spoke of bare foot doctors and he said that the ratio was going to be increased by having these public health visitors, etc Here I would like to state that though the deas are good, the way in which he wants to implement it, I am sure would not be conducive to these medical programmes

Again in the 1976 policy itself, our Government have stated that they want to create some para medical workers and community workers in these villages For this purpose, then they have decided to make use of the school masters of the villages, postmen, gram sevaks and dais for rendering health services in these rural areas and in the villages. Now the hon. Minister has brought out this proposition where he is going to have bare-foot doctors. Bare foot doctors, I know.

SHRI RAJ NARAIN My dear friend, why are you going to commit hardship?

SHRI V KISHORE CHANDRA S DEO Because it is mentioned in the Report I can show you.

SHRI RAJ NARAIN They are not bare foot doctors

मैंने उनका नाम लिया है—जनस्वास्थ्य रक्षक।

SHRI V KISHORE CHANDRA S DEO Mr Deputy Speaker Sir, I am fully aware of the fact that bare foot doctors are neither do tors nor will they go around bare foot That is not exactly what I mean But what is the concept of bare foot doctors? What he suggested was that he would give a sort of training to these doctors in allopathy in homoeopathy and in several other things As it is, we have a lot of quacks operating in villages and small towns, and by doing this we are creating a sort of new class of doctors The hon Minister will only be encouraging officially a recogised class of doctors in these villages It will result in murdering the rural population rather than saving the people of this country If you want to have a group of para medical workers and community workers I suggest that we should go back to the recommendations that were made in our policy of 1975 and see that these important people of the villages are trained so that they can be made use of by the community, they are always available to the people and they can be made use of by the community for emergency and immediate needs

In this Report it is mentioned that one in every four PHC will be upgraded into 30 bed hospitals I certainly welcome this proposition But I feel that as it is the PHCs that we have are very inefficient Medicines are not available freely So, instead of upgrading every one for four, I hope the hon. Minister will give a serious thought to this and see that he upgrades all the primary health centres eventually, in subsequent course of

[Shri V. Kishore Chandru S. Deo]

time and also provide better health services and facilities to these sub-centres which are working under the primary health centres.

Most of the communicable diseases in our towns, cities and villages—you may be aware also of the fact—are normally spread through the pollution of water. I think it is high time that the Health Ministry should evolve a national plan to supply protected and covered water in all these villages so that the main communicable diseases like malaria, cholera, diarrhoea and gastroenteritis are controlled, as the polluted water which is used for drinking purposes is responsible for these diseases. Till today nothing has been done about this. I sincerely hope that a plan will be taken up to see that these facilities are made available to all villages, both large and small alike.

Nutrition and nursing is another important problem, which is very serious in our country. The condition of our infants and children is very bad due to lack of nutrition. This is one of the main things which affect the younger children when they grow up into adults. If at this stage they are given proper nursing and care and nutrition, then only they can grow up in a more healthy atmosphere, and both physically and mentally they will be useful to the society. Under this maternal and child health programme, I want the hon. Minister to see that more attention is given to infants and lactating mothers. As far as this is concerned, immunisation programme should be taken up in rural areas. We have these triple antigen vaccine, polio vaccine and small-pox vaccine. These are not made available to many of these small villages in the rural areas. I hope the hon. Minister will take pains to see that this facility spreads into the interior of villages in our country.

I am glad to hear from the hon. Minister that number of 'Dais' has increased from 3,000 to 50,000 and it will eventually be increased to one lakh. I would like the hon. Minister to see that the ratio of nurses to patients is also increased. We would have a double advantage in this: apart from providing employment, this would also ensure proper and better care. The hon. Minister must be aware of the fact that from our country, a lot of young girls are going abroad for employment—especially from Kerala and several other States. By increasing the number of nurses, you will be providing employment to a large number of people who are prepared to go abroad, in addition to this, I am sure all the patients in the hospitals and nursing homes will definitely get better care

Then I would like the hon. Minister to try to introduce a National Health Service, a sort of National Health Insurance Scheme. Such a scheme is there in U.K. and several other countries. The hon. Minister must be aware of this fact. It would take time to introduce this sort of thing. I am not asking the Minister to introduce it tomorrow. It may take some time, but I would like him to make an opening, to make a beginning so that eventually we can have this sort of scheme where even the economically downtrodden people, socially backward people, can avail themselves of the latest medical discoveries and facilities that are available to the affluent societies in our country. There should not be any discrimination as far as health services are concerned. As I said, in U.K. and other European countries, they have this National Health Insurance Scheme or National Health Scheme, which operates very effectively and properly. In Japan also they have got it. Considering the fact that in our country poverty is in abundance, there is malnutrition and people are suffering from several diseases, especially in the rural areas, I sincerely hope, the hon. Minister will take steps in this direction, so that eventually we may have some such National Health Service in our country.

The hon. Minister has said that he has raised the amount for controlling leprosy. I am glad he has done that. Our country leads in two diseases: one is leprosy and the other is blindness. I am really glad that he has made a larger allotment as far as leprosy is concerned. I hope he will give serious thought in respect of blindness also because our country is number one as far as blind people are concerned. I am not talking of political blindness...

श्री राज नारायण : पोलीटीकली ब्लाइन्ड की भी दवा है।

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Then, in this report, I find that one chapter has been devoted to use of Hindi in official work. Certainly I am not against use of Hindi in official work. But there is a limit to this. Fortunately or unfortunately this Hon. Minister is notorious for his attitude towards the Hindi language

SHRI RAJ NARAIN: Notorious and not famous! you have used the proper word.

SHRI K GOPAL (Kaqur): Yes, you are not famous but notorious!

SHRI K GOPAL (Korur): Yes, you

DEO: I may tell the Hon. Minister that Hindi is not going to improve our health services and family welfare programmes. Hindi can be used to some extent, as long as it does not create dissension among the non-Hindi speaking people because, if this sort of tendencies and linguistic forces come into play, especialy in the medical and health services which are national services, it would be a very sad thing for our country. I would like to say that the Minister should be less vocal in his attitude towards Hindi because there has been a lot of controversy over the language issue. So, I wanted specifically to say that language is not going to solve the problem as far as his Ministry is concerned.

SHRI K. GOPAL: Hindi will not cure any disease.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Before I conclude I would again like to thank you for the opportunity given to me to speak today and I would like the Minister to look at things in a broader perspective. I would again like to appeal to him to revert back to the policy of 1976 minus the coercion part of it so that he may emancipate the country from suffering and poverty.

श्री केशव राव धोंडगे (नादेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हेल्थ की मांगें पेश की है। मै उन पर अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदर साहब, मैंने श्री राज नारायण जी की तकरीर को बड़े गौर से सुना है और में आशा करता था कि उसमे कोई इंकलाबी बात का जिक्र होगा। मगर दुःख की बात है कि इसमें सभी दामो की बात, कुछ पैसे की बात की गयी है, कोई इंकलाबी काम की बात इसमें नजर नही आयी ? हम लोग रामराज की बात करते है। प्रधान मंत्री जी और स्वास्थ्य मत्री जी का दावा है कि हम रामराज कायम करना चाहते है। मैं पूछना चाहता हू कि क्या रामराज मे लोग जडी-बूटी खा कर जिन्दा रहेंगे ? क्या ऐसा होगा कि राम राम कहते रहो और जो मिले वह खा कर जिन्दा रहो। भूखा-प्यासा रह कर आदमी कसे जिन्दा रह सकता है। सही मायनो मे अगर राम से मोहब्बत है और आप रामराज लाना चाहते है तो पहले आपको जनता को बन्दर बनने से रोकना होगा। आज आम आदमी के पास न खाने के लिए अनाज है, न रहने के लिए मकान है और न पीने के लिये पानी। आप तो राम के भक्त हैं। आप तो अयोध्या में राज करते रहेंगे। मगर जनता, बन्दर की तरह इधर-उधर भागती रहेगी। ऐसे रामराज कायम करने की बात से मुझे दुख होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस देश में रामराज चाहते है, आप भी

[श्री केशव राव सोंडगे]

रामराज चाहते हैं। अगर रामराज का यही मतलब है तो सदर साहब मैं कह सकता हूं कि यह रामराज नही है।

सदर साहब, इस देश की जनता शहरो में ही नही रहती है, वह देहातो मे भी रहती है। वहां जो जनता रहती है उसकी बीमारी को हमे दूर करना है। उसकी बीमारी है, गुरबत। उसकी जबर्दस्त बीमारी है पिछडा-पन। उसकी जबर्दस्त बीमारी है अज्ञानता। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए जब तक हम इन्कलाबी कदम नहीं उठायेंगे तब तक हिन्दुस्तान की कोई बीमारी सही मायने मे दूर नही हो सकती है।

सदर साहब, आजादी के तीस साल के बाद इस मुल्क मे पैसे वाला अपना इलाज कर सकता है। जिसके पास पैसा हो उसे दवाइयां भी मिल जाती है। गरीब आदमी जिसके पास पैसा नही है, दवाएं नही खरीद सकता है। इसलिए गरीब आदमी का इलाज ही नही हो पाता है। जिसकी जेब में पैसा है, जिसकी जेब गरम है, उसका इलाज है, जिसके पास पैसा नही है उसका कोई इलाज इस देश मे नही हो पाता। सरकारी दवाखाने मोजूद हैं लेकिन उन से बहुत कम लोगो को फायदा होता है। डाक्टर लोग बराहेनाम काम करते हैं। मरीज का महज प्रेसक्रिप्शन लिख कर दे देते हैं। दवाइयां वहां से नही मिलती हैं। बाहर से लोगों को लेनी पड़ती हैं। लिख कर देना ही उनका काम रह गया है। अब जो बाहर मैडीकल स्टोर हैं वहां पर मुफ्त तो दवाई नही मिलती है। आप तो इनक्लाबी मिनिस्टर हैं। आप ने अपनी लम्बी जिन्दगी जेलों मे गुजारी है, आप बीस पच्चीस साल जेल मे रहे हैं। कम से कम आप तो कोई ऐसी स्कीम लाएं ताकि जो गरीब तबका है उनको फ्री मैडीकल एड मिल सके। सब बैकवर्ड लोगों का मुफ्त इलाज हो। अगर इस तरह की स्कीम आप लाते तो मैं आपको बधाई देता, आपको मुबारिकबाद देता, आपका स्वागत करता। लेकिन अभी तो स्वागत करने वाली इस में कोई बात नही है। हालत आज बहुत बुरी है। देहातो मे कोई भी मैडीकल एड मौजूद नही है। बडे बड़े लोगों के लिए ही ये दवाखाने है, गरीबो के लिए नही हैं। बाजारो मे दवाइयां है मगर गरीब खरीद नही सकता। मैं कहना चाहता हू कि ताल्लुका प्लेसिस मे जो सरकारी दवाखाने है या डिसपैंसरीज हैं उनकी देख-भाल अच्छी तरह से की जाए। वहां पर सब दवाइयो का भी इंतजाम माकूल होना चाहिये। अच्छे इलाज की वहा पर व्यवस्था होनी चाहिये। मैं नादेड मतदार संघ से आता हू। वहा पर जो ताल्लुके पडते है, कधार, भुखेड, विलोली नादेड, देगलूर, अहमदपुर वगैरह वहा पर न तो ब्लड बैंक है, न एक्सरे मशीज है, न आक्सीजन देने का कोई इतजाम होता है। ब्लड और पेशाब के एग्जेमिनेशन तक का वहा पर इंतजाम नही है। मुझे एक बार साप ने काटा। मै काधार ताल्लुका अस्पताल मे गया वहा पर एंटी स्नेक वैनम का इंतजाम तक नही था। तालुको के दवाखानो पर आक्सीजन देने का कोई इतजाम नही है। बाबा आदम के जमाने की हालत दवाखाने मे है। कोई इम्प्रूवमेंट नही हुआ है। वहा पर एक्सट्रा डाक्टर तक नही है। कोई खास दवाइयो का इतजाम नही है। पागल कुत्ता काट खाता है देहातियो को तो एंटी रैबिट वैक्सीन वहा नही होती है। लोग परेशान हो जाते हैं और मरते हैं। उनका इलाज वहां पर नही हो पाता हैं। जब यह हालत है तो कौन सा इनक्लाब आप ला रह हैं यह मेरी समझ मे नही आता है।

आप मलेरिया इरेडिकेशन की बात करते हैं। जो हालत अब चल रही है उस में मैं समझता हू कि आप पब्लिक को ही इरेडिकेट कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि बुरी बीमारियों के इलाज की कोई व्यवस्था

नहीं है। वहां पर आपको अच्छा इलाज की सुविधायें मुहैया करनी चाहियें। आपको मोबाइल अस्पतालों का इंतजाम करना चाहिये। शहरों के अन्दर तो आपने अस्पताल काफी खोल रखे हैं अच्छी बात है। लेकिन देहातों में, ताल्लुका लेवेल पर इनकी बहुत कमी है। आप को इस कमी को दूर करने के लिए मोबाइल अस्पतालों का इंतजाम करना चाहिये। मैं यह नहीं कहूंगा कि हर देहात में आप मोबाइल अस्पताल रखें। लेकिन फिलहाल हर ताल्लुका के अन्दर कम से कम एक या दो मोबाइल अस्पतालों का होना बहुत जरूरी है ताकि जो बीमार पड़ते हैं उनके इलाज की व्यवस्था हो सके। मेरे साथी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में यह स्कीम जारी है। बड़ी खुशी की बात हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्कीम नहीं है न देश के किसी राज में। जनता गवर्नमेंट का राज है। उसको कम से कम लोगों की सेहत को बरकरार रखने के लिए इलाज का तो इंतजाम करना चाहिये। बीमारी कभी हो जाए तो पहली ही स्टेज पर उसकी छानबीन हो जानी चाहिये, उसका पता लगा लिया जाना चाहिए ताकि उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि आज जो दवाखाने हैं वे रिश्वतखोरी के अड्डे हैं। वहां पर भ्रष्टाचार होता है। वहां पर पैसे ले कर इलाज होता है। बड़े लोगों का अच्छा इलाज होता है। उनके लिए ही वहां पर इंतजाम है। गरीबों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जिस के पास पैसा नहीं है, सिफारिश जिसकी नहीं है, जो बड़ी जात का नहीं है, मंत्री का जिस के पास वसीला नहीं है उसका इलाज नहीं हो सकता है। चन्द डाक्टर अच्छे भी होते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी खराब हैं। चन्द अच्छे भी हैं। मेरे कंधार के मैडीकल अफसर डा० रनदिवे बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसके लिए मैं यहां पर उनकी प्रशंसा करता हूं और उनको मुबारिकबाद देता हूं। वह पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। वह निष्कलंक हैं। ऐसे ही सभी डाक्टरों को होना चाहिये।

आपके पास मलेरिया इरैडिकेशन की स्कीम हैं। इस काम में आप बाहर के देशों की मदद भी ले रहे हैं। इरेडिकेशन की बात तो दूर, इस पर आप कंट्रोल भी नहीं कर पाए है। इमरजैंसी में जब मैं ग्यारह महीने तक डिटेंशन में था तो कई दिनों तक मैं इसी मलेरिया से बीमार रहा। मच्छर कहीं भी खत्म नहीं हुए हैं। देहातों में, शहरों में कहीं खत्म नहीं हुए हैं। एम०पीज० के क्वार्टर्ज से खत्म नहीं हुए हैं। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि पिछले महीने की बीस तारीख को मैं बम्बई से यहां हवाई जहाज से आया। एयर बस तक में मच्छर थे।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बिना टिकट सफर करते हैं।

श्री केशवराव धोंडगे : शहरों के तो आप खत्म नहीं कर सके हैं कम से कम एयर बस से ही खत्म कर दें। वे नान बायोलेंट तो नहीं हैं। तीन तारीख को इस माह मैं बम्बई से दिल्ली आया तो भी यही हुआ। मच्छरों की इंटरनैशनल कम्युनिटी बन चुकी है, देशी हो या विदेशी वे किसी को बख्शते नहीं हैं। मैंने इसके बारे में एविऐशन मिनिस्टर को लिखा है, आपको भी लिखा है। कम से कम देहातों के मच्छरों को आप रहने दें, उनको तो दूर नहीं कर सकते हैं लेकिन एयर बस के मच्छरों को तो आप दूर करके दिखा दें। वह भी आप नहीं कर सकते हैं।

श्री अमीराम जागड़ी (मथुरा) : हवाई जहाज की क्यों फिक्र करते हैं।

श्री केशवराव धोंडगे : जागड़ी साहब अपना राम राज्य है, फिक्र करने की क्या बात है। जितने लोग मरेंगे उतनी ही आबादी कम होती जाएगी। फैमिली प्लानिंग अपने

[श्री केशव राव खोडगे]

आप हो जाएगा। हवाई जहाज की इसलिये फिक्र की क्योंकि अपने देश की बदनामी विदेशों में होती है।

आजकल नौजवानों में गुप्त रोग बहुत ज्यादा होने लग गए हैं लड़के लड़कियों में बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, कालेज वालों के बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। इसके बारे में भी आपको कदम उठाने चाहिये। इस पर रुकावट लगना बहुत जरूरी है। फौरन इन पर रोक लगनी चाहिये नहीं तो हमारा जो नौजवान तबका है वह हमेशा के लिए बरबाद हो जाएगा।

आपने पब्लिक हैल्थ सैंटर भी खोल रखे हैं। यहां पर आप पर कैपिटा दस पन्द्रह पैसे ही खर्च करते हैं। साठ सत्तर हजार लोगों के लिए एक ही पब्लिक हैल्थ सैंटर की व्यवस्था देहातों में की गई है। वहां पर कभी डाक्टर होता है कभी नहीं होता है। अब आप ही बताएं कि कैसे इलाज हो सकता है। फिर पन्द्रह सोलह पैसे पर कैपिटा खर्च करने से क्या गरीबों का इलाज हो सकता है। आप देहात के पब्लिक का भी इन्सान समझें और उसके साथ इन्सानियत का व्यवहार करें। लोगों की मेहनत का ठीक करें। थोड़ा बहुत उनको आरोग्य भी आप करें। इस लिहाज से उनको इलाज की सुविधा देना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। इलाज के अभाव में वे लोग जादू टोने वालों की, छू मंतर करने वालों की, जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले बेवकूफों की शरण में जाते हैं और बेमौत मर जाते हैं। आपको चाहिये कि इस काम में आप राज्य सरकारों की मदद करें। इस जिम्मेदारी को, पब्लिक हैल्थ की जिम्मेदारी को आपको लेना चाहिये। राज्य सरकारों को खूब आर्थिक मदद देनी चाहिए। तभी जनता के स्वास्थ्य की हिफाजत की जा सकती है।

हमारे देश में मैडीकल कालेज बहुत कम हैं। जो हैं भी उनके अन्दर फीस बहुत ज्यादा ली जाती है। कैपिटेशन फी इतनी बड़ी होती है कि बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चे को मैडीकल कालेज में कभी नहीं भेज सकता है। आजकल मैडीकल कालेज बड़े लोगों के लिए हैं, प्रिवलेज्ड क्लास के लिये हैं। ये देहातों में होने चाहियें। एक एक ताल्लुके के अन्दर एक एक होना चाहिये। आज नहीं तो दस साल के बाद या पन्द्रह साल के बाद आप देखें कि हर जिले के अन्दर चार पांच मैडीकल कालेज कायम किये जाएं। इसके बगैर यह काम नहीं हो सकता है। यह काम सरकार का ही करना पड़ेगा।

तमाम अस्पताल बिजिनैस बन चुके हैं, कुछ अपवाद है, करप्शन और एक्सप्लायटेशन का अड्डा बन चुके है। इनका राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। जितने भी हैल्थ सैंटर है, दवाखाने है प्राइवेट हों या सरकारी इनका आप राष्ट्रीयकरण करें। इसके बगैर आप डाक्टरों को देहातों में नहीं भेज सकेंगे। वहां आज देहातों में क्या मिलता है? दवाई तालीम काम, रहने का ठीक जगह कुछ भी तो नहीं मिलता है और सरक्षण भी नहीं मिलता। इसलिए देहातों से लोग क्यों शहरों की तरफ नहीं आएंगे। मैं उनको कहने हैं कि देहातों में जाओ। वह बेचारा अंधेरे में जा कर रहें। वहां भूख और मौत के सिवा क्या रखा है? मुझे अफसोस और गम है कि आप देहाती लोगों का इन्साफ नहीं दे सकते। आप उनको इंसान कब मानेंगे? आज तक नहीं माना गया है इसका मुझे गम और गुस्सा है। वे लोग कुत्ता की मौत मरते हैं। उनके लिए दवा का इंतजाम ठीक हो इसके लिए जरूरी है कि मैडीकल इस्टीट्यूशन्ज का राष्ट्रीयकरण हो।

लोक नेता जयप्रकाश जी हमारे महान नेता हैं। उनके लिए डायलसिस मशीन का इंतजाम आपने किया। बहुत अच्छा किया।

गरीब आदमी जब किडनी की बीमारी से परेशान हो जाता है तो वह डायलसिस के लिए कहा जाए ? उसके लिए भी इसको मुहैया किया जाना चाहिये। जो सहूलियत जय प्रकाश जी को मिल सकती है वह अदना से अदना आदमी को भी, देहाती आदमी को भी मिलनी चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि देश में हमारे मरीज बगैर डायलेसिस के मर जाते है, कुछ नही कर सकते। महज मौत के अलावा दूसरा कोई उनका इलाज नही है। मैं पूछना चाहता हूं कि डाइलेसिस मशीन कितने अस्पतालों मे है जिले के ? कही नही है। इसलिये गरीब लोग अपने शहर मे उसका लाभ नही उठा सकते। इसलिये स्टेट के अन्दर उन अस्पतालों में डाईलेसिस का इन्तजाम होना चाहिये जिसका मुफ्त लाभ गरीब लोग उठा सकें।

इसी तरह से रिहैबिलिटेशन डिपार्टमैंट है। महाराष्ट्र मे कैंसर से और पैरेलिसिस की वजह से जिनके अंग बेकार हो जाते है उससे सम्बंधित इलाज की व्यवस्था केवल बम्बई में ही है। मेरा निवेदन है कि मराठवाडा और विदर्भ मे भी इसकी सुविधा होनी चाहिये ताकि मरीज लोगो को बम्बई में न जाना पडे।

माताओ और बच्चो की बीमारी बहुत खराब है, उनको न दवा मिलती है न अच्छा खाना मिलता है, न अच्छा पानी मिलता है। इसलिये कम उम्र में मरते है। कम से कम साफ पानी तो लोगो को देहात में पीने के लिये मिलना चाहिये। लोग स्वच्छ पानी के अभाव में परेशान हैं। इसका डाइरेक्ट ताल्लुक आप से नही है, मगर साफ पानी और सेहत का घनिष्ट संबंध है। जनता को पानी की व्यवस्था करना सरकार का फर्ज है। इसी प्रकार कुटुम्ब नियोजन का शिक्षा के जरिये प्रचार होना चाहिए। आजकल दीवारो पर एक स्लोगन है कि 'पहला बच्चा अभी नहीं तीन के बाद कभी नहीं'। यह स्लोगन ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि 'पहला बच्चा अभी अभी और तीन के बाद कभी कभी'। तो प्रोपेगेन्डा से ही अकेले प्रचार नही होगा बल्कि लोगो को बताना होगा शिक्षा के माध्यम से उसके क्या लाभ हैं। वह कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे एक ही बच्चा है, तब भी मैं गरीब हूं। न मुझे दवा मिलती है, न मैं सुखी हूं। एक ही बच्चा होने के बाद फिर कुटुम्ब नियोजन का फ़ायदा क्यों नही होना चाहिये। उसको मालूम होना चाहिये कि छोटा परिवार होने से फायदा होता है। केवल प्रोपेगेन्डा करने से लोग इसको नही मानेंगे। और इमरजेंसी के दौरान जिनका जबरदस्ती ऑपरेशन किया गया उनको दुबारा ठीक करना आपका फर्ज है। कई लोगों के एक ही बच्चा था जो मर गया। उनके और बच्चा कैसे हो ? तो ऐसे लोगो की नसबन्दी जोडने का काम सरकार का है। उन्हे कम्पेन्सेशन तो देना चाहिये, लेकिन साथ ही नसबन्दी भी सरकार को जोडनी चाहिये। महाराष्ट्र में और देश के अन्दर जहां भी ऐसे केसेज है उनकी नस जोडी जायें। सहायता का आपने आश्वासन दिया था। वह [illegible] है ?

देश मे जैसे नेशनल टैक्स पालिसी, नेशनल प्राइस पौलिसी, नेशनल ऐजूकेशन पौलिसी आवश्यक है, ऐसे ही नेशनल कौमन सिविल कोड की भी जरूरत है। जब तक ऐसा नही होगा तब तक कुटुम्ब नियोजन और कल्याण का प्रचार अच्छी तरह से नही हो सकता है। कुछ मजहब के लोग कहते है कि उनके धर्म मे नसबंदी ऑपरेशन मना है। जब मजहब की बात होती है तो यह देश तो सभी का है, चाहे हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई को भी, हो सभी का है, फिर यहां भी कौमन सिविल कोड होना चाहिये। अगर ऐसा नही होगा तो फेमिली प्लानिंग के बारे में जितनी आपको कामयाबी मिलनी चाहिये वह नही मिलेगी। इसलिये मुल्क मे जो ग्राम तबके के लोग है, जो सुविधाओं का सेन्ट्रेलाइजेशन शहरो में किया है उसका

[श्री केशव राव धोंडगे]

डासेन्ट्रेलाइजेशन देहातों में होना चाहिये और देहातों को वह सुविधायें प्राप्त होना चाहिये, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होना चाहिये, और अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

अन्त में एक बात और कहनी है। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के अन्दर दो, तीन महीने के पहले एक चीज मालूम हुई है कि कुछ बोगस डाक्टर भर्ती हो गये थे जो मैडीकल यूनिट के अन्दर काम करते थे। उन बोगस डाक्टरों को पकड़ा गया। उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अगर यह सही बात है तो यह घालमेल किस ने किया, किस के जमाने में हुआ, कौन इस के लिए जिम्मेदार है? यह हालत सफदरजंग अस्पताल की है। ऐसे केसेज कई जगह देहातों में हुए हैं, और शहरों में हुए हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान की जनता को अगर तमाम रोगों से बचाना है तो उन के लिए मदद करना और यह सहूलियतें देहात के अन्दर ले जाना यह सरकार का अव्वलीन फर्ज है। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित मांग रखी गई है और इस संबंध में जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी नयी योजनाओं की एक मोटी रूपरेखा सदन के समक्ष रखी है, इसी से यह बात साफ हो जाती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जिस रफ्तार से जो हमारी जनता पार्टी के मैनिफ़ेस्टो में निहित उद्देश्य थे उन को पूरा करने के लिए तत्पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री के व्यक्तित्व और स्वभाव का पूरा असर या छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय में जितने ज्यादा विवाद राष्ट्रीय स्तर पर उठे हैं वे बहुत मौलिक विवाद हैं जिन पर चिन्तन शुरू हुआ है और जिन का कोई रास्ता भी ढूंढा गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी रास्ता ढूंढा है। अपने देश में जो स्वास्थ्य के बारे में धारणा और दृष्टिकोण है वह हम जानते है। अब तक स्वास्थ्य सुविधा केवल वह वर्ग जो सुविधा सम्पन्न था उस के लिए थी। आप आकड़े देखें, शहरों में अस्पतालों की कितनी संख्या है, शहरी आबादी को स्वास्थ्य की कितनी सुविधा है और जो अपनी ग्रामीण आबादी है वहां पर अस्पताल नहीं, अगर अस्पताल है तो डाक्टर नहीं, डाक्टर है तो कम्पाउडर नहीं और डाक्टर कम्पाउडर है तो दवा नहीं। यह सारी स्थिति वहां है। इसीलिए जनता पार्टी का जो मैनिफ़ेस्टो था उस मैनिफ़ेस्टो में यह साफ दिया गया था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए जो मांग पेश की गई है और जो राशियों का आवंटन किया गया है वह भी इस बात को साबित करता है कि हमारा दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास का है।

दूसरी बात यह है कि हम केवल अस्पतालों के जरिए या केवल सरकारी संस्थाओं के जरिए अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए यह संभव नहीं है क्योंकि पिछले तीस वर्षों में 5372 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और करीब 37755 सब-सेंटर्स खोले गए जिस में कहीं एक डाक्टर और कहीं दो डाक्टर रखे गए, मगर इस के बावजूद जो स्वास्थ्य पर असर पड़ना चाहिए था वह असर नहीं पड़ा है। आज हिन्दुस्तान की जनता सब से ज्यादा रोगी है। हमारे बच्चे सब से ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं और तमाम प्रकार के रोग उन को हो जाते हैं, अन्धा होना, मानसिक विकास रुक जाना, शारीरिक विकास रुक जाना, ये सारी बातें हैं और इसलिए आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की थी कि हम कोई ऐसी योजना स्वीकार करें, जिस का लक्ष्य हो कि हम गांवों के उन गरीब लोगों तक जिन को कोई

सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य सेवा पहुंचा सकें। इसी को दृष्टि में रख कर यह जो एक वालंटियर जन-स्वास्थ्य रक्षक की योजना बनाई गई है यह योजना अपने में बहुत क्रान्तिकारी योजना है। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उस के बारे में बताया कि विदेश से जो वर्ल्ड बैंक टीम आयी थी उस ने भी इस योजना की भूरि भूरि प्रशंसा की है तथा तमाम देशों से जो शिष्ट मंडल आए हैं उन्होंने भी इस योजना की तारीफ की है क्योंकि यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली कांग्रेस की सरकार में भी सन् 64-65 में एक कमेटी का गठन किया गया था, उस ने भी कोई एक रूपरेखा बनाई थी, फिर उस के बाद एक श्रीवास्तव कमेटी भी गठित हुई थी, उस ने भी 1975 में कुछ सस्तुतिया सरकार के सामने पेश की थी। परन्तु उन सस्तुतियों को जिनको स्वीकार नहीं किया जा सका जो कार्यान्वित नहीं की जा सकी उनकी भी सीमा बहुत सीमित थी। उसमें केवल स्कूल कालेजों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को और सरकारी संस्थाओं के जो कर्मचारी थे उनका लेकर इस योजना को चलाने का प्रयास किया गया परन्तु जो रिपोर्ट आई उसमें साफ है कि विश्व-विद्यालयों, कालेजों के अध्यापकों या सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा जो उत्साह दिखाया जाना चाहिये था वह उत्साह नहीं दिखाया गया। इस सम्बन्ध में जो वर्तमान सरकार की योजना है वह ज्यादा क्रान्तिकारी है। उसमें सभी का, पूरी देश की जनता को शामिल करने की इच्छा है। इसीलिए उसमें दिया गया है कि एक हजार की आबादी के ऊपर एक ऐसे रक्षक या सेवक का चुनाव होगा, उसकी ट्रेनिंग होगी, सामान्य रोगों के निदान की जानकारी दी जायेगी। इस योजना को लेकर अखबारों में बड़ा विवाद चला क्योंकि अपने देश में एलोपैथी, पश्चिम की जो विदेशी चिकित्सा पद्धति है उसका बड़ा प्रभाव है। इस देश में अंग्रेजी का भी बड़ा प्रभाव है इसलिए कोई ऐसी योजना जिसका इस देश की माटी से सम्बन्ध हो, जिसका देश की गरीब जनता से सम्बन्ध हो, इस प्रकार की कोई योजना चले जिससे शहरों में एयर-कंडीशंड कमरों में रहने वाले डाक्टरों की लगे कि हमारी उपादेयता या उपयोगिता घट रही है तो एक झूठा विवाद देश के स्तर पर चला दिया जाता है। देश के स्तर पर यह विवाद चलाया गया कि यह बेयरफुट डाक्टर्स होंगे, हम तो लाखों रुपया खर्च करके अपनी डिग्री लेते हैं, मि० राज नारायण एक पोलिटिकल स्टण्ट चला करके पूरी चिकित्सा पद्धति को ही विकृत करना चाहते हैं। इस तरह का झूठा प्रचार पूरे देश के पैमाने पर चलाया गया परन्तु वह भी साफ हो गया कि उसमें कितना दम है। यह माना गया कि जितने डाक्टरों की आवश्यकता है वह हम मोहैया नहीं कर सकते। मेडिकल कालेजेज में पढ़े हुए डाक्टर्स गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं है, पर्वतीय इलाकों में जाने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं है। इस के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिवेंटिव है या बहुत से रोग ऐसे हैं जिन के बारे में अगर दवा की पहले ही जानकारी हो जाये और उस का उपाय किया जाये तो उन रोगों से देश की जनता को मुक्ति मिल सकती है। अपने देश में गांवों में तमाम ऐसी देशी दवाइयां हैं, लोगों को उन की जानकारी है, अगर उन का संकलित किया जाये और उन की जानकारी दी जाये तो वह बहुत उपयोगी हो सकती है। इस माने में विभाग ने जो यह योजना रखी है वह बहुत क्रांतिकारी है।

इस योजना के कई पहलू हैं। इस का एक पहलू तो यह है कि हम लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाये। इस का दूसरा पहलू यह है कि अपने देश में जो बेरोजगारी है उस को दूर करने के लिए अपने लोगों को कुछ काम दे सकें। यह एक उत्पादक काम है और सेवा का काम है। इस का तीसरा पहलू

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

यह है कि हम अपने देश की जनता को स्वास्थ्य की जानकारी दें। लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना—यह शैक्षणिक पक्ष है एजूकेटिव पहलू है। इस प्रकार से भी हम अपनी जनता की सेवा कर सकेंगे। इस माने में यह योजना बड़ी क्रान्तिकारी योजना है—ऐसा मैं मानता हूं।

14.00 hrs

इसी प्रकार से दवाइयों की बात है। आज हमारे गांवों में महिलाओं को किस प्रकार प्रसव पीड़ा होती है कितने ही बच्चों तथा महिलाओं की मृत्यु हो जाती है गन्दगी के कारण टिटनेस के केसेज हो जाते हैं। अभी हमारे गांवों में इस काम के लिए पेशेवर दाइयां या चमाईन जिनको कहते हैं वह हैं। परन्तु अब धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो रहा है इस प्रकार की जो महिलायें थीं उन में बहुत सी तो अकुशल हैं बहुत सी अब इस काम को करना नहीं चाहती हैं व इस काम को घटिया किस्म का काम मानती हैं अपने स्वाभिमान के विरुद्ध मानती हैं। कुछ इस प्रकार की शिकायतें भी मिली हैं कि हंसिया या कैंची से नार काट दी जाती थी जिस से टिटनेस या इस प्रकार की तमाम बीमारियां हो जाती थीं और मौतें हो जाती थीं। इन सब बातों को देखते हुए यदि इन दाइयों को ट्रेनिंग देकर डिप्लोमा दिया जाय तो हम देश और समाज के लिए एक अच्छी सेवा दे सकेंगे।

तीसरी योजना जो बहुत क्रान्तिकारी लगती है—"रेफरल काम्प्लेक्स सर्विस सिस्टम" की है। अभी तक जो मैडिकल कालिजिज या विश्वविद्यालय होते थे, वे अपनी दुनिया तक ही सीमित रहते थे, इन का सामान्य जनता से सम्बन्ध नहीं हो पाता था। जो पेशेंट उन के यहां आ जाते थे, केवल उन का ही इलाज होता था। लेकिन अब जितने मैडिकल कालिजिज खोले जा रहे हैं, यदि इन के प्रशासन के अन्दर इनके ... के अन्दर यदि उन के जिले, तहसील और उपनगरों को भी शामिल कर लिया जाय, तो इस से बहुत फायदा होगा, उन का गांवों के साथ सीधा सम्बन्ध हो जायगा। इस के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारतीय चिकित्सा परिषद् ने भी अपने नियमों में समाधान किया है और इस पद्धति को मान्यता दी है। इस वित्तीय वर्ष में 25 मैडिकल कालिजों न कार्यान्वयन के हेतु इस योजना को स्वीकृत किया है। इसी योजना के अन्तर्गत यह भी कहा गया है हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक चलता फिरता क्लिनिक देने के लिये इंगलैंड की सरकार सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है। इस योजना का हमें सर्वाधिक फायदा मिलेगा—ऐसा मैं मानता हूं।

परिवार कल्याण और परिवार नियोजन के बारे में इस सदन में और इस सदन के बाहर भी अखबारों में काफी चर्चा हुई है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारे वर्तमान मंत्री जी हैं वे इस परिवार नियोजन कार्यक्रम में ढील कर रहे हैं प्रयास को ढीला कर रहे हैं। मगर जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया गया है—हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से परिवार नियोजन या परिवार कल्याण के बारे में जो नीति जाहिर की गई है उस में साफ तौर से कहा गया है हमारी जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में भी साफ कहा गया है, कि परिवार नियोजन के लिये हमारा एप्रोच कोअर्सिव नहीं होगा, एजूकेटिव एप्राच होगा, शैक्षणिक एप्राच होगा और साथ ही वालन्ट्री भी होगा। इस की शिक्षा के लिये बहुत सी योजनायें चलाई जा रही हैं। इस समय हमारे पास जो आंकड़े हैं उन के अनुसार 15 वर्ष या उस से नीचे की आयु के बच्चों की संख्या देश की पूरी पोपुलेशन का 42 प्रतिशत है यदि इन को इस के बारे में शिक्षा दी जाय तो इस का बहुत लाभ होगा। एन० सी० ई० आर० टी० और राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालयों ने अपने सिलेबस में इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार किये हैं, यदि उसी के मौडल

पर पूरे देश के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया जाय जो परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की शिक्षा दे तो उस का व्यापक असर पड़ेगा। इस के अतिरिक्त कैम्प लगाये जायें और लोगों को इस की शिक्षा दी जाय। पिछली सरकार का जो सब से बड़ा दोष था पाप था, वह यह था कि उस ने पुलिस, सेना और कानून की ताकत इस्तमाल कर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की लेकिन वह दृष्टिकोण गलत था। वह यह मान कर चलते थे कि जो सरकार की विफलता है जो सरकार की असफलता है, उस का कारण केवल आबादी है। वर्तमान जनता सरकार इस बात को नहीं मानती। यह सही है कि आबादी बढ़ रही है और आज 615 मिलियन हमारी आबादी हो गई है और 1947 के मुकाबले में 270 मिलियन आबादी बढ़ी है। तो यह संकट है और चिन्ता का विषय है परन्तु सरकार यह मान कर नहीं चलती है कि केवल जन-संख्या ही सब कुछ कारण है। इसलिए जनता सरकार को अपनी एप्रोच अपनी दृष्टि और अपनी नीति में भी फर्क करना पड़ेगा। बदल करनी पड़ेगी ताकि उत्साहवर्धक नतीजे निकलें। इसके लिये यह आवश्यक है कि जो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और संगठन हैं उन का इस में पूरा सहयोग हो और जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उन को भी इस विचारधारा को इस योजना को इस कार्यक्रम को देश की जनता और खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचारित करना चाहिए।

नैतिकता के बारे में हमारे नेता डा० लोहिया जी कहा करते थे कि हमें नैतिकता के बारे में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। उन्होंने एक बार कहा था कि छ वैध बच्चों वाली एक औरत के मुकाबले में एक अवैध बच्चे वाली औरत ज्यादा नैतिक है। इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर नैतिकता के बारे में चले तो मैं समझता हूं कि इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को हम सफल कर पाएंगे और उस लक्ष्य को पूरा करेंगे।

इस के साथ ही साथ दवाओं को हम सस्ता करना पड़ेगा। बहुत सी दवाएं फैशन की दवायें हो गई हैं। तमाम प्रकार के टानिक हैं और दवाएं हैं जो कि एक साधारण आदमी के लिए आवश्यक नहीं हैं। जो लोग मोटे हो गये हैं वे दुबला बनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन का मोटापे के कारण और रईसी के कारण नींद नहीं आती है तो वे दवाओं के जरिये नींद लाना चाहते हैं। कुछ लोग जो बूढ़े हो गये हैं वे ऐसी दवाएं खा कर जवान होना चाहते हैं। इस प्रकार की दवाएं जो हैं वे एफ्लुएंट सोसाइटीज के लिए तो ठीक हैं लेकिन मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार की दवाओं का उत्पादन यहां पर नहीं होना चाहिए। बल्कि जो जीवन उपयोगी दवायें हैं, उन का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए और उन के दाम भी कम होने चाहियें ताकि वे दवायें सस्ती आम आदमी को सुलभ हो सकें। जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उस को इन दवाओं के बनाने में सहायता देनी चाहिए ताकि वे सस्ती हों और देश के परिवेश में आसानी से सुलभ हो सकें। आप यह देखिये कि दूसरे मुल्कों में और खास तौर से चीन में और जो दूसरे क्रान्तिकारी मुल्क हैं उन्होंने अपने यहां की चिकित्सा पद्धति का बहुत विकास किया है और उस को मार्डन बनाया है। उन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति का अनुसन्धान कर के, अपने भूगोल और अपनी परम्पराओं के परिवेश में अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उस को बनाया है और मैं भी यह चाहूंगा कि यह ज्यादा ग्राह्य होना कि हम भी उसी तरह से अपनी चिकित्सा पद्धति को विकसित करें। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उस ने जो इस मामले में चिन्तन किया है और उस के काम करने का जो तरीका है वह बहुत ही उत्साहवर्धक है और इसीलिए इस मंत्रालय ने देश की जनता के अन्दर और खास कर गरीब लोगों के अन्दर एक आत्मविश्वास पैदा किया है और लोग अब यह सोचने लगे हैं कि यह जनता सरकार

[श्री ब्रजभूषण तिवारी]

सचमुच में जनता का सरकार है और यह जो स्वास्थ्य मंत्रालय है यह सचमुच गरीब लोगों का मंत्रालय है ।

इस के साथ साथ अस्पतालों के प्रशासन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वह भी एक अच्छी चीज है । वह जो कमेटी बनी है, वह यह देखेगी कि अस्पताल का संचालन ठीक तरह से हो और जो गरीब लोग हैं, उन को दवाएं मिलें । दवाओं के मिलने की गारन्टी होनी चाहिए तभी गरीबों का भला होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

*SHRIMATI V JEYALAKSHMI (Sivakasi) Hon Mr Deputy Speaker Sir on the Demands for Grants of the Minister of Health and Family Welfare who has vowed to speak only in his mother-tongue Hindi I would like to express my views in my mother tongue Tamil and I entreat the Minister to be attentive to what I am going to say about his Ministry

Sir 80 per cent of our population lives in rural areas and the remaining 20 per cent lives in urban areas To cater to the medical needs of 0 per cent of our population 80 per cent of the Doctors are concentrated in urban areas From the newspapers I find that 20 000 Doctors are unemployed in the capital city of our country Yet in the Willingdon Hospital the Doctors are made to work for 18 hours a day In the neighbouring rural areas of Delhi the villagers fighting the onslaught of diseases for days together they do not get any medical attention While there is one Doctor for every 10 000 people in urban centres there is one Primary Health Centre for every 84 000 villagers We have 5352 Primary Health Centres in the country out of which there is neither a Doctor nor a Health Visitor in 1900 Primary Health Centres There are about 44,000 sub-centres in the country out of which only 39 000 sub-centres are effectively functioning I quote from an Article about the existing state of affairs in these Primary Health Centres

> Most of the PHC are staffed by fresh medical graduates Not all the centres are well-equipped or fully staffed though they are supposed to be focal centres for every medical service in rural India In fact, they have failed to be so in many spheres Their performance in the detection and treatment of tuberculosis as well as in maternity and child welfare has been far from satisfactory

I am sorry to say that the slogan of Go back to Villages which seems to be the soul-breath of the Ruling Party at the Centre has not been translated into action during the past year of Janata rule The rural medical needs have in fact been neglected by the Central Government

I can say without fear of contradiction that during the one year Janata Administration the population of the country has gone up As compared to 1976-77 during the period I April—December 1977 voluntary sterilisation has come down by 82 per cent and the acceptors of family welfare methods have also declined by 68 per cent The voluntary termination of pregnancy has also dwindled by 24 per cent In 1977 78 Plan a sum of Rs 121 47 crores was proposed for family welfare projects In the Budget Estimate for 1977-78 it was brought down to Rs 98 61 crores I would like to know why this reduction was made in the Annual Plan allocation for Family Welfare Even this allocation has not been fully appropriated The anticipated expenditure is of the order of Rs 90 crores only This shortfall proves that the family welfare schemes have not been successfully implemented I demand that the Officers of the Ministry res

*The original speech was delivered in Tamil

ponsible for not utilising the allocated funds should be proceeded against, as this failure will stop the fall in the population growth on account of steps taken by the former Government

When the State Governments committed to conduct the family welfare programmes on a war-footing want money, the Central Government shows its empty hands. It is really unpardonable that the funds allotted for the Central Sector schemes are not spent in full. I will give you from the Annual Report a comparative picture.

	Allocation Crores	Anticipated Expenditure Crores
1974-75	5 45	4·79
1975-76	6 33	6 16
1976-77	8 37	7 81
1977-78	9 68	7 53

Immediately I will be told that the former Congress Government at the Centre was equally guilty of such lapses I have not said this with any political motivation I say this in the interest of the people of the country which is no doubt the common objective of all of us here Whether it is the Congress Government or the Janata Government, the primary medical needs of the people of the country have not yet been met

Coming now to the problem of food adulteration I am pained to say that only 10 businessmen were convicted last year for adulteration A total of Rs 1 62,500 was realised from them It is not enough to levy fines and collect them Food adulteration is a crime against humanity and nothing short of public hanging should be the punishment The people are not going to tolerate such leniency towards offenders of such serious crimes I quote from the Annual Report:

> During the year 1976, a total number of 1,29 344 samples were drawn out of which 23,298 samples were found adulterated giving a percentage of adulterated samples as 18 per cent excluding States of Bihar Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Manipur and Delhi from where reports are still awaited.

This percentage may be very much higher after reports from these States are received

> During the year under report food inspectors of the Directorate General of Health Services drew a total of 103 samples out of which 28 were found adulterated 62 cases were prosecuted There were 10 convictions 34 cases were discharged or acquitted A total fine of Rs 1,62,500 was realised

From this statement if the people feel that the Janata Government is soft towards sinister gang of adulterators they will not be far wrong

It is claimed that Drugs Standard is a social measure intended to ensure that the community at large obtains drugs of standard quality The provisions of the Drugs and Cosmetics Act of 1940 are being enforced by the Central Drugs Control Organisation From the shabby way and shoddy manner in which this Act is being implemented, I feel that the State Governments may be entrusted with its enforcement Why should huge sums of money be spent on the Central Drugs Control Organisation which in fact does nothing worthwhile? During the period April to November, 1977 drugs, drug intermediates and

[Shrimati V Jeyalakshmi]

chemicals required for the manufacture of drugs valued at Rs 54 crores were imported Out of 279 samples sent for testing only 15 samples were found to be not of standard quality I quote from the Annual Report of the Ministry

> Consignments of drugs, which were found to be not of standard quality were either re-exported to the country of origin or destroyed or permitted to be re-conditioned

The value of such re-export or destruction or re-condition has not been indicated If the legal provisions cannot be effectively implemented, it will be good to repeal such laws rather than having them on the statute book What is the use of having organisations which do not implement the provisions of such social laws?

In the total mortality 25 per cent is infant mortality in the age group of one year and below In these circumtances you will be surprised to know that only a paltry sum of Rs 67 50 lakhs was spent last year on immunisation of children 0—5 years against diphtheria whooping cough and tetanus while their number is about 20 crore in the country I am sure that even this money has been spent on urban children and not single rural child would have derived any benefit from this

Sir the Pasteur Institute of Southern India in Coonoor was a historical landmark for its efficient working and now it is in its last breath A Project Report for DPT Vaccine production at the Institute has been prepared and I request the hon Minister to implement it immediately especially when the DPT Vaccine is in acute short supply

I quote from an article

> "In 1962 the National Smallpox Eradication programme was launched and in a period of less than 8 years 136 5 million primary vaccinations and 625 million secondary vaccinations were carried out By 1974-75 the objective was achieved

> As against this though the BCG Vaccination Programme was started as early as 1949 with the help of the International Tuberculosis Campaign and later WHO and UNICEF it has failed in significantly reduce the prevalence and incidence of tuberculosis in the country The National Sample Survey revealed that an average 1 8 per cent of the population has T B (This was conducted in 1955—58) Subsequent observations do not show any appreciate change except that there is a decline in the mortality rate Though the BCG vaccine is being produced in India (Madras) since 1948 the production is still inadequate to meet the potential demand In addition operational and packaging problems and insufficient number of BCG teams have been responsible for the poor coverage Out of the 23 million born annually only a small percentage get the BCG vaccine

MR DEPUTY SPEAKER From which magazine you are quoting?

SHRIMATI V JEYALAKSHMI From the Illustrated Weekly of India—an article written by eminent Doctors

> 'A combined vaccine—Triple or DPT—against diphtheria, whooping cough and tetanus is also being used routinely The first three month, of life and the fourth and the fifth dose are usually administered at the ages of 2 and 5 This would mean that annually we would need over 100 million dose of this vaccine The total production in the country is grossly inadequate to meet this demand'

It is regrettable that how much DPT is being produced within the country is not known as it has not been mentioned in the Annual Report

> "The polio vaccine, which is to be used at the same ages as the DPT

and along with it is to be administered orally. The annual requirement of this vaccine would, again, be over 100 million does In the year 1978, only 4 million doses were available. This vaccine has the greatest acceptability amongst all vaccineation procedures, is very cheap and easty to administer But it is not fully exploited to eradicate the crippling diseases of poliomelitis."

When the country needs 100 million doses we are producing only 4 million doses of such medicines How can we think of reducing infant mortality? Sir, it must be borne in mind that the wealth of the country lies in its healthy citizenry. We should create more productive capacity for these important medicines so that we can have in our robust youngesters a bright future

It is also necessary to give importance to indigenous systems of medicine which alone can give cheap medicine to our common people While Awurveda, Homeopathy, Unani and such other indigenous systems get overdue encouragement in the hands of the Central Government, the Siddha system in Tamil Nadu, which is as old as the country itself, has not received its due from the Central Government I demand that Siddha system of medicine must be encouraged by the Central Government

Mahatma Gandhi said that India lives in villages The Janata Party Members and Ministers who claim to be the true torch-bearers of the ideals of Mahatma Gandhi must ensure that 80 per cent of our rural population gets adequate medical attention Here, I may stress that the expenditure incurred by the State Governments on family welfare programmes in rural areas must be given as outright grants by the Central Government.

Before I resume my seat, I once again reiterate that till now the rural population has been neglected in the matter of medical amenities. Coming as I do from the rural areas, I can share their enguish and agony and it is time that we atone for our past mistakes by providing adequate medical facilities in the rural areas

श्री युवराज (कटिहार) उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं एक बुनियादी प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहूंगा। यह ठीक है कि जनसाधारण को अहर्ता प्राप्त डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध कराना और अंशकालिक अर्थ-व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दलों को प्रशिक्षित करना, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम है, उन को करना और मलेरिया रोग के विरुद्ध संघर्ष तेज करना, चिकित्सा विषयों में शिक्षा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण का बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना इस मंत्रालय का काम है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि 30 साल पूर्व भोर कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि कम से कम इस देश में ग्रामीण जनता को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये 5 हजार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हो। उपाध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष बीत गये, भोर कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही और 30 वर्ष के बाद आज 5 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हो सकी है।

आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि यह गरीब देश जो है इस की ग्रामीण आबादी दुनिया की सभी आबादी से अधिक गरीब है। आज भी 85 प्रतिशत भारत की जनता को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस का कारण यह है कि जो जिला स्तर के हमारे अस्पताल है या प्रखंड स्तर का जो हमारा स्टेट हास्पिटल है उस में दवा नहीं होती। बहुत कम दवा आती है। अधिकतर अस्पतालों में डाक्टरों का अभाव है। या तो डाक्टर नगरों में रहते है, नहीं तो विदेश चले जाते हैं। लेकिन टर्की में जब उन्हों ने चिकित्सा की शिक्षा का प्रारंभ किया था तो ऐसे छात्र प्रथम वर्ष से ही जो चिकित्सा शिक्षा

[श्री युवराज]

लेते थे उस मे उन का ग्रामीण जनता के जीवन मे जोडने की अनिवार्यता थी । अगर ऐसी पद्धति यहा पर भी होती तो आज ऐसी स्थिति यहा नही होती । जिस देश मे 106 मैडिकल कालेजेज है और अनेक चिकित्सा की सस्थाये है वहा उन के होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि गावो में ऐसे लोग जो बिलो पावर्टी लाइन है हरिजन और पिछडे वर्ग लोग है उन को दवा नही मिल पाता है । अगर वहा कोई अस्पताल है तो डाक्टर के बिना कोई चिकित्सा नही हो पाती है । प्रखड के स्तर मे अगर कोई डाक्टर है तो वह प्रत्येक प्रखड में तीन जो प्राथमिक केन्द्र है वहा जाता नही है । इस तरह यह क्या हो रहा है इस देश में दिल्ली पटना बम्बई आदि मे बडे बडे इन्स्टीट्यूट है जहा लोगो का उपचार होता है लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जिस आदमी को कोई रोजी रोजगार नही मिल पाता जो कुपोषण से पीडित है वह जब बीमार पडता है और अपने गाव के निकटतम अस्पताल मे जाता है तो उसे वहा कोई दवा नही मिल पाती है । ग्रामीण दवाओ पर और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालो पर हम कितना खर्च करते है इसे देखे । आप पाएगे कि जो हमारी सेवा का केन्द्र होना चाहिए था जो सब से पहले गावो की तरफ ध्यान देना चाहिए था वह नही दिया गया है ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने 2 अक्तूबर 1977 मे एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का आरम्भ किया है । इन की योजना है कि दो तीन वर्षो मे 8–9 करोड की आबादी के बीच एक एक हजार की आबादी पर एक एक जन-स्वास्थ्य रक्षक को पदस्थापित किया जाय और उसी के प्रशिक्षण के लिए इन के कार्यक्रम चल रहे है । मैंने एकाध बार निवेदन किया था कि आज जितनी चिकित्सा सस्थाए खडी है गावो मे प्रखड के स्तर पर या प्राथमिक चिकित्सा के जो केन्द्र हैं उन मे से 40 प्रतिशत प्राथमिक चिकित्सा के केन्द्र अधूरे पडे हैं । कही नीव डाली गई है तो दीवार नही है, कही दीवार खडी है तो ऊपर छत नही है और कही मकान बन गया है तो वहा चिकित्सा के लिए कोई डाक्टर उपलब्ध नही हो पाता है । विलेज का जो एक हैल्थ वर्कर है वही असल में ग्रामीण जनता का डाक्टर है । इन की योजना है कि एक हजार की आबादी एक व्यक्ति को चुनेगी जो प्रशिक्षण लेगा । वह प्रशिक्षण कौन देगा जो क्वालिफाइड डाक्टर है । मै कहना हू कि जितने लोग प्रशिक्षित हुए है जिन को दो सौ रुपए स्टाइपेन्ड तीन माह तक मिलता है आप इस की जाच करवाए 75 प्रतिशत जो प्रशिक्षित लोग न कही कोई दवा देते है न कही कोई काम करते है । सब अपना काम करते है । आशिक रूप मे भी वे जनता के बीच नही जाते है । किस तरह लोग रह किस तरह बीमार होते पर लोगो को दवा मिले इस की कही कोई व्यवस्था नही है । तब यह कहेगे कि अभी हमने शुरु किया है । लेकिन मैं यह कहना चाहूगा कि यही जिम्मेदारी अगर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षको पर सौपी जाती जिन गावो के बच्चो को वे पढाते है उन गावो की जिम्मेदारी वे लेते तो मै समझता हू कि वे इन लोगो से ज्यादा कारगर साबित होते जिन को चुना गया है और जिन्हे प्रशिक्षण किया गया है । मै समझता हू कि यह 4 7 करोड रुपया जो 77–78 मे था और जो इस काम मे खर्च होगा वह रुपया हमारा बेकार जायगा । गावो की जनता को चिकित्सा की कोई सुविधा नही मिल सकेगी ।

मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि मैं बिहार मे आता हू हमारे यहा पटना शहर की आबादी 6–7 लाख है । पटना नगर मे जो लोग रिक्शा चलाते हैं या कुली का काम करते है बिलो-पावर्टी-लाइन जिनकी आमदनी है क्या वे लोग मसहरी खरीद सकते है ? पटना ही नही, उसी प्रकार के जो और शहर हैं जैसे आप कलकत्ता मे चले जायें—उन तमाम नगरो में लोग सो नहीं सकते हैं,

मच्छरों के मारे परेशान हैं । सन् 1976 में साढ़े सात लाख लोग मलेरिया से पीड़ित हुए और 1977 में, जैसा आप कहते हैं, 60 लाख लोग पीड़ित हुए तथा हजारों नहीं लाखों लोग मरे । हमने जहां मलेरिया का खत्म छोड़ा था वहां वह वापिस आ गया है । इस सम्बन्ध में जिस राजनीतिक संकल्प की आवश्यकता थी जिस मुस्तैदी के साथ सफ़ाई का काम करना चाहिए था वह नहीं हुआ । हम नगरों में अंडरग्राउन्ड नाली बनाने का काम वहां कर सकें । आज पटना में जाकर देखे जानिए। गंदगी से भरी रहती है वहां पर कोई अंडरग्राउन्ड ड्रेनेज सिस्टम नहीं है । लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है । मंत्री जी कहेंगे कि पानी पिलाने का काम हमारे विभाग का नहीं है लेकिन जन स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर भारत की जनता को शुद्ध पेय जल नहीं मिलेगा तो पेट की बीमारियों का इलाज डाक्टर की चिकित्सा से नहीं हो सकेगा । इसलिए इसका अन्यान्याश्रित सम्बन्ध है शुद्ध पेय जल की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगा । इस देश में केवल दस प्रतिशत लोगों को ही शुद्ध जल नलों के द्वारा मिलता है लेकिन इस देश के गांवों की क्या हालत है ? आज जरूरत इस बात की है कि ... अधिक खर्च करने के बजाय केन्द्रीय सरकार शत-प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल ... पर खर्च करे ।

हमने कई बड़े बड़े अस्पताल बनवाये हैं, केन्द्रीय सहायता के बल पर बड़े बड़े अस्पताल चल रहे हैं । इसी दिल्ली शहर में आप विलिंगडन अस्पताल चले जायें आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट चले जायें, वहां पर सात-आठ सौ पलंग हैं लेकिन रोगियों की संख्या अपार है । रोगी नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं । इसमें बेचारे डाक्टर भी क्या करें । जरूरत इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा वार्ड बढ़ाये, अच्छे डाक्टर्स और अच्छे इक्वीपमेन्ट्स की व्यवस्था करें तभी रोगियों की सेवा की जा सकती है। आज अस्पतालों में इनडोर और आउट डोर पेशंट जो इलाज करवाते हैं उनके रिश्तेदारों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । वे बेचारे सड़कों पर या स्टेशनों पर मारे मारे फिरते हैं । आज जहां दिल्ली हरियाणा में उत्तर प्रदेश, पंजाब राजस्थान से जो लोग चिकित्सा कराने के लिए आते हैं उनके रिश्तेदारों के लिए अस्पताल के बगल में धर्मशाला की व्यवस्था करनी चाहिए । इसके लिए अलग से ब्लाक बनाए जाने चाहिए। साथ ही बेड्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए । आज दुनिया में जो विकासशील या विकसित देश हैं उनके मुकाबले हमारे देश में सबसे कम चिकित्सा और दवाई पर खर्चा होता है । और इस देश में सबसे कम बिहार में पर कैपिटा हेल्थ पर खर्च किया जाता है । आज हालत यह है कि सम्पूर्ण देश में सबसे कम खर्चा बिहार में दवाई और हेल्थ पर हो रहा है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता कि जब तक ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं होती जब तक इस दिशा में कोई आमूल परिवर्तन नहीं होता तब तक केवल सतह को छूने से इस समस्या का निदान नहीं होगा। इसका निदान तभी सम्भव है जब हमारा राजनीतिक संकल्प कार्यान्वित होगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) Mr Deputy Speaker Sir, in his introductiory speech on the Demands of the Ministry of Health & Family Welfare the hon Minister has claimed that he has brought about a revolution in the field of medical science. I do not agree with him at all Sir only 2 per cent of the total plan budget has been allocated for Health At page 12 of the Report of this Ministry for 1977-78, it has been said:

"Out of the oltlay of Rs 124.50 crores for Centrally sponsored

*The Original speech was delivered in Bengali

[Shri Ajit Kumar Saha]

Schemes Rs 75 00 crores have been allocated for Malaria Containment, Rs. 7 00 crores for Leprosy Control, Rs 450 crores each for Smallpox Eradication and Training and Employment of Multipurpoe Workers Rs 22 63 crores for Rural Health Scheme (CHWS) and Rs 4 44 crores for Re-orientation of Medical Education'

The hon Minister has of course stated that he has increased the allocations under certain heads like malaria control leprosy control etc We accept that he has increased these allocations to some extent but keeping in view the size of our population even that is too meagre We all know that 70 per cent of our people live in villages But the allocation for Rural Health Schemes is only Rs 22 63 crores in the budget This small amount has been allocated for about 40 or 45 crores of people who live in the rural areas in our country We are ashamed to say that even after 30 years of independence there is no provision of drinking water in about 4 lakh villages This budget is totally silent about providing clean drinking water in the villages In this reoprt I do not find any stress on the importance of pure drinking water for the health of the people and no funds have also been allocated for this purpose Although after the Janata Government came to power the hon Prime Minister and the Health Minister repeatedly assured that pure drinking water will be provided in the villages but there is no indication of its implementation in the Ministry s budget as no funds have been allocated for this purpose Then Sir health is said to be a State subject If the Centre spends only 2 per cent of its budget on health, how much can we expect from the State Government? Out of the funds provided by the Centre, the States cannot be expected to spend any substantial amount for Health That is why all those medical colleges, hospitals, health centres etc, that are under the control of the State Government are in a pitiable condition today Speaking about Medical, Colleges Sir, there is a medical college in the Bankura district of West Bengal The number of beds in this college are too few and inadequate, 2 3 patients are kept in one bed Some patients are kept on the verandas under the open sky The financial condition of the State Government is not such that they can undertake extension and expansion of accommodation or other medical facilities The ambulance facilities are also so inadequate th t serious patients from far flung places cannot be brought to the hospital for treatment Sir Bankura particularly South Bankura is inhabitated mostly by Adivasis and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people Central Government is responsible for the welfare of these people Therefore I will urge upon Raj Narainji to provide more funds to the State Government so that more primary health Centres may be opened in the backward areas like Idpur Raipur, Ranbandh etc where a substantial number of Santhals and Scheduled Castes people live More funds should be made available to the State Government for the welfare of the e people

Sir a few days ago a meeting of the State Health Ministers was held here The three day joint conference of the Central Council of Health and Family Welfare recommended the setting up of a Medical and Health Education Commission to ensure a coordinated approach to medical education and carrying forward the process of reorientation"

The hon Minister has said that he would hold consultation with the Ministry of Education and try to see that health education may be included in the course of studies in the primary and middle schools. I will urge upon him to ensure that health education is made a compulsory subject in the primary and middle schools Proper attention may kindly be paid to this aspect /

Sir, the joint conference made another recommendation. It said "Private practice by Government doctors and also those in medical colleges should be banned. Instead, compensatory non-practising allowance might be given." If the Government accepts this recommendation then I believe some of our doctors may be induced to work in the primary and subsidiary health centres in the villages which are facing a serious shortage of doctors. The poor patients in the rural areas will thereby be greatly benefited. Along with this, Sir, I will request the Government to revive the L.M.F. courses where certificates used to be issued to medical students previously. The degree holders in medicine and surgery are generally not interested in going to the rural areas for want of proper facilities there. Therefore the lesser qualified certificate holders may go to the villages and the poor village people will stand to benefit. This may kindly be considered. Sir, the earlier malaria eradication programme has been scrapped and now the malaria control programme has been initiated. In the city of Delhi malaria is again spreading. Why in Delhi alone, the way malaria is staging a come-back in the whole of this country is really a matter of great concern. Malaria is spreading in Calcutta also. The incidence is increasing everywhere. The reason for this is water-logging due to faulty and inadequate drainage system. The State Governments must be given more funds to improve the drainage system. They are in poor financial condition and cannot undertake this huge task all by themselves.

The incidence of Filaria is also increasing. Proper attention should be paid to control it.

Now I will say something about Leprosy. In my constituency, Bankura, there is a leprosy centre, called the Gouripur Leprosy colony. The patients have often complained to us that proper supply of medicines are not available at that centre. The food supplied to them is also very poor in quality. The old contractor system for food is continuing there and the patients are not getting proper food. The poor patients are absolutely helpless. Some of them have lost their limbs and being leprosy patients, they cannot move out or approach people for complaining or protesting. The leprosy Department is under the Central Government, I will therefore request the hon. Minister kindly attend to this.

Sir, the incidence of blindness is also increasing in the country. About 50 lakhs of people are suffering from blindness. The main reason for blindness is said to be malnutrition. If they get proper nutrition, they perhaps would not have turned blind. Another dangerous thing is adulteration which is also increasing day by day. Even in Delhi, it has been found that the mustard oil that is selling in tins under the brand 'Kanodia' is so highly adulterated that its consumption may even result in cancer. Attention should be paid to the aspect of adulteration of foodstuffs.

Sir, about 8 lakh people in our country are suffering from cataract of the eyes. I will therefore request that mobile eye-hospitals may be provided for the people where eye operations may also be undertaken, by qualified doctors. This will enable a large number of poor people to regain eye-sight. About Family Welfare, Sir, the name family planning has been changed to family welfare. Attention must be paid to see that there is no compulsion and coercion in the family welfare programmes of Government. Due to the attocities committed on the people in the name of family planning during emergency, people have become scared of it. They must be persuaded and educated in matters of family control. The fear must be removed from their minds. Publicity must be given to the benefits of family welfare programmes. The voluntary welfare organisations should be associated in these programmes. The

[Shri A K Saha]

women s organi ations and the Far mers and Trade Union Organisations should also be associated in these pro grammes for their success

Sir a class of people with vested interests propagate among the people that all our misery poverty etc are only due to our rising population But this is not correct In our neighbouring country China there are 80 crores of people Whereas our population is only 60 crores But there is no problem of poverty or unemployment They have included family planning in their national plans and that is working very smoothly They have been able to achieve hat being a socialist country But in our country we are not meeting with success because the capitalist system is prevailing in our country The women have not been emancipated as yet Unless the women are properly educated in the matter of family planning, success will be elusive Women should be emancipated and the younger generation should also be educated in this A little publicity on the Radio and T V is not going to achieve much There must be voluntary mass involvement in these programmes With that Sir I conclude

DR BIJOY MONDAL (Bankura) Mr Deputy-Speaker Sir I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Health and Family Welfare

The name of this Ministry has been changed when this hon Minister took over this Ministry It is a welcome decision and it is consistent with the philosophy of family welfare

The national health programme of a big country like ours needs a good infrastructure for its proper implementation The country has a good technical team of doctors and medical personnel and these doctors sometimes claim that they are not going to the villages as they have not found these places of work convenient for them I say that there is a great demand for Indian doctors in various countries abroad and we have found that doctors from India are working in a very bad atmosphere in countries like the Middle East, UAR Africa and other places So why the Indian doctors are not going to our villages has to be given deep thought It is found that when a doctor is sent to a health centre in a village that primary health centre has no medicine and the doctors have no accommodation It is also found that doctors are put in a very awkward position when patients come and demand medicine and demand the supply of other preventive drugs and the doctors cannot supply them They are taken to task and the doctors are sometimes assaulted also due to the misunderstanding of the local people and the patients In a country like ours which has a fine technical team of doctors they are not being utilised properly due to lack of resources and due to lack of money and due to lack of cheap drugs and other things

Recently a scheme was introduced—the scheme of Community Health Workers in every village—but that scheme, probably will not be helpful to the people of India because these people who are recruited as Community Health Workers need the qualification of only Sixth Standard and they get only 12 weeks training for getting them equipped with the idea of treatment and preventive aspects of medicine I think this type of personnel will not be enough to treat the people of the villages and, more especially they will not be able to take on the responsibility of the preventive aspect of diseases

I would like to say, in this connection, that the Community Health worker's scheme which has been taken up by the Central Government, is not

being properly implemented by the State Governments. I would like to draw the attention of the Minister and the Central Government to the fact that it should be properly implemented. Or, the money that is paid to the Community Health Workers—who get Rs. 50 per month and Rs. 50 p.m. for medicine—may be utilised for some other purposes. If possible, we should at least appoint part-time doctors with that money If a doctor is available in the village and that doctor is entrusted with the job of treating the people in the villages and is asked to handle the preventive aspects also, on behalf of the Government, then the money which is now being given to the Community Health Workers could be given to the doctor who is treating the village people without any fees at present. Therefore, doctors must be initiated in this scheme of community health service, there can be *ad hoc* appointments, so that this type of scheme could be successful. The community health programme requires a rethinking on these lines. As it is, the workers engaged in this programme, having a very low standard of education as well as with a very short duration of training will not prove effective either on the preventive side or on the curative side of the health.

Another thing about which I would like to mention is that the system of medical education in India today is a back-dated one. In view of the various modern developments, the complexion and character of the community has undergone a lot of change and we have today many complex and complicated problems. The teaching system of medical education has, however, not changed with the changing times. I would suggest that the medical education should be separated from the general university education. This is because the preventive aspect has been neglected all along and more stress was all the time given to the curative side. The curative side is given more importance than the preventive side here. On the other hand, preventive aspect requires more emphasis and importance as compared to the curative side.

14.57 hrs.

[SHRI SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

We find that the general universities are concerned only with giving the medical examination; they are not intrested in introducing a change in the medical education according to the changing times. In view of this, I would request that separate medical universities should be established in each State and they should think over the present needs of the society and bring about the required changes in the matter of medical education The whole medical education including the Indian system of medicine should come under such State medical universities. That would be the real answer for this.

Sir, the country needs more hospitals, specially in the rural areas to meet the health demands of the rural population. My other colleagues here have already mentioned that drinking water is one of the main sources for transmitting infectious diseases from one person to another. For fighting out these infectious diseases, certain positive steps need to be taken and one such step would be to provide good drinking water to the people. That is very important and we must take steps in that direction.

15.00 hrs.

Another thing which we should consider is the supply of cheaper drugs to the rural population. We find that even today certain life saving drugs are not available in the market and the cost has gone up to two to three times. I would suggest to the Government that our drug industry should produce certain life saving and basic drugs at a very low cost and that drugs should be available to our villagers in the villages where the people are living below subsistence standard.

Population explosion is going on. The poverty line which was 35 per cent in 1947 has increased to 70 per

[Dr Bijoy Mondal]

cent during the last 30 years It is rather something which was not taken into consideration by the then previous Government

Lastly I shall say a few words regarding the Third Pay Commission s recommendations It was found in the Third Pay Commission s recommendations that all General Duty Officers of Grade II were to be made Class I on 1-1-1973 But for the last five years the case of these 600 officers is still pending No action is being taken in this regard

Officers in the category of Class I were also due automatic promotion on 1-1-1973 Since 1 1-1973 their cases are also pending In that matter also no action has been taken

Additional Secretary had assured that posts of Super Time Grade II Officers will be increased so as to make it 30 per cent of the Senior Class I Posts Nothing has been heard about this

The Third Pay Commission has also recommended to reserve Super Grade II posts of GDOs But even then Special Officers are being posted in these posts leaving no room for GDOs

Foreign assignment of the doctors has been banned by the Central Government But State Governments have not banned this This discrimination should be removed

The other thing to which I shall draw the attention of the Government is the indiscriminate extensions which are being given to doctors thereby blocking the promotion of the doctors in the lower ranks This extension may be granted in exceptionally qualified doctors cases but indiscriminate extension may not be granted to others

With these words I conclude

SHRI P V PERIASAMY (Krishnagiri) I would like to say something in regard to family planning

I am a doctor I have worked in the rural areas where no doctor was prepared to go

Sir in our country 60 per cent of the poor—downtrodden—people whose parents are earning below Rs 60 per month are completely suffering from all sorts of contagious diseases like tuberculosis leprosy and scabbies and helminthic infection Because the poor people are working in the field they get infected with hook worms spreading the diseases like ascarasia which will suck all the nutritious food that they are taking and they may become anaemic and it may lead also to loss of eye-sight resulting in night blindness Because the people are poor they are suffering a lot Not only that Scabbies are most commonly affecting the poor only If they are not properly treated it may lead to renal failure They may need haemodialysis That facility is available only in capital cities and not in the rural areas

I would like the hon Health Minister to provide the haemodialysis facility in all the medical colleges It is the poor who suffer from malnutrition diseases they are also affected by hookworm infection They will become severely anaemic and they will die as a result of that Sir the poor people are earning an income which is below the subsistance level So you should give more facilities to the poor

Sir the country is faced with population explosion That is because most of the people are not educated Because of that they go on producing We do not know what will happen to our future My suggestion is that family planning must be spread through education A picture should be taken and that should be shown in all the villages in the cinema houses etc The picture should depict as to what are the common diseases that the poor people will get and how to prevent them Picture should be shown in the villages on how to avoid birth and how to prevent septic abortion which some quacks resort to People will understand well by seeing the pictures They will also become vigilant and they will learn what are the diseases

they are getting. My suggestion is that all panchayat councils will have to be provided with the family planning pictures so that they can be shown in all the villages and by seeing them the people will understand what are the facilities given after sterilisation etc. Otherwise they are not at all able to utilise the sterilisation facilities By seeing the picture alone they will understand how to prevent birth Sir, 40 per cent of our population are more than 15 years of age and in three years period they will become adults, or reach the stage of reproduction How are you going to check this? These adults should be permitted to see those pictures. It is only through that that your family planning may succeed in this country

Now, Sir I would like to say something regarding the triple antigen, B C G and Polio vaccine In the district headquarters they are not able to get the polio vaccine Government is ready to spend thousands of rupees on the person suffering from titenus We can easily prevent the disease by making available in the dispensaries the triple antigen vaccine It is not available in the taluk headquarters, Panchayat Union dispensaries and in the primary health centres.

I would like to ask the hon. Health Minister to see to it that in all the panchayat union dispensaries, primary health centres and in taluk headquarters, the triple antigen vaccine, polio vaccine and B C G. vaccine are made available.

At the same time I would like to say that in taluk headquarters we are not having any x-ray plants and clinical labs. Suppose a man comes with fracture we have to refer him to district headquarter hospital which is fifty to sixty miles away. In this process the patient is put to lot of difficulty and is also not able to get proper treatment. Then, Sir, clinical examination is of foremost importance for finding out diseases. Each and every primary health centre and taluk centre should have clinical labs.

Then, Sir, we do not get streptomycin and chloromycin. I am a doctor. I had been to my native place and I prescribed streptomycin and chloromycin but we were not able to get streptomycin even in district headquarter hospital. All these imported vital drugs like streptomycin, chloromycin and tetracycline should be made available and they should be given to poor at a cheaper rate.

Now, I come to aminitoye fluid test which is not available in India. It is rather a matter of shame. Through aminitoye fluid test we can study the chromosomes and find out whether the pregnancy is that of a male or female child. When, Sir, termination of pregnancy has been legalised, I do not know, why we cannot conduct this test Supposing somebody wants a male or a female child he can utilise this test Earlier this test was available in the All India Institute of Medical Sciences I would ask the hon'ble Minister to make available this aminitoye fluid test hereafter.

Then, Sir, in the villages most of the poor are suffering from mal-nutrition. Mal nutrition produces hypoprotinimia, night blindness, de-generation of eyes. So, we should take care of mal-nutrition among the poor. At the same time I would like to say that we are now preparing at Coonoor an anti-rabies vaccine. This institute should be given more encouragement and implements Then, Sir, at Central Pharmacy, Madras a machine for the preparation of distilled water, dextrose and normal saline is lying idle. It was bought ten years ago. I would ask the Minister to make use of this machine for the production of above items to fulfil the requirements of the State Government

Now, I would like to say a few words about medical education Now, the students are studying pre-preparational course which is not at all useful. Whatever subjects are taught in the pre-university are once again taught in the pre-preparational course. So, Sir, I would suggest that instead the

[Shri P V Periasamy]

present period of one year be made two years for the study of anatomy, physiology, bio-chemistry, organic chemistry etc Then, Sir, at present those who pass MBBS are doing one year house-surgeon This period of one year can be extended to one and a half years thus devoting six months to medicines, six months to surgery and six months to OBG In this way they will have more training knowledge and practical experience

Then, Sir, in Tamil Nadu we are having nilakalyani medicines, namely, vincorosea These medicines are meant for the treatment of blood cancer At present the foreign countries are purchasing the raw material from us at a very cheap rate and then they process this raw-material at their place through sophisticated machines and sell this anti-blood cancer drug at a very high rate So, I would like the hon ble Minister to allocate more money and prepare semi-solid preparations and export them so that we may earn more foreign exchange

Nitya Kalyani is very famous in South India and you must utilise this drug and make use of it At the same time in Tamilnadu we are having mobile dispensaries instead of introducing bare foot doctors Suppose a bare foot doctor goes and give aspirin to a peptic ulcer patient the reaction is that there is perforation in the peptic ulcer and he may die So instead of introducing bare foot doctors, Tamil Nadu Government has introduced some mobile clinics increased the mobile clinics with more facilities to serve the poor people and appointed more qualified doctors There are so many doctors unemployed and so those doctors can be taken and appointed and given more facilities in the mobile clinics so that they can work in the rural areas Now qualified doctors are working only in the urban areas and sometimes people are able to get special treatment needed only in the urban areas not in the rural areas Suppose somebody has CCF and you want to have cardio-vascular treatment, it is available only in urban areas, suppose somebody has acute renal failure or when you need dialysis treatment you can have them only in the urban area You have to make arrangements for saving the life of the poor in the best way possible

Qualified doctors who are working in government hospitals are practising privately in the evenning times and earn money They will advise them to come to the hospital and send them for investigation and then they will give treatment in such a way which adds to their income Government doctors should not be allowed to have private practice in the evening because there are so many unemployed doctors and they should be given a chance and they should be helped by giving loans from banks for opening nursing homes, that way unemployed doctors should be encouraged to come up Those who are already in employment should be curbed from having private practice

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore) I will be very brief because Shri Kishore Chandra Deo from our party had already initiated the debate I want to stress that health and family welfare according to our Constitution are state subjects and the state Governments should look after the details of implementing health programmes and health education and the Central Government is only there to set policy directions and give guidelines and give aid But unfortunately an impression has been created in this country that the Central Government is today manned by people who do not believe in the advances of modern science and technology and modern medicine by people who are obscurantists who want to go back to the primitive days You know a long time back Dr Lohia wrote a small treatise on Marx Gandhi and Socialism If I were to write a small treatise on the situation that is today perhaps it could be called Gandhi, Marx and Raj Narain, Gandhi, Lohia and Raj Narain To talk of Gandhi and Lohia, both were great men, educated abroad; both were

great politicians; one thing that is to be noticed about them is that both were never in power, never in government; they never even knew that their disciples would one day be in government. Gandhiji personally believed in nature cure even when his wife was dying.

SHRI RAJ NARAIN: Dr. Lohia has written a book, "Will Power". You must read that book.

SHRI SAUGATA ROY: What I was saying is that Gandhiji even when his wife died refused to have an operation. But when his niece had appendicitis, he allowed appendictomy. Dr. Lohia gave the theory of Janbasha, Janbusha, Janbojan and Janswasthya.

श्री राज नारायण : जन शब्द का नहीं बल्कि 'लोक' शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया था क्योंकि लोक शब्द में जन, नदी, नाले, पहाड़ सभी आ जाते है ।

SHRI SAUGATA ROY I am sorry, Lokbasha, Lokbusha, Lokbhojan and Lokswasthya. He gave that theory because he was in the Opposition and wanted to attract young men to his side He did not take it from the point of view of the Government. But unfortunately today in the Government we have people who have taken Gandhiji's and Dr. Lohia's words literally and they have brought those approaches in the running of the Government. As a result of that the clock is being set back. What has been the main achievement of the country in the last thirty years? It has been that this country has been able to cut down its death rate The average death age which was around 24 in 1947 has gone upto 50 and this has been mainly due to improvement in nutrition and eradication of communicable diseases. We have eradicated small pox and we have eradicated malaria. But in one year, Shri Raj Narain, our favourite, with all his half-baked theories about Gandhiji, Lohia and nature cure, what has happened in the country. We have a reincidence of malaria and Kalazar and the number of sterilisation goes down from seventy lakhs to eight lakhs. What is the most dangerous of all— it is for the country to take note of it —is that there has been no medical college or dental college which has been set up in the whole of last year and the Government does not propose to open any new medical college in the next year. Today we know that our villages are short of allopathic doctors and that there is a great clamouring for admission into medical colleges and the Government has stopped any expansion of further higher education in modern medicine. It is alright; the Indian medicine is alright. But let me say this. Mr. Raj Narain is following Mao Tse-Tung. But what Mao Tse-Tung has done? In a totalitarian country with limited resources, he introduced the concept of bare-foot doctors and the bare-foot doctors went to the villages and they lived in the communes and they worked with the people He discovered the old arts of China like acupuncture. But you have to remember that Mao Tse-Tung's was a highly centralised Government and there in the name of doctors, people do not act as quacks. They will be shot. There is a Communist Party to control them Here when you talk of Janswasthya I agree with the concept that in our country more than medicine basic health education is necessary As Gandhiji used to say, if at least our people know how to dispose of their nightsoil, half of the diseases like hookworm would be eliminated. That is necessary But in our country where there is no organisation at the bottom level, no political organisation, no political will, it is bound to happen that these people will turn into quacks, who will after some time write 'Dr.' before their names and dole out medicines. That has happened time and again and that will happen again. That is why the Indian Medical Association has opposed unequivocally your new Rural Health Scheme. Not, that I am against it. As I said, I agree with Dr. Lohia's and Gandhiji's ideas, but what machinery do you have to implement these ideas? It is alright to do nature cure for minor ailments. But I am making

[Shri Saugata Roy]

a statement here in the House that given a choice 99 per cent of the people will choose allopathic medicine rather than homeopethic, ayurvedic and unani medicine People go to them because they do not have the money to buy drugs because they do not have money to go to doctors If you can provide drugs at cheaper rates and cut down the foreign monopoly on drugs people will take to modern science and medicine Today is the day when man is reaching the Moon and you are getting his telemetry and ECG sitting here on earth

This is no time to go back, this is the time to look forward Today is the day when man is having heart-transplant lung transplant Kidney Transplant and liver transplant this is not the time to look back So I say that the approach of the Government should be science oriented Modern oriented We should not give an idea abroad that India is again becoming primitive We are lapsing back into our previous times into our ignorant times and this is the approach that should be stopped I wish Sh Raj Narain remains the Health Minister for five years let him forget for five years that he was an agitator following Dr Lohia's lines and let him remember that he is the Health Minister of a newly emerging country called India to which the benefits of modern science and medicines have reached Only then can be fight with the modern diseases

MR CHAIRMAN Let him also take the assistance of Dr Sushila Nayar

SHRI SAUGATA ROY Sir one or two points I want to add With reguard to the Indian Institute of Experimental Medicine it is now under the CSIR I want him to take it under ICMR (Indian Council of Medical Research) Secondly I want him to give some more aid to the Chittaranjan National Cancer Research Centre in Calcutta which has been doing pioneering work in cancer research

The third is with regard to the population policy that has been set out Now that one year has passed the question of forcible sterilisation is over Now, this population policy should be implemented with all sincerity, giving proper incentives to the people and Indian medicine, let it remain for some people who want to do research Let him reach the benefits of modern medicine and modern scientific advances to the common man

Lastly, I want to tell you one thing It is my charge you may say that under this Ministry the CGHS is in a very precarious condition I have a number of clipping on the CGHS which say that 600 ad hoc doctors were about to be dismissed

Lastly what about the appointment of the Director General of the CGHS? I quote from the *Times of India* dated 9th January 1978

Supersessions grow in CGHS

The appointment of Dr B Shankran as Director General of Health Services by superseding three top health and medical administrators has caused great resentment among Central Government Health Service officers in the country'

And what do they also say? They say

Senior officers have also questioned the propriety of having two members who are specially indebted to Dr Shankran on the Departmental Promotion Committee Dr. Shankran is also treating a VIP's son for fractures'

We all know who the VIP's son is who was involved in an aeroplane accident and who had a fracture He is being treated by Dr Shankran I say that the Health Ministry has been overruled by the Prime Minister's Secretariat Mr Raj Narain, you are a forthright man, you should have protested that the Health Minister's words should have been kept The Prime Minister's Secretariat should not have intervened in the matter of the appointment to the CGHS

Sir, I do not have any more time I would again state that in our country we have made a lot of progress in

[Shri Saugata Roy]

science and medicine. I believe that instead of talking all the time about the Indian system, let us talk about how we can put the country on the modern medical map of the world and give encouragement to those doctors and scientists who are doing pioneering work, and in this context I also request him to bring forward a law to allow kidney, lever and heart transplants. Under the present law it cannot be done. To allow for kidney transplant you need a new law. That should be immediately brought about. That is all I want to say.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र ने डा० शंकरन के अपाइंटमेंट के बारे में जो कहा है वह बिल्कुल निराधार, बेसलेस है। उनकी सूचना सत्य से परे है। उनका किसी डब्ल्यू०एच०ओ० के लड़के को सेवा करने या ट्रीटमेंट करने के कारण अपाइंटमेंट नहीं हुआ है। उनका अपाइंटमेंट अप्राप्रियेट मेनर से हुआ है।

He is the outstanding personality. Therefore, he has been appointed.

SHRI SAUGATA ROY: But there has been a supersession.

SHRI RAJ NARAIN: Don't go by newspapers You come to me. I will show you all the papers.

SHRI SAUGATA ROY: Yes, I will come to you.

SHRI RAJ NARAIN: Yes.

MR. CHAIRMAN: Dr. Sushila Nayar. I want you to just start now so that you can continue on Monday.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi): Sir, I rise to support the Demand's for Grants.

MR. CHAIRMAN: You can continue on Monday.

15.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 292 and 293).

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की मुझे अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.30½ hrs.

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 2, 3, etc.)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923."

The motion was adopted.

SHRI PRASANNBHAI MEHTA: I introduce the Bill.

15.31 hrs.

PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 1, 2, etc.)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936.

*Published in Gazette of India Extraordinary. Part II. Section 2, dated 7-4-78.

MR CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936"

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA I introduce the Bill.

15.31½ hrs.

PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 2, 4 etc)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972

MR CHAIRMAN The question is

'That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Payment of Gratuity Act 1972"

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA I introduce the Bill

---

15 32 hrs.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of sections 1, 2, etc)

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

MR CHAIRMAN The question is

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 '

The motion was adopted

SHRI PRASANNBHAI MEHTA: I introduce the Bill

15.32½ hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Insertion of new article 16A)

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh) I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India

MR CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India'

The motion was adopted

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV: I introduce the Bill

---

15 33 hrs

MENTAL HEALTH BILL—*Contd.*

By Dr Sushila Nayar

MR CHAIRMAN We now take up further consideration of the following motion moved by Dr Sushila Nayar on the 23rd March 1978, namely

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration"

SHRI FURNA SINHA (Tezpur) Sir, Dr Nayar's Bill is a step in the direction of looking into the cases of the mentally deranged in the society brought for medical care, confined to the procedure of their detention, confinement and care of their person and property Under the Lunacy Act, there

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 7-4-1978

are provisions for almost the same things as envisaged by Dr. Nayar, in this Bill. But what I find wanting is, however, the point *viz.* how easily the mentally sick persons could be brought to the psychiatrist, for the observation, then care and treatment as a disease which is curable.

After the first phase of treatment when a patient goes back to the society, what care should be taken to see that the relapse does not occur, and that he does not come back to the mental hospital, to remain confined for another period of years, as a result of which he never becomes a person useful to the society? This is to be taken into consideration in drawing up any Bill or in devising any measures for treatment of the mentally ill persons. As you all know, insanity is not a continuous process. There are fits of insanity. There are instances when people undergoing treatment in mental hospitals have been found to be sane, completely cured and have been given a vocation, such as to work in a vegetable garden. Suddenly, all of a sudden, he becomes mad. Very soon, within a short time, he becomes sane again and his Superintendent will see him doing the normal work. In the same way, people who have been normal, who have been doing work there, all of a sudden, relapse to a period of insanity, attempt to strangulate the people who look after them. Many such things have happened.

As I have told you the other day, I live nearest to the mental hospital in my constituency and I have also been the President of the Association of Workers there. Their conditions of work are deplorable. It is no exaggeration to say that 50 per cent of the workers, both male and female keepers, have been injured by the inmates when they became insane. The restrictions imposed on them by their conditions of work are such that they cannot use any weapons even to chastise insane people. They wear uniforms and waist belts. Even that waist belt cannot be used for self-defence. But all the while they have to look after the insane persons. This is one aspect which I have come across during my visits to that place and my discussions with those workers. No special allowance is given to them for the risk which they are taking and no compensation is given to them if they die while in such a service. After all, they are only fourth grade employees, but they are looking after, not criminals in a jail, but non-criminals who are more dangerous, namely, lunatics inside the hospital. This aspect should be considered.

Another aspect is, after a mental patient has been discharged after cure, when he goes back to society, there is a likelihood of his becoming insane again. His relatives may be enjoying his property. But they will not take care of him, unless his parents or children are living. The other relations, like cousins and brothers will not look after him. Therefore, I would suggest that there should be some sort of levy on the people who are enjoying the property of people who are suffering from mental diseases, and that money should be utilized for running some asylum where these people can be kept for the rest of their life. They can cultivate vegetable, tend cattle or do some such odd jobs, or they may be employed even in the mental hospital. Some of the patients after treatment become useless for intelligent work, become just automatons, who can do only fixed kind of work, or monotonous work like drawing water from a well or cutting earth. That kind of work can be given to them outside the hospital also. The hospital should not remain a prison for him. He can be taken to an open air asylum, where he can be given some sort of jobs like cutting earth, looking after cattle or growing vegetables. These are also aspects which have to be considered when we discuss a Bill relating to people who are mentally ill.

[Shri Purna Sinha]

Those people who work with mental patients for 10 or 15 years continuously do not remain sane. They also become abnormal and behave like insane people

AN HON MEMBER Then what is the fate of the President of the Workers' Association?

SHRI PURAN SINHA I go there only casually to look after them A person who works with mental patients day in and day out for eight hours a day becomes abnormal in course of time During my work connected with the Association I have noticed that even educated people even people who come from higher strata of society, when they work in these hospitals for long periods, behave in such a way that we feel they have to become insane So, some care should be taken of those people also They should not be made to work for their full term as Government employees in those hospitals After working there for about ten years or so they should be transferred elsewhere so that they do not develop insanity and thereby ruin not only themselves but also their families That has also to be seen besides looking after his security and after care

A Bill like this may be a very good exercise it is commendable, because during the last 30 years the Congress Government did not look into the case of the insane people The insane people on the streets behave madly They have to be brought under treatment because lunacy has been found to be curable The insane can be made useful members of society But this Bill must also look into certain aspects which can be known by a direct study of a mental hospital, whether at Tezpur Ranchi or any other place We have to find out the real causes of insanity, how to mitigate it and have to prevent people becoming insane.

I can give one instance There was an illiterate poor, young boy in my State who became insane and was confined to a mental hospital You will be surprised to know that after three years of his detention in the mental hospital, he drew sketches, formed models, then he became sane and was released. Today, he is an outstanding artist in my constituency He models good figures, he designs, he draws and his artistic work is on display to the public But, he again became insane, how? I may give you the real story. He was asked to erect a monument of the 1942 movement at a place where there was police firing in which 18 or 19 people had died The design was his own He started doing work but the people who were supposed to pay him did not pay him regularly What happened? One day he became insane. He took a hammer in his hand and started breaking whatever he had built He became violent, and had to be detained in a mental hospital So, I say, insanity is not incurable, but if, after treatment sufficient care is not taken of the person who was insane earlier, he may become insane again

This Bill only suggests what should be done with the property of the insane, how to look after the insane, who should be the visitors etc But these are only superficial things which are also covered by the Indian Lunacy Act There should be a Lunacy Act which would go into the matter from top to bottom, from the root of it to the ultimate cure For that purpose I think Government should also take the opinion of experts in the medical field psychiatrists, in drafting a Bill which would supersede the provisions of the present Indian Lunacy Act and decide how to treat the criminal and non-criminal lunatics It should also decide whether a mental hospital should be only State-owned, a small asylum or prison for insane people, or it should be a real hospital, a national institution where people from all parts of the country may find a place easily. There should be a scientific basis for their treatment and cure, so that they may return to society as useful persons Such a Bill is necessary.

I have taken part in the discussion on this Bill because I have some personal knowledge as to how a mental hospital is being managed, how the people working there behave, the medical attention paid to the patients and the treatment meted out to them. I would appeal to the hon Mover of the Bill to withdraw it and leave it to the Government to bring forward a comprehensive Bill The other day the hon Health Minister stated that the Government was contemplating bringing forward such a Bill which would cover all the aspects of the mentally ill I do support the principle of the Bill, the spirit of it, and I congratulate the hon ex Minister on the pains she has taken in presenting it, but I feel that a comprehensive Bill by the Government will be more appreciated The provisions to be included therein should be based on technical knowledge as also the other aspect which I have already pointed out

With these words, I request Dr Nayyar to withdraw her Bill

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय मित्र सिन्हा साहब ने यह कहा है कि डाक्टर नायर इस विधेयक को वापस कर ले । मैं बहुत चकित हो गया कि जो काम सरकार नहीं कर सकी उस को एक गैरसरकारी सदस्य उपस्थित कर रही है, उन्होंने इतना परिश्रम किया है और उस को वह वापस कर लेने के लिए कहते हैं । वस्तुत डा० नायर केवल एक सामान्य सदस्य नहीं है बल्कि वह इस स्वास्थ्य विभाग की एक अधिकारिणी रह चुकी है और एक विशेषज्ञ हैं । यह इडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 का है । आज यह 65 साल पुराना हो गया है । असल इस का इतिहास तो यह है कि 1890 में इंग्लिश ऐक्ट बना और उसी के आधार पर यह इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट 1912 का बना । इस का यह नाम ही बताता है कि यह बिल्कुल आउट आफ डेट है । यह ल्यूनेसी नाम ही गलत है । बिल्कुल अन्धविश्वास और रूढिवादिता के आधार पर यह ल्यूनेसी शब्द है । किसी को ल्यूना का, चन्द्रमों का कोई प्रकोप होगा और वह पागल हो जायगा । यह तो बिल्कुल मीडिएवल पीरियड में जो अन्धविश्वास की थियौरी थी, थयौरी आफ ऐक्टियालाजी आफ पैरासीलियस वह चीज है । इसीलिए उन्होंने कितना सुन्दर नाम रखा है—मानसिक स्वास्थ्य विधेयक । वस्तुत पागलपन एक सोशल स्टिग्मा के रूप में है और कोई पागल होता है तो हम लोग भी ऐसा समझते हैं कि वस्तुत. जिस प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसी प्रकार से यह मानसिक स्वास्थ्य भी है समूची दुनिया की जो फिगर्स हैं उन को देखने से ऐसा मालूम पडता है कि जैसे जैसे हमारा समाज ज्यादा काम्पलेक्स हो रहा है उसी प्रकार से यह मानसिक बीमारिया बढती जा रही है । न्यूरोसिस, साइकोसिस, सीजाफ्रेनिया, डिमनेशिया प्रीकाक्स और और भी कितने ही प्रकार की यह बीमारिया होती है । यही नहीं बहुत सी जो बीमारिया होती हैं, एपलेप्सी और ब्लड प्रेशर वगैरह भी उसी से धीरे धीरे बढते हैं । दुनिया मे इस के सबध मे काफी विचार चल रहा है । डेन्मार्क मे यह बीमारी 1 परसेंट है । यू एस एस आर मे 1 परसेंट मानसिक बीमारी के लोग हैं । यू एस ए में 3 परसेंट है । कैनाडा मे 3 4 परसेंट है, यू के मे 2 परसेंट हैं जर्मनी मे 3 परसेंट हैं और हिन्दुस्तान मे अभी तक सरकार आकडे भी उपस्थित नहीं कर सकी है । सरकार के पास आकडे नही है कि कितने लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं एक सैम्पल सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि 3 से 5 प्रतिशत लोग यहा मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं । जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के विज्ञ पुरुष है उन्होने अन्दाजा किया है कि 5 मिलियन लोग हमारे यहा मानसिक रूप से बीमार हैं ।

[डा० रामजी सिंह]

अब जब इतनी बड़ी समस्या हो यानि जिसमें देश में अंधे हैं इससे ज्यादा मानसिक रोगी हैं, राष्ट्र के समक्ष ऐसी बड़ी समस्या जब खड़ी हो तो इसका समाधान होना चाहिए और अभी सिन्हा जी ने जो कहा कि इसका वापस करलें यह सचमुच चकित कर देने की बात है। सरकार के सामने जब भी ऐसा प्रश्न आया है तो वही पिटा पिटाया उत्तर मिला है कि सरकार इस विधेयक को ला रही है । डा० कर्ण सिंह का भी मैंने ऐसा ही उत्तर देखा कि हम ला रहे हैं और 1963 में भी यह कहा गया कि हम ला रहे हैं। तो यह कब तक लाएंगे? क्या जब तक सरकार खुद पागल न हो जाए तब तक ? इसलिए मैं समझता हूं डा० नैयर ने इस सदन का और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा उपकार किया है जब उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 यहां सदन में पेश किया। उन्होंने इस विधेयक को पेश करने में बड़ी मेहनत की है और काफी अध्ययन किया है (व्यवधान) मैं इस बात को सुनकर आश्वस्त हुआ हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इससे भी ज्यादा कांप्रिहेंसिव बिल लायेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : ला दिये हैं ।

डा० रामजी सिंह : यह अच्छी बात है कि आप ला दिये हैं। कुछ संशोधन करके उसको पास किया जा सकता है। डा० नैयर ने अपने विधेयक के द्वारा पहले तो इसके नाम का पुर्नसंस्कार किया है । ल्यूनेसी शब्द से ही लोगों के दिल सहम जाते हैं। इसलिए उन्होंने इसके नाम में परिवर्तन किया है। फिर उन्होंने प्रवेश के संबंध में कहा है इंडियन ल्यूनेसी ऐक्ट में जो प्रवेश विधियां हैं वह बहुत ही कम्बर्सम हैं । उसमें आउट डोर पेशेंटस के लिए कोई सुविधा नहीं है। यही नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे संश्लिष्ट समाज के अनुरूप नहीं हैं। हिन्दुस्तान में 4 दिसम्बर, 1970 को जो वर्ड नेशनल कान्फ्रेन्स आन वेलफेयर आफ मेंन्टली रिटायड हुई थी उनमें भी इन समस्याओं पर काफी जोर दिया गया था। वास्तव में ही मानसिक स्वास्थ्य की समस्या इस आधुनिक युग में बहुत ही प्रधान और महत्वपूर्ण समस्या है। अमरीका में जो यू०एस०ए०कमेटी आन हैंडीकैप्ड पर्सन्स बनी थी तो वहां के प्रेसीडेन्ट कनेडी ने 1963 में कहा था :

"There should be a war on mental retardation."

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रेव्यू की रिपोर्ट है कि न्यूयार्क स्टेट में बीस में एक आदमी पागल खाने में रहता है । आज वस्तुत: जो समस्या हमारे सामने है वह जैसे जैसे समाज संश्लिष्ट हो रहा है वैसे वैसे यह समस्या और भी विकराल बनती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने इस संबंध में जो सुझाव दिये हैं, मैं समझता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो कांप्रिहेंसिव बिल रखा है उसमें उन चीजों पर ध्यान दिया होगा। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन ने मेंटल हेल्थ के सम्बन्ध में जो चर्चा की है उसमें एक अनुशंसा उन्होंने की है :

"The Committee recommends that 1954 Report continue to be used as a guide to the organisation of the services for the mentally retarded."

इस सम्बन्ध में मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहता। यह ठीक बात है अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि जल्दी जल्दी से बिल ले आयेंगे और उस बिल में कुछ संशोधनों की अगर जरूरत होगी, जैसे कि डा० नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक में कुछ अच्छी चीजें हैं, उनका समावेश करके यह सदन उस विधेयक को पारित कर सकेगा और उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र होंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। अपने देश में जो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हास्पिटल हैं उनमें किस प्रकार का कष्ट होता है उसके कुछ उदाहरण डा० सुशीला जी ने दिए हैं। उस दिन उन्होंने बताया था कि श्रीनगर के अस्पताल में कुछ बीमार जाड़े के कारण मर गए। जेलों में भी पागलों को किस क्लेश के साथ रखा जाता है वह इमर्जेंसी में हमने देखा। तो मैं यह

कहना चाहता हूं कि इसके लिए अधिक से अधिक अस्पताल होने चाहिए। अभी तक 34 या ज्यादा से ज्यादा 50 हैं। उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की अवस्था से जब कि हमारा समाज—परिवार के अन्दर तनाव, संस्थाओं के अन्दर तनाव, पार्टियों के अन्दर तनाव—रोज हमारा जीवन तनावों से अभिपूरित हो रहा है, ऐसे समय में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये। यह भी जनस्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि सुशीला बहन ने जो परिश्रम किया है और जो महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं उन का समावेश भी सरकारी विधेयक में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसी सत्र में वह बिल हमारी सुशीला बहन के सुझावों के साथ पारित करने की दिशा में प्रयत्न करें

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) मैं बहन सुशीला जी को बहुत धन्यवाद देता हूं—उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। परन्तु जैसा सरकार ने कहा है कि सरकार विधेयक बना रही है, बल्कि बन चुका है और पेश होने वाला है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 1912 में अंग्रेज सरकार ने पागलपन के बारे में एक विधेयक बनाया था, उस के बाद अब तीस साल बाद हमारा ध्यान उस तरफ़ गया। इस लिये मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी जनता सरकार के स्वास्थ्य मंत्री—श्री राज नारायण जी—इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं।

लेकिन मैं बहिन जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करूंगा—आप ने पागलपन की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, परन्तु हमारे देश के सामने एक और समस्या भी है। इस देश में अर्ध-पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, उन का समाधान इस विधेयक में कैसे किया जायगा। मैं राज नारायण जी से भी यह सवाल पूछना चाहता हूं—पागल तो इस देश में हैं ही, लेकिन अर्ध-पागल की संख्या भी इस देश में बढ़ती जा रही है, उन का समाधान आप कैसे करेंगे? 19 महीने के एमर्जेन्सी के काल में हमने इन अर्ध-पागलों की स्थिति को देखा—इस लिये इन का समाधान भी होना बहुत जरूरी है। इस बिल से तो इन का समाधान मुझे सम्भव नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात में अवश्य कहना चाहता हूं, यद्यपि इस बिल से तो उस का सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। हमारे यहां आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि बीमारी को दबाने के बजाय, बीमारी की जड़ को दूर किया जाये। सूखते हुए पेड़ का हरा करना है, तो पत्तों पर पानी छिड़कने से बात नहीं बनेगी, उस की जड़ में पानी पहुंचाना होगा। हम यह सोचना होगा कि पागलपन का कारण क्या है? पागलपन का मूल कारण क्या है और किस कारण से पागलपन पैदा होता है। सभापति महोदय, पागलपन अब और वृद्धि पर चलेगा, पागलों की संख्या यहां बढ़ती जायेगी—ऐसा मुझे भय लग रहा है। अभी जो आंकड़े डा० रामजी सिंह ने दिए हैं उन से स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में भी यह समस्या बहुत जोरों पर है। पागलपन की समस्या शारीरिक नहीं, मानसिक रोग है। मन की अवस्था जब उस सीमा पर पहुंच जाती है कि वह कन्ट्रोल नहीं कर पाता है, उस की बुद्धि और आत्मा कन्ट्रोल से बाहर हो जाती है, बुद्धि असफल हो जाती है, तब पागलपन पैदा हो जाता है। इस का मूलकारण है, मन का अशान्त होना और मन के अशान्त होने का कारण है—ये तमाम समस्यायें। वर्तमान समाज की समस्यायें इतनी टेढ़ी और जटिल बन गई हैं कि उन का समाधान करने में हर माता-पिता लगभग अर्ध-पागल

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

जैसे चल रहे हैं। इस देश में उस का सारा कारण है—गरीबी, बेकारी और नशा। इन कारणों से ये चीजें आ रही हैं। अगर सरकार चाहती है कि देश में पागलों की संख्या कम हो और उन की बेचैनी का इलाज हो और उन की प्रोपर्टी की रक्षा के लिए कुछ प्रबन्ध हो, तो मैं यह समझता हू कि उन कारणों को दूर करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए जिन की वजह से लोग पागल हो जाते हैं। केवल स्वास्थ्य मंत्री जी के कुछ करने से बात नहीं बनेगी। इस में चिकित्सालय शामिल होना चाहिए और इस में होम मिनिस्ट्री भी शामिल होनी चाहिए। इन सब के कोपरेशन से ही भूल समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हू। आज स्थिति यह है कि मां–बाप अपनी लड़की को पढ़ाते हैं और जब वह बड़ी हो जाती है, तो उन के सामने उस की शादी की समस्या आ कर खड़ी हो जाती है। लड़के वाले पैसे की मांग करते है। अब अगर किसी माता-पिता के दो, तीन लड़कियां हैं और उस के पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वे पागल नही होंगे तो क्या होंगे। मैं उन लड़कियों को जानता हूं जो पागल जैसी अवस्था मे आ गई हैं। आज समाज की स्थिति इतनी टेढ़ी और जटिल बन गई है कि बेकारी इस देश मे बढ़ गई है और जो गरीब लोग है वे न मालूम क्या क्या ऊट-पटाग खाते हैं और पीते है और पागल जैसी उन की अवस्था हो जाती है। इस तरह की चीजो पर नियन्त्रण करना होगा और इन समस्यायो के समाधान होने के पश्चात् अगर कोई पागल बनता है, तो फिर उस की परवाह करनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक मे इस तरह की बातो की तरफ ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। पागल की प्रोपर्टी का ध्यान किया जाए, इस के बारे म इस विधेयक में कहा गया है। मैं तो यह चाहूंगा कि पहले उस की मेन्टल हैल्थ का ध्यान किया जाए। इस में सवाल यह पैदा होता है कि उस पागल का ध्यान कौन करे? सब से पहली बात यह आती है। आज हम देखते हैं कि गलियो में और सड़को मे पागल घूमते रहते हैं। नौजवान पागल लड़कियां घूमती रहती हैं और उन के सामने पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहती है। बालक, गलियों मे उन पागलो के पत्थर मारते है और वे नंगे, फटे पुराने कपड़े पहने घूमते रहते हैं और चौराहों पर खड़े हुए हंसते रहते हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान नही दिया जाता है। इसलिए मै चाहूगा कि कानून मे इस तरह का परिवर्तन करना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पागलपन की रिपोर्ट आए, तो पुलिसवालो का यह कर्तव्य हो जाना चाहिए कि वह उस पागल को ला कर अस्पताल में बाकायदा पहुंचाए।

16:00 hrs.

मैं आप को एक उदाहरण देना चाहूगा। मैं अभी कलकत्ता गया था। वहा मैंने एक अच्छे घराने की पागल स्त्री को देखा। वह बहुत सुन्दर स्त्री थी यानी नौजवान थी लेकिन उस के बच्चा न होने के कारण उस के पति ने उस को तंग किया। एकाध महीना वह उस के साथ रही लेकिन बाद में पागल अवस्था में आ गई। इस का परिणाम क्या हुआ कि वह गुण्डो के हाथ में आ गई। मैं आर्य समाज में पहुचा हुआ था, मेरे पास इस बात की रिपोर्ट आई। वह भले घर की स्त्री थी। मैंने उस स्त्री को वहां से ला कर रांची के अस्पताल मे भिजवाया ताकि वहां पर उसका इलाज हो सके।

अभी कल परसो की ही बात है। मैं 29 मार्च को लखनऊ स्टेशन पर था। वहां मैंने शाम को एक नौजवान लड़की पागलो की तरह हंसती फिरती देखी। एक तरफ वह हंसती फिरती थी और उस के पीछे एक और पागल बोलता आ रहा था "मैं यह कर दूंगा और वह कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट बदल दूंगा"। मैंने कहा यह क्या बात है। जहां पर लखनऊ मेल आ कर रुकती है

उस प्लेटफार्म पर दो पागल थे, एक वह थी और एक वे पागल थे। कोई मिलिट्री का आदमी मालूम पड़ता था। उसकी कोई-न-कोई समस्या होगी क्योंकि यूनिफार्म उसके कंधे पर थी। वह पुरानी जरूर थी।

हर शहर में इस प्रकार की घटनाएं आपको मिल जाएंगी लेकिन उन बिचारों की कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यहीं दिल्ली शहर में एक ऐसी पागल औरत को जानता हूं जो कि गुण्डों के हाथ में पड़ गयी। उस बिचारी के गर्भ रह गया। उसके बच्चा हुआ और वह उस बच्चे को लिये घूमती रही। किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है। ऐसे लोगों की क्या दुर्दशा होती है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

इसलिए पहले तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को वह अस्पताल पहुंचायें। जो इस प्रकार से सड़कों पर मारे-मारे फिरते हैं उनके लिए अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए। आप बेशक इसके लिए संविधान में परिवर्तन कीजिए, या कोई कानून बनाइये या होम मिनिस्ट्री में ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए जिससे पुलिस पर यह जिम्मेदारी हो कि वह ऐसे लोगों को अस्पताल पहुंचाये।

आपने प्रापर्टी के बारे में तो सोचा है लेकिन बहुत सारे लोग समाज में ऐसे भी हैं जो पागल हो जाते हैं। उनके पागल हो जाने के बाद उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। परिवार की पूछताछ करने वाला कोई नहीं होता है। मोहल्ले के लोग उस परिवार के सदस्यों का अनुचित लाभ उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग 40 वर्षों से सामाजिक कार्य करता आ रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं कि किसी परिवार का यदि कमाने वाला पागल हो गया है तो उसके परिवार के सदस्यों की क्या अवस्था होती है। उसकी नौजवान लड़की है, छोटा बच्चा है, कमाने वाला तो पागल हो गया, उसके परिवार का क्या बनेगा, इसे कोई नहीं देखता है। उसके पास कोई प्रापर्टी नहीं है। उसकी असली प्रापर्टी तो उसके बच्चे हैं, उसकी धर्म पत्नी है। उनको देखने वाला कोई नहीं होता।

मैं अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहूंगा। वैसे तो आपको ज्ञान होगा कि देश में कितने पागल हैं, उनकी संख्या के अनुसार कितने अस्पतालों की आवश्यकता है, और इस समय हमारे देश में कितने अस्पताल हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पागल की बात तो अलग है, आज एक टी०बी० के बीमार को अस्पताल में दाखिला नहीं मिलता है। लोग दाखिले के लिए हमारे पास रिकमण्डेशंस के लिए आते हैं। देश में बीमारियां बढ़ रही हैं लेकिन उनके हिसाब से देश में अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं। देश में आज अस्पतालों की बड़ी कमी है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप चाहें आयुर्वेद या होम्योपैथी का इलाज करायें लेकिन रोगियों के इलाज की देश में पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। हर व्यक्ति को बगैर किसी सिफारिश के अस्पताल में दाखिला मिल जाए, ऐसी व्यवस्था आप करें।

श्रीमन यह मस्तिष्क क्यों बिगड़ता है? यह मन के असंतुलन से बिगड़ता है। हमारे देश में वर्तमान समय में यह व्यवस्था नहीं है कि हम ऐसे रोगियों के दाखिले का पूरा प्रयास कर सकें। रोगी को सिफारिश से ही दाखिला मिलता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे बिना किसी सिफारिश के इस प्रकार के रोगियों को अस्पतालों में दाखिला मिल जाए। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि यह एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज हुई है कि मन के असंतुलन से मस्तिष्क का संतुलन खराब हो जाता है।

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

इस मन के असंतुलन से केवल व्यक्ति पागल ही नही हो जाता बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियो भी लग जाती हैं। बहुत-सी बीमारियो की जड यह मानसिक असतुलन है। इस मन को नियत्रित करने की दिशा मे भी हमारा प्रयास होना चाहिए।

मनुष्य अपनी चिन्ताओ पर बेचैनी पर और इन से सम्बन्धित समस्याओ पर समाधान पा सकता है। अभी अमरीका मे ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारिया जिनकी तरफ इशारा किया गया है और जिन का सम्बन्ध मन से है, उनका इलाज वहा डाक्टरो के पास नही है। दो चार बीमारियो का ही है, अधिकाश का नही है। अगर सरकार योग पर, मैडीटेशन पर ध्यान दे और इसको अस्पतालो का अंग बना दे, इसको भी अस्पताल मान कर चले और देश भर मे इसका प्रचार और प्रसार करे तो बहुत सी बीमारिया हैं जिन का इलाज हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारी एक दास मनोवृत्ति बन गई है। जब तक विदेश के लोग किसी बात पर मुहर नही लगाते है, वे उसको अपना नही लेते हैं तब तक हमारा मस्तिष्क उसका स्वीकार करने के लिए तैयार नही होता है। अमरीका मे यहा के हमारे योगी पहुचे, वहां उन्होंने इसका प्रचार किया और वहा इस पर ग्रन्थ लिखे गये। उन्होने वहा अपने शिष्य बनाए और शिष्य ले कर वे यहा आए। तब जा कर यहा के लोगो ने कहा कि इस मे तो कुछ तत्व मालूम पडता है और तब हमारे लोगो का ध्यान इस ओर गया। मैं चाहता हू कि इस ओर सरकार का ध्यान जाए। आप योग और मैडीटेशन पर साइंटिफिक रिसर्च यहां पर कराए। अमरीका मे हो रही है। दुख है कि हमारी अपनी विद्या है और यहां पर इस पर रिसर्च नही हो रही है। कोशिश यही की जानी चाहिए कि वह पागल बने ही नही और जो कारण हैं उनको ही दूर कर दिया जाए। अगर आज थोडा सा भी मैडीटेशन पद्रह बीस मिनिट वह करता है और उसको इसका ज्ञान हो जाता है, अभ्यास हो जाता है तो बहुत सी समस्याओ पर उसका काबू हो जाता है और पागलपन की स्थिति तक वह बहुत मुश्किल से पहुच पाएगा। इस पर आप ध्यान दें।

मैं इस विधेयक का आदर करता हूं, स्वागत करता हू। मैं आशा करता हू कि स्वास्थ्य मत्री भी इस विधेयक की भावना का स्वागत करेंगे और एक कम्प्रिहैंसिव विधेयक जल्दी लाएगे ताकि यह एक जो बहुत बडी समस्या है इसका समाधान हो सके। ये जो बीमारिया पैदा होती है ये आर्थिक समस्याओ बेकारी, बेरोजगारी, आदि की वजह से भी पदा होती हैं। साथ ही हमारी सामाजिक समस्यायें भी है। श्रद्धेय जय प्रकाश जी ने जो नारा दिया है सम्पूर्ण क्रान्ति का उसको साकार करने के लिए सभी मत्रालयो को मिल बैठ कर इस समस्या का समाधान निकालाना होगा। वही इसका स्थायी इलाज कर सकेगा।

इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हू।

श्री राज नारायण : इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर दू कि डा० सुशीला नायर के व्यक्तित्व का मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी काफी प्रभाव है। गांधी जी से जो उनका सान्निध्य था उसका भी मेरे ऊपर काफी प्रभाव है। माननीय सदस्यो ने जिन्होने भाषण किए हैं उनका भी काफी प्रभाव है। यदि मे डा० नायर से यह सादर साग्रह निवेदन करू कि उनके इस विधेयक की सारी भावनाओ का सरकार अपने विधेयक में समावेश करलेगी और सरकार शीघ्रातिशीघ्र विधेयक प्रस्तुत करने जा रही है और इसको वह वापिस ले लें तो मे समझता हू कि मैं अपने कर्त्तव्य का ही पालन करूगा।

हमारा विधेयक भी तैयार हो गया है। उसको तैयार करने में जिस तरह से इसको

तैयार करने में काफी परिश्रम करना पड़ा है, काफी परिश्रम करना पड़ा है। तमाम राज्यों की राय पहले मांग ली गई है। हमारा जो कानून विभाग है उसने भी उसको अच्छी तरह से देख लिया है। फिर उस पर कुछ न कुछ सुझाव आते ही रहते हैं। जैसा उसका नाम मानसिक स्वास्थ्य विधेयक है। अब इसी पर हमारे यहां विवाद है कि इसका नामकरण क्या हो? मानसिक स्वास्थ्य के माने क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक रोग निवारण विधेयक रख दीजिये, कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक आरोग्य विधेयक नाम रख दीजिये, कुछ लोग कहते हैं कि विकृतता निवारण विधेयक नाम रख दीजिये। यह मामूली बातें हैं। तो हम भी जो विधेयक लायेंगे हम यह भी सिफारिश करेंगे कि जौइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय जिसमें माननीया सुशीला नायर जी भी रहेंगी, और जो लोग बोले हैं, जो लोग जानकार हैं वह भी रहेंगे, दोनों सदनों के लोग रहेंगे और अच्छी तरह से विचार विनिमय कर के उसकी एक अवधि रख दी जाय कि एक महीना, दो महीने के अन्दर उस विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाये, और यह मामला चल जायेगा।

मैं इतना बता देना चाहता हूं कि पागलपन, पागल शब्द से मुझको भी थोड़ा सा यह शब्द अरुचिकर है। इसका बदलना जरूरी है। और उसको कैसे बदला जाय यह हमने डा० सुशीला नायर के लिये रख दिया ताकि उनकी सूझबूझ और बहुत ही अच्छी परिपक्व राय आयेगी। मगर एक बात है, यहां अगर मैं रस में जाऊं तो पागलपन कहीं कहीं बहुत गहरा हो जाता है:

तंत्री नाद कवित्त रस, सरस राग रति रंग,
अनबूड़े बूड़े तरे, जे बूड़े सब अंग।

तो कहीं कहीं कभी पागलपन भी बहुत भला हो जाता है। वह पागलपन क्या है? जैसे मीरा का कृष्ण में अनुराग, राधा का कृष्ण में अनुराग, प्रेम पागल। तो वह तो मैंने केवल आपके थोड़े से मस्तिष्क के बोझ को हल्का करने के लिये बता दिया।

एक माननीय सदस्य : आप भी पागल हैं किसी के।

श्री राज नारायण : हम पागल हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये। हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो उस के पीछे हम पागल हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है इस के लिये तो फिर कभी संसद् सदस्यों की गोष्ठी हो तो उस में विचार विनिमय किया जाय। मगर एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग जो अपनी भारतीय पद्धति के बारे में कुछ यहां पर बोल गये, आयुर्वेद के बारे में बोल गये और यह बोल जाते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। अब एक तरफ दुनिया मंगल गृह पर जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं। मैं उन से कहना चाहूंगा कि वह अपनी भारतीय संस्कृति को और भारतीय प्राचीन ग्रन्थों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ें। गृहों का जितना अच्छा विश्लेषण आप के यहां हैं उतना अच्छा विश्लेषण आप दुनिया में कहीं नहीं पायेंगे। समझ लीजिये कि आपके यहां जो लोग गृहों का निराकरण करने के लिये तमाम लोगों को इधर उधर से देखते हैं समझते हैं, वह क्या है। इन गृहों का सच्चा ज्ञान भारत ने सब से पहले दिया। इन गृहों की दूरी तक नापी, गृह कहां से कहां गये इसके बारे में बताया। ग्रहण के स्वरूप की कल्पना की। मगर यह लोग भूले हुए हैं। तो मैं इन के लिये खाली इतना बता देना चाहता हूं कि अगर मैं आयुर्वेद का नाम ले लूं, ब्रह्मचर्य का नाम ले लूं, अगर कोई ब्रह्मचारी रहे, उस वृत का पालन करे तो पागल हो ही नहीं सकता। मानसिक विकृतता आ ही नहीं सकती। अगर मानसिक विकृतता को दूर करना है तो आप निश्चत रूप से इस बात को मान लीजिये, योग पर बैठिये, साधना कीजिये, ध्यानावस्थित होइये।

रामायण के बारे में यहां बोल गये। पहले रामायण पढ़ो तो। राम राज्य के बारे में

[श्री राज नारायण]

बोल गए। उसे पढ़ो तो। जब विभीषण आये हैं राम के पास तो लोगों ने क्या कहा "आन न जावे निशाचर माया, कामरूप केहि कारण आया। महाराज यह निशाचर है इस को अपने दल में न लो, इस की माया जानी नहीं जा सकती। तो राम ने क्या कहा :

"सुनहू सखा कह कृपा निधाना,
जेहि जय होय सो स्यन्दन आना।"

जब विभीषण घबरा गया और कहने लगा :

"रावण रथी विरथ रघुबीरा,
देख विभीषण भयउ अधीरा।"

तब राम ने कहा :

"सुनहु सखा कह कृपा निधाना,
जेहि जय होय से स्यन्दन आना।"

"हे विभीषण, सुनो। जिस से जय होती है, वह रथ हमारे पास है।" क्या रथ है ?

सौरज, धीरज, तेहि रथ चाका,
सत्यशील दृढ़ध्वजा पताका,
बल विवेक दम-परहित घोड़े,
क्षमा दया, समता रजु जोड़।

अर्थात् हमारे रथ के चार घोड़े हैं : बल, विवेक, दम और परहित। स्वहित नहीं, परहित। बल के साथ विवेक, विवेकपूर्ण बल। विवेकहीन बल और सत्ताराक्षसी है। हम ने जो इमर्जेन्सी काल यहां काटा, वह राक्षसी काल था, वह विवेकहीन बल था।

आप महाभारत को पढ़ें और कृष्ण तथा गांधी की तुलना करें। हम संसद्-सदस्य हैं, मगर इतिहास के कालचक्र का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। कृष्ण पैदा होते हैं जमुना के किनारे और मारे जाते हैं समुद्र के किनारे। गांधी पैदा होते हैं समुद्र के किनारे और मारे जाते हैं जमुना के किनारे। इन दोनों अवतारों का अध्ययन करना चाहिए। मैं नेहरू जी पर छोड़ दिया है।

कृष्ण ने कहा कि मैं तब इस दुनिया से जाऊंगा, जब यदुवंशियों का संहार करा दूंगा—अपने वंश का। उन का वंश बहुत ही ताकतवर और बलवान था। वह कहते थे कि अगर मैं नहीं रहूंगा, तो हमारे यदुवंशियों के पास इतनी सत्ता है कि वे किसी को रहने नहीं देंगे। इसलिये मैं पहले उन का संहार करा लूंगा। फिर उन्हों ने दुर्वासा मुनि को बुलवाया, शाप दिलवाया, और यदुवंशी आपस में लड़-कट कर मर गये।

कृष्ण को मारता है बाली नामक बहेलिया। राम ने मारा था बाली को। तो बाली नामक बहेलिये ने मारा कृष्ण को, अर्थात् राम को। इस बात को पकड़ लें। अगर मानसिक स्वस्थता हममें है, तो हम इस बात को क्यों नहीं पकड़ते ? गांधी ने 29 जनवरी, 1948 को एक लेख लिखा कि कांग्रेस को तोड़ दो। वह लेख पढ़िये। 30 जनवरी को वह लेख अखबारों में प्रकाशनार्थ दे दिया। तब बड़े बड़े नेताओं ने गांधी जी को मना किया कि अभी आप का लेख नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, तो जावेगा, समय आ गया है। उन्हों ने लेख को प्रकाशनार्थ अखबारों को दे दिया और प्रार्थना सभा में आने लगे। उसी सभा के बीच से एक हत्यारा उठता है, गांधी जी को रास्ते में घेरता है, पाकेट से पिस्तौल निकालता है और उन पर तीन वार करता है। गांधी जी खून से लथपथ होते हैं और प्राण-पखेरू उड़ जाता है। सादे वेश में तीस सिपाहियों की टोली पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा वहां तैनात की गई थी वह तीस सिपाहियों की टोली कहां थी ? उस हत्यारे को एक माली के बेटे ने पकड़ा। जो फूलों की क्यारी में काम कर रहा था। उस ने कुदाल फेंक दिया और हत्यारे को पकड़ लिया।

मानसिक विकृतता सत्ता-लोलुपता से भी आ जाती है। इस का भी निवारण करना है। सत्ता-लोलुपता, सत्ता छीनने की लिप्सा, अभिलाषा आप लोक सभा में कल, परसों और नरसों के भाषणों को पढ़ लें। सब के पीछे उन्माद है। उस उन्माद को हम पलटते रहते हैं। आप समझिए कि मानसिक स्वस्थता और मानसिक विकृतता क्या है? इंटर्नल डेंजर के नाम पर अपने देश मे एमर्जेंसी को लागू कर दिया, यह मानसिक विकृतता के अन्दर आएगा या नहीं? मेरा यह सवाल है। उठ रहे हैं ये सवाल कि कोई दे जवाब। इस सवाल का जवाब होगा। यह भी एक मानसिक विकृतता है। यानी किस तरह से दिमाग खराब हुआ कि इस तरह की एमर्जेंसी आन्तरिक खतरे के नाम पर अपने देश में लग गई और श्री जय प्रकाश नारायण, जिन्होंने सन् 42 मे हजारी बाग जेल को लांघ कर क्रान्ति की बुझती हुई चिन्गारी मे अलग आग फूंक दी थी, उन को भी पकड कर के बन्द कर दिया। मोरारजी भाई आज हमारे प्रधान मंत्री हैं उन को भी पकड़ कर के बन्द कर दिया। चौधरी चरण सिंह बीमारी की हालत में थे, उन के पांव की हड्डी बढी हुई थी, उन को भी पकड़ कर बन्द कर दिया। हम से सब लोग रातों रात बन्द कर दिए गए। ... (व्यवधान) .... हम तो हमेशा ही तन्दुरुस्त रहते हैं, हम रंगीले जवानों के लिए तो बहार ही बहार है। इस तरह से सब बातों को आप समझिए: आज जिन बातों को मैं यहां पर रख रहा हूं, मेरा प्रयत्न होगा कि इन के बारे में भी विचार हो, जब ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में यह चीज जाय और इस पर भी सोच समझ कर कोई व्यवस्था हो। डा० सुशीला नायरजी के विधेयक में यह नहीं है और हम ने जो विधेयक रखा है वह उस से बहुत विकसित है, साकार है मगर उस में भी इस की व्यवस्था नहीं है। एक मर्तबा एशियाटिक साइकिया-ट्रिस्टस कान्फिरेंस थी, उस में वर्ल्ड के कई बड़े-बड़े डाक्टर आए थे, उन के सामने मैंने यही समस्या रख दी। मैंने कहा और मैं यह यहां सदन में डिक्लेयर करके जाता हूं कि मैं मरूं तो मेरा दिमाग और मेरा पूरा का पूरा शरीर अस्पताल को दे दिया जाय। मेरा कोई परिवार नहीं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई घर नहीं, किसी से मेरा रिश्ता नहीं, यो सामाजिक दृष्टि से आप देखेंगे तो रिश्ते हो सकते हैं। बाकी हमारा कोई सबंध नहीं है। 1958 से इतने साल हम को अपना घर छोड़े हो गए। 58 बार हम कांग्रेस के राज में जेल गए। क्यों? 58 बार मैं जेल गया और 15 साल मैंने जेल में गुजारे जब से भारत आजाद हुआ। क्यों? इस को भी खोजिए। इस मे भी कहीं मानस-विकृतता आती है या नहीं? इस के बारे में भी देखना चाहिए कि मैं पागल था क्योंकि मैं बराबर जेल जाता था, डंडे खाता था, लात खाता था। आप देखिए, यह हमारे मित्र कामत साहब है, इन को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। इन्होंने देखी है, हमारी पुरानी दाढी कितनी खड़ी थी?

श्री हरि विष्णु कामत : शानदार थी।

श्री राज नारायण : 1956 के मार्च महीने मे काशी विश्वनाथ मंदिर मे हरिजनों का प्रवेश कराने मै गया और श्रीमती इंदिरा गांधी की पुलिस जबर्दस्ती मुझ को तीन फर्लांग दाढ़ी पकड कर खींच ले गई। सैकड़ों लोग जेल में बन्द कर दिए गए। आज जो बहुत से लोग हरिजनों के नाम पर कोकोडाइल टीयर्स बहाते है, मैं उन से पूछता हूं कि वे कहां थे? यह मानसिक विकृतता की बात है या नहीं? मैं यह कहता हूं कि —

उछरने वाले अभी तक बाम से न उतरे,
और तड़पने वाले तड़प कर फलक को छू आए।।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैंने अपनी दाढ़ी इसीलिये लम्बी नहीं रखी है ताकि कोई खींच न सके।

श्री राज नारायण : जी हां, आप उस को बढ़ाइये ।

तो इस के बारे में भी खोज होनी चाहिए कि मानसिक विकृतता यह है या नही। इन तमाम बातों को देखिए । सामाजिक विश्लेषण करते समय देखिए कि कौन किस समय किस दृष्टि से सामाजिक विश्लेषण करता है। उन दृष्टियों को देखिए । नाट लैस देन डजेन बार तो मैं ने केवल हरिजनों के लिए जेल काटी है। उन के मकान के लिए, उन के खेत के लिए, उन के कुए के लिए, उन के पानी के लिए उन के साथ डडा लेकर लडाई की है और हम तो बन गए, अब क्या बताए ?

नयी नयी बिटिया नये नय गीत ।
गा ले बिटिया भर भर गीत ।।

तो यह सब मानसिक विकृनता में आएगा या नही, इस पर भी विचार हो और गभीरता के साथ विचार हो । इसीलिए मैं माननीय सुशीला नायर जी से करबद्ध प्रार्थना करूगा कि इस को वे वापस लें । वे उस कमेटी मे बैठें । जो कुछ भी कमी इस विधेयक में हो जो सरकार पेश कर रही है उस को देखें और उन के विधेयक से जो उस में और विकास हुआ है उस को देखें ।

मैं इस सबध में आप को और बातें बता देना चाहता हू ।

कुछ फीगर्स भी मैं आप को देना चाहता हू। मैं यह पढ़ रहा था, पहले मैं कोट करना नहीं चाहता था लेकिन चूकि कुछ लोग बोले इसलिए कोट कर रहा हू ·

Dr Glen Davidson, project co-ordinator, who is now in the city has, opined that the systematic approach and inherent features of Ayurveda will have an impact on the medical profession in America."

आयुर्वेद के बारे में उन्होने यह अपनी राय दी है । आगे वे कहते हैं .

"The S.I U. faculty has investigated medical systems in other parts of the world but have found Ayurveda to be the most systematic"

उन्होने कहा है कि आयुर्वेद जो है वह दुनिया मै सब से ज्यादा सिस्टेमेटिक है, यह हम ने पाया है। आयुर्वेद के द्वारा हम कहां तक पागलपन को दूर कर सकते हैं इस पर भी हम को सोचना पडगा। मैं त्यागी जी का जवाब दे रहा हू । डा० सुशीला नैयर को ही जवाब नही दे रहा हू । त्यागी जी ने कहा कि दवाओ की क्या व्यवस्था है, इलाज क्या है तो जैसा मैं ने कहा, हम इस के बारे में भी सोच रहे है । हमारा आयुर्वेद, हमारा यूनानी हमारा योग, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा– यह सभी जो चीजे है यह पागलपन को दूर करने मे, विकृति को दूर करने मे, विक्षिप्तता को दूर करने मे और मानसिक स्वस्थता को लाने मे कहा तक कारगर होगी, इन बातो पर भी हम विचार कर रहे हैं । आप ऐसा मत सोचे कि उधर हमारी दृष्टि ही नही है

श्री हरि विष्णु कामत । क्या यह सही है कि आयुर्वेद पंचम वेद कहलाता है।

श्री राज नारायण : महाभारत पचम वद कहा जाता हैं, आयुर्वेद उपवेद है ।

आध्र प्रदेश मे मेंटल हास्पिटल दो हैं, असम मे एक है, बिहार मे दो हैं, दिल्ली में दो हैं, गोवा मे 1 है, गुजरात में चार हैं, हरियाणा में एक भी नही है, जम्मू कश्मीर में दो हैं, केरल मैं तीन हैं, मध्य प्रदेश मे दो हैं, महाराष्ट्र में पाच हैं, मैसूर म दो हैं, उडीसा में एक है, पजाब में एक है, राजस्थान में दो हैं, तमिलनाडू में एक है, उत्तर देश में तीन हैं और वेस्ट बगाल में चार हैं । इस प्रकार से देश में कुल 38 मेंटल हास्पिटल हैं।

साइकियाट्रिक क्लिनिक्स जो हैं उनकी भी अलग-अलग फीगर्स मैं आपको दे देता

हू । आंध्र प्रदेश में दो, बिहार में दो, दिल्ली में चार, गुजरात में एक, हरियाणा में एक, जम्मू कश्मीर में एक, केरल में एक, मध्य प्रदेश में एक, महाराष्ट्र मे एक, मैसूर मे दो, उडीसा मे दो, पजाब में एक, राजस्थान में एक भी नही है, तमिलनाडू मे दो, उत्तर प्रदेश म एक भी नही है और वेस्ट बगाल में पाच हैं ।

जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा है, कुछ प्राइवेट लाग भी व्यवस्था करते है । जहा तक हमसे हो सकेगा, उनकी सहायता भी हम करेंगे । हम देखेंगे कि यह फूर्ने फर्ने और विकसित हो और रास्ते पर चले । अब मैं सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहता, जल्दी-जल्दी बता देता हू ।

अब मैं आप का इस की भूमिका बतलाना चाहता हू— डा० सुशीला नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 पर मैंने विभिन्न माननीय सदस्यो, जिन मे डा० सुशीला नैयर भी सम्मिलित है, के विचार बड़े ध्यान से सुने । इस से पहले कि मै इस विधेयक पर टिप्पणी करू, मै सरकार के उन प्रयासो का सक्षिप्त म उल्लेख कर देना चाहूगा जो उस ने भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 को जो इस समय भारत में लागू है, बदलने के लिये किये । सरकार इस बात को समझती है कि भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबध, जो मुख्यत' यह सुनिश्चित करने के लिये थे कि किसी पागलखाने में जब किसी व्यक्ति को भर्ती किया जाय या रोका जाय, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हो ऐसा किया जाय, अब पुराने पड गये हैं । मानसिक रुग्ण इन व्यक्तियो के प्रति अब समाज का रुख बहुत कुछ बदल चुका है और अब यह महसूस किया जाने लगा है कि इस बीमारी से कोई एप्रोब्रियम नहीं जोडा जाना चाहिये, क्योंकि यह एक साध्य रोग है, खास कर यदि इस का प्रारम्भिक अवस्था में ही निदान हो जाय । इसी उद्देश्य को ध्यान म रखते हुए सरकार ने उस पुराने पड गये पागलपन अधिनियम को बदलने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विधेयक का प्रारूप बनाना शुरू किया ।

28 सितम्बर, 1966 को केन्द्रीय मत्रिमडल ने ऐसा कानून बनाने के लिये एक स्थूल नीति अनुमोदित की । तथापि ऐसे एक विधेयक को वस्तुत पेश करने म विलम्ब हो गया, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस विधेयक का प्रारूप पूर्णत. व्यापक हो और इस विषय पर नवीनतम अनुसधान के आधार पर इस में आधुनिक विचारणा की नवीनतम प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हो, इस विधेयक को सभी राज्य सरकारो/केन्द्र शासित क्षेत्रो में परिपत्रित किया गया और इस विषय से सम्बन्धित सगठनो से भी सम्पर्क किया गया ताकि इन सब के विचार प्राप्त हो सकें । विभिन्न विकसित देशो में इस विषय से सम्बन्धित कानून की प्रतिलिपियां भी प्राप्त की गई । यद्यपि कुछ राज्य सरकारो तथा केन्द्र शासित क्षेत्रो ने इस के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये, किन्तु अधिकाश किन्तु अधिकाश राज्य सरकारो आदि ने स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद अपने विचार भेजने मे देर कर दी। 1975 मे सरकार ने यह महसूस किया कि क्योंकि इस मामले मे विलम्ब हो गया है, इसलिए विधेयक के प्रारूप में इस विषय पर नवीनतम चिकित्सीय दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित नही होता । फलत इस विधेयक का प्रारूप फिर से तैयार किया गया । अब सरकार के पास एक विधेयक है, जो भारत में व्याप्त स्थितियो के परिपेक्ष्य मे उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हद तक एक नवीनतम प्रबन्ध है ।

जहां तक डा० सुशीला नैयर के मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1977 का प्रश्न है, यह बतला देना प्रासगिक होगा कि यह विधेयक लगभग वैसा ही है, जैसा कि 1966 में जब डा० सुशीला नैयर केन्द्रीय स्वास्थ्य मत्री थी, सरकार द्वारा तैयार किया गया विधेयक था । तब से 1966 के इस सरकारी विधक

[श्री राज नारायण]

के बहुत से उपबंध विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित हो चुके हैं। विधेयक की भाषा को भी विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक बार परामर्श करने के परिणामस्वरूप कानूनी दृष्टि से अधिक स्वीकार्य बना दिया गया है। इन सामान्य सुधारों के अलावा हमारे विधेयक में कुछ अतिरिक्त उपबंध भी उपलब्ध हैं जो डा० सुशीला नैयर द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक में शामिल नहीं है। ये उपबंध है—

धारा 19 इस धारा में मानसिक रूप से रुग्ण ऐसे व्यक्तियों की भर्ती करने की व्यवस्था है जो कतिपय विशेष परिस्थितियों में स्वयं भर्ती होने की अपनी इच्छा को व्यक्त न कर सकते हों।

धारा 46 : इस धारा में यह व्यवस्था है कि यदि इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश के अनुसरण में पागलखाने में भर्ती कोई मानसिक रोगी यह महसूस करे कि वह ठीक हो गया है तो वह अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है।

धारा 52 : इस धारा में किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील किए जा सकने की व्यवस्था है।

धारा 92 : इस धारा में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी मानसिक-कित्सा अस्पताल आदि का मेडिकल अफसर इन्चार्ज अपनी संस्था में रखे गये हुए मानसिक रोगी की मानसिक और शारीरिक दशा के बारे में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट देगा।

धारा 94 : इस धारा में कतिपय परिस्थितियों में राज्य के खर्च पर मानसिक रोगी को कानूनी सहायता दिए जाने की व्यवस्था है।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हमारे प्रस्तावित विधेयक की धारा 46, 52 और 94 मानसिक रुग्ण व्यक्तियों के प्रत्यक्ष हित में शामिल की गई है। विधेयक की धारा 19 इस अधिनियम के उपबंधों में कतिपय अंतरों का दूर करने के उद्देश्य से शामिल की गई है। धारा 92 अस्पताल आदि में देख-रेख के लिए रखे गए मानसिक रुग्ण व्यक्तियों के हित में भी है। इन बातों को देखते हुए और यह देखते हुए कि मैंने अनेक बार इस सम्मानित सदन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति को सूचित कर दिया है कि सरकार शीघ्र ही संसद में मानसिक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है, गैर-सरकारी सदस्य डा० सुशीला नायर से अपना विधेयक वापिस लेने का पुन: अनुरोध करता हूं और सादर और साग्रह अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक वापस ले लें और जो सरकारी विधेयक हो, वह ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में जाए और डा० सुशीला नायर अपनी सारी जानकारी, अपने सारे ज्ञान और अपनी सारी प्रतिभा ले कर उस कमेटी को सुशोभित करें और उस कोटी को सुशोभित कर के उस का एक सुन्दर स्वरूप दें और सम्मानित सदस्यों ने जो भाव यहां पर व्यक्त करे है, उन सभी भावों का उस में समावेश हो।

श्री हरि विष्णु कामत : कब तक यह विधेयक प्रस्तुत होगा ?

श्री राज नारायण : मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस सदन में आए और इसी सत्र में आ जाए। वह विधेयक बना हुआ है।

अब अगर डा० सुशीला नायर को कुछ हमारे में अविश्वास हो, तो मैं उन से कहूं

कहना चाहता हूं जैसा हनुमान जी ने श्रीराम से कहा था कि अगर मेरे में शक्ति हो, तो मैं अपना पेट चीर कर दिखा दूं और फिर आप देखेंगे कि हमारे हृदय में राम नाम अंकित होगा। वही मैं डा० सुशीला नायर जी से निवेदन करता हूं कि वे अविश्वसनीय वातावरण में विचरण न करें। अविश्वसनीय वातावरण से विचरण करने से बुद्धि में मंदता आती है। इसलिए मैं कर-बद्ध प्रार्थना करूंगा, विनय के साथ प्रार्थना करूंगा कि उन की इच्छा, उन की मंशा जो कुछ वे अपने मंत्री रहते हुए नहीं कर पाईं उसे जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी और व्यापक रूप से पूरा करेगी।

इन शब्दों के साथ पुनः उन से निवेदन करते हुए और इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करते हुए, मैं चाहूंगा कि सदन उन से कहे कि वे अपना विधेयक वापस ले लें और उस के स्थान पर एक सरकारी विधेयक व्यापक रूप में यहां पर प्रस्तुत हो और शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत हो। इस से न तो धरा फटेगी और न ही गगन फटेगा।

डा० सुशीला नायर (झांसी) मैं सभी सम्मानीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और इस विधेयक का स्वागत किया है। श्रीमन्, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का अविश्वास नहीं करती, मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि उनके दिल में रोगियों के लिए कुछ करने की तमन्ना है। वह मानसिक रोगियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और दूसरे रोगियों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूं कि उन्हीं की तरह मैं भी इस सम्बन्ध में बातें करती थी। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री थी उस समय, जब दूसरे लोग इस प्रकार के बिल लाया करते थे, मैं भी कहा करती थी कि इस संबंध में सरकार विधेयक ला रही है। यह बात नहीं है कि हमने उस समय बिल ही बनाया था, हमने बिल तैयार किया था और यह जो बिल मैंने इस सदन के सामने रखा है, यह वही बिल है जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने तैयार करवाया था। हां, इसमें कुछ विशेषज्ञों की सलाह से थोड़ा बहुत सुधार अवश्य किया है। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बिल में कुछ और जोड़ा हो। लेकिन श्रीमन् मैं नम्रता से फिर कहना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी के बिल में और मेरे बिल में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो बिल मैंने सदन में पेश किया है उसमें मैंटल हास्पिटल्स और, मैन्टल नर्सिंग होम्स की बात कही है और जो बिल मंत्री जी लाये हैं उसमें साएकिएट्रिक होस्पिटल्स एंड साएकिएट्रिक नर्सिंग होम्स के बारे में कहा गया है। अधिकतर सब बातें एक सी हैं। इसी प्रकार से दो चार धाराएं मंत्री जी ने और बढ़ायी हैं। आपके बिल की करीब सभी धाराएं मेरे बिल में मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि आपका कहना है कि हम इसी सत्र में यह बिल लायेंगे। लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव है कि पूरी इच्छा होते हुए भी और पूरा परिश्रम करते हुए भी, मैं पांच वर्ष तक बिल लोक सभा में नहीं ला सकी। मुझको मानसिक स्वास्थ्य के बिल के लिए समय ही नहीं दिया गया। 1962 से 1967 तक हमने इस बिल को लाने का प्रयास किया था। 1975 तक यह बिल नहीं लाया गया। फिर इस पर पुनर्विचार किया गया। इस पर पुनर्विचार के बाद यह बिल हमारे सामने आया है, जिस पर कि आज आप विचार कर रहे हैं। मंत्री जी इसे वापस लेने को कह रहे हैं।

मंत्री महोदय से मेरा इतना ही निवेदन है कि जब वे इस प्रकार का बिल स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, इस बिल की भावना से आप सहमत हैं तो मेरा कहना यह है कि बजाय इसके कि आप दूसरा बिल लाएं जिसके लिए आपको लोक सभा से समय मिले या न मिले, जब कि यह बिल लोक सभा

[डा० सुशील नायर]

के सामने है तो इसी बिल को प्रवर समिति के सामने आप क्यों नहीं रख देते ? आप इसमें जो छोटा-मोटा सुधार करना आवश्यक समझें वह प्रवर समिति द्वारा कर सकते हैं । इस बिल को मंत्री जी प्रवर समिति को भेजने की सहमति दें ।

श्रीमन मे यह बिल प्रवर समिति के लिए पेश करती हू और स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हू कि वे इस विधेयक को पास करने का समय लंबाये नही । मानसिक रोग एक बहुत बडी समस्या है । मे अपने परिवार में मानसिक रोग को देख चुकी हू और मित्रो के यहा भी । इसी वजह से मेरे दिल में यह लगन है तडप है । मे जानती हू कि मानसिक रोगियो की क्या हालत होती है, उनका दाखिल कराने में कितनी कठिनाई होती है । अस्पताल में रोगियो की क्या हालत होती है, यह सब मे जानती हू । मे इस सम्बन्ध में अनुभव कर चुकी हू, देख चुकी हू । श्रीमन मंत्री महोदय, बडे लगन वाले उदार व्यक्ति हैं । मैं उन से सहमत हू कि मानसिक रोगी केवल पत्थर फेंकने वाला पागल ही नही होता है । जिस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने गलत काम किये वह भी एक प्रकार की मानसिक विकृति ही थी । अंग्रेजी में इसे इमोशनल इनसिक्योरिटी कहते हैं । इमोशनली इनसिक्योर व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि मे बहुत बडा हू, मेरे से बडा कोई नही है और वह अनेक प्रकार के गलत काम करता है । इस देश में एक जिन्ना थे थे जो इसी प्रकार से मानसिक विकृति के शिकार थे और उनके कारण इस देश का विभाजन हुआ । इसी प्रकार की मानसिक विकृति वाले एक हिटलर थे जिस ने यूरोप मे खून की नदियां बहाई । मानसिक विकृति को शुरू में ही पकड लिया जाए, उसको दुरुस्त कर दिया जाए, यह अत्यन्त आवश्यक है । इस विषय में आयुर्वेद का भी स्थान है, यह मे अच्छी तरह से जानती हू ।

मे स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हू कि हमारा जो शब्द है स्वास्थ्य वही सब से अच्छी डैफीनीशन है मानसिक हैल्थ की । स्व मतलब सैल्फ । स्थ अर्थात स्टेबलिटि स्थिरता जिस की अपने अन्दर स्थिरता है स्टेबिलिटी विदिन सैल्फ । यही मेंटल हैल्थ का सिन्क्रिट है । हमारा हिन्दी का शब्द स्वास्थ्य मेंटल हैल्थ की खूबसूरत डैफीनीशन है ।

इससे आगे जा कर मैं कहना चाहती हूं कि बंगलौर में एक मेंटल हैल्थ इस्टीटयूट है । वहां पर एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे । उनके द्वारा हमने सिजोफेनिया वालो का ट्रीट्मैंट कराया था और वह इतना सफल हुआ था कि हम ने वहां पर पचास बैड उसके लिए कर दिए थे । ऐसे बहुत से किस्से है जिन का आप जानते हैं ।

16 53 hrs

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

जो विधेयक मैंने पेश किया है उस में अस्पताल के अन्दर चिकित्सा, आउट डोर तरीके की चिकित्सा, क्लिनिक द्वारा चिकित्सा, स्वेच्छा से मरीज अस्पताल में जा सके और अस्पताल से निकल आए, मैजिस्ट्रेट के पास अपील इत्यादि करने की व्यवस्था सब चीज मौजूद है । मे स्वीकार करती हू कि मंत्री महोदय के पास जितने साधन है मेरे पास इस बिल को रिवाइज करने के, सुधारने के उतने साधन नही थे । मैंने जितने भी मेरे मित्र थे, विशेषज्ञ थे, उन से पूछ कर इस में सुधार जितना मैं कर सकती थी किए । अब इस में और भी जितने सुधार वह करना चाहते हैं बडी आसानी से प्रवर समिति के सामने आ कर वे कर सकते

हैं और दूसरे लोग भी अपने सुझाव उस समिति को दे सकते है । अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि दो चार छ महीने मे यह बिल कानून बन जाएगा और अनेकानेक मानसिक रोगियों को राहत मिलेगी । अगर मंत्री महोदय इसको स्वीकार नही करेंगे, इसको वापिस लिए जाने का आग्रह करेंगे तो यह सारी प्रक्रिया लम्बी जाएगी । प्रभु जाने कब उनको वक्त मिलेगा । उनकी इच्छा रहते हुए भी काम इतना होता है लोक सभा में कि सभव नही हो पाता है कि सभी बिलो को लाया जा सके या पास करवाया जा सके ।

सभापति महोदय, मे आपकी आज्ञा से ये बीस नाम प्रवर समिति के लिए उनकी सेवा में पेश करना चाहती हू । डा० कर्ण सिह, डा० सरदीश राय, श्री कृष्ण कान्त, डा० मुरली मनोहर जोशी, श्री हरि विष्णु कामत, श्रीमती मृणाल गोरे, श्री सी० के० चन्द्रप्पन

MR CHAIRMAN: The motion is for the consideration of the Bill.

DR SUSHILA NAYAR: I am saying that the Bill .

PROF P G MAVALANKAR (Gandhinagar): She is moving an amendment for sending it to the select committee.

DR. SUSHILA NAYAR: I am saying that the Bill which I have presented, may be agreed to by the hon. Health Minister and sent to Select Committee, consisting of the 20 names that I have given here, plus such names as may be given by the Rajya Sabha, so that the few small changes that have been made in the Government draft Bill which the Minister wants to present, can be incorporated in this very Bill. I read out the remaining names. They are: Prof. P. G. Mavalankar, Shri Saugata Roy, Shri Vasant Sathe, Shrimati Pramila Chavan, Shri Satyanarayana Rao, Shri Venkataraman, Dr. Bapu Kaldate, Dr. Ramji Singh, Prof. Dalip Chakravarty, Shri Ravindra Varma, Shri Shanti Bhushan, Shri Raj Narain and Dr. Sushila Nayar. These are the 20 names that I would suggest. I would request most humbly, most forcefully, with folded hands that the Health Minister may please accept this Bill in the interests of the suffering mentally sick people. He may please introduce such changes as he desires in this very Bill in the Select Committee, so that there is no chance of this matter being again put in cold storage I know the Health Minister will not wish to do it. मुझे विश्वास है कि वह इस काम को जल्दी कराना चाहते है । लेकिन होगा नही । मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रही हू । मैंने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन पाच बरस मे यह बिल पास नही करा पाई । उन से भी नही होगा । मानसिक रोगियो के लिए यह बहुत दुख की बात है कि यह विधेयक फिर से खटाई में पड जाये । इसलिए अत्यन्त विनम्रता से मंत्री महोदय से पुन निवेदन है कि वह सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और इस मे उन के अपने जो भी सुधार है, उन्हें शामिल कर लें ।

श्री राम बेनी राम (पलामू) · सभापति महोदय, मेरा पायट आफ आर्डर है । क्या किसी प्राइवेट मेम्बर को यह राइट है कि वह स्वयं सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरो के नाम प्रोपोज करे ?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Chairman, so far as that point of order is concerned, I do not think anything precludes the hon. Member from suggesting certain names for consideration by the hon. Minister. It is the Minister who will finally suggest the names of Members. But nothing precludes a Member from suggesting some names for the consideration of the Minister.

श्री राज नारायण . सभापति महोदय, मैंने सविनय, सादर, साग्रह माननीया डा० सुशीला नायर से करबद्ध प्रार्थना की है कि वह इस साधु विधेयक को वापस ले लें, क्योंकि उनकी सारी मंशा को रखते हुए, और व्यापक दृष्टिकोण से, तमाम राज्यों के जो समितियां आई है, उनका और तमाम विशेषज्ञों तथा विश्व के अनेक विद्वानों की सम्मतियों का समावेश करके सरकार ने एक विधेयक तैयार किया है । उस विधेयक को ला-डिपार्टमेंट और अन्य सम्बन्धित डिपार्टमेंट्स ने देख लिया है । वह विधेयक हम जल्दी से जल्दी लायेंगे । मालूम नहीं क्यों एक मामूली सी बात को समझा नहीं गया, जो डाक्टर की समझ में आनी चाहिए, और वह है व्हील आफ हिस्ट्री—इतिहास चक्र ।

एक जमाना था सुशीला जी के मन्त्रि-मंडल काल का । एक जमाना है हमारा । 1969 में श्री नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए तिकडम, साजिश और धोखे से हराया गया । लेकिन वही श्री नीलम संजीव रेड्डी आज राष्ट्रपति पद पर विराजमान हैं । 1969 में श्री मोरारजी देसाई मन्त्रि-मंडल से साजिश, तिकडम और बेईमानी के द्वारा हटने के लिए मजबूर किये गये । मगर वही मोरारजी भाई देसाई आज भारत के प्रधान मंत्री के पद पर आसीन है । यह है इतिहास का कालचक्र जो काम सुशीला जी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नहीं कर पायी जनता पार्टी की सरकार उस काम को कर पाएगी, मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं । इसलिए मैं फिर उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इतिहास के काल-चक्र को समझते हुए अपने विधेयक को वापस लेने की अनुग्रह कृपा करें और सरकार के विधेयक लाने के अवसर का इंतजार करें और अगर नहीं करें तो . . (व्यवधान) . .

17.00 hrs.

श्री० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर): मंत्री महोदय ने कहा कि लाएंगे, तो कितनी जल्दी लाएंगे यह बता दें ।

श्री राज नारायण : जल्दी से जल्दी, त्वरित गति से, इसी सेशन में लाएंगे और उसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेज देंगे । सुशीला जी उसमें विराजमान रहेंगी ।

डा० सुशीला नायर : मुझे खेद है कि मंत्री महोदय ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की और वह नहीं करेंगे तो पार्टी के एक डिसिप्लिन्ड सदस्य के नाते मुझे विधेयक वापिस लेना पड़ेगा लेकिन मुझे खुशी इस में बिलकुल नहीं है, इतना मैं कहना चाहती हूं । मैं सदन की आज्ञा चाहती हूं वापिस लेने की ।

I beg leave of the House to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto

MR. CHAIRMAN The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to the treatment and care of mentally ill persons, to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted

DR. SUSHILA NAYAR: I withdraw the Bill

The Bill was by leave, withdrawn.

17.02 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 51)

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

As I rise to move the Bill which stands in my name for the consideration of the House, a Bill which seeks to amend article 51 of the Constitution, which seeks to incorporate a new provision in that article, my heart is filled with prayerful humility, my mind is uplifted by a joyous pride—humility because I think Providence and God that it has fallen to my lot to move in this supreme people's forum of the largest democracy in the world for its consideration an issue of momentous consequence for the future of mankind, an issue which, as far as I am aware, has not been debated in this House so far, nor perhaps even in the predecessor Assembly, the Central Legislative Assembly, an issue which has gathered momentum during the last fifty years or more of this century and particularly after the tragic conclusion, of the Second World War.

However, I have got a pride in my heart because, India being the largest democracy on earth, the Parliament of India should, in the fitness of things, move in this direction, a direction chalked out by the ineluctable destiny of mankind—in the poet's words: "that one divine event to which the whole creation moves", and in the words of another poet: Mankind seeking, groping, to found, establish, "the Parliament of Man, the Federation of the World". Our sages and seers, our poets and our philosophers from time immemorial have uttered words of wisdom in poetry and song, immortal words of perennial philosophy—words which we find in this very House of Parliament, of the largest democracy on earth, the quintessence of that wisdom of our sages and saints. Entering Parliament House by Gate No. 1 and walking straight on towards the great Central Hall where the Constituent Assembly of India met 30 years or more ago, your eyes are arrested by letters of golden hue, the colour of burnished gold, of tapta kanchan, letters which proclaim words of divine wisdom, eternal verities which have always inspired mankind.

अयं निजः परोवेत्ति
गणना लघुचेतसाम्
उदार चरितानां तु
वसुधैव कुटुम्बकम्

Mankind is one family. That was proclaimed by India centuries ago, millennia ago and I am glad to say that is quintessence of wisdom which alone can save mankind in the coming years, in future—Sasudhaiva Kutumbakam—it will be a beacon to that grand future, to the ultimate establishment of a World Government, a World Order based on World Law. That is what is meant by World Government,—a World Order based on World Law. And I am happy that this idea, this noble idea, this inspiring idea, inspiring objective has been accepted, endorsed, espoused and proclaimed once again in our modern times. The United Nations and its predecessor, the League of Nations after the First World War, took a faltering step, small step in that direction. And now mankind is awaiting the big step. And that step, I see, is not far off. It is not a distant dream after all It will be achieved in our times. I have no doubt, I have no apprehensions on that score because without that there will not be a world without want, a world without fear which our Prime Minister has proclaimed so often during the last 12 months—a world without fear, a world without want. There cannot be a world without want,

[Shri Hari Vishnu Kamath]

without a world without war. There cannot be a world without fear, without a world without war. There cannot be a world without war without a World Government. That, Sir, is the ineluctable and logical conclusion that one can arrive at and one does arrive at if you think on this problem. Mahatma Gandhi in his very simple style, on the subject some years ago, 40 years ago, wrote:

> Nationalism is not the highest concept. The highest concept is World Community. I would not like to live in this world if it is not to be one world . . . ."

> "Our objective is one world, we have to work for it and the brotherhood of humanity."

What did Jawaharlal Nehru say on the same subject?. He said:

> "I have no doubt in my mind that world federation must and will come, for there is no other remedy for the world's sickness."

And this is what the great mystic Maha Yogi of modern time, of modern India, Sri Aurobindo, put in his own inimitable and forceful style—with its most compelling logic—and this is from the book, "The Ideal of Human Unity" (A Post Script Chapter, written in 1950):

> "Even a World State in which both Capitalism and Communism) could keep their own institutions and sit in a common assembly might come into being and a single world-union on thisfoundation would not be impossible. This development is indeed the final outcome which the foundation of the U.N.O. presupposes; for the present organisation cannot be itself final, it is only an imperfect beginning and useful and necessary as a primary nucleus of that larger institution in which all the peoples of the earth can meet each other in a single international unity, the creation of a World State is in a movement of this kind the one logical and inevitable ultimate outcome."

I am happy to say that I was present on the historic occasion in October last, 4th October, 1977, in the United Nations. As a delegate I was deputed there by the Government and I was happy to be there on that historic occasion when the Minister of External Affairs, the leader of our delegation, Shri Atal Bihari Vajpayee, made for the first time in the history of the United Nations a speech which was remarkable for its content as well as for its form, not to say anything of the language, and the rhetorical style in which he spoke. Hindi was heard in the Hall of the United Nations for the first time in its history. That was a big break-through though, of course, I am sorry to say that the impact could not be assessed because very few cared to listen to the speech in Hindi and most of the delegates, 90 per cent or more perhaps, listened to the translation either in English or in French or in Spanish or in Russian or in Chinese or in Arabic. We the Indian delegates listend to the speech in Hindi and, perhaps, a few delegates of Nepal ....

MR. CHAIRMAN: Did you speak in Hindi?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I spoke later. I did not speak in Hindi. That was the first speech and so far —the last speech made in Hindi in the United Nations. I would come to that later on when I speak on the demands of the Ministry of External Affairs, the difficulty of making Hindi as a language of the United Nations and the hurdles that are there. When I speak on the demands of the Ministry of External Affairs later on during this session, I will deal with that. I do not want to waste the time of the House now to say who spoke in Hindi and who did not. I only wanted to make a point that the Minister spoke in Hindi. That was a break-through. But what he said also in the course of his speech was even more important. He referred to, as a matter of fact, the very words वसुधैव कुटुम्बकम् and went on to say that not merely he wants a new international economic order, but

he said, he wants a new international political order and on the basis of that quintessence of wisdom, those words of wisdom वसुधैव कुटुम्बकम् we have to build a new world order. I forget the exact words he said I wanted to get a copy of the full text of his speech yesterday, but I have not been able to get the copy so far, I tried my best, I hope to get it next time before the fortnight lapses that I may quote from that speech of our External Affairs Minister, not Foreign Minister He is not foreign to us, he is External Affairs Minister, and wrongly called Foreign Minister And he ended, he concluded his peroration with those two words which have never been perhaps heard in the annals of the United Nations, in the Halls of the United Nations

जय जगत जय जगत

and in English 'Hail One World" That is how it is ended so that I do not have to persuade the Ministers or my colleagues, intelligent colleagues, hon colleagues in this House, with regard to the necessity for this world government and for promoting and strengthening the movement towards a World Order I do not have to undertake much labour on that score, that is what I feel. And I am sure, many of my colleauges would endorse the idea underlying the Bill which is brought forward, introduced, moved today in the House for consideration of this Lok Sabha Moreover, it is not that we are alone Some friends may think that we are alone and this may be a sort of mad cap idea—either a wise crack or a mad cap idea—Some Members may feel, but it is not so

As a matter of fact, during the last 25 years, after the Second World War, the movement towards world government, towards world federalism has been growing apace and making much strides towards its ultimate solution, its ultimate achievement, attainment A world federalists union—I am not sure what was the exact designation—was founded soon after the First World War and there was an India Chapter also.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South) The world association of world federalists

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Thank you The Professor is more *au courant* with the subject than I am, I am thankful to him The world association was founded of which there was an India Chapter also, that means an Indian branch, of which the late Shri Ayyangar, who was at the time, the Deputy Speaker, I think, of the Lok Sabha, 1950 or 1951, he was the President or the Chairman of India Chapter, and I was member of that body also at that time

It, unfortunately, did not make much headway in India during those years And I introduced a Bill in the Third Lok Sabha on these very lines in 1964 or 1965 seeking to amend Article 51 But being a Private Members' Bill, it did not get a chance at all for a motion for the consideration of the Bill and so it fell through And then I was out of the House for ten years I came back last year and as soon as I came back, I reintroduced the Bill because I feel that there is a definite movement in the whole world, wide world, not all countries perhaps, but a few important countries There are groups of World federatists, there are groups who stand for World Government, there are groups who stand for a World Order and a World Law and which want to get together, as I have mentioned in the Statement of Objects and Reasons.

In the 'Statement of Objects and Reasons', I have said very briefly, in two or three sentences

> "The time is opportune, may ripe, for all good men and good governments of the world to get together and make earnest efforts for convening a World Constituent Assembly as a preparatory step towards the establishment of a Parliament of Man and Federation of the World. War cannot be abolished, nor can a warm living peace descend on earth, unless such a world order based on World Law is firmly founded."

[Shri Hari Vishnu Kamath]

I am happy to note and to convey to you and to the House that, not being aware of it, not at all being aware of that movement outside, last year about the time I introduced this Bill in the House, in July last—it was perhaps, a telepathic communication which went on, I do not know at the same time, in the same month, end of June or early July, there was a world Constituent Assembly convened not by Govegnments but by peoples of the world, voluntary organizations, which met at Innsbruck, Austria. That World Constituent Assembly, in July 1977, when I introduced the Bill here in Parliament for that purpose—I came to know about it only later on when I got a communication from them; I got it when I was in the United Nations—met together and they have formulated as a matter of fact—anticipating my Bill, the object of my Bill—a Constitution for the Federation of Earth, that is, the World Federation Government Constitution, a very enlightening, interesting and knowledgeable document, to show that they know what they are doing, that it is not a sort of building castles in the air at all:

Article 1 'Broad Functions of World Government',

Article 2 'Basic Structure of World Federation and World Government', and so on it goes.

The first Chapter is 'The World Parliament'; then comes 'The World Executive'; then comes 'The World Administration'; then comes 'Integrative Complex'; then comes 'The World Judiciary'; then comes 'The Enforcement System'; then comes 'The World Ombudsmus'. They call it 'Ombudsmus', perhaps the plural of the Scandinavian word 'Ombudsman' is not 'Ombudsmen' but 'Ombudsmus', that is why they have used the word 'Ombudsmus'—'The World Ombudsmus'. Then comes 'Bill of Rights for the Citizens of Earth'; then 'Directive Principles for the World Government' then 'Safeguards and Reservations'; then 'World Federal Zones and the World Capitals'; then 'World Territories and Exterior Relations'; then comes 'Ratification and Implementation; then 'Amenment'. It is a very comprehensive Constitution that they have framed—the World Constitute Assembly which met informally and unofficially at Innsbruck, in Austria, in June-July 1977.

Now, what do I propose, what do I seek, through my Bill? Before I come to that, I would like, briefly, to refer to what Einstein, the mathematician-mystic of this Century, said. His name is well known; I need not say how he had to flee Hitler's Germany in the Thirties and seek refuge in the United States where in Princeton University he worked on till he passed on a few years ago

He was asked some time in the 1950s, I believe, when the atomic race was in progress and the super powers were building up stock-piles of atomic bombs and people thought that the Third World War might erupt any day and might devastate humanity—he was one of those who was asked by someone· "What do you think, Mr. Einstein, what weapons will humanity use in the Third World War?". The mathematician, the mystic, scratched his grey old head for a few seconds and then he said "Well, I don't know about the Third World War, but in the Fourth World War they will fight with sticks and stones" meaning thereby...

AN HON. MEMBER: Total destruction.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Yes, total destruction in the Third World War so that there will be nothing left to use but sticks and stones. There will be no weapons left at all.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S. KUNDU): But Adam and Eve will be left?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Yes, they will be left.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Thank God he says that some people will be left so that they can fight again;

SHRI HARI VISHNU KAMATH: So, that is the stark reality that faces us today If we wish to avoid a Third World War—the Third World War cannot be avoided as long as this hangover of the 19th Century political doctrine of national sovereignty still stalks the earth—national sovereignty to make war. To make war is one of the cardinal features of national sovereignty. In modern times, man has gone to the moon and looked at the earth from the moon and got a vision of the earth as to what it is, cut the earth to its size by seeing what a small plannet, after all, it is in the universe. But even in this age when man has reached the moon, even now, there is the race for armaments and people still cling to the notion and doctrine of national sovereignty National frontiers have no meaning now. Distance has been annihilated more or less The old science fiction by Jules Verne.—when he wrote that book 'Round the World in 80 Days' (not so long ago, when I was at school. I read that book, about 50 years ago) we thought it must be a great achievement to go round the world in 80 days. But now people will think, why waste 80 days in going round the world, we can go round the world in 80 hours or even less by that supersonic called 'Discord' or 'Concord' or whatever else it is When distance is thus annihilated, you can reach the other end of the world in a few hours, you can hear music from the other end of the world in a few seconds. These are the astounding technological developments and scientific discoveries, and yet, the old crude notion of national sovereignty persists and afflicts humanity—the sovereign right of a nation to make war, to declare war. I am sure that the super-powers like the USSR, (Russia) and America will fight a last ditch battle to retain this right of a sovereign nation to declare war. Therefore, it is very necessary that all other nations should join together even if these two super-powers do not agree; there are groups of people in America, the United States, who are pressure groups, well meaning groups of people who want to further this idea. About Russia, I do not know whether such groups are functioning, but even in the USSR there are such men like Andrei Sakharov and other dissidents. But whether, if they have such plans, they will be permitted to expound them and whether the public have a right to know about them, I do not know. But in America there are some groups and it is but right that we should collaborate with such people and groups. To my mind, the two great problems of the world are wars and the population problem, the food problem I may be regarded as a mystagague, but I for one feel that under a wise and beneficent Providence, who is omniscient, omnipotent and omnipresent, this world taken as a whole, as one entity, not separate nations, separate countries, the world taken as a whole is not overpopulated and cannot be over-populated. It was Dr. Kurt Waldheim, the present Secretary-General of the United Nations, who speaking at the world Demographic Conference in Bucharest in 1974, said that the world's terraqueous resources, resources of land and sea, land and water both—food resources—can support a population of 76 billion people. He said that the world resources, if man can but labour, can but strive to husband those resources, utilise those resources to the full by his talent and by his labour, can support 76 billion people of the world. Today, some countries are over-populated. You may even say that India is over-populated, but India's basic malaise is under-production of food, not over-production of babies. That is how I may formulate

[Shri Hari Vishnu Kamath.]

that; that also has to be controlled, but the basic malaise of India is under-production of foodgrains.

The productivity of our land in agriculture—I do not compare it with United States or other European effluent nations—even compared to Japan in the East and Israel in the West is perhaps one-third and not more than half. This is the basic malaise and the other problem is of population; food and population are inter-linked.

As I said, if the world is taken as one entity, it is not over-populated. Look at Africa; the whole of Africa is perhaps ten times the size of India; I am not sure, it may be more than ten times or it may be fifteen times. The entire population of Africa—Sub-Sahara and Supra-Sahara—is less than 300 million. So is the case of South America, also of Australia. The population of Canada is 20 million, and its area is bigger than India. Even in the case of the United States, it is 220 million and the land area is bigger than that of India; one and a half time or one and one-third So also is the case in respect of Brazil. Compared to all these countries, India and China may appear to be over-populated, but if there is a World Government, it will be a world without passports, a world without frontiers, a world without war, world without want, and without any population problem—maybe you think that I am conjuring up a vision which is a utopia and which has no reality, but I did conjure up a similar vision in the Constituent Assembly to which I will not refer today, but if chance occurs next time during the debate, I will refer to that. A World Government can re-distribute population also. It can undertake re-distribution of population and see that countries which are over-populated do not suffer from that malaise. The food resources could be distributed evenly among the nations of the world. If food can be re-distributed, why not population?

Then there are problems of ecology—ecological problems, environmental problems, which to-day dominate the scientific stage in all countries of the world, and which have to be solved only on a world basis. Because, take for instance, air, vayu-

वायु सर्वमो महान । as Geeta says.

It is the biggest force It is the same vayu from Alaska to Shanghai. That vayu can spread poison. It can bring you precious life, and it may also kill you. If ecology makes' the world one, if jet travel has made the world one, if people crossing from one continent to another in a few hours has made the world one, what stands in the way of making the world truly one, of having a World Order based on World Law and that is through a World Government? That is the objective of the Bill.

Now friends may ask—how can the objective of the Bill be achieved and how can Government support this Bill? I am anticipating the difficulty of the Government. May I make a humble submission that I have deliberately, advisedly foreseen, anticipated the Government's difficulty. I have sought to....

Something is going on on the dais.

MR. CHAIRMAN: I am hearing you. I am just looking at the end of your speech. I am trying to see where is the end of the speech.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: You will see the end very soon. It is the end of the tunnel. Light is coming very soon. This is the fag end of my observations.

I am sorry that you have got impatient. This debate will be carried on to the next day. It is not going to end to-day and let us have patience.

MR. CHAIRMAN: Others will also like to speak.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I have now sought to amend Article 51. Article 51 is a part of the Chapter captioned 'Directive Principles' of State Policy'.

Yesterday somebody asked—are you going to amend the new Chapter of fundamental duties—51 A? 51A—one of the vicious provisions of emergency; I do not know what you may call it—an unhealthy provision of the emergency period—I have nothing to do with that.

My Bill deals with Article 51 of the 'asli' Constitution and not 'nakli' Constitution Article 51 reads as under. Will you kindly give your personal attention to that for a few seconds.

"51. The State shall endeavour to—

(a) promote international peace and security;

(b) maintain just and honourable relations between nations;

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another; and

(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

All this, Sir, is leading us, Government and the Parliament towards...

What is all this for? Have you got some goal objective or not? Or are you grooping in the dark? What are you doing all this for? Is there not some objective worth while? Worth our while—our efforts in India, is all that not worth something—bigger to incorporate a new sub-clause (e)?

If my amendment is accepted, it will read as follows:

"The State shall endeavour to collaborate with other nations for the early formation of a world Constituent Assembly to draft the Constitution for a world federal Government."

Mark my words. One of my friends said to me that if I say 'the State shall do so', then he cannot accept that proposition at all. Some one from the Treasury Benches—I won't mention who—said so. The words are. "The State shall endeavour to" as in her articles. Have we implemented the other articles? Has the Government implemented the article on Education? Look at that article. What a mockery it has become. About education—Article 45 says:

"The States shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years"

Nothing has been done. It remains just a directive. It may not be implemented till 2,000 A.D. Again, look at Article 41. It says:

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work.. ..."

All these articles in this chapter of the Constitution start with the expression 'shall endeavour'. What are the duties cast on the Government? What obligations are cast on the Government? Nothing. I have said 'shall endeavour'. Endeavour may take a long time, it is a continuous process It is not that they will achieve in one or two years or five years or ten years. The State's endeavours for education have continued for the last thirty years. But, nothing much has come out of it so far. Article 45 is still only on paper. It has not been implemented. Of course I shall feel sorry if this my Bill is not implemented because other nations also come into the picture. But, so far as we are concerned, so far as India is concerned, we can say to the world —I will expect the Minister to say in this House that first, we accept the idea of a World Government in principle. We stand for that. The ultimate objective of humanity should be a World Order. I would be happy

[Shri Hari Vishnu Kamath]

and proud and, with all humility in my heart, utter a prayer to the Almighty, if the Minister also says that we, the Government of India and the people of India will or are prepared to collaborate, strive with other likeminded nations for the attainment of this objective

If that call from the largest democracy on the earth goes from here, who knows what will be the impact of this call? who knows how the other nations will react? Because, in some of the countries which I have visited during the last few months, I have had talks with some people, they said that if India the largest democracy should take the initiative in the matter and shows the light to a world in darkness, show the light to a world enveloped in darkness, a world which is saying the same prayed as Gandhiji used to

"Lead kindly light amidst the encircling gloom
Lead thou me on
The night is dark
And I am far from hope
I do not ask to see the distant scene
One step enough for me"

That "one step enough for me" must now come from the Government If they take that step I shall be happy

They may accept the concept of a World Government in principle, accept the idea and also declare that they are prepared to collaborate with other likeminded nations for the attainment of this ultimate objective of mankind I am sure that the Minister, the Government, will have no difficulty in formulating their stand on this basis If that basis is assured I am sure that the light which is shed from here, from Parliament, from Lok Sabha will travel its vibrations, will travel all over the world and will illuminate the hearts and minds and uplift the minds of mankind

I therefore move the Bill to amend the Constitution of India for the earnest and the urgent consideration of this House so that this Parliament of India may lay the first foundation stone of a World Government, of a World Order based on a World Law.

MR CHAIRMAN Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration'

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) सभापति जी, जो विधेयक श्री कामथ ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, सिद्धान्त रूप मे मैं उस का समर्थन करता हू और सम्भवत कोई भी व्यक्ति जो इस देश मे रहता है और इस देश की सस्कृति और सभ्यता मे विश्वास करता है, इस का विरोध नही कर सकता। हमारे देश की सस्कृति की दो तीन विशेषतायें हैं—एक तो यह कि हमारे अन्दर टालरेशन होना चाहिये, दूसरे यह कि दूसरा के लिये त्याग की भावना होनी चाहिय, इतना ही नही, दूसरो के विचारो का आदर करने की आदत भी हमारे अन्दर होनी चाहिये। हम केवल अपने बारे मे नही सोचते, अपने परिवार के बारे मे नही सोचते अपने शहर के बारे मे नही सोचते, अपने देश के बारे मे नही सोचते, हमारी सस्कृति सारे ससार के बारे मे सोचती है। इस लिये ससार के हित मे जो कोई भी कार्यवाही हो, हमारे देश और हमारी सरकार का उस का समर्थन करना चाहिये। आज दुनिया के देश एक-दूसरे के साथ जुडे हुए है। इन्टर डिपेन्डेन्ट हैं। कई बहुत समृद्ध देश हैं कई बहुत गरीब देश है और डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। अगर दुनिया मे शान्ति रखनी है तो डिस्पैरिटीज को खत्म करना होगा, इकानामिक डिस्पैरिटीज, सोशल डिस्पैरिटीज और जो दूर करने की भावनायें है, उनको खत्म करना चाहिये। जब तक ये खत्म नही होगी, तब तक यह वर्ल्ड-गवर्णमेन्ट-आर्डर या वर्ल्ड कांस्टीचूएन्ट असेम्बली की बातें केवल हवाई बातें है, इस का कोई लाभ नहीं होगा

आज हम देखते हैं—कहां अमरीका है और कहां श्री लंका और भारत है। दोनों की पर-केपिटा इन्कम में जमीन और आसमान का अन्तर है। ये चीज खत्म होनी चाहिये आज हालत क्या है—लोग शान्ति चाहते हैं, हर देश शान्ति चाहता है, लेकिन जो पोलिटीकल लीडर्स है, हर देश के पोलिटीकल लीडर्स के विचार संकुचित है, वे अपने देश से आगे नही देखना चाहते, वे यह देखते है किसी तरीके से हम दूसरो का हिस्सा कैसे छीन सकते हैं। हमारे देश की सभ्यता, सभापति महोदय, आप जानते हैं। हमारे देश का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि हमने किसी के ऊपर कभी आक्रमण नही किया। हम आक्रमण करने मे विश्वास भी नही करते, हम टैरिटोरियल एक्सपेंन्शन मे विश्वास नही करते। हमारे पूर्वजो ने भी नही किया और हम भी नही करते। लेकिन यह भावना आज दूसरो मे नही है। इस लिये आज जब हम वर्ल्ड-आर्डर या वर्ल्ड कास्टीचूएन्ट असेम्बली की बात करते है तो हमे उस के लिये पहले एक रास्ता तैयार करना होगा और वह रास्ता यूनाइटेड नेशन्ज के आधार पर तैयार होगा।

अभी कार्टर साहब आये। उन्होंने कहा—आप नान-प्रालीफेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दीजिये कि आप एटम बम या न्यूक्लिअर बम का परीक्षण नही करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा—हम शान्ति के लिये उपयोग करेंगे, लडाई के लिये नही करेंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने उस समय एक सवाल भी किया—आप के पास जो एटम बम है या रूस के पास जो एटम बंम है या जिन-जिन विग-पावर्स के पास हैं, आ प पहले उन सब को खत्म कीजिये। उस के बाद हम हस्ताक्षर करेंगे। आज दुनिया मे शान्ति की बात ऊपर-ऊपर से चल रही है, कोल्ड-वार अभी भी जारी है। इण्डियन ओशन में क्या हो रहा है? बड़ी-बड़ी ताकत वहां पर हैं। इस लिये अगर हमें वर्ल्ड की कास्टीचूएन्ट असेम्बली बनानी है तो पहले कुछ एलीमेन्ट्री काम करने होंगे—जितने भी भयानक हथियार आज किस-किस के पास हैं, सब से पहले उन सबको समाप्त किया जाय। केवल इन्टरनल सेक्यूरिटी के लिए जितने हथियार आवश्यक हैं, उनके अतिरिक्त जितने भी हथियार हैं वे सब हमे खत्म करेंगे। अगर यह नही होगा, तो यह केवल यूटोपियन आइडिया रह जाएगा और कभी व्यवहार मे नही आएगा। इतना ही नही, हमारे देश का एक सिद्धान्त पंचशील का है। जवाहर लाल नेहरू जी इस का बहुत जिक्र करते थे कि जिस तरह से हम भारत में चाहते हैं कि स्वय से बर्ताव किया जाए, वैसे ही दूसरो के साथ बर्ताव करना चाहिए। यह भावना हमारे देश की संस्कृति मे है, हमारे देश के अन्दर है, हर एक व्यक्ति के अन्दर है लेकिन यह भावना अभी दूसरे देशों मे नही आई है और जब तक यह भावना नही आती है, जब तक शान्ति स्थापित नही हो सकती है। कहने को बातें कुछ भी नही कही जा सकती हैं और आज जो यह वर्ल्ड एसेम्बली की बात है, वह होना मुश्किल है क्योंकि आज आप देख रहे है कि कोल्ड वार चल रही है, डिस आर्मामेंट के बारे मे बातचीत चलती है, तो बडे बडे जो देश हैं वे आर्मामेंट को नही छोडते है। वे चाहते हैं कि दूसरे लोग आर्मामेंट न करें लेकिन खुद उस को नही छोडना चाहते है। वे चाहते है कि दूसरे देश एटम बम न बनाए लेकिन वह खुद बनाना चाहते है। इस तरह से दुनिया मे शान्ति कभी स्थापित नही हो सकती है। अगर वर्ल्ड कायम करना है और फेडरल गवर्नमेंट बनानी है या वर्ल्ड एसेम्बली बनानी है, तो उसके लिए कुछ तैयारी करनी पडेगी, कुछ सैल्फसेक्रिफ इस करनी पडेगी और लार्ज हर्टेडनैस से हमे एक दूसरे को समझना पडेगा कि हम सब का एक परिवार है और हम उस एक परिवार के अंग हैं, हमारा सब का एक कुटुम्ब है। जब तक यह नही होगा, तब तक कुछ नही होने वाला है। क्या संसार इस चीज के लिए तैयार है कि हम यह तैयार करे कि सरकारे लडाई करेंगी और हमारे आपस मे झगडे नही होंगे। सब देश मिलजुल कर यह तय करें कि लडाई नही करेंगे, लेकिन इस के लिए शायद वे तैयार

[श्री कंवर लाल गुप्ता]

नहीं हैं। हम ने पाकिस्तान को ग्राफर किया कि हम नो-वार डेक्लरेशन की बात करें लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ। तो ये एलिमेंटरी प्रीपेरेशन्स जब तक नहीं होंगी, कि नो वार पैक्ट हो, हमारे जो हथियार हैं, वे सारे खत्म होने चाहिए और इस तरह का हमारा एक बिहेवियर होना चाहिए जैसा कि भाइयों के साथ होता है, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हू कि इन सब तैयारियो के सबध मे यूनाइटेड नेशन्स में एक कमेटी बने, तो वह कुछ रास्ता बता सकती है और उस के ऊपर अमल हो सकता है।

मैं यह भी चाहूंगा कि आज जो वीटो की पावर कुछ देशो के हाथो मे है, जो कि बडे देश कहे जाते हैं, वह भी समाप्त होनी चाहिए। आखिर जब सब बराबर हैं, तो वीटो की पावर कुछ देशो के हाथ मे ही क्यो होनी चाहिए। दुनिया मे कोई देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो गुलामी के अन्दर रहे और हर एक देश आजाद हो। जब तक यह सब तैयारी नहीं होती है, तब तक मुझे माफ कीजिए, वर्ल्ड की एसेम्बली का आइडिया केवल एक यूटोपियन आइडिया ही रह जाएगा, वैसे मैं यह समझता हू कि यह एक अच्छा आइडिया है, जिस की मुखालफत नहीं की जा सकती और सब मे सब देश आगे बढ कर दुनिया की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और उन को करना चाहिए। मैं इस विचार से सहमत हू लेकिन आज भारत के अन्दर ही आप देखिये कि एक स्टेट की दूसरी स्टेट के साथ लडाई है, कहीं पानी पर झगडा है और कहीं एक कास्ट दूसरी कास्ट के साथ लडती है, एक धर्म वाले दूसरे धर्मवालो के साथ लडते हैं। अभी यहां पर दो दिन से हरिजनो के बारे मे चर्चा चल रही है। आज इन्सानियत इन्सानियत से लड रही है। आज एक इन्सान दूसरे इन्सान को इन्सान नहीं समझता है। आज यह हालत है। जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक इतनी लम्बी छलांग लगाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा।

सभापति महोदय, दुनिया में शांति, सिक्योरिटी और एक-दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाये रखने के लिए हमारे संविधान का आर्टिकल 51 हमारे देश का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखता है। इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण क्या है वह आर्टिकल 51 मे स्पष्ट है। अगर यह जोड भी दिया जाए तो उससे क्या हर्ज होने वाला है। मेरे विचार में कोई हर्ज नहीं होने वाला है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसके लिए हमें कुछ काम करना पडेगा। उसके बगैर यह चीज बेकार होगी।

सभापति महोदय, मैं यह भी चाहता हू कि इसकी शुरूआत हो और इसकी शुरूआत यूनाइटेड नेशंस करे। इसके अलावा आज जो एक दूसरे के देश मे हस्तक्षेप किया जाता है—कहीं सी॰ आई॰ ए॰ के द्वारा, कहीं के॰ जी॰ बी॰ के द्वारा, यह सब बद होना चाहिए। जब तक यह हस्तक्षेप बद नहीं होता, तब तक इस दिशा में कोई भी बात सोचना गलत होगा। मैं सोचता हू कि यह जो कोल्ड वार होती है, उसके बाद कहीं भयानक युद्ध हो गया तो सारा ससार ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इस चीज की आवश्यकता है। लेकिन इससे भी पहले हमे कुछ और बातें करनी पडेंगी। पहले लोग गुलाम रखते थे। आज कोई गुलाम नहीं है। पहले पैसे से गुलाम खरीदे जाते थे लेकिन आज वह गुलामी खत्म हो गयी है। उसी तरीके से यह जो इन्टरनेशनल कान्स्टीट्युन्ट असेम्बली का विचार है जो कि यूटोपियन आइडिया लगता है, वह भी कभी साकार हो सकता है। जब मनुष्य यह समझ जाएगा कि भविष्य में किसी भी तरह के टकराव से मानवजाति समाप्त हो सकती है, उसका विनाश हो सकता है तो वह जरूरी इस तरफ आएगा क्योंकि उसके सामने इसके सिवाय और कोई चारा नहीं होगा।

सभापति महोदय मैं यही कहना चाहता हूं कि यह हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार है। जो भी इस देश की सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करने वाले हैं, वे इसका विरोध नहीं कर सकते और हमारी सरकार भी इसका विरोध नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इस पर अमल होना है तो इसके लिए दुनिया

के साथ म्युचल अण्डरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, एटमोस्फियर बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही जो शर्तें मैंने कही हैं वे भी जरूरी होंगी।

इन शब्दों के साथ मैं श्री कामथ जी के बिल का सिद्धांततः समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इस बिल के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है।

श्री हरि विष्णु कामथ : आज तो सवाल उठता नहीं है। एक घंटा इस बिल के लिए 20 तारीख को दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं यही कह रहा था कि इसका एक घंटा बचा है। जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स की कार्यावलि का दिन होगा, उस दिन यह आ जाएगा।

18.00 hrs.

GRAINS BOARD BILL*

SHRI YADVENDRA DUTTA (Jaunpur): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of an autonomous Board for fixation of minimum prices every year of all the agricultural commodities in the nature of foodgrains and for matters connected therewith.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of an autonomous Board for fixation of minimum prices every year of all the agricultural commodities in the nature of foodgrains and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI YADVENDRA DUTT: I introduce the Bill.

18.01 hrs

BACKWARD AREAS DEVELOPMENT BOARD BILL*

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for all-sided development of all economically backward areas of the country.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Board for all-sided development of all economically backward areas of the country."

The motion was adopted.

SHRI YADVENDRA DUTT: I introduce the Bill.

---

18 1 hrs.

ANTI-ESPIONAGE BILL*

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for capital punishment to spies for espionage in India and their summary trial.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for capital punishment to spies for espionage in India and their summary trial."

The motion was adopted.

SHRI YADVENDRA DUTT: I introduce the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 7-4-78.

18.02 hrs.

MOTION RE. ATROCITIES ON HARIJANS—*Contd.*

MR CHAIRMAN We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Ram Vilas Paswan on the 4th April, 1978, namely·—

> "That this House expresses its concern at the atrocities being committed on Harijans in Bihar, U P, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and other parts of the country "

along with the amendments moved thereon

SHRI B SHANKARANAND (Chikkodi) Mr Chairman, I would like to make a submission before the discussion is started Now, out of six hours time allotted to this subject, the time left for Janata Party is only 28 minutes and for my party i e, Congress—I, it is 24 minutes and for the Congress Party it is 19 minutes So, the time may be allowed accordingly to the respective speakers I have submitted only three names from my party and I request that eight minutes may be given to each Member of my party

MR CHAIRMAN Let us see

SHRI C M STEPHEN (Idukki)· There is no question of "let us see"

श्री युवराज (कटिहार) सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है पाच माननीय सदस्यो ने इस मोशन पर सशोधन प्रस्तुत किये हैं। उन मे से श्री मण्डल कल अपने सशोधन के पक्ष मे तर्क पेश कर चुके हैं। बाकी चार सदस्य बचे हैं। मेरा प्रार्थना है कि जिन सदस्यों ने सशोधन प्रस्तुत किये हैं, आज हो सूची से उन्हें प्राथमिकता दी जाये।

श्री आर० एल० राकेश (चायल) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते थे, उन्हें भी अभी तक समय नहीं मिल पाया है। उन्हे इस बारे मे महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें वरीयता दी जाये।

श्री शिवनरायण सरसूनिया (करोल बाग) । सभापति महोदय, हरिजनो पर होने वाले अत्याचारो के सम्बन्ध मे पिछले दो दिनो मे भरपूर बहस हा चुकी है। इस सम्बन्ध मे श्री रामधन जी द्वारा आकडे प्रस्तुत किये गये हैं। हमारे अन्य साथियो ने भी दिनो-दिन होने वाली बहुत सी घटनाओ का जिक्र किया है, जिन को पुन आप के सामने रख कर मै इस सदन का समय नही लेना चाहता हू।

18 04 hrs

[DR SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

सविधान मे हमे जा आरक्षण दिया गया है, उस के सम्बन्ध मे सविधान मे यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक कमीशन बनाया जायेगा, जो अनुसूचित जातियो और जनजातियो के आरक्षण के लिए व्यवस्थायें करेगा। परन्तु इस कमीशन की आज तक की सारी रिपार्टों और सिफारिशो को रद्दी की टोकरी मे डाल दिया गया है। इस के अलावा डिपुटी कमिश्नरो के दफ्तर बन्द कर दिये गये हैं। यह कहना चाहिए कि इस कमीशन के पर काट दिये गये हैं। बेशक यह समरा पाप पिछली सरकार ने किया। लेकिन हम ने सब को सुधारने, उस को आगे बढ़ाने और वह कमीशन कुछ एफेक्टिव हो सके, उस के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किए गए। लोगों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाए घटती हैं उस के साथ साथ गृह मत्रालय मे हमारे संरक्षण के लिए जो प्रकोष्ठ है और अस्पृश्यता निवारण के लिए

जो कानून था उस को भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। सरकारी नौकरियों में हमारी स्थिति अभी तक बिलकुल नगण्य सी चली आ रही है क्योंकि यह सरकार चाहे किसी को भी रही है लेकिन उस ने ईमानदारी से उन का पालन नहीं किया। उस के बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। सब से पहले एक तो यह उदाहरण है कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने जब कम्यूनल एवार्ड के आधार पर मुसलमानों को सन् 1939 में रिजर्वेशन दिया था तो केवल सात साल के अंदर जितना रिजर्वेशन उन को दिया गया था, शत प्रतिशत उसे पूरा कर दिया गया लेकिन इधर अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की स्थिति यह है कि 31 वर्ष पूरे हो गए, टार्गेट प्राप्त करना तो दूर रहा, उस का आधा या चौथाई भी अभी तक नहीं हुआ। यों यह जो संरक्षण है यह केवल सरकारी नौकरियों में है, लेकिन उस के साथ साथ अर्द्ध सरकारी जितनी अंडरटेकिंग्स है उन के बारे में मैंने अभी इसी सदन में प्रश्न किया था कि हर मिनिस्ट्री के नीचे जितनी अंडरटेकिंग्स आती हैं उन में प्रत्येक में अनुसूचित जाति के लोगों की सेवाओं में किस तरह की स्थिति है लेकिन मुझे यह बताते हुए बड़ा दुख है कि हर अंडरटेकिंग से जवाब यह आया है कि अभी तक इन्फार्मेशन कलेक्ट की जा रही है। जिस तरह से गृह मंत्रालय की तरफ से प्रावधान है कि एक चालीस प्वाइंट रोस्टर बनेगा और उस के हिसाब से सीटें एलाट होंगी, उसी तरह से उन को सब जगह संरक्षण दिया जायगा और उस की पूर्ति की जायगी, यदि वह नियम आज तक वहां पर लागू किए गए होते तो आज यह स्थिति न होती कि हमारे सामने उस का चित्र न आए। सरकार की ओर से रोज नारे दिये जाते हैं, चिन्ताएं व्यक्त की जातीं हैं, नेता भाषण देते हैं, लेकिन उस के पीछे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वह टस से मस नहीं होती, वह उन नियमों को ऐसे तोड़ मोड़ देती है कि जिस के कारण लोग वहां आ नहीं पाते हैं। अभी अभी अंडर सेक्रेटरियों को सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी बनाने की लिस्ट सरकार की तरफ से आया हुई। उन के अंदर एक भी अनुसूचित जाती के सदस्य को नहीं लिया गया है। हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य जितने भी आइ० ए०एस० में हैं उन में से बहुत से ऐसे हैं कि सीनियरिटी के हिसाब से वे बिलकुल सीनियर थे और उसी तरह से उन का आउट-स्टैंडिंग रेकार्ड था लेकिन उस के बाद भी उन को इग्नोर कर दिया गया। आज भी अभी मोटरोलाजिकल टिपार्टमेंट में एक शेडयूल्ड कास्ट आफिसर को जो साल भर पहले प्रोमोशन दिया हुआ था उस को इसलिए रिवर्ट किया जा रहा है कि दूसरी जगह किसी दूसरे को प्रोमोशन दे दिया। हमारे साथ इस तरह से द्वितीय नागरिक वाला व्यवहार सदा सदा से चला आ रहा है : हमारे लिए जो कुछ भी संरक्षण या दूसरी बातें रखी गई है गृह मंत्रालय उस को पूरा नहीं कर पाया। मैंने तीन मंत्रालयों के बारे में जानकारी हासिल की, वहां पर जो प्रशिक्षित लोग हमारे पास मौजूद है, उन के पत्रों के बारे में, उन के जो टैस्ट हुए है उन के बारे में, उन के जो इंटरव्यू हुए है उन सब के बारे में उन की स्थिति अच्छी होते हुए भी उन को अप्वाइंटमेंट नहीं दिया गया और यह कह दिया गया कि नहीं, वे सक्षम नहीं थे जब कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी आदेश है कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के प्रत्याशी यदि किसी विशेष प्रशिक्षण में प्रशिक्षित नहीं मिलते हैं और वे मिनिमम ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त हैं तो उन को ले कर वह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन ये जितनी जागीरें, अंडरटेकिंग्स बनी है इन सब जागीरों में जो उन के डयरेक्टर और परसोनल डायरेक्टर हैं वे गृह मंत्रालय के किसी भी नियम का पालन नहीं करते। वे उस के ऊपर ध्यान नहीं देते, स्वतंत्रता से चलते हैं और उस के कारण अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों पर कुठाराघात

[श्री शिव नारायण सरसूनिया]

हो रहा है। इस प्रकार से इस ओर जो ध्यान देना चाहिए वह अभी तक नही दिया जा सका।

हम जब मंत्रियो से बात करते हैं तो हमें कई बार इस तरह की चीजें मिलती हैं जिनके ऊपर हमे दुख होता है। मै माननीय गृह मंत्री जी के पास एक समस्या के लिए गया था। मैने जाकर प्रार्थना की कि मै मिलना चाहता हू, आप मुझे टाइम दीजिए। पहले मिलने के लिए इनकार कर दिया फिर अकेले मुझ से मिले तो मिलने पर जो उनके रिमार्क्स थे वह आज भी मेरे दिलो दिमाग पर बोझ बने हुए हैं। उनके बारे में आज तक कही कोई उत्तर नही है। उन्होंने कहा तुम्हारा लिस्ट में नाम है, तुम कहो, क्या कहना चाहते हो। उसके बाद जब मेरी बात सुनी तो कहते हैं नहीं, यह तुमने कामपिरेसी चला रखी है, तुमने लहर चला रखी है, मेरे खिलाफ आन्दोलन बना रखा है। और भी दो तीन एम०पीज० के नाम लिए, कि इन सब ने मेरे खिलाफ केस रचा रखा है। इसी तरह के आप ला एड आर्डर की बात करते हैं, लोग तो रोज मरते रहते हैं, सृष्टि के आरम्भ से। क्या बन्द हुआ है ? और न आगे बन्द होगा। जब इस तरह का जवाब हमें मिलेगा तो किस तरह से हमें विश्वास होगा कि हमारा सरक्षण किया जायेगा। उसके बाद लिस्ट में जो बात कही वह भी मैं आपको बताना चाहता हू। उन्होने कहा अच्छा, यह तो सब कुछ होता रहेगा, इनकी बात क्या करोगे, तुम अपनी बात कर लो। तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है, अपने घर को बचाओ। हम यहां पर लोकसभा मैं चुनकर आये हैं, हमें मीसा से डर नहीं लगा, हम जिन्दगी की परवाह नहीं करते हैं, किसी से बिक कर नहीं आये लेकिन होम मंत्रालय के मंत्री महोदय हमें इस तरह से थ्रेटन करें जबकि हम इस बात के लिए उनके पास जायें कि हमारे इलाके की ला एड आर्डर की स्थिति खराब है तब वे कहें कि तुम्हारे घर पर आग लगी हुई है। तुम्हारे ऊपर आफत आने वाली है, तुम अपनी आग बुझाओ। 25 तारीख को मेरे साथ यह घटना घटी, मैने वरिष्ठ अधिकारियो को लिखा लेकिन किसी ने आज तक मुझे संतोष नही दिया। कम से कम यही कह देते कि नही, यह कोई बात नही है, यह एक के साथ नही, बहुत से हरिजनो के साथ यह बात हुई है। मै किसी एक व्यक्ति के विरोध मे नही हू। हमारे साथियो ने जो कुछ बाते रखी है उनके ऊपर कुछ लोगो का मत लगता है कि हम जान बूझ कर अलग जा रहे है लेकिन हम जनता पार्टी के है, एक नौका में हम बैठे हैं परन्तु हमारे साथ जो व्यवहार होता है, जो घटनाये होती है वह हमारे अन्दर जो बेदनायें पैदा करती है, रोज हमारे ऊपर अत्याचार होते है, कत्ल होते है उसको सुनने के लिए काई तैयार नही और इस तरह की दलीलें दी जाती है जिनका कोई तुक नही। आखिर इन बातो को सुनकर किसका हृदय खराब नही होगा, कौन दु खी नही होगा ? हम इस बात को नही सोचते कि यह किसी पार्टी का मामला है बल्कि यह राष्ट्रीय मसला है, नेशनल मसला है।

सबसे पहले लैण्ड रिफार्म का नारा दिया गया। जमीदारो से जमीन छीन ली गई लेकिन हमे नही दी गई। हमारे नाम पर उनसे जमीन छीनी गई लेकिन हम लोग आज भी जमीन के बगैर है। जिनको जमीन दी गई वे काश्त नही कर सकते। उन्होने जमीन को अच्छा बना लिया तो उसके बाद उनसे जमीन छीनी जा रही है। यह स्थिति हर जगह है। दिल्ली प्रदेश मे मैं था तो कझोला गांव में जिनको जमीन दी थीं वहां पर अभी महीने महीने भर पुलिस इसलिए बैठी कि वे अपनी काश्त कर सकें। जब दिल्ली की यह स्थिति है तो फिर देश के गांवों में क्या स्थिति होगी ? अभी 8-10 दिन पहले मेरे क्षेत्र में एक गांव की बात है, गांव के लोगों

ने एक महिला के साथ जबर्दस्ती करनी चाही, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखानी चाही तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज यह कहा जा रहा कि रिपोर्टें ज्यादा लिखी जा रही है, इस लिये बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है, आधी से ज्यादा रिपोर्टें तो लिखी ही नहीं जाती। बहुत ज्यादा घटनायें हो रही है, पहले भी होती थी, लेकिन क्या यह इसी तरह से होता रहेगा? क्या हम को द्वितीय नागरिक बन कर रहना होगा? इस के लिये कोई कारगर कदम उठाना होगा। जनता ने करवट बदली है, पुरानी सरकार को बदल कर नई सरकार आई है—इस परिवर्तन में हरिजनों, बैकवर्ड क्लासेज के लोगों और तमाम गरीबों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्होंने भी इस परिवर्तन में बहुत बड़ा भाग लिया है, इसलिये उन को इन्कार नहीं किया जा सकता है। उनकी स्थिति को नहीं सुधारा गया, उनकी जमीन का जो झगड़ा चल रहा है, यदि उस को हल नहीं किया गया, तो यह झगड़ा और ज्यादा बढ़ेगा।

हमारे भाई रामधन जी ने कहा कि हम इस मामले को यू०एन०ओ० में ले जायेंगे। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं—यू०एन०ओ० में ले जाने से क्या हल निकलने वाला है, क्या वहां ले जा कर हम यह कहेंगे कि हमें बचाओ, हम मारे जा रहे है, हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं उन को बतलाना चाहता हूं—यदि हमारे साथ इसी तरह का व्यवहार होता रहा, तो हम मांग करेंगे कि हमारा स्थायी स्थान होना चाहिये, हमारी जगह होनी चाहिये, हमारी जमीन होनी चाहिए, जिस के ऊपर हम इज्जत से रह सकें। बाबा साहब अम्बेदकर ने जिस समय आन्दोलन शुरू किया था और कहा था कि हमारा इलैक्टोरेट अलग होना चाहिये, अगर उस समय उन की मांग को मान लिया गया होता, तो यह समस्या आज हल हो गई होती। अगर उस समय महात्मा गांधी ने आमरण-अनशन कर के उन से इस तरह का आन्दोलन न करने का वचन ले लिया था, जिस की वजह से यह समस्या आज भी उसी तरह से बनी हुई है।

सभापति महोदय, इसी दिल्ली में जब दोनों प्रावधान फेल हो गये, गृह मंत्रालय हमें सुरक्षा नहीं दे पाया और राष्ट्रपति द्वारा बनाया हुआ इदारा भी फेल हो गया, वह भी हमें संरक्षण न दे सका, हमारे लिये प्रावधान नहीं बना सका, तो फिर हरिजनों ने पिछले सोमवार से भूख-हड़ताल शुरू की। 101 हरिजन रोज वोट-क्लब पर 24 घंटे भूख हड़ताल करते रहे—मैं पूछता हूं क्या किसी ने वहां जा कर उन के दुख-दर्द को पूछा? यहां पर जो पहली सरकार थी—उस के कारनामों का हम जानते है। जब कहीं बाढ़ आई तो उस ने झूठा प्रचार किया कि हरिजनों के खेत डूब गये जब कि उन को कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन आज तो हमारे आंसू तक भी पोंछने के लिये कोई तैयार नहीं है।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं—कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये, इस तरह से शुरुआत होनी चाहिये, जिस से हम को लगे कि वास्तव में हमारी सुनवाई हो रही है। आज जो लोग यहां अपने विचारों को व्यक्त कर रहे है, इसलिये नहीं कर रहे हैं कि हम केवल अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि इस लिये कर रहे है कि हमारे पीछे जो समाज बैठा हुआ है, जो रोता है, बिलखता है और कहता है कि तुम्हारे यहां बैठे होने के बावजूद भी हमारे साथ यह व्यवहार हो रहा है, हमारा यह हाल हो रहा है। इस समाज को बरगला कर पिछली हुकूमत ने 30–31 साल तक यहां हुकूमत की, लेकिन अब यदि उसी समाज के साथ ठीक तरह से, सन्तुलित रूप से व्यवहार नहीं किया गया, उस की परवाह नहीं की गई, तो इस के परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसी लिये, सभापति महोदय, हम ने एक नई मांग की है, एक नया विकल्प दिया है कि हमारा

[श्री शिवनारायण सरसूनिया]

एक अलग मंत्रालय बनाया जाय, जिस तरह से आप का रिहैबिलिटेशन मंत्रालय बना हुआ है। पाकिस्तान से उजड़ कर दो करोड़ लोग यहां आये, उन के लिये अलग से व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था के कारण वे 10-15 साल में आबाद हो गये, हम जो हजारों सालों से उजड़े हुए हैं, क्या हमारे लिये उस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती? अगर इस तरह की सशक्त व्यवस्था हिन्दुस्तान में कायम कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि जो बार-बार संरक्षण का सवाल पैदा होता है, वह सवाल पैदा ही न हो। और हमेशा के लिये हल हो जाय।

आज हमारे जितने भी आफिसर्ज लगे हुए हैं, वे सब परेशान हैं। क्योंकि उन के खिलाफ इस तरह के संघ बन गये हैं —जो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, एन्टी-रिजर्वेशन के नारे लग रहे हैं। आज रिजर्वेशन के प्रति इतनी गलत बात पैदा कर दी गई है, ऐसी भावनायें पैदा कर दी गई हैं—जब कि हमें केवल 15 प्रतिशत दिया जा रहा है और 85 प्रतिशत उन्होंने अपने लिये रिजर्वेशन किया हुआ—लेकिन उस के बाद भी हमारे ऊपर आक्षेप लगाये जाते हैं, छींटे कसे जाते हैं कि यह सरकार तो हमारे लिये है।

जो संकल्प यहां रखा गया है, उस का समर्थन करते हुए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस तरह की कोई न कोई मशीनरी कायम हो जिससे हमारे ऊपर जो जुल्म किये जाते हैं, उन को रोका जा सके। हमारे साथ जो व्यवहार होता है उस में स्वच्छता आनी चाहिये, दोषियों को दण्ड दिया जाना चाहिये, जिस से हमारे समाज को यह विश्वास हो सके कि यह सरकार अब हमारी है और हमारे लिये कुछ करने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): I am grateful to you for giving me time now when I can get the Prime Minister's attention when I am speaking. He is happily present here. May be I will not be present when he replies, I am saying that in advance.

I am very glad indeed that the House had decided to give some extra time to consider this motion before the House, in which the House proposes to express its concern. I think this is the minimum that we can do about this problem. It is in this softer way the question is on the agenda of the House today. But I must remind the House and the Prime Minister particularly that this question in this peculiarly difficult form has been on the agenda of our national life for the last one year. This is not something which has happened overnight in the last few weeks.

I know somebody can say that the question of the Harijans, the scheduled castes and scheduled tribes, is not a question of recent origin, it stretches back to so many years, to the centuries. So, how can you say it is only for the last one year?

When I am saying one year, I refer to the particular form, the extreme form of the atrocities. It was, really speaking, a warning to the nation, that something very serious was happening, that somebody must sit up very seriously and apply his mind to it. It was in this acute form that this question was before the country.

When we were trying to raise this question here in the House about what happened in Belchi, in Meerut and other districts...

AN HON. MEMBER: In Maharashtra.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: In Maharashtra. If it has happened in Maharashtra, I can say I am ashamed of it, there is nothing to be proud about, there is nothing to explain away. I am equally ashamed of it if it is happening in Maharashtra.

But my main point is that when we were trying to invite the attention of the Government and trying to have some sort of constructive dialogue with Government, I must say that out of despair I had to give up this effort with the Prime Minister. I would remind him about my correspondence with him on this question.

18.23 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

When I wrote to the Prime Minister, sending along with my letter a report of some of the members of the party who visited, some of the States, not only Belchi—they had gone to Bihar, and then to Gujarat and some other places—I was told by the Prime Minister that this was politically motivated. Therefore, I had to give up the correspondence out of sheer despair.

With all my respect to him, my main objective at that time was to establish some sort of constructive communication and dialogue, because this is not a question of one party, of the State Government or the Central Government, this is not a question where you can say that it falls in the State List or the Central List or the Concurrent List. This is a question which lies on the national conscience, therefore, the nation has to take it in the correct spirit and face the question I must say that all these things, all these issues or incidents were happening in different States, all the States I would say if that satisfies somebody, but the question is not where it happened, but that they were happening, and one has to go into the reasons for it.

From the details that some of the members of the party then gave me, it had some special provocation this year, in the last few years if you like. Some new rights were given to the Harijans, some lands were given, bonded labour was sought to be removed. It is this which was, really speaking, giving them some human rights for the first time in practice. It happened because people who were not pleased with these things were taking a sort of anti-social attitude and making an organised effort to attack the Harijans and the result was the atrocities. Therefore, it has social and historical significance. If you merely rule it away as a problem of law and order, it will be a great mistake. We have then not understood the problem at all. The problem of Scheduled Castes, the problem of Scheduled Tribes and minorities is a problem which requires awakening of social conscience of the nation. For that matter, all the parties together have to have some sort of a constructive programme. But the Government will have to take a lead in this matter and take a special responsibility. Every time we come here and some Members raise this question, it is found that it is merely explained away in a routine manner. That hurts more. We are told that Harijans are 15 per cent and the atrocities are only 1 per cent This sort of an explanation of happenings in the country in a statistical way is adding insult to injury. Therefore, I do not merely take this opportunity and criticise the Government but I am again making an apeal to the Prime Minister because he himself is a well known leader who has his own idea about it; I know that he has also done something in this matter in a constructive way, not that I need to speak about it But I certainly say that we need to emphasise this particular aspect because it has assumed special significance now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): What is your constructive suggestion?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: If you sit along the table, certainly we can talk about it. At least economic rights and social privileges that they are getting today, some people are getting jeolous about it and are trying to deny those things. Certain elements in society in an organised fashion try to do it and if these elements get protection from the Government indirectly by connivance, by negligence, by positive support then what happens? This is the main question. As I told you, specific instances were

[Shri Yashwantrao Chavan]

brought to notice that certain lands were given to the people in the last two, three years, and by forcefully attacking these people, they were dispossessed of the lands. The reasons for some of the troubles were that they refused to go on labour in a usual bonded form. This old slavery they did not want; they want to rebel against it. You will have to go into the causes as to why it took place. These are of special significance. The constructive suggestion is that the political parties must sit together and accpet certain responsibilities. It is not enough to tell a police station officer that you go and enquire about it. Well, that is one way of doing this. This is a police way of doing it. What I am trying to say is that there is something deeper and one needs to go into the matter much more fundamentally. We will have to find out many ways of dealing with it. It is not enough. If there are other forms of bonded labour, we will have to find it out and attack it ruthlessly if we can. As Government wants to attack law and order problems this is the worst law and order problem. Law and order problem has to be effectively dealt with—not when incidents start happening. They will have to deal with it at the root, go into the root cause of it. These are positive and constructive suggestions of doing it It is not enough to investigate the incident when it took place. It is necessary to see that such incidents do not take place. The people themselves in the villages, the higher castes in the villages should feel it their duty and responsibility, morally they should feel ashamed if such incidents do occur. Unless that sort of feeling in the country especially in the rural side is created, nothing will happen. This is a national programme; this is not a one-party programme. I do not say it is merely a Government programme. Unless of course, Government takes a lead in this matter, nothing is going to happen.

On the contrary, we find that merely certain technical explanations are being given about it. One feels that somebody is trying to justify. That is the worst part of it; that hurts the conscience of the nation; that hurts the pride of the people. That is the main point.

I would recommend you to read some of the correspondence between myself and the Prime Minister. The Prime Minister felt that I was merely trying to make a political capital out of it to raise it in the Parliament. I was totally dismayed. I wrote to him, "I must leave it at that. I do not want to carry on correspondence further". My intention was to establish some sort of a contact. I am mentioning to this correspondence only today. I am very glad that the members from the Government Benches have started raising this question. At least now he will realise that the question was not raised with any political motivation, with any party interest, but because it is a very serious question which is affecting the minds of the people at large and the nation as a whole.

I think, in our country, in the last one century, all the important leaders of our country, from Raja Ram Mohan Roy to the present days, have tried to create a public opinion about it. But even then we have not succeeded enough by merely creating a public opinion. Unless we create certain political social sanction behind all our efforts, nothing is going to make any further progress. Therefore, I thought it my duty to speak on behalf of my party and say that it is very well done by those who have moved this motion. It is good that now, today, it is not only one party speaking, it is the entire House speaking and it is the nation speaking on this issue of Harijans. I would request the Prime Minister, when he replies, that let him not merely speak because he has to justify a Government or a Ministry. He is more than a Prime Minister. I would expect him to look at the question from this point of view and go into the problem much more fundamentally and give us a programme.

As the Prime Minister, he can give us a programme, a programme for the nation, a programme for all the political parties. This is a non-party issue. This cuts across all the political frontiers or party affiliations. Let us create a situation in the country that the question of Harijans, the question of Girijans the question of minorities is given the same priority which it deserves.

Sir, I have done.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष जी, जहां माननीय चव्हाण साहब जैसे विरोधी दल के नेता अपने सौम्य और उदात्त भाव प्रदर्शित कर रहे हों, जहां हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी उपस्थित हों, और जहां सदन की सर्व-सम्मत भावना इस संकल्प के साथ जुडी हुई हो वहां बहुत अधिक कहना आवश्यक नही है। यह आवश्यक है कि अभी जो हमारे चव्हाण साहब ने कहा है कि इसको दलीय परिपेक्षा मे न रखा जाय बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में इसके निवारण के लिये प्रयत्न किया जाय। अखबारों की कतरने सब के सामने हैं, उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नही है। आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से जिस कार्य को महात्मा गांधी ने शुरू किया था उनकी भावना को किस प्रकार से फिर पुनर्जीवित किया जाय। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हरिजन बन्धु गाय के रूप में उपस्थित है जिनकी पूछ पकड़ कर राजनीतिक वैतरणी तरने की हम सब कोशिश कर रहे है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय को टटोलें और कुछ रचनात्मक सुझावों के लिये हम अपने विचार उपस्थित करें।

अध्यक्ष महोदय, सचमुच में जो स्थिति है हरिजन भाइयों की वह बहुत दुखी है। कल सदन मे जो हमारे कुछ बन्धु बोल रहे थे, अभी भी हमारे बन्धु कुछ बोले, भले ही कुछ लोगों को अच्छा न लगता होगा, कुछ चाहते होंगे कि हिन्दुस्तान का विखंडन हो। लेकिन हिन्दुस्तान की सार्वभौम संसद् जिस समस्या को हल नहीं कर सकती तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी उस समस्या को हल नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, मैं उनकी भावनाओं के साथ अपने हृदय को जोडता हूं। सचमुच में विश्रामपुर, बेलची, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में जो घटनायें हुई हैं अगर मैं अथवा मेरा परिवार उन के शिकार होते, तो मेरा हृदय किस प्रकार से उद्विग्न रहता? "भारत काहू न करे कुकरमा"। उनका हृदय विदीर्ण है। इसलिए उन की जो वाणी निकलती है, उस की मै केवल एक आक्रोश की वाणी समझता हूं, यथार्थ वाणी नही मानता हूं।

लेकिन इस का मतलब यह नही है कि हम इस समस्या को यहां पर पूर्ण विराम दे दें। दुख तब होता है, जब हम इस समस्या का राजनीतिकरण करने लग जाते हैं। प्रधान मंत्री जी और विरोधी दल के सभी नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या पर एक राष्ट्रीय बैठक होनी चाहिए, जिसमें सब लोग अपने रचनात्मक सुझाव दें। बेलची की घटना हो जाने के बाद वहां का पोस्ट मार्टम करने से हरिजन भाइयो का कल्याण नहीं हो सकता है। प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर। इसलिए मै आप की सेवा मे कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, हालांकि हमारे विद्वान महान नेता अपने सुझाव रखेंगे।

सब से पहली बात यह है कि इस बारे में हम क्या एहतियाती कार्यवाही करते है, हरिजन भाइयो पर कोई जुल्म न हो, इसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्ज लेते है। हम ने कहा है कि जिलाधीश और जिला आरक्षी अधीक्षक इस प्रकार की घटनाओं के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। लेकिन अभी तक जहां-जहां ऐसी घटनाएं हुई है, वहां के जिलाधिकारियों अथवा जिला आरक्षी अधीक्षकों के विरूद्ध कौन सी कार्यवाही हुई है, यह सोचने और समझने की बात है।

आज हरिजन बन्धुओ को जिस प्रकार जलाया गया है वह आजाद हिन्दुस्तान के लिए कभी स्वाभिमान का विषय नहीं हो सकता है। कानून मंत्री बैठे हुए हैं। उन से मेरा निवेदन है कि जब मानवों को जलाया जाता हो, तो

[डा० रामजी सिंह]

ऐसे मामलो में समरी ट्रायल होना चाहिए। जब अदालतो में लम्बी कार्यवाही चलती है, तो ये दरोगा या थानेदार बिक जाते है, जिस के कारण हरिजन न्याय प्राप्त करने से वंचित रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामलो के लिए समरी ट्रायल हो और दोषी व्यक्तियो के विरूद्ध दो तीन महीने में कार्यवाही होनी चाहिए।

हरिजन बन्धु गरीब है। जो आर्थिक रूप मे पिछड़े हुए हैं, वही सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें कानूनी सहायता दी जाय, केवल शब्दो में ही नही, बल्कि उसके लिए धनराशि का आवंटन हो, ताकि जो सामन्त लोग उन पर अन्याचार करते हैं और हजारो रुपयो के वकील रखते हैं, हरिजन उनका सामना कर सके।]

लेकिन जैसा कि हमारे महान् नेता, श्री चव्हाण ने कहा है यह सरकार का ही काम नही है जनता का भी काम है। जनता की भावनाओ को जिस प्रकार बापू जी ने झकझोरा था, शायद आज हम उस की ओर मुखातिब नही हो रहे हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी और सब लोग मिल कर फिर एक बार हरिजन और गिरिजन भाइयो के लिए कुछ करें। हमारे शास्त्रो में कहा गया है कि युधिष्ठिर अपने कुत्ते को छोड कर भी स्वर्ग नही जा सके, और हम भी अपनी आबादी के पंचम हिस्से को छोड कर भारतवर्ष में सुख और शांति से नही रह सकते।

कल कुछ हरिजन भाइयों ने कहा कि स्वर्ण इस विषय पर क्यो बोले। वे ऐसा नही कह सकते। मै विनय के साथ कहना चाहता हू कि भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि मानव ने मानव को जलाया। लेकिन यह उस का सौभाग्य भी है कि बापू और दूसरे महापुरुषो ने, जो हरिजन नही थे, हरिजनो के लिए बहुत कुछ किया। इसलिए हरिजनो की समस्या राष्ट्र की समस्या है। हरिजन और गैर-हरिजन, हम सब, मिल कर इस समस्या से लड़ेंगे और संविधान के नाम पर शपथ लेंगे कि हम इस को दलीय राजनीति के लिए शोषण का अखाड़ा नही बनायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी आप के सामने मै एक और चीज कहना चाहूगा। सचमुच मैं ऐसी जो कुछ घटनाएं हुई हैं जैसे विश्रामपुर की घटना कितनी दर्दनाक घटना है। एक गाव के लोग नही, कई गावो के लोग वहा जमा हुए और उन्होने वहा उन को जलाया। मैं कहता हू कि अगर भारतवर्ष मे कोई न्याय की कीमत है तो उस इलाके में सामूहिक जुर्माना भी होना चाहिए।

इस संबंध में चव्हाण साहब ने ठीक कहा कि यह केवल सामाजिक सवाल नही है, आर्थिक सवाल है और सचमुच मे अगर किसी भी प्रशासन मे, इंदिरा जी के प्रशासन मे भी अगर गरीबो और हरिजन भाइयो को जमीन दी गई तो देनी चाहिए, अच्छी बात है। यह अलग बात है हम लोग बिहार के है, कोई राजनैतिक शोषण के लिए, मै नही कह रहा हू, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने परचे दिए गए थे उस मे 60 से 40 प्रतिशत परचे केवल परचे रह गए, जमीन पर उन का कब्जा नही मिला और आज कहते है कि उनको जमीन से हटाया जा रहा हैं। इसलिए सचमुच मैं अगर उन को देना है तो सही ढंग से देना चाहिए। मुख्य बात तो यह है कि जब तक हिन्दुस्तान की आर्थिक परिस्थिति नही बदलेगी, भूमि-सुधार के कानूनो का प्रगतिशील कार्यान्वयन नही होगा, तब तक यह सामंती ढाचा बना रहेगा तब तक हरिजन और जो पिछड़े हुए लोग है, जो हमारे अन्त्योदय के भाई है वे कभी आगे नही बढ़ सकते है।

लेकिन सब से बडी बात यह है कि यह अस्पृश्यता का प्रश्न कहा से आया? यह कि यह अस्पृश्यता का प्रश्न हिन्दुस्तान की सडी गली जाति व्यवस्था से आया। गीता में कहा है—

चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्॥

यह जो चातुर्वर्ण्य की बात कही गई है, चार

वर्ण तो रहे, लेकिन वर्ण-व्यवस्था नहीं है आज। आज वर्ण-अव्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था की विकृति से जाति-व्यवस्था पैदा हुई। जाति व्यवस्था की गर्हित और कुत्सत चीज जो है उसी को अस्पृश्यता कहते हैं। इसलिए बापू के शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करना चाहूंगा। उनके हृदय में कितनी ज्वाला है आप देखें। इस अछूतिस्तान की मांग में आप के आक्रोश में वह शब्द नही है, इस में आपके हृदय की पुकार नही है क्यो कि भारत-माता को विखंडित करने वाला भारतवासी नही हो सकता। लेकिन बापू ने कहा था—

"यदि अस्पृश्यता के काम रहने के कारण मुझे हिन्दू धर्म छोड देना पड़े तो मे जरूर छोड़ दू और कलना पड़ लू या बापतिस्मा ले लू। पर मुझे तो अपने धर्म पर इतनी श्रद्धा है कि मुझे उसी में जीना और उसी में मरना है। सो इस के लिए फिर मुझे जन्म लेना पड़े तो मै भंगी के ही घर लूगा।

मैं इन्ही शब्दो के साथ यह कहता हूं कि सचमुच में यह भारतवर्ष हमारा घर है और इस को हम अच्छा बनाएंगे। इस को छोड़ने की बात कह कर के सम्पूर्ण राष्ट्र के दुख को आप बढ़ावेंगे नही। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस का विचार विमर्श होना चाहिए और जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

"अमृत बरसे शीघ्र नहीं तो रेगिस्तान रिसाता है।" आपको समय नहीं खोना चाहिए।

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): Mr. Speaker, Sir, I rise today with a feeling of pain and of gratification to participate in this debate—pain because of the blood-curdling cruelty that continues to be meted out to a section of our brethren and gratification because of the very heartening response that is seen in the House, irrespective of the Party distinctions. Whether belonging to the ruling Party or the Opposition Party, the reaction to these incidents has not been prosaic, formal or perfunctory, but something which is coming out deep from the heart. This shows that the heart of the nation is one as far as this question is concerned. This gives us hope that we will be able to solve this problem. As was pointed out by Mr. Chavan, this is a real national problem which we will have to look at from the national perspective.

I am remined of the great role of Mahatma Gandhi played in this respect. A section of the people who were the scum of society were exploited, bound down, enslaved and treated as worse than criminals or animals. Gandhiji came forward and gave them the name of 'sons of God' or 'Harijans'. He completely identified them as such and he gave us the philosophy and the message that until and unless they are raised up and treated as more than equals by making up for all the evils that were done against them through the centuries, he told us that this country will not attain Swaraj.

When the fathers of the Constitution wrote down the Constitution, there was a message coming out of it. We gave ourselves a Constitution to enshrine justice and equality—social, economic and political. Art. 15 took care that special provisions must be made for them and, in making them, equality of job opportunities need not be treated as violated. Art. 46 says that they may be taken special care of. Not only that, but it charges the State with the responsibility of protecting them against injustice and exploitation. There are Articles 338 and 336 making special provision for special office, a special provision for a Commission and making special provision for treating them in a special manner, and making special provision that there must be a Ministry in Orissa, Madhya Pradesh and Bihar to look after the welfare of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes.

[Shri C. M. Stephen]

I am pointing out all this to show that, from out of the Constitution, there is a message flowing out, a message not of formality but a message of solicitude. Even as a father will take care of his weak son, here is a class of people who through the historical process of centuries were ill-treated and brought down to the last base and, when the country became free, its responsibility is not merely to treat them as just one among others but to treat them as the weakest among us, needing and deserving special solicitude: that special solicitude which the weakest child of the family is expected to get from the father, is what the Constitution demands of us.

Thirty years have gone by. Let us not be in a mood of recrimination and mutual accusation. Let us be in a mood of introspection and mood of painful survey of the whole scene. Comparisons are absolutely cruel when we treat of a mater like this—what was the position in such and such a year and what is the position in such and such year. That bespeaks of an attitude which does not conform to, and which is not in tune with the message that I made mention of. Here, this House had many occasions to discuss this matter. After this Lok Sabha, under your presidentship, started functioning on one basic or the other we had occasions to discuss this matter but it so happens that no sooner a discussion is over than we hear another story of another batch of Harijans being burnt alive, another story of another set of Harijan women being raped and a story of cruelty committed on Harijans. This bespeaks of a national malady. Day before yesterday I read in the press that in Madras, in the Assembly, a discussion took place—that the wife of a Harijan, the wife of a Deputy Collector who happens to be a Harijan, was disrobed in public.

Attempts are made to justify it as a Holi prank. Holi prank can go against the wife of a Harijan and not against any other high caste person. Here is a justification coming, Sir. I am saying, let this House, let everyone of us sit back, examine and analyse the basis of this malady. I do not want to show an accusing finger against anybody, but I felt ashamed, pained, when I heard the crude comparison in terms of percentages and statistics. Fifteen percent of the people—only one percent of the crime has been put on them indicating thereby that fourteen percent of the crime is still due to them. Is that the way this question is to be approached? Is that the way that somebody who is put incharge must approach this? I had expected a mental revulsion coming up in complete protest that our brethren are being treated crually. Is this this approach expected of us? But I am heartened that that approach is not reflective of the mind of the nation, not reflective of the mind of the House; glory to this House, glory to this nation that this approach is not reflective of the mind of the nation and there lies the hope for this nation. Any steps absolutely necessary must be taken.

A demand was raised here that there must be a special Ministry to take care of them. If amendmen of he Constitution is necessary in case what is provided is not sufficient, that will have to be thought of. There is already a provision for collective fine wherever untouchability is practised or cruality is heaped on. Who has ever invoked this provision? Except in Gujarat in one instance, I have never heard of this collective fine process being imposed. This matter of collective came in Bombay Presidency, when Shri Morarji Desai himself was the Chief Minister. This provision was brought in and I felt proud when I hear Shri Mararji Desai making an announcement that he would go on a hunger strike if this thing is stopped. That sort of thing can certainly correct upto a certain extent.

I do agree that this is a matter which must be treated as above party. Anybody who ill-treats Hariajns must be treated as a criminal of the first water and must be approached as a special

leper who must be put down with the strongest hand. It is this approach that is necessary. The discussion that has taken place here during three days must carry this message to the nation, and this message is being carried to the nation, where the Government, Opposition and everybody agrees also not to make political capital out of it. I, on my part, say, that I approach it, not a spirit of making political capital out of it, but in a spirit trying to solve this problem. That is all I have to say.

As said by some hon. friends on the other side, the nation is today on the tip of a volcano. We can face an enemy and survive, we can solve certain other problems and survive, but if discontentment and frustration is there from Kashmir to Kanya Kumari among a large section of the people, whose sweat gives bread to this nation, sure as anything, this country is in for a complete explosion, out of which there can be no survival Therefore, this is indicative of the grave danger that we are facing and with a spirit of facing the danger, we huve got to approach this problem.

I may again repeat, as I said on the previous occasion, that the solution to this problem is for them to organize themselves and to assert their rights Nobody can help unless they help themselves They should organize and assert themselves, because they are the base of this country; they are not to seek and to beg, but to organize and assert. This is because it is on their shoulders that this country can exist and survive. If they assert themselves, nobody can suppress them. It is for the others to come along as Gandhiji did saying, "We are with you and together; either we sink or together we swim". That attitude can take us across. I on behalf of my party, put on record our deepest resentment against whatever is going on and we pledge our full support to any efforts that may be made to solve this problem constructively. We extend our hands of support to find a solution to this problem because it is a national problem, the solution of which is a desideratum if the nation has to survive. In that spirit, I support this motion.

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से हरिजनों पर अत्याचारों की वारदातों की बहुत ही हृदय-विदारक चर्चाएं यहां पर हो रही है और यह ठीक है कि दिन प्रति दिन हरिजनों के प्रति जो घटनाएँ घट रही हैं, उन मे कोई कमी आने का प्रश्न नही उठता है। इसलिए 'नही' कि पिछले 30 वर्षों से जब से हम स्वतन्त्र हुए है, तभी से जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति मे बदलाव आना चाहिए था, वह नही आया। अब प्रश्न यह है कि किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदला जाए क्योकि बगैर उसके बदले अत्याचार में, अन्याय में, असमानता में कमी नही हो सकती। मैं आप से निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिनके कारण यह असमानता बनी हुई है और जो अन्याय हो रहा है, यह केवल कानून के बस की बात नही है। हम महात्मा गांधी जी की चर्चा करते हैं। महात्माजी ने साबरमती आश्रम में जो हरिजन उद्धार के सिलसिले में प्रयोग किया, वह सबको मालूम है। वह एक भूमि थी, जहां पर यह काम आरम्भ हुआ। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया और जो हरिजन उद्धार के कार्यक्रम थे, उन को आगे बढ़ाया। न केवल उन्होंने इस देश को राजनीतिक चेतना प्रदान की बल्कि उन लोगों के बौद्धिक, सांस्कृतिक स्तर को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया और न केवल अपने संस्कार से और अपने आचरण से बल्कि 'यंग इन्डिया', 'नव-जीवन' और 'हरिजन सेवक' आदि पत्रिकाओं को निकाल कर व्यापक रूप से उन्होंने प्रचार का काम किया।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जो घटनाएं घटती हैं, उस की खबर पुलिस में शीघ्र पहुंच पाती हैं या नहीं, यह देखने की बात है। आज गांव

[श्री युवराज]

में जो काम करने वाला चौकीदार है या दफादार है, जोकि निश्चित रूप से शोषित और दलित वर्ग का एक साधारण आदमी होता है, ऐसी घटनाओं की खबर शीघ्र नहीं दे सकता है। और अगर देता भी है तो बहुत देर से वह खबर पहुचती है और इसका कारण क्या है। उन को तन्ख्वाह कितनी मिलती है। हमारे यहा उनको केवल 70 रुपए महीना मिलते है।

कई माननीय सदस्य हमारे यहा तो केवल 10 रुपये मिलते है।

श्री युवराज अभी हमारे यू०पी० के माननीय सदस्य बतला रहे है कि उनके यहा केवल 10 रुपये मिलते है। हमारे यहा बिहार मे उन को 70 रुपये तन्ख्वाह मिलती है। ऐसे लोगो के हाथ मे अत्याचारो की खबर देने का काम है। जब उस का इतनी कम तन्ख्वाह मिलती है तो वह अपने गाव के धनी आदमी के पास जाता है और उस से वह अपने खाने के लिए दो सेर, चार सेर अनाज ले आता है। वहा उसकी पत्नी काम करती है और उन के यहा उस के भाई और लडके काम करते है। जब दो सेर, चार सेर गेहू वह अपने खाने के लिए वहा ले लाता है, तो वह उन लोगो के खिलाफ क्या शिकायत करेगा। जब इस तरह से आर्थिक असमानता बनी रहेगी, जो हमारा भूमि सुधार का कानून है, जो हमारा मिनीमम वेजेज एक्ट है, ये सब ठीक से कार्यान्वित नही होगे, तब तक जहा ये घटनाए घटती है, उन की खबर काफी विलम्ब से पहुचेगी। जो गाव मे चौकीदार है या दफादार है, वह घटनाओं की सूचना नही दे पाता है। बहुत बूढे लोग इस काम मे गावो मे नियुक्त हुए हैं और वे लोग खबर नही दे पाते हैं। धनी लोगो से उनको दो सेर अन्न मिलता है, तो वे उन के खिलाफ खबर नही दे पाते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हू कि आज जो ये घटनाए घट रही हैं, उन को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियो मे परिवर्तन लाने के लिए हम को पहल करनी पडेगी। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बदलाव करना होगा। लेकिन जिनके हाथो मे सत्ता है, उनकी बडी जिम्मेदारी है। यह ठीक है कि सत्ता मे रहने वाले लोग केवल इस काम को नही कर पायेगे। हम सब लोगो को मिल कर इस काम को करना होगा। नही तो यह काम नही हो सकेगा।

19 00 hrs

अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी जरूरत है कि जहा यह घटना होती है वहा इससे सख्ती के साथ निपटना होगा। जो लोग अपराधी है, उनको दण्ड देना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नही होगा कि केवल छानबीन कर ली जाए या कोई कमीशन बिठा दिया जाए। हमे आर्थिक और सामाजिक पुनर्रचना का कार्यक्रम भी तीव्रता के साथ लागू करना होगा। इस कार्यक्रम को लागू करने मे केवल इतना ही पर्याप्त नही होगा कि हमने लेण्ड सीलिंग का कानून बना दिया है। हमे भूमि-हीनो को भूमि देनी होगी। उन्हे घर बनाने के लिए जमीन देनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जितनी भी घटनाए घटती है उन सब के पीछे कोई न कोई सामाजिक और आर्थिक कारण होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम देश के तमाम मुख्य मत्रियो का एक सम्मेलन बुलाएं और बुला कर उनसे कहे कि वे मुस्तैदी के साथ इस समस्या का समाधान करें। इस समस्या का समाधान उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान से ही सभव हो पायेगा। मुख्य मत्रियो से आपको यह कहना होगा कि प्रान्तो मे जितने भी कानून इस सम्बन्ध मे बनते हैं उनका उन्हें कठोरता से पालन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग प्रान्तों में जाते हैं तो हम लोग जा कर के सर्किट हाऊसों में ठहरते हैं। अगर गांधी जी आज होते तो उनका आज एक अलग आन्दोलन होता। अगर वे होते तो उनको इस समस्या को सुलझाने का अलग ही रास्ता होता। वे आज के शासकों की तरह मूकदर्शक बन कर न रह जाते। गांधी जी को केवल कानूनी कार्यवाही से ही संतोष नहीं होता। इसलिए मैं अपने मंत्रिमण्डल के लोगों से, राज्य मंत्री से, और जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनमे कहना चाहता हूं कि वे जहां भी दौरे पर जाएं तो वे किसी हरिजन के गांव में जा कर रुकें। वहां ठहरें और देखें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। उसके बाद वे समाधान करें कि उन्हें उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करना है। आज हरिजनों के गांव में पानी नहीं है। पानी के लिए उन्हें गांव के बड़े, धनी लोगों के ट्यूबवेल पर निर्भर करना पड़ता है। जब हम सभी लोग हरिजनों के बीच में जा कर रहेंगे तभी हमें उनकी समस्याओं का पता चल सकेगा। हमें उनके जीवन में निकट से झांक कर देखना होगा। हम सभ्यता और संस्कृति की बड़ी दुहाई देते है और उसी से संतुष्टि कर लेते है। लेकिन कदम-ब-कदम पर इनके आदर्शों पर आचरण नहीं करते।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर काफ़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और स्वयं प्रधान मंत्री जी बहस का उत्तर देने आये हैं इसी से यह अंदाजा लगता है कि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रति कितनी सचेष्ट है और सरकार के दिल में कितना दर्द है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हरिजन का प्रश्न सारे देश में पैदा हुआ है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि दुनिया में जितने देश हैं, इतिहास निकाल कर हम देखें तो सभी जगह इस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कमो बेश में, चाहे सभ्यता का ढोंग भरने वाले पश्चिमी देश हों और चाहे हिन्दुस्तान हो। वहां के नीग्रो, यहां के हरिजन, चाहे अफ्रीका का और चाहे रोडेशिया का हो। दुनिया के सामने यह एक प्रश्न पैदा है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। और हिन्दुस्तान में जो हरिजन समस्या है इसका निराकरण करने पर बहस कम होती है, बल्कि इन समस्याओं को उभारने का काम ज्यादा होता है। हम हरिजन अत्याचार पर रोयेंगे, आंसू बहायेंगे, आक्रोश में उत्तेजना में बहस करेंगे। उससे समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। अगर समस्या का समाधान निकलना है तो मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान में जो जाति व्यवस्था है उसने केवल प्रशासन को ही ग्रसित नहीं किया है बल्कि हिन्दुस्तान की न्यायपालिका पर भी अपना असर डाला।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गहराई के साथ देख रहा था तो मैंने देखा कि बिहार में जो आंकड़े आये 1967 में जुल्म 74, चार्जशीट 52 में और अदालत में अपराधी को सजा केवल दो केसेज में। 1968 में जुल्म 84, चार्जशीट 51 केसेज में अदालत में केसेज गये और सजा केवल 5 केसेज में, 1970 में 83 जुल्म, चार्जशीट 63 में और सजा शून्य। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक जगह का रोग नहीं है। अपराध होते हैं, एक तो पुलिस चार्जशीट कम देती है, और देती भी है तो न्यायपालिका में जा कर हरिजन पर जुल्म करने वाला अपराधी रिहा हो जाता है, इसलिये अपराध करने वाले का मनोबल ऊंचा होता है कि हरिजन के मारने पर जेल नहीं मिलेगी। दो, तीन साल केस में जायेंगे और अगर 50 रुपया जुर्माना होगा

[श्री हुकम देव नारायण यादव]

एक बीघा जमीन लेब कर मुकदमा लड़ते रहेंगे, लेकिन हरिजन पर अन्याय करेंगे। इसलिये सजा होना जरूरी है। जैसा माननीय रामजी सिंह कह रहे थे समरी ट्रायल होना चाहिये।

मैं बिहार के मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जैसे बिसरामपुर की घटना हुई, 7 दिन के अन्दर चार्जशीट दाखिल कर मामले को सेशन्स कोर्ट में दे दिया गया। इससे जल्दी और क्या हो सकती है। इससे पहले हरिजन को जलाने पर 10 दिन के अन्दर उस केस में सेशन्स कमिट कर दिया गया। बिहार की सरकार और मुख्य मंत्री बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जगहों की मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बिहार के मुख्य मंत्री स्वयं घटनास्थल पर जाते हैं। उन्होंने एक हरिजन सैल स्थापित किया है जिसका इन्चार्ज हरिजन नहीं है, मैं आपको बताऊं उस अधिकारी का नाम के० बी० सक्सेना है जहां हरिजन वाली कोई घटना होती है वह मौके पर जाते हैं, 5, 7 दिन के अन्दर केस को सुपरवाइज कर के सेशन में मामला दे कर तब सेक्रेटेरियट को वापस आते हैं। यह कार्यवाही करने के लिये संकल्प और इच्छा भी होती है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हम चाहते हैं कि हरिजन के ऊपर से अन्याय मिटे तो सबसे पहले हमको अपने दिल को भी साफ़ करना पड़ेगा। हम संसद सदस्य हैं, मेरे क्षेत्र के अन्दर अगर हरिजनों पर जुल्म की कहीं कोई बात होती है, सूचना मिलती है तो हिम्मत के साथ कहना चाहिए चाहे हमारा समर्थक हो क्यों न हो, लेकिन यह कहना चाहिये कि अगर हरिजन पर अत्याचार होगा तो सामूहिक रूप से वहां सत्याग्रह करेंगे, उस अत्याचारी का सामाजिक बहिष्कार करायेंगे और उसका हुक्का पानी बन्द करायेंगे, मजदूरी बन्द करा देंगे और उसको खेती आबाद नहीं होने देंगे। अगर सामाजिक मुकाबला करने की हम में शक्ति होगी तभी मुकाबला होगा। लेकिन हरिजन के लिये आंसू बहा कर, अपने दरवाजे पर कोई हरिजन आये तो उसको सम्मान न दें, हरिजन की बात तो करें लेकिन जो गरीब अपने घर की बगल में हो उसको बराबरी का सम्मान न दे, यह दो तरह की बातें देश में होती रही हैं। कथनी और करनी में भेद चलता रहा। एक तरफ़ कहा गया सम्पूर्ण जगत ही ब्रह्म है, दूसरी तरफ इन्सान को अपवित्र कहा गया, यह सिद्धान्त में कुछ और रहा, व्यवहार में कुछ और रहा।

इस सदन और सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर वे हरिजन-समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो वे ईमानदारी से जाति-व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास करें, जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा कोढ़ है। इस के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाये। संसद-सदस्य मिल कर सरकार पर यह दबाव डालें और जनमत तैयार करें कि जब तक अन्तर्जातीय विवाह नहीं होंगे तब तक जाति मिट नहीं सकती है और इस लिए अन्तर्जातीय विवाह को सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दिया जाये। ऐसा करने पर जाति टूटेगी और हरिजन तथा हम सब बराबर होंगे। रामधन की बेटी की शादी और मेरी बेटी की शादी जब एक जमात में होने लगेगी, तो न वह हरिजन रहेंगे और न हम सवर्ण रहेंगे। इसी तरह इस समस्या का समाधान होगा।

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से सदन में जो बहस हो रही है, उस में बहुत से आंकड़े दिये गये हैं। आंकड़े मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन आंकड़ों को यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है।

आज जो घटनायें घट रही हैं, उन पर विचार करते हुए हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि पिछले तीस सालों में क्या

हुआ है और पिछले एक साल से क्या हो रहा है। सवाल यह नहीं है कि 1 परसेंट जुल्म हो रहे हैं या 15 परसेंट हो रहे हैं। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के शब्दों में अगर हिन्दुस्तान में कहीं एक भी ऐसी घटना घटती है, तो हिन्दुस्तान के लोगों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। अगर हम इन घटनाओं को बहुत लाइट वे में ले रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर हम इन घटनाओं को पृष्ठभूमि में जायें, तो हमें कुछ और ही चीज देखने को मिलेगी।

आज इन घटनाओं के कारण जो ज्वालामुखी इस देश में सुलग रहा है, अगर वक्त रहते इन घटनाओं को न रोका गया, और वह ज्वालामुखी इसी तरह सुलगता रहा, तो कहीं एक दिन ऐसा आये कि वह ज्वालामुखी फट जाने और उस की लपेट में पूरा देश ही आ जाये।

जैसा कि मैंने कहा है, हरिजनों पर कहां कहां और कैसे कैसे हमले और अत्याचार हो रहे हैं, उन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन इस समय मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या क्या करना चाहिए।

मैं राजस्थान से चुना हुआ हूं और राजस्थान में सब से कम घटनाएं घटी है। जब से राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहां आज तक कोई भी कत्ल की घटना नहीं हुई है, और उस का एक कारण है पिछले कुछ दिनों में राजस्थान सरकार ने जो कार्य किया है, वह बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार यह काम किया कि एक हरिजन को अपना होम मिनिस्टर बनाया, जिस से वहां के लोगों का जनोबल ऊंचा हुआ और बने हुए तमा पिछड़े हुए लोगों ने महसूस किया कि हमारा आदमी आज होम मिनिस्टर बना है। और जो दूसरे लोग थे उन लोगों को कुछ भय हुआ कि नहीं, अब सम्पत राम हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि हर राज्य के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर ऊंची जाति का है तो होम मिनिस्टर शेड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिये, अगर कलेक्टर शुड्यूल्ड कास्ट का है तो डिप्टी कलेक्टर ऊंची जाति का होना चाहिए, दारोगा अगर ऊंची जाति का है तो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का आदमी सब-इंस्पैक्टर जरूर होना चाहिए।

पुलिस के अंदर या अदालतों में जो मामले जाते है उन में जातियों का कोई हवाला न हो। जब आदमी अदालत में या कहीं पर भी जाये तो उस की जाति न पूछी जाय और हरिजन शब्द का प्रयोग तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। मैं पंजाब की गवर्नमेंट को जो उन्होंने यह आर्डिनेन्स लागू किया है उस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और हिन्दुस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि पूरे देश के अंदर यह चीज लागू की जाय कि किसी भी आदमी की जाति न पूछी जाय। चाहे स्कूल में हो या कचहरियों में या किसी भी जगह हो उस की जाति न पूछी जाय। जिस गांव में शेड्यूल्ड कास्ट पर अत्याचार हो उस गांव पर सामूहिक जुर्माना होना चाहिए और वहां पर जो प्रधान है उस को डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए कि वह जिन्दगी के अंदर कभी भी प्रधान न बन सके।

मैंने यह कुछ सुझाव दिए है और मैं चाहूंगा कि भारत सरकार इस के ऊपर गौर करे। इन के ऊपर वह अमल करे और देश के अंदर जो असुरक्षा की भावना बढ़ रही है उस को बढ़ने से रोके।

MR. SPEAKER: The Prime Minister.

श्री शंकर देव (बोदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम वहां पर है और बहुत दिनों से है। मेरी शिकायत है कि मुझे टाइम नहीं दिया गया। कल भी यह बात कही गई थी कि टाइम दिया जायेगा लेकिन नहीं दिया गया।

MR. SPEAKER: We have given six hours to this debate. All the 544 Members cannot get a chance.... (*Interruptions*) I have already called the Prime Minister.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Mr. Speaker, it is a matter of great pain for me to hear all that I have been hearing now and to know what was spoken in the first four hours when I could not be present here.—Painful not because Government is abused or that Government is blamed, but painful because such things should happen at all and that there should be occasions for such debates. One feels ashamed before the world because all this news goes to the whole world. It is not at all a matter of statistics in my view. But statistics have been given because that is how they were provocatively cited. There should be no provocation, I do agree. But after all, those who are in charge of Government are also human and if they are attacked persistently without any fault, they are bound to feel sore about it. Why is it not understood by my friends who also have a feeling of legitimate soreness. But I do not want to dwell long on it.

I see the hon. Leader of the Opposition, who spoke and found fault with what I had written to him in this matter has gone away, may have gone away for some work, but it would have been better if he had been here.

SHRI K. GOPAL (Karur): Actually he wanted to be here. But he has some other work.

SHRI MORARJI DESAI: Then he should not have spoken.

SHRI K. GOPAL: He has some other work.

AN HON. MEMBER: Why is the Home Minister not here?

SHRI MORARJI DESAI: I am here for the Home Minister. The Home Minister is not here because it is not that the Home Minister does not want to be here, but it is painful to hear things which are being said and one does not want to get provoked. I am here and I have said that I will reply to it. As it is a censure against the Home Minister, it is a censure against me. I cannot hold the Home Minister more responsible for it than I hold myself or the Government. But it is a matter which must be considered not in anger but in a more quite atmosphere than we are doing. That is what I would like to plead, if I may say so. When the Leader of the Opposition said that I had written to him that this is a national question, not a political question, he felt angry about it and wrote to me that it is no use writing to me. That is what he repeated here. He gives me a compliment which I believe he does mean. But if that is the way of giving a compliment, it would be better not to give the compliment. What did I say to him? I have said everything to which he had referred. In my letter, I said to him "I am very sorry that this should happen, it is a shame for all of us. These are national things and it does not relate to only one party or another, and we have got to exert for it." But when you send teams only to the areas where there are Janata Party Governments and you do not send teams to the areas where your people are running the State Governments, what am I to consider? It is not a matter which refers to only one State. It is a blot on the whole of India. In all parts this is happening, not happening now, it has been happening for many many years. But that is no justification for its continuance. I do grant. But is it imagined that we can solve this problem by blaming those who cannot be blamed for it or by criticising Government which is earnest about its solution? If that helps, I have no objection if this Government disappears. I want you to know this. It was suggested that I should have gone on hunger strike. If he convinces me that my going on hunger strike and giving up my life will solve this problem, I am prepared to do it tomorrow.

SHRI C. M. STEPHEN: You have misunderstood me. I was only saying that I felt proud when I read that you made that statement. Not that I want him to go on hunger strike. Let us not put it out of context. I was really feeling proud when he said that and when he felt so much. I said that I felt proud about it.

SHRI MORARJI DESAI: No. It is not my hon. friend who says that. There are others also who say that. I am not referring merely to him

SHRI C. M. STEPHEN I am sorry.

SHRI MORARJI DESAI: But there are some suggestions by some people. I would be prepared to do it tomorrow if my hon. friends in the Opposition think that that will help, that it will remove the evil; I will do it tomorrow and disappear and I will consider myself obliged to Government and the country that I have been able to utilise my life for this purpose.

May I say, Sir, that I understand the feelings of pain and anguish of my own collegues who are Harijans because they feel the pain which I do not? But that does not mean that they should rub it on me. This is all that I plead with them. After all, am I responsible? Is my colleague the Home Minister, responsible for it? I do not know why we are blamed for it Yes, we have not been able to remove this scourge within one year of office. And there are incidents taking place. Whether they are more now or they are less now is not a consideration which weighs with me. I have said so often that even if there is one incident, I will feel ashamed about it. This is a canker which has eaten into our vitals I have even said that it is because of these sins of our society, of our people in this country, that we have been suffering for all these centuries. We had lost our freedom and we are suffering even today because we are not able to wipe out this blot here. That is my feeling in this matter and I believe that is the feeling of all my colleagues. We have been taking steps, wherever this happens, to bring the criminals to book, because I call them criminals who do these things, and see that they are brought to book very thoroughly. But I cannot claim that Government machinery has become very efficient yet. Am I to blame for that inefficiency? I do not want to blame anybody. Why have I to do that and provoke more attacks or more criticism for nothing? That does not solve this problem. I do not say that those who preceded us in Government were callous to it. I cannot say that. They had their own limitations, but they expect that our limitations should not be there. That is why I say, this is being utilised as a political stick with which they seek to beat Janata Government which is not fair at all, which is not right. It does not solve the problem. it bedevils it further. And that is why I am saying please do not give any political turn, to it. We should sit down together, not in a big conference, but in a small group; for in a big Conference, the same things will be repeated Will that solve the problem? Let us sit down. a few of us, and go into it very thoroughly and take proper steps. But that requires a calmer atmosphere, and that requires willingness for it. But if it is sought to be said that all these incidents are due to this Government, or that this Government is lax about it, how am I encouraged to call such a conference? Because they will again utilize that opportunity for their purpose. That is my fear. I may be wrong, but I am human and so are my hon. friends human; but why should they assume that I am not human? Why should they assume that my colleagues are not human?

One of my friends even said that there should be a separate State. How can that be, but that is not going to benefit. (*Interruptions*) That does not. Whether he does suffer or not, he feels it more, because he belongs to that sect. I can understand

[Shri Morarji Desai]

his bitterness, but will that bitterness solve the problem? It would not solve the problem The problem will be solved by all of us making a concerted effort to remove it, and to suffer for it That is what we ought to do I have offered to my Harijan brothers that if they offered a satyagraha, I am prepared to join them even if I am the Prime Minister I have offered it because, I wanted to assure them that I am willing to do anything that I can do But I cannot make futile efforts, which will not produce any result but may have mere propaganda value It is not a matter of propoganda, but of intense pain and shame for all of us But it is not the creation of the present generation. It has been with us for hundreds of years, and it has gone on ever since

Somebody went on to say that even Gandhiji did not do well. I cannot understand a person who can say this Does he forget that until Gandhiji took up this question in 1915-16, soon after his arrival from Africa, there was absolutely no feeling in this country against it? There were our saints, men of religion who have been crying against it for centuries, and yet it had had no dent on the system at all It is only when Gandhiji took it up and aroused the conscience of the society that the dent has been made, the evil has been attacked and results became perceptible, for which you will find no parallel in any other country during the last 2,000 years But that is no satisfaction Let me say this, there cannot be any satisfaction until this curse disappears I want to see that casteism goes Otherwise, this curse cannot go And if this goes, casteism will crumble These are the two sides of the same coin in my opinion But that cannot be done by mere legislation We have all to work for it It is because all of us did not work as hard in Gandhiji's time, and after it, as we should have done, that the evil has not yet gone We are all responsible for it. I will accept my share of responsibility for it Whatever I may have done, I have been attacking it not only now, for many years, for more than 40 years, I have wrestled with this problem I have not hesitated, as a Minister of the Government in Bombay, to take strong actions Harijan boys and girls were not allowed to sit in schools They were kept separate They were not even given water from the same pots I took it up in the most turbulent district And we issued orders to close the schools where the villagers did not give equal status to the children of those communities I said if they do not give them seats the schools will be closed They were closed There was even litigation But they did not succeed. Ultimately they had to come round and the problem was solved They got a fair deal there But we had to make that effort

In my own constituency, very near my place the harijans were not allowed to draw water from a well which was used by other people I declared it to be a public well so that they were entitled to take water from it and gave police protection Then the other people said "we will not take water from this well, we will have another well of our own". I said "you can have a well, if you want, but these people will take water from this well' Then they gave up, because that was the best well and they all began to take water from it

I do not say this in order to show merely my earnestness I am only saying that in spite of taking many such steps I must admit, I have not succeeded as well, as I want to succeed in this matter and I feel it intensely But what is one to do? One has got to persist in it

When it is said it will be taken to the UNO, is there a sense of proportion? Can we be compared to Africa? Is Government encouraging these things anywhere? Is not Government

taking steps to prevent it? Yes, I must say, that we have not been able to devise measures which would stop the occurrence of these things.

SHRI T. BALAKRISHNIAH (Tirupathi): May I ask for a clarification? (*Interruptions*)

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, why are they shouting? You are here to regulate the proceedings. I do not understand these things.. (*Interruptions*) What is this?

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): On an issue like this, why do you want to shout him down? (*Interruptions*)

SHRI MORARJI DESAI: Do not make it a harijan and non-harijan issue. Once a harijan.....

MR. SPEAKER: Once questions and answers start, it will go on endlessly.

SHRI T. BALAKRISHNIAH: Sir, I am a participant in the debate and I have got every right to put a question. I want definite information or answer from the hon. Prime Minister. Our hon. Prime Minister has said that if anywhere it is found that the Government is responsible for these atrocities, he will take action. But his own officers have said that they are helpless in the matter of putting down the atrocities, because the people who are the perpetrators of the crime are claiming that they enjoy the sympathy and support of the Government at the top. Tomorrow. I will show you the paper cutting.

SHRI MORARJI DESAI: I would request my hon. friend to let me know the names of those officers. I will dismiss them.

SHRI T. BALAKRISHNAIAH: Certainly. Tomorrow I will produce it.

SHRI MORARJI DESAI: I agree that steps have to be taken. But why does my hon. friend believe without verifying facts? I would like to know one instance where such a person has been supported by Government. And if any Minister has supported such a person, I will see that the Minister is not there. Why do you doubt it? So, that is not the question. Nobody has been supported. Why are imaginary charges being made? This is not the way at all. But everybody will not be able to reply and contain himself when he is under an attack, even when he does not deserve it. And if he loses he does not deserve it. And if he loses must sympathise with him. You may smile, you may laugh, it is only when one suffers one will realise. These are very serious matters and we have to take them very seriously.

It was said that there should be a separate Minister. Will that solve it? I am prepared to do it tomorrow. It will not. We have, therefore, appointed a Commission for it, and that Commission will be open to all of them.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Make a Harijan the Home Minister and tomorrow you will see the difference.

SHRI MORARJI DESAI: I have been a Home Minister for more than ten years, and I cannot claim that I have been able to finish this matter, and I do not think I was considered an Ordinary Home Minister. So, please do not have any prejudices and say that this is the remedy for it. This again is another dig at the Home Minister, which is very wrong. I must protest against it. This is not right. What is the meaning of saying these things? In such a situation a person will say something in self-defence. Then, the whole question gets blurred and only words remain. That is what happens. I would not like to do that, because these are things which cannot be justified on any account, whatever happens.

[Shri Morarji Desai]

We have got to put our heads together and see how best we can finish this evil, and that is where I would seek the co-operation of all friends.

I am aware that my hon. friends who have suffered are bound to be bitter about it. That does not help, but I cannot say that they should not be bitter. After all, I cannot feel as they feel, I have to admit it whatever my sympathy. Therefore, we must have patience with them. I would therefore plead with my hon. friends that if they want to be effective, this is not the way we can deal with this problem, this is not the way we can solve it. If they want to try to remove the Janata Party from Government, they will be the first victims if the Janata Party Government goes, let them understand. It will not benefit Harijans. It is not a question of Government or party. It is a question of the health of the nation, its honour and its self-respect. I believe that if the self-respect of even one person is hurt by me. I am not fit to serve anybody. This is what I hold and believe. And here it is not only self-respect which is wounded, but the very existence is at stake. Therefore, if people feel angry, we have to bear their attacks and find out ways and means to see that we do not allow such things to happen but we stop them altogether.

There are two ways of doing it. One is taking strong action against those who commit these crimes. Another is, for us to combine in those areas where these things happen to give strength to them and root out the evil in a nonviolent way as Gandhiji taught us. That would give them more courage.

It is said that when the Janata Party Government came, those people felt encouraged to do these things and that is why they are doing them. Does that not mean a political use of it? Have we asked them to do these things or are we conniving at them? Land was given, but given without proper precautions. That is a thing about which I have written to all the Chief Ministers. . .

SHRI SHANKAR DEV (Bidar): I am sorry. Lands have been allotted, definitely legally allotted and they were snatched away. Is he prepared to dismiss the Minister who has insulted all the scheduled castes and scheduled tribes by saying that only one per cent of atrocities have been committed? This is a great insult and we are not going to tolerate it.

SHRI MORARJI DESAI: May I say that instead of helping the process, it is halting the process? It is not going to help anybody. What have I said? I have said that I have written to the Chief Ministers that even if there are cases in which lands have been given in a wrong manner or should not have been given to them. .

SHRI SHANKAR DEV: He must be dismissed.

SHRI MORARJI DESAI: One can get mad with pain and sorrow but that does not help the pain and sorrow. Why get mad? That is what I am pleading. What I said was that even in such cases, they should not be vacated from the lands until they are given other lands which is suitable and which is good for them—not merely any land to be given, that I have said. I have also said that nobody should be allowed to take away the land by force whatever may be the reason, from them and they should be immediately dealt with. I am trying to keep track of such incidents and get reports. Ultimately, one has to see how best it can be done by them. I cannot dictate to people. I do not want to be a dictator.

SHRI C. M. STEPHEN: He is evading. We expect something else from the Prime Minister.

SHRI MORARJI DESAI: Is this not politiking? I am saying that steps have

to be taken. There are two kinds of steps and I am describing them and still my hon. friend, gets the impression that I am evading the issue. Why have I to evade this issue? Is this not politiking?

SHRI C. M. STEPHEN If this is politiking, there is going to be politiking.

SHRI MORARJI DESAI: My hon. friend can go on politiking I have no objection to it. I still seek his cooperation.

SHRI C. M. STEPHEN. That is there.

SHRI MORARJI DESAI· I know what is there. You are telling me this. I have far more experience than you have of public life. Therefore, I understand these things. But why get excited like this?

SHRI C. M. STEPHEN Why do you call it politiking?

SHRI MORARJI DESAI: I cannot mince words in these matters. I can do that with my Harijan friends but not with you.. .I will bear whatever they tell me but I would not take it from you.

SHRI C. M. STEPHEN. I do not expect any concession from you.

SHRI MORARJI DESAI: Let us be as clear as possible. I would be glad if it could be cleared. I have no objection to it. There is no question of any concession to anybody. Why does he talk like that? (*Interruptions*) I will deal with it; you need not bother. But I did say that wherever it has happened, strong action should be taken and the officer responsible for negligence should be suspended and disciplinary action should be taken against him to remove him. I have also said that this applies to officers in whose charge this happens.

SHRI SHANKAR DEV: The Minister must resign.

SHRI MORARJI DESAI Minister cannot resign for the fault of officers. Then every Minister will have to resign every day. Even if my hon. friend becomes the Minister, he will not last a day. This is what will happen. Therefore, why make a proposition which is impossible?

So we must strengthen them and see that they do not suffer particular harassment in the villages. In several places, they are depending on the whole village population for their living. Therefore, they do not allow them to do anything. We should see that they do not have to do that and see that they stand up for their rights in a non-violent manner. If violence comes in, it is not going to benefit anybody. I do not know if violence would solve the problem. It is so bad. It has to be solved. But I do feel that violence will not solve the problem. So, we have to take all steps necessary to see that this ends as soon as possible.

I seek the cooperation of my friends there Any suggestions that they would wish to make, I will give them respectful consideration. But, ultimately, I do think and, I hope it will be understood that I can act only on those suggestions about which I am convinced. We can discuss them. I am prepared to meet a few friends on this matter. It is not a question of the Government or the Opposition. This is a matter for all of us. We have, therefore, to meet and see that we find practical solutions for this problem.

I seek the cooperation of all my friends When I said that a political advantage is sought to be taken, I feel that that does not help. After all, it is the business of the Opposition to find fault with me. If they don't I do not consider them worth it. Therefore, that is not the question. The question is the manner in which the cause is to be served. That is all my

[Shri Morarji Desai]

plea. I do not know why my good friend gets excited. He cannot help it, he must get excited! Let him not do it. It will injure his health.

श्री बसन्त साठे (अकाला) : यह जो आध पौन घंटे का प्रवचन हुआ है, क्या इस में कुछ रीएशोरेंस निकला है ? (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं विरोधी दल के नेता माननीय स्टीफ़न साहब और साठे साहब आदि सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वे यह न समझ लें कि हम लोगों ने जो इतनी गर्मागर्म बहस की है, इससे उन लोगों को कोई लाभ होने वाला है । उन्होंने तीस साल तक जो कूड़ा-करकट जमा किया है, जो गन्दा नाला बनाया है, उसी में इन कीड़ों का जन्म हुआ है। उन्हीं की नीतियों के कारण आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

MR. SPEAKER: Mr. Paswan, let us keep a high level of the debate. Let us not get into another controversy.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह इन लोगों की देन है। इसलिए, आप इन लोगों को शान्त रखें ।

मैं कहता हूं कि आज कहा गया है कि इस को राजनैतिक भावना से न लें। सब से बड़ा कांड हुआ है बेलची का। उस से बड़ा कोई कांड पिछले कुछ समय के अंदर नहीं हुआ है। क्या मैं अपने कांग्रेस के माननीय साथियों से पूछ सकता हूं कि दिल्ली में बैनर ले कर, पोस्टर और पैम्फलेट बांट कर और अखबारों में निकाल कर के बेलची कांड का जो मेन अभियुक्त है इन्द्रदेव चौधरी उस की रिहाई की मांग नहीं की गई ? प्रदर्शन कर के 14 मार्च को मांग की गई कि इन्द्र देव चौधरी को रिहा करो। आप को शर्म नहीं आती है ? .... (व्यवधान) ...और आप कहते हैं कि इसको हम राजनैतिक भावना से नहीं ले रहे हैं। इन्द्र देव चौधरी की रिहाई की मांग की गई पटना में 14 तारीख को।

इसलिये मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस को राजनैतिक भावना से हम न लें । यदि कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के हरिजन एम पी आज तक सतर्क रहते, तैयार रहते, जागरूक रहते तो हम लोगों को यह दिन देखने का मौका नहीं मिलता। हम लोग जागरूक हैं, कांशस है और अपनी सरकार के ऊपर भी सवारी करने के लिए तैयार हैं इसलिए कि हम लोगों को भी आप के ऐसा दुर्दिन देखने का मौका न मिले । माननीय प्रधान मंत्री जी जिन के प्रति हमारी सारी आस्था है, उन से मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन आप लोगों से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जनता पार्टी की हुकूमत जिस के माध्यम से इस देश को नयी दिशा मिलने वाली है, देश में परिवर्तन होने वाले हैं, इस को आप पांच साल तक धैर्य के साथ देखें और उस के बाद जज करें, उस समय भी यदि हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर आप नहीं चिल्लाइएगा, हम चिल्लाएंगे ।

मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधान मंत्री के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। आशा है प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार उस पर ध्यान देगी ।

पहली बात तो यह है कि यह बात सही है कि घटना होती है । घटना घट जाना किसी के बश की बात नहीं है। लेकिन घटना घटने के बाद हम उस पर क्या कार्यवाही करते हैं ? हम ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि जिससे घटना घटे ही नहीं और इस के लिए मैं ने उस दिन सुझाव दिया था कि आज जो भारत सरकार के सामने लाचारी है, भारत सरकार कहती है कि हरिजनों और आदिवासियों का मामला, उन के ऊपर ऐट्रासिटीज का मामला स्टेट का मामला है,

हम उसमें डायरेक्ट इटरफेयर नही कर सकते हैं, उस सबध मे आप कानून में सशोधन कीजिए, सविधान मे सशोधन कीजिए, जो नये उपाय खोजने हो वह खोजिए लेकिन स्टेट और सेंटर दोनो की बराबर जिम्मेदारी इस की रहे कि काई घटना कही हो तो हम भारत सरकार का भी पकड सके और वहा राज्य सरकार को भी पकड सकें।

दूसरी बात—बिहार के मुख्य मत्री ने घोषणा की थी, जगजीवन बाबू यहा बैठे हुए है, उन्ही के समक्ष उन्होने कहा था कि हमे दो चीज करनी होगी। पहली चीज यह कि या तो जितने गरीब हैं उन को हमे हथियार देना होगा और नही तो जितने पूजीपति है उनसे हथियार छीनना होगा। बेमेल लडाई नही चलेगी। एक तरफ रायफल और दूसरी तरफ लाठी, यह लडाई नही चलने वाली है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हू कि जिन क्षेत्रो मे भी इस तरह की कठिनाई हो, जिन क्षेत्रो मे भी हरिजनो के ऊपर अत्याचार हो, जुल्म हो, उन क्षेत्रो मे आज आप हथियार तो सब को नही दे सकते है, लेकिन कम से कम जो पूजीपति है, जो बडे बडे लोग है उन से हथियार छीन लीजिए। वह हथियार भी क्राइम की, उत्पात करने की एक जड है।

तीसरी बात—हमारे साथियो ने सजेशन दिया है कि अत्याचार करने वाले की नागरिकता छीन ली जाय। मैं समझता हू कि सरकार का इसमे कठिनाई नही होगी लेकिन जो माननीय सदस्यो की भावना है वह यह कि उस के लिए कठोर से कठोर दण्ड का विधान बनाया जाय। जो आदमी हरिजन के ऊपर या आदिवासियो के ऊपर अत्याचार करता है, उस की इज्जत के साथ खिलवाड करता है उस के साथ मे कठोरता से पेश आए और उस के लिए स्पेशल कानून बनाने की बात हो तो स्पेशल कानून बनाएं।

मैं एक बात और सरकार के सामने रखना चाहता हू। मैं ने उस दिन भी कहा था कि जाति पाति का जन्म देने वाले ये मन्दिर और मठ है जहा बडे बडे शकराचार्य और आचार्य बैठे हुए है। शकराचार्य जैसे लोग पटना मे और दूसरी जगह जाकर जातिवाद का बीज बोते है और कहते है कि यह जातिवाद जन्मजात आधार पर है। उस के लिए मैं ने उस दिन सुझाव रखा था कि एक रेलीजस इस्टीच्यूशन, धार्मिक सस्थान खोलिए और जिस तरह स्कूलो मे पढाई होती है उसी तरह उस मे हरिजन का भी बच्चा पढे, ब्राह्मण का भी बच्चा पढे, राजपूत और बनिये का भी भी बच्चा पढे। जो उस मे डिग्री ले कर निकले वह जा कर मदिर मे या मठ मे या जहा भी शकराचार्य या और जो आचार्य बनना हो वह बने। कभी कोई नही कह सकेगा कि यह ब्राह्मण है या हरिजन है। वहा वह आचार्य बन कर रहेगा। कोई समझेगा नही कि क्या है। इसलिए एक रलीजस इस्टीच्यूशन खोल कर के आप ऐसा कीजिए।

20.00 hrs.

चौथी बात—अभी सरकारी नौकरी की बात हम लोग करते है। लेकिन मैं भारत सरकार से मांग करता हू कि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे, सरकारी अर्ध-सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उस मे आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। आप ने केवल सरकारी नौकरियों मे 15 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है और उस मे भी कोटा पूरा नही होता है। उस मे सूटेबिलिटी और अनसूटेबिलिटी का मामला आता है। इसलिए मैं आग्रह करूगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे आप आरक्षण की व्यवस्था करे। नौकरियो के मामले मे अभी भी लिखा हुआ है—

[श्री राम विलास पासवान]

If a suitable candidate belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe is not available, then the vacancy will be de-reserved'

प्रधान मंत्री जी का चाहिये कि इस नियम का तुरन्त समाप्त करें। जब आप कहते है हरिजनो मे लाख से ऊपर ग्रैजुएट है लाखो पढे-लिखे लोग हैं प्रथम श्रेणी मे जाने लायक है तो ऐसी स्थिति मे इस प्रकार के नियम को रखने का क्या मतलब है ? इस प्रकार के नियम से अफसरो को गलत काम करने के लिये बल मिलता है। इस लिये मेरा आग्रह है कि इस नियम को तुरन्त समाप्त किया जाय।

इसके साथ मेरा आप से निवेदन है कि आप शेडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए एक पाच वर्ष की योजना बनाये और इस प्रकार की व्यवस्था करे कि पाच साल के बाद इस देश मे कोई भी ऐसा हरिजन का परिवार नही रहेगा, जिसमे कम से कम एक आदमी या तो सरकारी नौकरी मे न लगा हो या किसी रोजगार मे न लगा हो। यदि आप इस प्रकार की योजना शुरू करेंगे तो हम समझेंगे कि आप वास्तव में क्रान्तिकारी काम कर रहे है। आप इस देश के सारे हरिजन परिवारो की लिस्ट बना लीजिये और यह व्यवस्था कीजिये कि पाच साल के अन्दर उस मे से एक आदमी या तो सरकारी नौकरी में होगा या कोई रोजगार कर रहा होगा।

जहा तक अनुसूचित जाति और जनजाति के कमिश्नर का मामला है आप देखे—कि कमिश्नर की रिपोर्ट कितने साल के बाद आई है। मैं सरकार से कहूगा कि यह बहुत बडा मामला है। कोई चीज बनाई जाती है तो उस के पीछे एक उद्देश्य रहता है लेकिन जब वह दबा दी जाती है तो सारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है। आप कोई भी नीति बनायें, पालिसी बनायें अगर उसका कार्यान्वयन न हो या उस का कार्यान्वयन करने वाले ठीक लोग न हो, तो कुछ भी नही लगा। मेरा सुझाव है कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट प्रति वर्ष सदन मे आनी चाहिये और उस के साथ साथ एक्शन-टेकन रिपोर्ट भी पेश की जानी चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं एक सुझाव और रखना चाहूगा—जहा भी हरिजनो पर इस प्रकार के जुल्म होते है—सभी जगह पुलिस स्टेशन्ज बने हुए है। अगर आप उनकी रिपोर्ट ले तो वे कहेंगे कि हमारी क्षमता 30 केसेज की है हम 300 केसेज कैसे देख सकते है। जो डकैत है वे तो जीप पर आते है और हम साइकल पर जाते है तो हम उन का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि हरिजनो पर जो अत्याचार होते है उन का मुकाबला करने के लिए आप स्पेशल सेल बना दीजिये। पाच सात पुलिस स्टेशन्ज मे एक सेल बना दीजिये जो हरिजनो के मामलो की तुरन्त कार्यवाही करे और तुरन्त अपनी रिपोर्ट दे और कोर्ट मे तुरन्त फैसला हो। इस काम के लिये अलग से पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे साथी श्री हुकुम देव जी ने अन्तर्जातीय विवाह का सुझाव दिया है। उस मे मेरा सुझाव है कि बडी जाति की लडकी हो और छोटी जाति का लड़का हो, उन की शादी होगी, तभी अन्तर्जातीय विवाह माना जायगा। आज नीची जाति, हरिजन, की लडकी से ऊची जाति के बहुत से लड़के विवाह कर लेते हैं, इसलिये बडी जाति की लडकी और छोटी जाति का लडका विवाह करे तब उस का अन्तर्जातीय विवाह मान कर उन के लिये आइ०ए०एस० और पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी जगहो के लिये आरक्षण किया जाय। यदि आप इन सारी चीजो को करते हैं तब इस समस्या का निदान

हो सकेगा। मैं प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि यह देश किसी का नहीं है, चाहे इंदिरा रानी हों, चाहे गांव की महतरानी, दोनों के समान अधिकार हैं।

इस देश में न कोई रहा है और न कोई रहेगा। न राजा रहा है, न रानी रहेगी, यह मिट्टी है, मिट्टी कहानी कहेगी। इसलिये इस पर अमल करने का निश्चय करके जाइये, जनता पार्टी हरिजनों के लिये काम करे, ताकि आने वाला इतिहास जनता पार्टी को याद करे और भारत सरकार को याद करे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

MR. SPEAKER: Certain amendments to the motion have been moved by some hon. Members. I shall put them to the vote of the House.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): When the main motion has been withdrawn, there is no need to put these to the vote of the House.

MR. SPEAKER: No, the rules require these to be put to the vote of the House.

Is any hon. Member pressing any particular amendment?

SHRI B. P. MANDAL: I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 1.

Amendment No. 1 was, by leave withdrawn.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 2.

Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.

SHRI YUVRAJ (Katihar): I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 3.

Amendment No. 3 was, by leave, withdrawn.

MR. SPEAKER: Is Shri Rajagopal Naidu there? He is not there. I shall now put amendment No. 4, moved by Shri P. Rajagopal Naidu to the vote of the House.

Amendment No. 4 was put and negatived.

SHRI ROOP NATH SINGH YADAV (Pratapgarh): I seek leave of the House to withdraw my amendment No. 5.

Amendment No. 5 was, by leave withdrawn.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I seek leave of the House to withdraw my motion.

The motion, was, by leave, withdrawn.

20.10 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 10, 1978/Chaitra 20, 1900 (Saka).

GMGIPMRND—I—31 LS(3)—7-6-78—880.